राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 123

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 11 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

द. अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बने मयंक

>> 14

मोदी–चिनफिंग मुलाकात से पहले रिश्तों में तनाव

कूटनीति ▸ कश्मीर पर चीन का रुख अनौपचारिक वार्ता के परिणाम को करेगा प्रभावित

आज चेन्नई पहुंचेंगे चीनी राष्ट्रपति, आने से पहले खेला पाकिस्तान कार्ड

जयप्रकाश रंजन, मामल्लपुरम

चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर मामल्लपुरम (महाबलीपुरम) में नरेंद्र मोदी-शी चिनफिंग के बीच होने वाली दूसरी अनौपचारिक वार्ता की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा इंतजाम की वजह से शहर में पसरा सन्नाटा कुछ वैसा ही है जैसा इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात से 24 घंटे पहले भारत और चीन के रिश्तों में पसरा है।

मोदी के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अफसरों ने इस वार्ता की तैयारी इस सोच से शुरू की थी कि द्विपक्षीय रिश्तों की राह में बड़े रोड़े बने मुद्दों को जड़ से मिटाने की कोशिश हो, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि कश्मीर मुद्दा भारत-चीन के बीच नई अड़चन बन रहा है। मोदी-चिनफिंग अगले 48 घंटों में जब तीन दौर में बातचीत करेंगे तो रिश्तों में कश्मीर की वजह से पसरे तनाव को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा मशक्कत करेंगे।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच यह दूसरी अनौपचारिक बातचीत है। पहली बातचीत अप्रैल, 2018 में वुहान (चीन) में हुई थी। जानकारों की मानें तो वार्ता से ठीक पहले दोनों देशों ने जिस तरह का कूटनीतिक अंदाज दिखाया है उससे साफ है कि एक दूसरे पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। चिनफिंग के भारत आने से ठीक पहले चीन का पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को आमंत्रित करना और द्विपक्षीय वार्ता में कश्मीर पर चीन के राष्ट्रपति की तरफ से बेहद आपत्तिजनक बयानबाजी भारत को दबाव में लेने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने चिनफिंग के बयान की जिस अंदाज में निंदा की और उसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया वह भारत के बदले तेवर को दर्शाता है। यही वजह है कि वरिष्ठ राजनयिक एमके भद्रकुमार ने कहा है कि इस बार वुहान वाली भावना नहीं दिख रही है। प्रख्यात कूटनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी ने कहा है, 'चीन भारत को पाक के चश्मे से नहीं देखता बल्कि वह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ छद्म तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।'

इन तनाव भरे क्षण में भी दोनों तरफ के विदेश मंत्रालयों की तरफ से मोदी-चिनफिंग वार्ता को कामयाब बनाने की जबरदस्त कोशिश चल रही है। एक अधिकारी ने कहा, हालात वुहान वार्ता से पहले जितने खराब थे उतने अब नहीं हैं। तब कुछ ही माह पहले डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने कई महीनों तक तैनात रही थीं। इस बार बहुत कुछ पॉजिटिव है जिसे लेकर दोनों नेता रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि मोदी-चिनफिंग के बीच होने वाली मुलाकात के बाद जारी बयान माहौल में आए तनाव को खत्म कर देंगे। भारत में चीन के राजदूत ने कहा, 'दोनों देशों के बीच सिर्फ सकारात्मक रिश्तों की गुंजाइश है, इसके लिए मिलजुलकर शांति बनाने की कोशिश की जाएगी।'

इसके बावजूद इससे इन्कार नहीं कि मोदी व चिनफिंग मुलाकात पर पाकिस्तान और कश्मीर का साया पड़ चुका है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि मोदी कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर चीन की तरफ से इसे उठाया जाता है तो उन्हें हालात से अवगत कराने की पूरी तैयारी है।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइल फोटो। एपी

जबर्दस्त होगी चिनफिंग की अगवानी

विदेश मंत्रालय और तमिलनाडु सरकार की तरफ से चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। चीन के राष्ट्रपति और उनके साथ आए दल को भारत व चीन के बेहद पुराने रिश्तों को महाबलीपुरम स्थित तीन अहम ऐतिहासिक स्थलों के जरिये पेश किया जाएगा। ये स्थल हैं अर्जुन की तपस्या, पांच रथ, समुद्र किनारे स्थित मंदिर (शोर टेंपल)। मोदी शुक्रवार शाम चिनफिंग को लेकर तकरीबन 1300 वर्ष पूर्व पहाड़ों को काटकर बनाए गए गुफाओं और भित्ती चित्रों के दर्शन कराएंगे। देर शाम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है जो भारत–चीन के रिश्तों को दिखाएगा। सनद रहे कि इस शहर से ही चीन में बौद्ध धर्म के विस्तार की शुरुआत हुई थी। यह शहर चीन के कारोबार का एक बड़ा केंद्र था जिसके जरिये चीनी व्यापारी समूचे दक्षिण भारत में कारोबार करते थे।

मोदी–चिनफिंग कार्यक्रम

- दोपहर 2.00 बजे चेन्नई एयर पोर्ट पर पहुंचेंगे चिनफिंग, फिर होटल जाएंगे।
- शाम 5.00 बजे प्रधानमंत्री मोदी उन्हें तीन ऐतिहासिक स्थलों पर लेकर जाएंगे।
- इसके बाद दोनों नेता शोर टेंपल जाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे।
- शोर टेंपल लॉन में बैठकर ही दोनों नेता बातचीत करेंगे।
- शोर टेंपल परिसर में मोदी चीनी राष्ट्रपति के लिए निजी डिनर आयोजित करेंगे।
- शनिवार सुबह दोनों नेता फिशरमैंस कोव रिजॉर्ट में अकेले बातचीत करेंगे।
- इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी।
- वार्ता के बाद पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति के लिए लंच आयोजित करेंगे।
- दोपहर 12.45 बजे चिनफिंग चेन्नई एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।

वुहान टू मामल्लपुरम पेज>>5

सरोकार

बारिश की बूंदें सहेजेगी आइआइटी में तैयार ये ईंट

वाराणसी : आइआइटी बीएचयू ने बारिश की बूंदों को सहेजने का बेहतरीन उपाय ढूंढ निकाला है। गलियों में बिछाई जा सकने वाली ये ईंट आवागमन में सुविधाजनक होने के साथ ही बारिश की बूंदें भी सहेजेगी। बारिश का जल व्यर्थ बह जाता है। इस ईंट से यह दिक्कत दूर होगी। (पेज–10)

जागरण विशेष

निर्माण क्षेत्र में क्रांति के लिए तैयार है एफआरपी

जमशेदपुर : टाटा स्टील के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग ने फाइबर रिइनफोर्स्ड पॉलीमर (एफआरपी) और ग्राफीन की मदद से ऐसा उत्पाद तैयार किया है जो बेहद हल्का होने के साथ बेहद टिकाऊ है। इससे निर्माण क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होगा। (पेज–10)

नाराज बैंक ग्राहकों से वित्त मंत्री ने कहा–बदलेगा कानून

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिफारिशों के लिए बनाई कमेटी

मुंबई, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को गुरुवार को पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले के पीड़ित खाताधारकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सहकारी बैंकों में बेहतर कामकाज के लिए कानून में बदलाव करने की सिफारिश के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस कांफ्रेंस में कहा, नियामक संस्थाओं को और बेहतर बनाकर भविष्य में घोटालों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। सरकार इस पूरे मामले को समझकर आगे ऐसी घटनाएं रोकने के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाएगी।,आर्थिक मामलों व वित्तीय सेवाओं, ग्रामीण मामलों व नगरीय विकास मंत्रालयों के सचिवों, आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर की कमेटी गठित की जाएगी। अगर जरूरी होगा तो सरकार संसद के शीत सत्र में सहकारी बैंकों का संचालन करने वाले कानूनों में संशोधन करेगी।

आरबीआइ गवर्नर से करेंगी बात : पीएमसी बैंक के गुस्साए खाताधारकों ने दक्षिण मुंबई स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर हंगामा किया। बात और बढ़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारी प्रेस कांफ्रेंस हाल में घुस आए। प्रदर्शनकारियों ने सीतारमण के पहुंचते ही नारेबाजी शुरू कर दी। वह अपनी जमा रकम को वापस देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद सीतारमण ने अंदर एक कमरे में कुछ प्रदर्शनकारियों से संक्षिप्त बैठक कर उनकी मांगों को सुना। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खाताधारकों की परेशानियों को सुना और उन्हें समझाया कि कई राज्यों वाले इस बैंक का नियमन आरबीआइ के हाथ में है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस बारे में आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास से बात करेंगी और वह उन्हें खाताधारकों की परेशानी के बारे में आगाह करेंगी।

नेताओं की जागीर सहकारी बैंक : सहकारी बैंक आमतौर पर राजनेताओं या अन्य प्रभावशाली लोगों की जागीर बन जाते हैं। उन्हें नियमों से परे मानकर नियमों की अनदेखी करते हुए बड़े कर्ज दे दिये जाते हैं और रकम डूबने पर वह बोझ बैंक के खाताधारकों पर डाल दिया जाता है। पिछले दो दशकों में कई सहकारी बैंक विफल रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाला एकदम नया है। पिछले महीने यह घोटाला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक से सिर्फ एक हजार रुपये ही निकालने की शर्त लगा दी। लेकिन बाद में खाताधारकों के विरोध-प्रदर्शन के बाद 25 हजार रुपये तक निकालने की छूट दे दी। दिवालिया होने की कगार पर पहुंची रियाल्टी क्षेत्र की कंपनी एचडीआइएल को इस बैंक ने अपने पास मौजूद रकम का 70 फीसद हिस्सा बतौर कर्ज दे दिया था। एचडीआइएल ने 9000 करोड़ रुपये का यह कर्ज अब तक नहीं चुकाया है। पंजाब और महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक में 4500 करोड़ रुपये के घोटाले के सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने बैंक से रकम निकालने पर रोक लगा दी है।

पीएमसी घोटाला

- कहा–शीतकालीन सत्र में संशोधित हो सकता है बिल
- भाजपा कार्यालय के बाहर खाताधारकों का प्रदर्शन

मुंबई में गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने पीएमसी बैंक घोटाले के पीड़ित खाताधारकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। प्रेट्र

बकाएदारों को बेलआउट पैकेज, खाताधारकों को राहत नहीं : कांग्रेस

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष चरन सिंह सापरा ने कहा, कर्ज बकाएदारों के लिए बेलआउट पैकेज है, पर खाताधारकों को कोई राहत नहीं दी गई है। वित्त मंत्री ने जो कुछ भी कहा वह जबानी जमा खर्च है। आम जनता को संकट से उबारने का कोई प्लान नहीं है। सरकार दो रातों में आरे कालोनी के हजारों पेड़ों काट चुकी है, क्या पीएमसी बैंक संकट का हल 17 दिनों में नहीं निकाल सकती है।

बंगाल में तिहरे हत्याकांड को राज्यपाल ने बताया शर्मनाक, सरकार से मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- दशहरे के दिन की गई थी संघ कार्यकर्ता, गर्भवती पत्नी और 8 साल के बच्चे की हत्या
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा, पुलिस की निष्क्रियता से अपराधियों का दुस्साहस बढ़ा

बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में विजयादशमी (दशहरे) के दिन हुए तिहरे हत्याकांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। दशहरे के दिन हुए इस नृशंस हत्याकांड को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा-'मैं इस तरह की वारदात से स्तब्ध और दुखी हूं। यह बंगाल में कानून व्यवस्था की संकटपूर्ण स्थिति को दिखा रहा है। धनखड़ ने कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। यह दिखाता कि किस तरह राज्य में सरकारी तंत्र और पुलिस काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने राज्य सरकार से घटना की तत्काल रिपोर्ट मांगी है।

उल्लेखनीय है कि बंधु प्रकाश पाल (35), उनकी गर्भवती पत्नी ब्यूटी मंडल पाल (30) और बेटे अंगन बंधु पाल (8) की घर से खून से लथपथ लाशें बरामद हुई थीं। उनकी धारदार हथियारों से हत्या की गई थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बंगाल शाखा के सचिव जिष्णु बसु ने बंधु प्रकाश पाल के संघ के सक्रिय कार्यकर्ता होने का दावा किया है। वहीं वारदात को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि बंगाल में पुलिस की निष्क्रियता के चलते ही अपराधियों का दुस्साहस बढ़ रहा है। ज्यादातर घटनाएं बंगाल में दिनदहाड़े हुई हैं। उम्मीद है कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी बंगाल में महिलाओं की दुर्दशा को समझेंगी और तत्काल कार्रवाई करेंगी।

जगदीप धनखड़ फाइल फोटो

मुर्शिदाबाद हत्याकांड के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार पेज>>5

न्यूज गैलरी

राज–नीति ▸ पृष्ठ 3

संघीय ढांचे के लिए कांटा है अनुच्छेद 356 : योगेंद्र नारायण

नई दिल्ली : राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण ने संविधान के अनुच्छेद 356 को केंद्र व राज्यों के बीच टकराव की शुरुआत का मूल करार देते हुए इसे समाप्त किए जाने की जरूरत बताई है। उन्होंने राज्यपालों की नियुक्ति के लिए पीएम, नेता विपक्ष व गृह मंत्री की चयन समिति बनाने सुझाव भी दिया।

महासमर ▸ पृष्ठ 4

एक भारतीय जवान के बदले दुश्मन के 10 मारे जाएंगे : शाह

सांगली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई है और पूरी दुनिया ने माना है कि अगर भारत का एक जवान शहीद होगा तो दुश्मन के 10 मारे जाएंगे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी व शरद पवार स्पष्ट करें कि वे अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ हैं या पक्ष में।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

जवाबी कार्रवाई में पाक की पांच चौकियां तबाह, तीन सैनिक ढेर

जम्मू : बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को पुंछ के सात सेक्टरों बालाकोट, बलनोई, देगवार, खड़ी करमाड़ा, शाहपुर किरनी, कसबा और गोंतरियां में भारी गोलाबारी की। इसमें सात घर क्षतिग्रस्त हो गए और महिला समेत दो नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में बालाकोट सेक्टर के उस पार पाक सेना की पांच चौकियां तबाह हो गईं और उसके तीन सैनिक मारे गए।

आजकल ▸ पृष्ठ 16

पोलैंड की ओल्गा और ऑस्ट्रिया के हैंडके को साहित्य का नोबेल

स्टॉकहोम : साहित्य के क्षेत्र में नोबेल विजेताओं के नाम के लिए दो साल का इंतजार गुरुवार को खत्म हो गया। स्वीडिश अकेडमी ने 2018 और 2019 के लिए साहित्य का नोबेल जीतने वालों के नाम का एलान कर दिया है। 2018 की विजेता पोलैंड की लेखिका ओल्गा तोकार्जुक और 2019 के विजेता ऑस्ट्रिया के उपन्यासकार व पटकथा लेखक पीटर हैंडके बने हैं।

दवा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सहित चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 740 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह समेत चार लोगों को धोखाधड़ी के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अन्य लोगों में रेलिगेयर के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी, कवि अरोड़ा और अनिल सक्सेना शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने सार्वजनिक धन का गलत तरीके से अपनी कंपनियों में निवेश किया। शिविंदर के छोटे भाई मालविंदर मोहन सिंह के खिलाफ भी लुक आउट नोटिस जारी किया गया है।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. ओपी मिश्रा के मुताबिक, शिविंदर मोहन साउथ एक्स पार्ट दो, सुनील गोधवानी असोला फतेहपुर बेरी, रवि अरोड़ा गुरुग्राम व अनिल सक्सेना नोएडा सेक्टर 104 में परिवार के साथ रहते हैं। पुलिस ने कई महीने तक उक्त मामले में विस्तृत जांच की। आरोप सही पाए जाने पर डीसीपी वर्षा शर्मा के नेतृत्व में एसीपी अमरदीप सहगल, इंस्पेक्टर संजीव धोढ़ी, उमेश शर्मा, नितिन कुमार की टीम ने गुरुवार को चारों को पूछताछ के बहाने मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा के मुख्यालय बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। रेलिगेयर फिनवेस्ट के अधिकारी मंजीत सिंह सूरी ने मालविंदर, शिविंदर व सुनील व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। रेलेगेयर इंटर प्राइजेज के प्रमोटर रहे शिविंदर के आरएफएल में भी 85 फीसद शेयर है। गोधवानी रेलिगेयर एंटरप्राइजेज का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक था। कवि और अनिल रेलिगेयर में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत थे।

रेलिगेयर फिनवेस्ट के अधिकारी मंजीत सिंह सूरी ने लगाया था 740 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

एफएटीएफ बैठक से घबराए पाक ने पकड़े जमात और लश्कर के चार बड़े आतंकी

- प्रतिबंधित संगठन लश्कर–जमात के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हैं ये आतंकी
- काली सूची में डाले जाने के खतरे से डरा हुआ है इस्लामाबाद

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन लश्कर और जमात के चार बड़े आतंकियों को आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस कदम के बारे में अफसरों का कहना है कि संगठन का पूरा कोर नेतृत्व अब सुनवाई का सामना करेगा। लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के गिरफ्तार आतंकियों में प्रोफेसर जफर इकबाल, याहया अजीज, मुहम्मद अशरफ और अब्दुल सलाम शामिल हैं।

पाक ने यह कदम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की समग्र बैठक से पहले उठाया है। यह बैठक पेरिस में 12 से 15 अक्टूबर तक होगी। पेरिस स्थित वाचडॉग ने पिछले वर्ष जून में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला था। उसे एक कार्रवाई की योजना सौंपी थी जिसे अक्टूबर 2019 तक पूरा किया जाना था। ऐसा नहीं होने पर पाकिस्तान को काली सूची में शामिल होने का खतरा है। काली सूची में अभी ईरान और उत्तर कोरिया हैं।

आतंकवाद निरोधक दस्ता (सीटीडी) के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (एनएपी) में 'महत्वपूर्ण प्रगति' हुई है। सीटीडी पंजाब ने जमात-लश्कर के शीर्ष नेताओं को आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।, 'जमात-लश्कर प्रमुख हाफिज सईद पहले से ही जेल में बंद है और वह आतंकी फंडिंग करने के अपराध के लिए सुनवाई का सामना कर रहा है। अब जमात-लश्कर का पूरा मुख्य नेतृत्व सुनवाई का सामना करेगा।' सीटीडी ने सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अभी वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। 2012 में ही अमेरिका ने उसे पकड़वाने वाले को एक करोड़ डॉलर का इनाम देने की पेशकश की थी।

सीटीडी पंजाब आतंकी फंडिंग के मामले की जांच कर रहा है। इन आरोपितों ने आतंकी फंडिंग से जुटाए धन का इस्तेमाल कर संपत्ति बनाई है। सीटीडी ने कहा, 'संदिग्धों ने आगे इन संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए और धन जुटाने में किया। संदिग्धों व उनके संगठनों जमात-लश्कर को संपत्ति-परिसंपत्ति दान करने वाले कई लोग भी जांच के दायरे में हैं। संदिग्धों ने अल-अनफाल ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट बनाए, जो आतंकी संगठनों के मुखौटे के रूप में काम कर रहे थे। संपत्तियां सरकार द्वारा फ्रीज की जा चुकी है।'

पाकिस्तान ने एफएटीएफ बैठक के लिए अनुपालन रिपोर्ट तैयार की पेज>>13

सुपर मॉम मेरी कॉम से बढ़कर कोई नहीं

उलान–उदे (रूस), प्रेट्र : छह बार की चैंपियन एमसी मेरी कॉम (51 किग्रा) ने सटीक पंच और अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए महिला विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। 36 वर्षीय और तीन बच्चों की मां मेरी कॉम ने कोलंबिया की वालेंशिया विक्टोरिया को 5-0 से शिकस्त दी।

सुपर मॉम मेरी कॉम ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। वह विश्व चैंपियनशिप के इतिहास की सबसे सफल मुक्केबाज बन गईं और अपना आठवां पदक भी पक्का किया। पदकों की संख्या के आधार पर वह पुरुष और महिला दोनों में सबसे सफल हैं। पुरुष वर्ग में क्यूबा के फेलिक्स सावोन ने सर्वाधिक सात पदक (छह स्वर्ण, एक रजत) जीते हैं। मेरी कॉम के नाम अभी तक छह स्वर्ण और एक रजत पदक है, लेकिन वह 51 किग्रा में पहली बार पदक जीतेगी। वह राज्यसभा सदस्य भी है। (पेज–14)

घमासान

ब्रिटेन में कांग्रेस ने की कश्मीर पर चर्चा, भाजपा ने घेरा

ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा का ट्वीट किया, भाजपा ने कहा – देश कांग्रेस की इस शर्मनाक धोखेबाजी का जवाब जरूर देगा

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के एक ट्वीट ने भारतीय राजनीति में घमासान मचा दिया है। कॉर्बिन ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने ब्रिटेन में भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा की। कॉर्बिन का यह ट्वीट सामने आते ही भाजपा ने कांग्रेस को घेर लिया है और इस कृत्य को शर्मनाक बताया है।

कॉर्बिन ने बुधवार को ट्वीट किया था, 'ब्रिटेन में भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों से बहुत अर्थपूर्ण मुलाकात हुई। इस दौरान हमने कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा की। लंबे समय से इस क्षेत्र को जकड़े हुए भय व हिंसा का चक्र रुकना चाहिए और शांति स्थापित होनी चाहिए।' कॉर्बिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की है। ब्रिटेन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की कमान संभाल रहे कमल धालीवाल भी तस्वीर में दिख रहे हैं।

तस्वीर और ट्वीट सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरे में ले लिया। भाजपा ने कहा, 'कांग्रेस को भारत की जनता के सामने बताना चाहिए कि उसके नेता विदेशी नेताओं को भारत के बारे में क्या बता रहे हैं। इस शर्मनाक धोखेबाजी के लिए देश कांग्रेस को जरूर जवाब देगा।' भाजपा में विदेश मामलों के विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे विजय चौथाईवाले ने कहा, 'यह कांग्रेस है, जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता से सलाह ले रही है। वह सीधे पाक में अपने आकाओं के पास भी जा सकती है।'

कांग्रेस की ब्रिटेन इकाई ने दी सफाई : कांग्रेस की ब्रिटेन इकाई ने इस मुलाकात पर सफाई दी है। पार्टी ने कहा, 'जेरेमी से यह मुलाकात हमने अपनी पार्टी द्वारा कश्मीर पर लाए गए रिजॉल्यूशन की निंदा करने और यह पक्ष रखने के लिए की थी कि कश्मीर देश का आंतरिक मामला है। इस मामले में किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। भाजपा अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसे मुद्दा बना रही है।' कांग्रेस ने कहा कि भाजपा आर्थिक सुस्ती, बेरोजगारी और बैंकिंग संकट जैसे सवालों पर निरुत्तर है, इसलिए झूठ फैला रही है।

देश में कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा : इस बीच, देश में कांग्रेस ने इस मुलाकात से पल्ला झाड़ लिया है। वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के विदेश विभाग के प्रमुख आनंद शर्मा ने कहा कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस भारत की नीति एवं घरेलू मामलों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं है। शर्मा ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी को जो भी कहना है, वह यहां भारत में कहेगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति, इकाई या संस्था को यह अधिकार नहीं है। मैं लेबर पार्टी के नेतृत्व को भी इस बात से अवगत करा दूंगा, जिससे जेरेमी कॉर्बिन तक यह जानकारी पहुंच जाए। कांग्रेस पार्टी देश के आंतरिक विषयों पर किसी बाहरी से कभी बात नहीं करेगी।'

जेरेमी कॉर्बिन फाइल फोटो

गोरखपुर की आयशा बनीं एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त

नई दिल्ली : जब एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनीं गोरखपुर की आयशा खान ने उच्चायोग के अफसरों से उनके कामकाज को लेकर सवाल दागने शुरू किए तो भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एसक्वीथ भी हैरत में पड़ गए। दुनिया व जिंदगी के प्रति शायद उसकी जागरूकता ही वजह रही कि आयशा ने शहरी पृष्ठभूमि की लड़कियों को मात देते हुए एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने की प्रतिस्पर्धा में बाजी मारी। (पेज–7)

वैश्विक विरोध के बावजूद तुर्की के कुर्दों पर हमले जारी

इस्तांबुल : अंतरराष्ट्रीय निंदा को दरकिनार करते हुए तुर्की ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सीरिया के कुर्द नियंत्रण वाले इलाकों पर हवाई और जमीनी हमले जारी रखे। हमलों में नौ महीने के बच्चे मुहम्मद उमर समेत छह लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। 60 हजार से ज्यादा लोगों के जान बचाकर भागने की खबर है। तुर्की के कदम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने क्षेत्र में फिर से अस्थिरता का दौर शुरू होने की आशंका जताई है। (पेज–13)

संदीप दीक्षित ने पीसी चाको को भेजा कानूनी नोटिस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- मानसिक प्रताड़ना से हुई मेरी मां की मौत माफी मांगे प्रदेश प्रभारी

अध्यक्ष विहीन दिल्ली कांग्रेस में अंतर्कलह बेहद तीखी और व्यक्तिगत हो गई है। दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको को कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें अपनी मां की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। संदीप ने संगीन आरोप लगाया है कि चाको के मानसिक उत्पीड़न से उनकी मां का निधन हुआ है। शीला के निधन के ढाई माह बाद उनकी मौत के कारण ने कांग्रेस की गुटबाजी को आरपार की लड़ाई बना डाला है।

संदीप ने नोटिस में कहा है कि चाको मेरी मां का मानसिक प्रताड़ना के लिए माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। संदीप ने माफी न मांगने की सूरत में पुलिस में केस दर्ज कराने की भी बात लिखी है। ज्ञात हो, शीला दीक्षित की मौत के बाद सोनिया गांधी को उनके द्वारा लिखे कथित खत का जिक्र भी राजनीतिक गलियारों में होता आया है। हालांकि, शीला का लिखा वह कथित आखिरी खत अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। बताया जाता है कि पत्र में शीला दीक्षित ने सोनिया गांधी से पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी पर दुख जताते हुए उसे परेशानी का सबब करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पीसी चाको किसी वरिष्ठ नेता के इशारे पर कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। शीला के आखिरी दिनों में उनके मानसिक तौर पर परेशान रहने की बात उनके बेटे संदीप सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। संदीप ने मां की मौत के बाद यह बयान भी दिया था कि पार्टी में कुछ लोग ओछी हरकतें कर रहे हैं, जिसका नुकसान भी हुआ। शीला ने मौत से पहले सभी ब्लॉक कमिटियों को भंग करने, तीनों कार्यकारी अध्यक्षों के कार्यभार में फेरबदल और सभी 280 ब्लॉक में आब्जर्वर नियुक्त करने का अहम फैसला लिया था।

67 लाख रुपये की मुआवजा राशि सड़क दुर्घटना में मारी गई दक्षिणी निगम की महिला कर्मचारी सरोज के परिजनों को देने का आदेश दिया है एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने। दुर्घटना में महिला के पति भी घायल हो गए थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 11 अक्टूबर 2019

हिंडन एयरपोर्ट पर आज साढ़े बारह बजे उतरेगा पहला यात्री विमान

नई शुरुआत ▸ हेरिटेज और स्टार एयर के अधिकारियों ने जांची एयरपोर्ट की व्यवस्था, कंट्रोल रूम से चप्पे-चप्पे पर नजर रखेंगे पुलिसकर्मी, सीसीटीवी कैमरे भी शुरू

पिथौरागढ़ से नौ सीटर विमान यात्रियों को लेकर पहुंचेगा दोपहर एक बजे भरेगा उड़ान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

हिंडन एयरपोर्ट के शुरू होने का इंतजार शुक्रवार को खत्म होने जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर पहला यात्री विमान उतरेगा। पिथौरागढ़ से नौ यात्री यहां पहुंचेंगे। गुरुवार को एयर हेरिटेज और एयर स्टार के अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं, एयरपोर्ट शुरू होने से पूर्व ही इसकी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के माध्यम से एयरपोर्ट के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है।

मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इसके बाद से लगातार इसके शुरू होने के कयास लगाए जा रहे थे। शुक्रवार से हिंडन एयरपोर्ट से पहली उड़ान हो सकेगी। पिथौरागढ़ से नौ सीटर विमान यात्रियों को लेकर दोपहर साढ़े बारह बजे हिंडन पहुंचेगा। यहां से पहला विमान दोपहर एक बजे पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरेगा।

सात किलो तक ले जा सकेंगे सामान : हिंडन एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वाले यात्री महज सात किलो तक का ही सामान ले जा सकेंगे। सिर्फ एक हैंडबैग ले जाने की ही अनुमति होगी। उधर, एयरपोर्ट की शुरुआत से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली है। 55 पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग देकर यहां तैनात किया गया है। वहीं चप्पे-चप्पे पर कुल 17 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे एयरपोर्ट के हर हिस्से पर नजर रखी जा सकेगी। यहां मौजूद पुलिसकर्मियों को यात्रियों से अच्छे से बात करने के लिए भी ट्रेनिंग दी गई है।

पहले दिन से मिल सकेगी वाई-फाई की सुविधा : यात्रियों को यहां पहले दिन से ही वाई-फाई की सुविधा मिल सकेगी। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी। इतना ही नहीं यात्रियों को करीब 45 मिनट पहले चेक इन करना होगा। स्टार और हेरिटेज दोनों कंपनियों ने अपने चेक इन काउंटर तैयार कर लिए हैं। साथ ही लगेज बेल्ट और अन्य व्यवस्थाएं भी की जा चुकी हैं।

यात्री महज सात किलो तक का ही सामान ले जा सकेंगे। जागरण

एडीजी ने लिया जायजा

अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी), मेरठ प्रशांत कुमार ने हिंडन एयरपोर्ट पहुंचकर शुक्रवार से शुरू होने वाली उड़ान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों व एयरपोर्ट अधिकारियों से वार्ता भी की। पुलिस क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद डॉ. राकेश कुमार मिश्र मुख्य सुरक्षा अधिकारी का जिम्मा संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उड़ान बढ़ने के अनुपात में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक (नगर) श्लोक कुमार ने थाना प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद जितेंद्र सिंह को भोपुरा रोड और उसके आसपास से एयरपोर्ट तक जिगजैक बैरियर लगाकर वाहनों की जांच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट में आने वाले वाहनों को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया जाए। सभी वाहनों का विवरण रजिस्टर में लिखा जाए।

एयरपोर्ट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार को पिथौरागढ़ के लिए पहली उड़ान होगी। सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं।
-शोभा भारद्वाज, डायरेक्टर हिंडन एयरपोर्ट

जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए टैक्सी होगी पहली पसंद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- राइट्स ने एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए तैयार की मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट
- बेंगलुरू, आइजीआइ दिल्ली के आधार पर किया गया है आकलन

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए यात्रियों की पहली पसंद टैक्सी होगी। करीब 65 फीसद यात्री टैक्सी से एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। बेंगलुरू एयरपोर्ट पर 57 फीसद व दिल्ली में आइजीआइ एयरपोर्ट पर आने जाने के लिए करीब 51 फीसद यात्री टैक्सी का चुनाव करते हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट में विभिन्न विकल्पों का अध्ययन कर यह आंकड़ा पेश किया गया है।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2023-24 में यात्री सेवाएं शुरू होने का अनुमान है। शुरुआत से ही जेवर एयरपोर्ट पर करीब 53 लाख अस्सी हजार यात्रियों का अनुमान लगाया गया है। ये यात्री उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड से होंगे। यात्रियों को जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट परिवहन के विभिन्न माध्यमों की जरूरत होगी। जो कम से कम समय में सुविधाजनक तरीके से यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचा सकें। एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या ट्रांसपोर्ट पर काफी हद तक निर्भर करेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (नियाल) ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर राइट्स से रिपोर्ट तैयार कराई है। राइट्स ने एयरपोर्ट से दो सौ किमी की परिधि में आने वाले 43 जिलों के आधार पर अपनी प्राथमिक व्यवहारिक रिपोर्ट नियाल को सौंपी है।

राइट्स की मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए सौंपी गई प्राथमिक व्यावहारिक रिपोर्ट में जेवर एयरपोर्ट पर आने-जाने के लिए सबसे अधिक यात्री टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे। अन्य विकल्पों पर भी सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए योजना तैयार की जाएगी।
-शैलेंद्र भाटिया, नोडल अफसर नियाल

इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरू, दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट की तरह जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने जाने के लिए यात्री सबसे अधिक टैक्सी का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बार कार का विकल्प दूसरी प्राथमिकता होगा। बस से मात्र 10 फीसद यात्री की एयरपोर्ट तक पहुंचना पसंद करेंगे।

बेंगलुरू व दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पर आधार पर किया आकलन : राइट्स ने ट्रांसपोर्ट के विकल्प सुझाने के लिए बेंगलुरू व दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट का आधार बनाया है। बेंगलुरु में 57.4 फीसद लोग टैक्सी से एयरपोर्ट तक आते-जाते हैं। दिल्ली में 55.1 फीसद की पसंद टैक्सी है। इसके अलावा बेंगलुरू में एयरपोर्ट के लिए कार का इस्तेमाल करने वाले 20.8 फीसद, बस का 15.8 व रेल का विकल्प चुनने वाले 5.9 फीसद हैं। दिल्ली में कार से 11 फीसद, बस से 4.2 फीसद और मेट्रो से 28.6 फीसद यात्री एयरपोर्ट आते-जाते हैं। ऑटो व रेल से आने-जाने वाले यात्री नाममात्र के ही हैं। जेवर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने पर 25 फीसद कार से और दस फीसद बस का उपयोग करेंगे। एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं 2023-24 में शुरू हो जाएंगी। तब तक एयरपोर्ट मेट्रो का संचालन शुरू नहीं हो पाएगा। इसके 2025 से शुरू होने का अनुमान लगाया गया है। मेट्रो शुरू होने से बीस फीसद यात्री एयरपोर्ट के लिए इसका उपयोग करेंगे।

यात्री चलती ट्रेन से भी दर्ज करा सकेंगे एफआइआर

एनडीएमसी के कंवेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए जीआरपी वेबसाइट लांच करते केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय। साथ में दिल्ली पुलिस के आयुक्त अमूल्य पटनायक, आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार और अन्य अधिकारी। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

रेल यात्रियों की सुविधा के लिए गुरुवार को जीआरपी की वेबसाइट और सहयात्री मोबाइल एप लांच किया गया। एनडीएमसी कंवेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वेबसाइट और एप लांच किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एप के जरिये रेल यात्री किसी भी समय अपने साथ हुए अपराध की एफआइआर चलती हुई ट्रेन से दर्ज करा सकेंगे। वहीं अपनी शिकायत और सुझाव भी एप के जरिये दे सकेंगे। वहीं, जीआरपी की वेबसाइट से लोगों को रेलवे के संबंध में जानकारियों मिलने के साथ अधिकारियों को रेल में अपराध करने वाले बदमाशों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इससे अपराध पर अंकुश लगाकर रेल यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

24 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के जीआरपी प्रमुखों को वेबसाइट का सुपर एडमिन बनाया गया है। अलग-अलग उपयोगकर्ता आइडी व पासवर्ड दिए गए हैं। अधिकारी अपनी आवश्यकता अनुसार नियंत्रण पर्यवेक्षक अधिकारियों के लिए आगे अकाउंट बना सकते हैं। अपराधियों के आपराधिक डेटा बेस (कंपेंडियम) में पूरे भारत में रेलवे के क्षेत्राधिकार में देखा जा सकेगा। डकैत, लुटेरों, झपटमार, बैग उठाने वाले, जेबतराश, नशीले पदार्थों के तस्कर और बच्चा चोरी करने वाले बदमाशों की तस्वीर और गिरोह के सदस्यों के बारे में सभी राज्यों की जीआरपी को जानकारी मिल सकेगी। बदमाश रेल में बार-बार अपराध करते हैं। ऐसे में इनकी पहचान और इन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, अज्ञात शव, लापता व्यक्ति, वांछित अपराधी, फरार व घोषित अपराधी और अन्य महत्वपूर्ण मामले, कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों का विवरण भी साझा किया जा सकेगा। प्रमुख घटना व महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ यात्रियों की भीड़, प्रदर्शन, विरोध, बंद, त्योहार का मौसम या किसी भी दुर्घटना की सूचना भी एक साथ सभी राज्यों की जीआरपी को दी जा सकेगी। जीआरपी की वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। इसे एंड्रॉइड और आइओएस के लिए हाइब्रिड एप्लिकेशन में भी विकसित किया गया है। यह वेबसाइट एसएसएल (सुरक्षित सॉकेट लेयर) के साथ भी सुरक्षित है। वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी में होने के साथ इसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी तैयार किया गया है।

वेबसाइट के सभी पृष्ठों से वन टच के साथ हिम्मत प्लस, तत्पर और सहयात्री जैसे एप भी दिखाई देंगे। इस वेबसाइट से दिल्ली जीआरपी पुलिस स्टेशन के जियो टैगिंग के साथ 30 सेवाओं की जानकारी मिलेगी। शिकायत व एफआइआर करने के लिंक के साथ टैक्सी व ऑटो के विवरण भी मिलेंगे।

मोबाइल एप सहयात्री को किसी भी मोबाइल फोन पर चलाया जा सकेगा। रेल यात्रियों के लिए इसका हाइब्रिड एप्लिकेशन विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र और जीआरपी अधिकारियों के विवरणों को गूगल मैप के साथ जियो-टैगिंग द्वारा पता लगाया जा सके। इसके अलावा एप में क्यूआर कोड को स्कैन करने और एक आपातकालीन कॉल करने की सुविधा भी होगी। एप और वेबसाइट लांच किए जाने के मौके पर दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार, विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन, उत्तर रेलवे के जीएम टीपी सिंह, आरपीएफ के आइजी एसएन पांडे व डीसीपी डीके गुप्ता समेत जीआरपी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

राज्यसभा सदस्य की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जद (यू) के राज्यसभा सदस्य महेंद्र प्रसाद की कानूनी रूप से पत्नी होने का दावा करने वाली महिला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरुवार को क्राइम ब्रांच की तरफ से पेश हुए दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल (अपराध) राहुल मेहरा ने न्यायमूर्ति मनमोहन व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ को बताया कि राज्यसभा सदस्य की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

क्राइम ब्रांच द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार महेंद्र प्रसाद की पत्नी की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद महिला को गिरफ्तार किया गया था। प्रसाद की पत्नी ने महिला के खिलाफ आरोप लगाया था कि वह उनके गहने लेकर गई थी, लेकिन कई बार लौटाने का अनुरोध करने के बाद भी वापस नहीं कर रही। पुलिस ने द लीला होटल में महिला से पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि गिरफ्तार महिला को विदेश यात्रा से रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी से जवाब मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकार (ईपीसीए) की रिपोर्ट पर डीएमआरसी से जवाब मांगा है। ईपीसीए ने टैक्सी और तिपहिया आटो और साइकिल रिक्शा की पार्किंग के लिए कम जगह होने का मुद्दा उठाया है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने ईपीसीए की रिपोर्ट पर डीएमआरसी को नोटिस जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रो स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस अड्डे जैसे स्थानों पर टैक्सी, तिपहिया आटो और साइकिल रिक्शा की पार्किंग के लिए स्थान निर्धारित नहीं है जिसकी वजह से वाहनों की भीड़ रहती है और इससे यात्रियों को परेशानियां होती हैं। प्राधिकरण ने शीर्ष कोर्ट में पेश रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दिल्ली के लिए अंतिम स्थान तक मेट्रो स्टेशनों और कई तरह के यातायात वाले स्थानों को जोड़ना एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। यह शहर में निजी वाहनों की आवश्यकता को काफी हद तक कम करेगा।

पीठ ने इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को ईपीसीए की रिपोर्ट पर जवाब देने का निर्देश दिया और इसे नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। ईपीसीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि मेट्रो स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक यातायात के स्थानों से अंतिम छोर के लिए टैक्सी, आटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा को निःशुल्क पार्किंग स्थल की आवश्यकता है। इसलिए जहां पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं और बसों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, वहीं अंतिम छोर तक जोड़ने के लिए टैक्सी और आटो रिक्शा के बेहतर उपयोग की भी जरूरत है।

▸ ईपीसीए की रिपोर्ट पर शीर्ष अदालत ने किया तलब

रिपोर्ट के अनुसार आज की स्थिति में यातायात के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की परिवहन सुविधा अपर्याप्त हैं और टैक्सी, तिपहिया वाहनों और साइकिल रिक्शों के लिए पार्किंग स्थान के बगैर मेट्रो तथा अंतरराज्यीय बस अड्डों पर वाहनों की बहुत अधिक भीड़ हो जाएगी और यह यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मेट्रो स्टेशनों की डिजाइन में वाहनों की पार्किंग की आवश्यकता को शामिल करने की आवश्यकता है लेकिन ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि सड़क और स्टेशनों के ढांचे के ऊपर की जगह डीएमआरसी के दायरे में नहीं है। ईपीसीए ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में डीएमआरसी और अन्य संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डीएमआरसी प्रथम और दूसरे चरण के 126 स्टेशनों में से सबसे अधिक भीड़ वाले 38 स्टेशनों की पहचान की है जिनकी डिजाइन में शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। इनमें से छतरपुर, कश्मीरी गेट और जहांगीरपुरी स्टेशनों पर यह योजना लागू करने का विभिन्न चरणों में है लेकिन इसे गति प्रदान करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के अनुसार डीएमआरसी ने अपने तीसरे चरण के सभी 78 स्टेशनों के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है और इनमें आटो रिक्शा, बस और कार पार्किंग तथा यात्रियों को उतारने के लिए अलग लेन उपलब्ध कराने पर काम कर रही है।

यौन संबंध के बावजूद रिश्ता खत्म कर देना अपराध नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दुष्कर्म के एक मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपित को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यौन संबंध के बावजूद प्रेमी द्वारा छोड़ देना घृणास्पद लग सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ ने कहा कि अब यौन सहमति पर 'नहीं मतलब नहीं' के नियम से आगे बढ़ने का व्यापक अर्थ स्वीकृति है और 'हां का मतलब हां' है। पीठ ने पुलिस की अपील याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निचली अदालत के फैसले में कोई दुर्बलता नहीं थी।

पीठ ने कहा कि युवती का दावा है कि उसकी सहमति स्वैच्छिक नहीं थी, लेकिन उसे शादी के वादे के बहाने प्रेरित करके शारीरिक संबंध बनाया गया, लेकिन यह सुनवाई के दौरान साबित नहीं हो सका। पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि दुष्कर्म की पहली कथित घटना के तीन महीने बाद युवती स्वेच्छा से 2016 में युवक के साथ होटल में गई थी और विवाद का विषय नहीं है कि यह शादी करने के वादे से प्रेरित था। युवती ने प्राथमिकी में कहा था कि आरोपित व उसके बीच प्रेम संबंध हो गया और आरोपित ने उससे शादी करने का वादा किया था।

डेंगू के खिलाफ अभियान से जुड़े वीरेंद्र सहवाग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में डेंगू के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का भी साथ मिल गया है। सहवाग ने वीडियो जारी कर लोगों से डेंगू के खिलाफ लड़ने और चैंपियन बनने की अपील की है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करने की अपील की है, जिससे पूरी दिल्ली मिलकर डेंगू के खिलाफ लड़ सके।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक ट्वीट कर वीरेंद्र सहवाग को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास है कि दिल्ली के युवा आपका संदेश सुनकर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान में और उत्साह से जुड़ेंगे। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस अभियान की वजह से इस वर्ष डेंगू के मामलों में आश्चर्यजनक कमी आई है। दिल्ली नगर निकायों के एंटी मलेरिया मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते डेंगू के सिर्फ 74 मामले ही सामने आए हैं। इस साल अक्टूबर के पहले सप्ताह तक यह आंकड़ा 356 तक ही पहुंचा है। 2018 में इस समय तक करीब 650 मामले सामने आ चुके थे।

अभियान से दिल्ली को हर साल डेंगू से लड़ने में मिलेगी मदद : केजरीवाल : डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने इस साल मुख्यमंत्री को चेतावनी दी थी कि डेंगू का तीन से चार साल का चक्र होता है। दिल्ली में इस साल ज्यादा प्रकोप का अनुमान है। दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर डेंगू से लड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट के अभियान की परिकल्पना अर्थ आवर की तर्ज पर की गई। लोगों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने घरों का हर रविवार सुबह 10 बजे दस मिनट के लिए लगातार दस हफ्तों तक निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस अभियान के प्रभाव केवल इस वर्ष तक सीमित नहीं होंगे। इससे दिल्ली को हर साल डेंगू से लड़ने में मदद मिलेगी।

कई हस्तियों का मिल चुका है समर्थन

मुख्यमंत्री के इस अभियान को विभिन्न हस्तियों का समर्थन मिला है, जिनमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, बॉलीवुड के सितारे तापसी पन्नू, इमरान हाशमी, राहुल देव, महेश भट्ट जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी डेंगू अभियान को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी अभियान के समर्थन में अपने आधिकारिक निवास का निरीक्षण किया।

तीन माह के बाद बिगड़ी दिल्ली की हवा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

करीब तीन माह तक राहत के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर बिगड़ने लगी है। गुरुवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 211 जा पहुंचा। इस स्तर को हवा की गुणवत्ता के लिहाज से खराब श्रेणी में रखा जाता है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में यह दो सौ से ऊपर ही है। पर्यावरण और मौसम विशेषज्ञों की मानें तो अगले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता और बिगड़ने वाली है।

गौरतलब है कि कई साल बाद इस साल पहली बार ऐसा हुआ, जब लगातार तीन माह तक दिल्ली का एयर इंडेक्स अच्छा या सामान्य श्रेणी के दायरे में रहा। लेकिन मौसम बदलने के साथ ही यह राहत का दौर अब खत्म होता नजर आ रहा है। बीते तीन दिनों में एयर इंडेक्स लगातार यह बता रहा है कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट हो रही है। मंगलवार को एयर इंडेक्स 112 था, बुधवार को 173 पहुंचा और गुरुवार को 211 पहुंच गया।

दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। भिवाड़ी में गुरुवार को एयर इंडेक्स 200, धारूहेड़ा में 232, गाजियाबाद में 225, ग्रेटर नोएडा में 230, गुरुग्राम में 171, मानेसर में 184, नोएडा में 193 और पलवल में 120 रहा। सीपीसीबी ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ एनसीआर की ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली के वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के पीछे हवा की दिशा में आया बदलाव बड़ी वजह है। पहले हवा पूर्व दिशा से चल रही थी, अब पश्चिम की तरफ से हवा चलने लगी है। इस हवा की गति कम और इसमें नमी ज्यादा होती है। इसीलिए हवा में प्रदूषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ गई है। सफर इंडिया के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। अगले कुछ दिनों में हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम होने पर दिल्ली- एनसीआर को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मौसम में अब ठंड का अहसास होने लगा है। शुक्रवार के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि सुबह के समय हल्की धुंध होगी। गुरुवार को सूरज तो निकला, लेकिन धूप सामान्य ही रही। अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों ही इस मौसम के सामान्य तापमान है। हवा में नमी का स्तर 36 से 93 फीसद रहा।

केजरीवाल सी-40 सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित

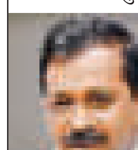

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को डेनमार्क में होने वाले सी-40 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। सम्मेलन के आयोजकों ने केजरीवाल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधन का अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सम्मेलन के सत्र गहरी सांस लें, स्वच्छ हवा शहर का समाधान... के दौरान उनका संबोधन होगा। साथ ही वह दुनिया के छह प्रमुख शहरों के महापौरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार ने यह फैसला तब लिया, जब विदेश मंत्रालय की तरफ से उन्हें डेनमार्क जाने की इजाजत नहीं मिली। गौरतलब है कि सी-40 जलवायु परिवर्तन के संबंध में साहसिक कार्रवाई करने और एक स्वस्थ व स्थायी भविष्य बनाने के लिए दुनिया के 90 से अधिक शहरों को जोड़ता है। सी-40 शहरों के महापौर स्थानीय स्तर पर पेरिस समझौते के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषण कम करने के अनुभवों को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान ऑड-इवेन की सफलता के बारे में भी बताएंगे। दिल्ली में पिछले पांच वर्षों के दौरान 25 फीसद वायु प्रदूषण को कम करने में सफलता मिली है। वर्ष 2016 में ऑड-इवेन की शुरुआत हुई। इसमें सड़कों पर भीड़भाड़, धूल और धुआं कम देखा गया।

नया कदम

अर्बन एक्सटेंशन रोड नंबर दो नाम से इस तीसरी रिंग रोड का प्लान दशक भर से है तैयार, मास्टर प्लान 2021 में भी है इसका उल्लेख

तीसरी रिंग रोड के लिए धन नहीं जमीन देगा डीडीए

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

तकरीबन एक दशक से फाइलों में ही बन रही दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के निर्माण में अवैध कब्जों के बाद अब बजट का पेच फंस गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने इसे बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से धनराशि की मांग की है जबकि डीडीए हजारों करोड़ की बड़ी रकम देने में असमर्थता जता रहा है। ऐसे में धनराशि के बदले जमीन देने के प्रस्ताव पर दोनों के बीच सहमति बनती दिख रही है।

गौरतलब है कि अर्बन एक्सटेंशन रोड नंबर दो नाम से इस तीसरी रिंग रोड का प्लान दशक भर से तैयार है। मास्टर प्लान 2021 में भी इसका उल्लेख है। इसे बनाने का मकसद यही है कि दिल्ली के बाहरी इलाकों से होते हुए वाहन पश्चिमी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली तक निकल जाए। इसके निर्माण से दिल्ली के बाहरी हिस्सों से मिलने वाले चारों नेशनल हाईवे भी इससे जुड़ जाएंगे।

पहले यह रोड प्रस्तावित जमीन पर अनधिकृत कब्जे जैसी अड़चनों से कागजों में ही लटकी रही। डीडीए ने अतिक्रमण-अवैध कब्जे हटाने और भूमि अधिग्रहण का काम पूरा किया तो अब बजट का पेच फंस गया है। हालांकि गत अगस्त माह में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस रोड की समीक्षा बैठक लेते हुए एनएचएआइ अधिकारियों से इसके निर्माण की समय सीमा तय करने के साथ-साथ निर्माण कार्य का टेंडर भी निकाल देने को कह दिया था।

समस्या यह आ रही है कि एनएचएआइ ने टेंडर निकालने से पूर्व डीडीए को इसके निर्माण पर आने वाला करीब पांच हजार करोड़ रुपये का खर्च वहन करने को कहा है। जबकि डीडीए इतना खर्च करने को तैयार नहीं है। डीडीए की ओर से एनएचएआइ को टोल बैरियर लगाकर सारा खर्च निकालने को कहा गया तो बताया गया कि टोल बैरियर सरकार के निर्देश पर कभी भी हटा दिए जाते हैं। डीडीए को यह चिंता भी सताने लगी है कि इस हीलाहवाली में कहीं फिर से अतिक्रमण या अवैध कब्जे न हो जाएं। इस बीच एनएचएआइ के एक सुझाव पर डीडीए भी राजी हो गया है। एनएचएआइ ने डीडीए से कुछ जमीन मुहैया कराने को कहा है, जिसे बेचकर रोड निर्माण की लागत निकाली जा सके। बताया जाता है कि जल्द ही डीडीए एनएचएआइ को जमीन दे देगा, जिसके बाद इस रोड के निर्माण का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

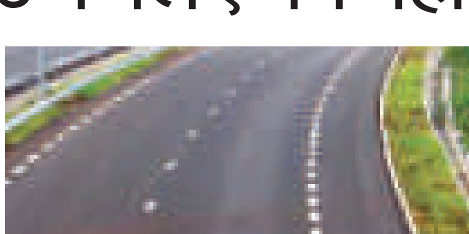
प्रतीकात्मक

पैसे के बदले एनएचएआइ को जमीन दी जाएगी। यह कहां और कितनी दी जाएगी, इस पर काम चल रहा है। जल्द ही समस्या सुलझा दी जाएगी।
-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

यह रहेगा रूट : पहले चरण में यह रोड एनएच-एक दिल्ली-अंबाला राजमार्ग पर नरेला से शुरू होगी जो रंगपुरी शिव मूर्ति के पास एनएच-8 यानी दिल्ली जयपुर राजमार्ग से मिलेगी। आगे चलकर इस रोड से एनएच-2 यानी दिल्ली-मथुरा राजमार्ग भी जुड़ जाएगा। जो फरीदाबाद की ओर से आते हैं और जिन्हें करनाल जाना है, उन्हें भी दिल्ली के जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही बाहरी, पश्चिमी, दक्षिणी दिल्ली में डीडीए की प्रस्तावित लैंडपूलिंग आवासीय योजना के लिए भी एक नया मार्ग मिल जाएगा।

दो फेज में बनेगी रोड : फेज-1 के तहत 49 किलोमीटर रोड का निर्माण होगा। यह पानीपत से दिल्ली की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे एक से होकर बाहरी दिल्ली से होते हुए एनएच 8 (दिल्ली- गुरुग्राम) होते हुए नेल्सन मंडेला मार्ग तक बनाई जाएगी। दूसरे चरण में नेल्सन मंडेला मार्ग से इसे एनएच 2 यानी बदरपुर से जुड़ने वाले नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। इस तरह महरौली, बदरपुर इत्यादि कई क्षेत्र इस रोड के जरिये जुड़ जाएंगे।

मेट्रो में पुरानी लाइनों पर बढ़ेंगे कोच

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही पुरानी लाइनों पर मेट्रो के कोच बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने 80 कोच खरीदने के लिए टेंडर आवंटित भी कर दिया है। उम्मीद है कि ये कोच अगले कुछ माह में दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में मेट्रो में प्रतिदिन करीब 30 लाख लोग सफर करते हैं। फेज-तीन की परियोजनाएं पूरी होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क 377 किलोमीटर और मेट्रो स्टेशनों की संख्या 274 हो गई है। इसलिए मेट्रो राजधानी में ही नहीं, बल्कि दिल्ली से एनसीआर के शहरों के बीच आवागमन के लिए भी सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन बनकर उभरी है। इस वजह से बड़ी संख्या में पेशेवर लोग दिल्ली व एनसीआर के शहरों के बीच मेट्रो से आवागमन करते हैं। यही वजह है कि सुबह व शाम को मेट्रो में भीड़ अधिक होती है। ब्लू लाइन, यलो लाइन व रेड लाइन की मेट्रो पर यात्रियों का दबाव बहुत ज्यादा है। अक्सर इन रूटों पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन में लोगों को खड़े रहने के लिए भी मुश्किल से जगह मिल पाती है। इस कारण डीएमआरसी ने पिछले साल अक्टूबर में 80 नए कोच खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब डीएमआरसी ने बेंगलुरू स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीईएमएल को ये कोच आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी है। 729 करोड़ की लागत से ये कोच खरीदे जाएंगे। इसका इस्तेमाल उक्त पुराने कॉरिडोर की मेट्रो में होगा। खास तौर पर रेड लाइन की मेट्रो में ये कोच जोड़े जाएंगे। इसलिए रेड लाइन की सभी मेट्रो आठ कोच में तब्दील हो जाएंगी। फेज-तीन में रेड लाइन का विस्तार रिठाला-दिलशाद गार्डन से बढ़ाकर गाजियाबाद न्यू बस अड्डा तक हो गया है। इसलिए रेड लाइन पर भी कोच बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इन 80 कोच के अलावा भी 40 कोच खरीदे जाने हैं। इस तरह पुरानी लाइनों पर करीब 120 कोच बढ़ाए जाने की योजना है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो की सभी पुरानी लाइनों पर सभी मेट्रो ट्रेनें आठ कोच की हो जाएंगी। अभी दिल्ली मेट्रो में 336 मेट्रो ट्रेनें हैं, जिनमें करीब 2200 कोच इस्तेमाल हो रहे हैं।

2155 किलोमीटर की गंगा आमंत्रण यात्रा (नौका अभियान) गुरुवार को देवप्रयाग से गंगासागर के लिए रवाना हो गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विंग कमांडर परमवीर के नेतृत्व वाली यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 34 दिन के इस अभियान में तीनों सेनाओं के 32 जवान भाग ले रहे हैं।

खत्म हो संघीय ढांचे के लिए कांटा बना अनुच्छेद 356 : योगेंद्र नारायण

स्वर्गीय नरेन्द्र मोहन स्मृति व्याख्यानमाला में बोले राज्यसभा के पूर्व महासचिव, राज्यपालों की नियुक्ति के लिए पीएम, नेता विपक्ष और गृह मंत्री की समिति बनाने का दिया सुझाव

कहा, जीएसटी काउंसिल से हुई केंद्र और राज्यों के संयुक्त शासन के स्वरूप की नई शुरुआत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण ने संविधान के अनुच्छेद 356 को समाप्त किए जाने की जरूरत बताई है। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की फेहरिस्त गिनाते हुए उन्होंने इसे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की शुरुआत का मूल करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने संघीय ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और गृह मंत्री की एक चयन समिति गठित करने का सुझाव दिया। उन्होंने जीएसटी को केंद्र-राज्यों के संयुक्त शासन के स्वरूप की नई शुरुआत बताते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए भी जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में एक नई वैधानिक संस्था के गठन की वकालत की। दैनिक जागरण समूह के प्रधान संपादक संजय गुप्त ने यह सुनिश्चित करने की जरूरत बताई कि राजनीतिक दलों के आपसी टकराव के बीच आम जनता को न पिसना पड़े।

दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक स्वर्गीय नरेन्द्र मोहन की स्मृति में 'संघीय ढांचा और राष्ट्रीय हित' विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला में योगेंद्र नारायण ने कहा, 'अनुच्छेद 356 भारत के संघीय ढांचे के लिए कांटा बन चुका है।' उन्होंने बताया कि किस तरह पहली बार इस प्रावधान को अंग्रेजों ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शामिल किया था, जिसे आजादी के बाद हमने ज्यों का त्यों अपना लिया। अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की पुरजोर वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अभी तक इसका 126 बार दुरुपयोग हो चुका है। 1957 में केरल में नंबूदरीपाद सरकार को गिराने के लिए हुए इसके दुरुपयोग से केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की शुरुआत हुई थी। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह राजनीतिक कारणों से विभिन्न पार्टियों की सरकारें इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करती रही हैं। योगेंद्र नारायण के अनुसार, संविधान में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कई और प्रावधान मौजूद हैं और अनुच्छेद 356 को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है।

संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए योगेंद्र नारायण ने राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह बिहार में राज्यपाल बूटा सिंह के विधानसभा भंग करने की सिफारिश और उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से दुखी तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर उन्हें मनाया था। मौजूदा प्रणाली में राज्यपालों को केंद्र सरकार के अधीन बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और गृह मंत्री की सदस्यता में एक समिति गठित करने का सुझाव दिया।

नई दिल्ली में गुरुवार को दैनिक जागरण प्रकाशन समूह के पूर्व प्रधान संपादक स्वर्गीय नरेन्द्र मोहन की स्मृति में 'संघीय ढांचा और राष्ट्रीय हित' विषय पर व्याख्यानमाला में बोलते राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण। जागरण

योगेंद्र नारायण ने राज्यों और केंद्र के बीच टकराव के कारण जनकल्याणकारी योजनाएं लागू होने में आ रही दिक्कतों पर चिंता जताई। इस संदर्भ में उन्होंने आयुष्मान भारत, खुले में शौच मुक्त करने, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को दिल्ली और बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में राजनीतिक कारणों से लागू नहीं किए जाने का उल्लेख किया, जिसका खामियाजा आखिरकार आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जीएसटी लागू किए जाने को संघीय व्यवस्था का सबसे सफल उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह की प्रणाली जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में भी अपनाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में एक वैधानिक संस्था बनाने का सुझाव दिया, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी ओर से नामित मंत्री सदस्य हों।

योगेंद्र नारायण के अनुसार, पिछले 70 साल में देश के राजनीतिक हालात के मुताबिक संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्यों के संबंध बदलते रहे हैं और अब राज्य और केंद्र के संयुक्त शासन का स्वरूप सामने आ रहा है। शुरू में केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकारों के तहत आपसी सहयोग से लेकर छठे से आठवें दशक के बीच टकराव का दौर रहा। लेकिन नौवें दशक के बाद गठबंधन सरकारों में केंद्र सरकार में राज्यों का दबदबा बढ़ गया। एनआइए और जीएसटी को योगेंद्र नारायण ने संघीय ढांचे के केंद्रीयकृत व्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत बताया। खासकर जीएसटी ने राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल और संयुक्त रूप से फैसले लेने का नया तरीका ईजाद किया है। यह संघीय ढांचे के लिए शुभ संकेत है।

दैनिक जागरण समूह के प्रधान संपादक संजय गुप्त ने योगेंद्र नारायण समेत सभागार में मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सभागार में तमाम नेता भी बैठे हैं। हकीकत यही है कि नौकरशाह भी राजनेताओं का मन बनाते हैं। कई बार देखने आया है कि राजनीतिक मतभेदों के चलते आम जनता को पिसना पड़ता है। राजनेताओं और नौकरशाहों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आपसी मतभेदों का खामियाजा आम जनता को न भुगतना पड़े। साथ ही आम जनता को यह नहीं लगना चाहिए कि उसके अधिकारों की रक्षा में संविधान समर्थ नहीं है।

ईडी ने पांच एकड़ का बंगला जब्त किया

मुंबई, प्रेट्र : पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव (पीएमसी) बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक एचडीआइएल के प्रमोटर के पांच एकड़ के बंगले को जब्त कर लिया है। मुंबई के पास स्थित पालघर जिले के वसई इलाके में यह संपत्ति स्थित है। हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) के एक प्रमोटर का यह बंगला है। ईडी ने हाल ही में पीएमसी बैंक घोटाले में एफआइआर दर्ज करने के बाद मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जांच एजेंसी अब तक 60 करोड़ रुपये से अधिक के जेवरात, एक बिजनेट जेट, 15 लक्जरी कारें, 1.5 करोड़ रुपये के दो फिक्सड डिपाजिट और दस करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ईडी इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की आपराधिक मामलों की शाखा की ओर से दर्ज की गई एफआइआर के आधार पर कर रही है। ईडी और मुंबई पुलिस की जांच का आधार आरबीआइ की ओर से नियुक्त प्रशासक की ओर से दर्ज कराई गई एफआइआर पर आधारित है। इस एफआइआर में एचडीआइएल के पूर्व बैंक प्रबंधकों और प्रमोटरों को नामजद किया गया है।

कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री के 30 ठिकानों पर आयकर छापा

- पूर्व सांसद के पुत्र भी हैं कार्रवाई के दायरे में, नीट से जुड़े करोड़ों रुपये की कर चोरी का मामला

बेंगलुरु, प्रेट्र : आयकर विभाग ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी. परमेश्वर तथा पूर्व सांसद आरएल जालप्पा के बेटे जे. राजेंद्र के 30 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 300 से भी ज्यादा कर्मचारी शामिल रहे। मामला मेडिकल में दाखिले की राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) से जुड़ी करोड़ों की कर चोरी का है।

आयकर टीमों ने परमेश्वर के कार्यालय, घर व संस्थानों के साथ-साथ उनके भाई जी. शिवप्रसाद तथा निजी सहयोगी रमेश के आवासों पर भी छापे मारे। कर्नाटक व राजस्थान के 30 ठिकानों पर की जा रही छापेमारी में 80 आयकर अफसरों के अलावा पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आयकर विभाग श्री सिद्धार्थ एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा तुमकुरु में संचालित दो मेडिकल कॉलेजों में नीट के दौरान कथित अनियमितता बरते जाने की जांच कर रहा है। इसी सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। परमेश्वर इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आरोप है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की जगह पर किसी दूसरे को बैठने की अनुमति दी गई और उसके बदले पैसे लिए गए। राजस्थान में छापेमारी के दौरान कुछ ऐसे ही अभ्यर्थियों की तलाश की जा रही है। परमेश्वर ने मीडिया से कहा, 'मुझे नहीं मालूम कि ये छापेमारी क्यों की जा रही है। उनके बुलावे पर मैं मिलने जा रहा हूं।' ज्ञात हो, परमेश्वर का परिवार सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्शन का संचालन करता है। इसकी स्थापना उनके पिता एचएम गंगाधरैया ने 58 साल पहले की थी। राजेंद्र आरएल जालप्पा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का संचालन करते हैं।

कार्रवाई पर बरसे कांग्रेस व जदएस नेता : आयकर विभाग की कार्रवाई कांग्रेस व जदयू नेताओं को रास नहीं आई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने ट्वीट किया, 'परमेश्वर, जालप्पा व अन्य के खिलाफ छापे गलत इरादे व राजनीति से प्रेरित हैं। उनके निशाने पर कर्नाटक के कांग्रेस नेता हैं। इससे वे हमें नहीं हिला सकते।' जदएस सुप्रीमो व पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा, 'यह निंदनीय है।' एम. मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे 'प्रतिशोध की राजनीति' करार दिया।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। उनकी सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के कमांडो हर समय तैनात रहेंगे।

सत्तारूढ़ पार्टी का महत्वपूर्ण पद संभालने के बाद नड्डा की सुरक्षा के प्रति बढ़ते खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। नड्डा ने करीब चार महीने पहले भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाला है।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नड्डा को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। सीआरपीएफ के कुल 35 कमांडो रोटेशन के आधार पर नड्डा को हर समय सुरक्षा प्रदान करेंगे। आठ-नौ कमांडो उन्हें नजदीकी सुरक्षा देंगे। देश के भीतर यात्रा के दौरान भी उन्हें यह सुरक्षा मिलती रहेगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ कमांडो नड्डा के दिल्ली स्थित आवास की भी सुरक्षा करेंगे।

अब नीति आयोग की निगरानी में होगा स्टेशनों व ट्रेनों का निजीकरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह का गठन
- समूह को 50 स्टेशनों व 150 ट्रेनों के निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की सौंपी जिम्मेदारी

रेलवे स्टेशनों तथा ट्रेनों के निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है। पांच सदस्यों वाला समूह प्राथमिकता के आधार पर 50 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करने के अलावा प्रमुख मार्गों की 150 ट्रेनों को निजी आपरेटरों को सौंपने के काम में तेजी लाने का उपाय करेगा। इनमें टेंडर की शर्तें और प्रक्रिया आदि तय करना शामिल है।

समूह में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और वित्त आयुक्त के अलावा आर्थिक मामलों और शहरी विकास विभाग के सचिवों को सदस्य तथा रेलवे बोर्ड के सदस्य, इंजीनियरिंग और सदस्य यातायात को सह-सदस्य के रूप में नामित किया गया है। समूह से एक साल के भीतर अपना काम पूरा करने व रिपोर्ट देने को कहा गया है।

समूह के गठन का सुझाव नीति आयोग ने ही रेलवे को दिया था। इस संबंध में पिछले दिनों आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकार अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद यादव को पत्र लिखा था। पत्र में स्टेशन विकास की योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए इसमें तेजी लाने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने की सलाह दी गई थी।

आयोग का कहना था कि इक्का-दुक्का मामलों को छोड़कर रेलवे ने स्टेशन विकास की दिशा में कोई काम नहीं किया है। इसलिए, इस कार्यक्रम को 400 स्टेशनों की बजाय केवल 50 स्टेशनों तक ही सीमित किया जाए। साथ ही नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन कर उसे इसके कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। देश के छह हवाईअड्डों के निजीकरण का हवाला देते हुए पत्र में अमिताभ कांत ने लिखा था, 'रेल मंत्रालय को 400 स्टेशनों का विकास कर उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन, इक्का-दुक्का स्टेशनों को ही ईपीसी मॉडल पर विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस संबंध में मेरी रेलमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। इसके आधार पर फिलहाल कम से कम 50 स्टेशनों को प्राथमिकता के आधार पर वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए काम किया जाना तय हुआ है।'

आयोग के अनुसार, 'पहले चरण में 150 ट्रेनों का चयन किया गया है। इससे यात्री ट्रेन संचालन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अधिकार प्राप्त समूह को इस प्रक्रिया को तेज करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। रेलवे बोर्ड के सदस्य, इंजीनियरिंग एवं सदस्य यातायात को भी इस समूह में शामिल किया जा सकता है।'

मानहानि मामले में राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- सभी मोदी चोर हैं बयान को लेकर सूरत में भाजपा विधायक ने दायर किया है मुकदमा

लोकसभा चुनाव के दौरान रैली में 'सभी मोदी चोर हैं' कहने को लेकर सूरत में दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। राहुल ने खुद को निर्दोष बताया जिसके बाद कोर्ट ने ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की। कांग्रेस नेता ने कोर्ट में पेशी से माफी की अर्जी लगाई। हालांकि इस पर 10 दिसंबर को सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने कहा, अगली तारीख पर राहुल का हाजिर रहना जरूरी नहीं है।

राहुल गुरुवार सुबह सवा दस बजे सूरत की जिला अदालत में पहुंचे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बीएच कपाडिया ने आरोप सुनाते हुए उनसे पूछा कि क्या उन्हें आरोप कुबूल है? इस पर उन्होंने कहा, 'उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है इसलिए आरोप स्वीकार नहीं है।' भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत राहुल के खिलाफ मुकदमा दाखिल हुआ तथा प्राथमिक सुबूतों की जांच के बाद कोर्ट ने राहुल को 10 अक्टूबर को पेश होने का समन भेजा था। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में राहुल ने एक रैली में कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी,

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में गुरुवार को सूरत की कोर्ट में पेश हुए। प्रेट्र

नरेंद्र मोदी.... आखिर इन सभी का उपनाम मोदी क्यों है? सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है?' पूर्णेश ने कहा, कांग्रेस नेता के इस बयान से वह और समुदाय के लाखों लोगों की भावना को ठेस पहुंची है।

राहुल बोले, मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं विरोधी : राहुल ने बाद में ट्वीट किया कि, 'मेरा मुंह बंद कराने के लिए व्याकुल, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा दर्ज मानहानि के एक मामले में पेशी के लिए मैं आज सूरत में हूं। मेरे साथ एकजुटता दिखाने के लिए जमा हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्यार एवं सहयोग के लिए मैं उनका आभारी हूं।'

स्कूली बच्चों के सपनों को 'ध्रुव' देगा नई रोशनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसरो मुख्यालय में प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम 'ध्रुव' की शुरुआत की
- पहले चरण में देश भर से चयनित 60 प्रतिभाशाली बच्चों को मिलेगा 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम 'ध्रुव' की शुरुआत की। इसके साथ ही कार्यक्रम के पहले चरण के तहत देश भर से चयनित 60 प्रतिभाशाली स्कूली छात्रों का 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो गया।

निशंक ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर दृष्टि का परिचायक है। यह प्रतिभाशाली छात्रों के जीवन के साथ समाज में भी बड़ा बदलाव लाएगा। कार्यक्रम में चयनित बच्चों को 'ध्रुव तारा' नाम देते हुए निशंक ने कहा कि ये देश के करोड़ों बच्चों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करेंगे। इसरो प्रमुख के. सिवन ने कहा कि चयनित बच्चों की प्रतिभा को ध्रुव तारे की तरह ही निखारा जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत इसरो मुख्यालय से किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं की सोच के लिए प्रेरणा स्त्रोत होगी। इस दौरान छात्रों की मुलाकात देश के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर (रि.) राकेश शर्मा से भी कराई गई। कार्यक्रम में कक्षा 9-12 तक के छात्रों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्कूली शिक्षा सचिव रीना रे, विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

ऐसे हुई शुरुआत : स्कूली प्रतिभाओं को निखारने के लिए यह कार्यक्रम रूस के सीरियस एजुकेशनल सेंटर की तर्ज पर शुरू किया गया है। इसमें विज्ञान, कला सहित दूसरे क्षेत्रों से जुड़े देश भर के प्रतिभाशाली बच्चों को 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी कवायद पीएम मोदी के पिछले साल जून के रूस दौरे के बाद से ही शुरू हो गई थी। वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीरियस एजुकेशनल सेंटर भी गए थे।

15 नए केंद्रीय विद्यालयों के भवन का उद्घाटन व छह की नींव रखी जाएगी आज : देश के 15 नए केंद्रीय विद्यालयों को शुक्रवार को अपना भवन मिल जाएगा। मंत्री निशंक इन सभी भवनों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह छह नए केंद्रीय विद्यालयों के भवनों की नींव भी रखेंगे। इससे 22 हजार से ज्यादा छात्रों को लाभ होगा। जिन स्कूलों को नए भवन मिलेंगे उनमें उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के शिवगढ़ का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है।

शिक्षा में फिसड्डी राज्यों में बदलाव की छिड़ेगी मुहिम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एचआरडी मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर शुरू की तैयारी
- नीति आयोग के इंडेक्स को बनाया जाएगा आधार, तय होगी जवाबदेही

प्रतीकात्मक

स्कूली शिक्षा के लिहाज से देश के फिसड्डी राज्यों में बदलाव को लेकर अब विशेष मुहिम चलेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर इस पर जल्द काम शुरू करने के संकेत दिए है। फिलहाल इसे लेकर सबसे ज्यादा जोर बच्चों में सीखने की क्षमता (लर्निंग आउटकम) को बढ़ाने को लेकर होगा। वैसे भी नीति आयोग की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट में ज्यादातर राज्यों के पिछड़ने की बड़ी वजह लर्निंग आउटकम का खराब प्रदर्शन ही था।

राज्यों के लर्निंग आउटकम में पिछड़ने की बड़ी वजह स्कूलों में पढ़ाई को लेकर ध्यान न देना है। वैसे भी कुछ राज्यों को छोड़ दें, तो मौजूदा समय में ज्यादातर राज्यों के स्कूलों की जो हालत है, उनमें मिड-डे मील से लेकर मुफ्त में ड्रेस, किताबें आदि को लेकर ही सबसे ज्यादा जोर है। पढ़ाई लिखाई की ओर से ध्यान नहीं है। ऐसे में शिक्षकों को पूरा समय ऐसी ही गतिविधियों में निकल जाता है। वैसे भी स्कूली शिक्षा में फिसड्डी राज्यों पर नजर दौड़ाएं, तो यहां के स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। ऐसे में जो शिक्षक है भी, वह पढ़ाई को छोड़ दूसरे कामों में लगे हैं। यही वजह है कि मंत्रालय का पूरा फोकस स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर है। इसके तहत पहली कोशिश शिक्षकों की कमी को खत्म करने और मौजूदा शिक्षकों को नए सिरे से प्रशिक्षण देने को लेकर है। फिलहाल शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जबकि राज्यों से स्कूलों से शिक्षकों की तैनाती को लेकर एक फार्मूला तैयार करने को कहा है। ताकि सभी स्कूलों को बच्चों के एनरोलमेंट के लिहाज से शिक्षक मिल सकें। वैसे भी प्रत्येक 25 छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए।

मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बदलाव की इस कवायद में इसके साथ ही नीति आयोग के परफार्मेंस इंडेक्स में शामिल उन सभी 30 बिंदुओं को भी आधार बनाया गया है। इसमें एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों की सुरक्षा, पेयजल आदि विषयों को रखा गया है। गौरतलब है कि नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स (एसईक्यूआइ) में उत्तर प्रदेश सहित जम्मू-कश्मीर, पंजाब, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश आदि राज्यों का प्रदर्शन बेहद खराब था।

बढ़ी मांग

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को मसौदा भेजकर मांगी अतिरिक्त धनराशि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मांग में वृद्धि पर मंत्रालय गंभीर

मनरेगा को अतिरिक्त 20 हजार करोड़ की दरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बढ़ी मांग के मद्देनजर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अतिरिक्त 20 हजार करोड़ रुपये की दरकार है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस बाबत वित्त मंत्रालय को मसौदा भेजकर अतिरिक्त आवंटन की मांग की है। शहरी क्षेत्रों में रोजी रोजगार की किल्लत के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना साल दर साल लोकप्रिय होती जा रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सभी ग्रामीणों को सालभर में सौ दिनों का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। देश में फिलहाल नौ करोड़ मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने के दौरान 140 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। पिछले वर्ष पूरे साल के दौरान 258 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए थे।

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में प्रत्येक जॉब कार्ड धारक मजदूर को अब तक औसतन 35 दिनों का काम दिया जा चुका है। जबकि मनरेगा

09 करोड़ मनरेगा जॉब कार्ड धारक है फिलहाल देश में

140 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं गत छह माह में

258 करोड़ मानव दिवल सृजित किए गए थे पिछले वर्ष

प्रतीकात्मक

के तहत सालभर में प्रत्येक अकुशल मजदूर को एक सौ दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 268 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए थे। जबकि 256 करोड़ मानव दिवस के सृजन का अनुमान था। पिछले साल प्रत्येक जॉब कार्ड धारक परिवार को औसतन 51 दिनों का काम मिल गया था। वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत 234 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए थे। उस समय साल में प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को औसतन 46 दिनों का काम मिल पाया था। योजना के तहत फिलहाल देश में कुल नौ करोड़ जॉब कार्ड धारक परिवार हैं।

चालू वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था, जो अब तक का सर्वाधिक आवंटन रहा है। वित्त मंत्री ने इसके साथ यह भी जोड़ा कि यह मांग आधारित कानूनी योजना है, जिसके लिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धन भी मुहैया कराया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि वित्त वर्ष का आधा समय बीत चुकने यानी सितंबर तक केवल 12 हजार करोड़ रुपये ही मंत्रालय को प्राप्त हो सका है। मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार की मांग गरमी के दौरान होती है। उस समय खेतिहर मजदूर खेती के काम से फारिग हो जाते हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मंत्रालय ने 20 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है। जबकि जनवरी महीने के आसपास मंत्रालय अपने खर्च की समूची समीक्षा कर वित्त मंत्रालय से पूरा भुगतान करने का आग्रह करता है। पिछले साल बजट में जहां 55 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। उसके अतिरिक्त 21 हजार करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने केवल छह हजार करोड़ रुपये का आवंटन मजदूरी वाले हिस्से के भुगतान के लिए किया था।

केंद्र सरकार की ओर से बजटीय आवंटन की धनराशि को राज्यों की मांग के आधार पर पहले ही भेज दिया जाता है। राज्यों में भी रोजगार की मांग के आधार पर पहले ही धनराशि खर्च कर ली जाती है। इसके आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समीक्षा के बाद पिछले साल के अनुभव के आधार पर वित्त मंत्रालय से धन की मांग की है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

दैनिक जागरण 4
शुक्रवार 11 अक्टूबर 2019
www.jagran.com

गोपीनाथ मुंडे की विरासत पर परिवार में सियासत

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

- महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी पंकजा व भतीजा धनंजय आमने-सामने
- पिछले विधानसभा चुनावों में पंकजा ने धनंजन को लगभग ढाई लाख मतों से हराया था

विरासत की सियासत

भाजपा के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक विरासत पर कब्जे के लिए एक बार फिर उनके परिवार में ही घमासान शुरू हो गया है। चचेरे बहन-भाई पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे इस बार फिर परली विधानसभा सीट पर आमने-सामने हैं।

वर्ष 2014 में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के चंद दिनों बाद ही गोपीनाथ मुंडे दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। इसके कुछ दिनों बाद ही हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनकी पुत्री पंकजा मुंडे पालवे एवं भतीजे धनंजय मुंडे आमने-सामने थे। मुंडे मराठवाड़ा के दिग्गज नेता थे।

उनके जाने का दुख भी ताजा था। लिहाजा पंकजा ने लगभग एकतरफा जीत हासिल की। वह ढाई लाख मतों से जीतकर देवेंद्र फड़नवीस सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बनीं। दूसरी ओर, मुंडे के निधन से खाली हुई बीड लोकसभा सीट पर उनकी छोटी बहन प्रीतम मुंडे चुनी गईं। यह बात न तो उनके भतीजे धनंजय को रास आई, न ही विरोधी दलों को। मुंडे के जीवनकाल से ही धनंजय परिवार में बगावत का बिगुल बजा चुके थे। बीड की राजनीति में चाचा के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के बावजूद जब अगली पीढ़ी को सियासी मैदान में उतारने का मौका आया तो मुंडे ने भतीजे की बजाय बेटी को ही तरजीह दी थी। धनंजय ने इसे दिल पर ले लिया और परिवार में फूट पड़ गई।

धनंजय मुंडे। फाइल

पंकजा मुंडे। फाइल

इसका फायदा राकांपा ने उठाया। मुंडे के रहते बीड में दाल न गलने से क्षुब्ध राकांपा नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने धनंजय को बीड की राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। राकांपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव ढाई लाख मतों से हारने के बावजूद अजीत न सिर्फ धनंजय को विधान परिषद में ले आए, बल्कि नेता विरोधी दल का पद भी दिलवाया। धनंजय भी बीड में राकांपा को मजबूत करने का भरसक प्रयास करते रहे।

उनके प्रयासों से राकांपा स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर देती रही। हालांकि, बीड का जनमानस पंकजा और प्रीतम मुंडे के साथ ही रहा।

लोकसभा चुनाव में प्रीतम मुंडे फिर से जीतीं और अब विधानसभा चुनाव में पंकजा मैदान में हैं। इस बार तो राकांपा ने कांग्रेस के साथ औपचारिक गठबंधन की घोषणा होने से पहले ही बीड के पांच उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। हालांकि, उसे बड़ा झटका तब लगा, जब पंकजा ने एक प्रत्याशी को भाजपा में शामिल करवा दिया।

राकांपा ने इस बार फिर पंकजा के सामने धनंजय को ही उम्मीदवार बनाया है। वर्ष 2014 में जहां गोपीनाथ मुंडे के न रहने की सहानुभूति लहर थी, वहीं इस बार पंकजा के विरुद्ध सत्ताविरोधी लहर भी हो सकती है। पंकजा पर पिछले पांच वर्षों में कई आरोप भी लगते रहे हैं। विधान परिषद में विरोधीदल के नेता होने के कारण उनके चचेरे भाई ही इन आरोपों को धार भी देते रहे हैं। देखना है कि इस बार धनंजय की यह धार काम आती है या गोपीनाथ मुंडे और पंकजा मुंडे द्वारा परली के लोगों के लिए किए गए काम।

जमीन घोटालों पर स्मृति ईरानी ने साधा रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना

बिजेंद्र बंसल , फरीदाबाद

स्टार प्रचारक

विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे परवान चढ़ रहा है, वैसे ही राजनीतिक दल आक्रामक होते जा रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार और जमीन घोटालों को लेकर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा।

स्मृति ने फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर का नाम लिए बिना उपस्थित लोगों से सवाल किया कि क्या वे 2014 की तरह उस उम्मीदवार को वोट देंगे, जिसने गरीबों की जमीन लूटकर कांग्रेस के दामाद को दे दी। स्मृति ने दूसरा सवाल किया कि देश और समाज को भ्रष्टाचार से खोखला करने वाली कांग्रेस को क्या तिगांव की जनता दोबारा वोट देगी। सभा में मौजूद लोगों की तरफ से जब नहीं की आवाज आई तो स्मृति ने कहा कि इस देश और समाज में भ्रष्टाचार का विष फैलाने वाली कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की जिम्मेदारी समाज के प्रत्येक नागरिक को निभानी होगी। उन्होंने कहा कि दिशाहीन व नेतृत्वहीन कांग्रेस का प्रत्याशी भी तिगांव, फरीदाबाद और हरियाणा को कोई दिशा व नेतृत्व नहीं दे पाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व के शिखर पर पहुंचाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं का जमाना है। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी राजेश नागर को विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर स्मृति ईरानी का उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने स्वागत किया।

फरीदाबाद के तिगांव में चुनावी सभा में लोगों का अभिवादन स्वीकार करती केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। साथ हैं उद्योग मंत्री विपुल गोयल। जागरण

मनोहर लाल ने भी साधा था ललित नागर पर निशाना: लोकसभा चुनाव के दौरान जब ललित नागर को चार बार सांसद रहे अवतार भड़ाना का टिकट काटकर फरीदाबाद से प्रत्याशी बनाया गया था तब सीएम मनोहर लाल ने पलवल की एक सभा में कहा था कि कांग्रेस ने अपने दामाद के दलाल को टिकट दे दिया है। इस बयान के बाद ललित नागर का टिकट बदलकर अवतार भड़ाना को दे दिया था।

सिद्धू पंजाब उपचुनाव में बने स्टार प्रचारक, लेकिन मैदान में उतरने पर संशय

नवजोत सिंह सिद्धू। फाइल

कैलाश नाथ, चंडीगढ़ : महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट से आउट हुए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब के उपचुनाव के लिए बनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में स्थान मिल गया है। अलबत्ता सिद्धू इस लिस्ट में खिसक कर 29वें स्थान पर आ गए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिद्धू चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पार्टी से दूरी बना रखी है।

दूसरी तरफ भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर भी भरोसा जताया है तो कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं के भरोसे ही प्रचार की कमान संभालने की जिम्मेदारी उठाई है। अकाली दल की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अब भी पहले स्थान पर ही हैं।

कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई लिस्ट से खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु गायब हो गए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आशु दाखा में कैप्टन संदीप संधू की कंपेन की बागडोर संभाल रहे हैं। आशु लुधियाना से हैं और दाखा लुधियाना जिले में ही आता है।

कांग्रेस ने 14 मंत्रियों को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। कांग्रेस ने आठों सांसद को लिस्ट में स्थान दिया है। इस लिस्ट में अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के धुर विरोधी व राज्य सभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो को भी शामिल किया है। उसके बाद अंबिका सोनी और प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ को स्टार कंपेनर बनाया गया है।

कांग्रेस की लिस्ट में प्रदेश के बाहर का कोई नेता नहीं : महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस की लिस्ट में जहां प्रदेश के बाहर का कोई भी नेता शामिल नहीं है वहीं, भाजपा के कार्यकारी प्रधान जेपी नड्डा पार्टी की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। भाजपा की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी शामिल हैं। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर के अलावा भाजपा ने गुरदासपुर के सांसद सनी देयोल को भी स्टार प्रचारक बनाया है। अकाली दल की कमान एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के हाथ में होगी।

'दुनिया ने माना, हमारे एक जवान के बदले दुश्मन के 10 मरेंगे'

बोले शाह ▸ जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर रुख स्पष्ट करें राहुल और पवार

कांग्रेस ने कहा था कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, पर एक भी गोली नहीं चली

सांगली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई है और पूरी दुनिया ने माना है कि अगर भारत का एक जवान शहीद होगा तो दुश्मन के 10 मारे जाएंगे। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मसले पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि वे इसके खिलाफ हैं या समर्थन में।

महाराष्ट्र के सांगली और सोलापुर जिलों में गुरुवार को चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, 'दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर मोदीजी संसद में ऐतिहासिक प्रस्ताव लेकर आए... उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाकर महान काम किया... सरकार वल्लभभाई पटेल का अखंड भारत का सपना आज साकार हो गया है।' उन्होंने कांग्रेस और राकांपा पर वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस कदम का विरोध करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने दावा किया था कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन कश्मीर में शांति है और वहां एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को महाराष्ट्र के सांगली में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्हें पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। एएनआइ

पूरी दुनिया भारत के साथ, पाक अकेला पड़ा: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इन लोगों ने देश और दुनियाभर में यह कहकर झूठा अभियान चलाया कि इससे समस्याएं पैदा होंगी। मोदीजी संयुक्त राष्ट्र गए और इस मसले पर पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है जबकि पाकिस्तान दुनियाभर में अलग-थलग पड़ गया है।'

अटल ने दी थी बधाई, कांग्रेस कर रही सवाल: राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस और भाजपा के बीच अंतर बताते हुए शाह ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रहित को प्राथमिकता देती है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) अलग हुआ था तो विपक्ष में होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बधाई देने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन कांग्रेस अनुच्छेद 370 हटाने, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रही है।

देश के टुकड़े करने की बात करने वाले जेल जाएंगे: शाह ने राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने और जेएनयू में नारेबाजी प्रकरण का जिक्र करते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'राहुलजी, अगर आप चाहें तो मुझे, मेरी पार्टी और मोदीजी को गाली दे सकते हैं। हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वालों के साथ खड़े होंगे तो जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा उसे भाजपा सरकार जेल में डाल देगी।'

मोदी की विदेश यात्राओं ने डाला असर: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के विपरीत अब भारत को देखने के दुनिया के नजरिये में बदलाव आया है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। मनमोहन सिंह ने मोदी से ज्यादा विदेश यात्राएं की थीं, लेकिन मोदी की विदेश यात्राओं का असर ज्यादा है।

कांग्रेस-राकांपा ने चुनाव से पहले ही मानी हार: भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस और राकांपा ने 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे भाजपा-शिवसेना और उसके सहयोगी दलों को दो तिहाई बहुमत से जिताएं या 288 में 222 सीटों पर विजयी बनाएं। शाह ने पवार से सवाल किया कि कांग्रेस-राकांपा सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्या किया था।

अनु. 370 हटना आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील : योगी आदित्यनाथ

राज्य ब्यूरो, मुंबई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटना आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। वह आज मुंबई में भाजपा के प्रत्याशी राहुल नार्वेकर के पक्ष में एक प्रचार सभा को संबोधित कर रहे थे।

भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की आज मुंबई में दो प्रचार सभाएं हुईं। कोलाबा सीट से भाजपा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर के समर्थन में योगी ने मुंबई में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। यह सभा दक्षिण मुंबई के हिंदीभाषी क्षेत्र मुंबादेवी में आयोजित की गई थी। यहां योगी ने कहा कि केंद्र की मोदी और राज्य की देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने सुशासन और राष्ट्रवाद को नई ऊंचाई प्रदान की है। योगी ने राष्ट्रवाद, आतंकवाद और विकास के मुद्दे पर कहा कि पांच साल में मोदी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया है। इससे पहले देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं परिवारवाद के हितों के लिए राजनीति होती थी।

इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को योगी ने ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के मुकुट से 370 हटाकर आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। 1953 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो विधान-दो प्रधान, दो निशान का विरोध किया था। उनके सपने को 70 साल बाद मोदी सरकार ने साकार किया है। योगी ने 370 के मुद्दे पर सरकार के निर्णय का विरोध करने वाली कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए देश सर्वोपरि नहीं था। यदि ऐसा होता तो अनुच्छेद 370 हटाने में 70 साल नहीं लगते।

योगी आदित्यनाथ। फाइल

योगी ने कहा कि 370 हटाने के बाद पकिस्तान घड़ियाली आंसू बहा रहा है। भारत ने उसे चेता दिया है कि इस बार छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इससे घबराए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत हम पर हमला कर सकता है। यूपी के सीएम ने कहा कि कभी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आतंकियों का 'सॉफ्ट टार्गेट' हुआ करती थी। पांच साल में मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित रही। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है।

राहुल गांधी को खाए जा रहे पार्टी के कुछ बड़े नेता : तंवर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- हरियाणा विधानसभा चुनावों में 22 टिकट बेचने का लगाया आरोप

साढ़े पांच साल तक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी के बड़े-बड़े नेता ही राहुल गांधी को खाए जा रहे हैं। ये भाजपा के साथ मिलकर पार्टी को खत्म कर रहे हैं। उसे आइसीयू में पहुंचा दिया है। भारत को कांग्रेस मुक्त करने का फैसला पार्टी के अंदर के ही कुछ नेताओं का है। ऐसी ताकतों को पहचानना पड़ेगा।

चंडीगढ़ में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में तंवर ने कहा कि कांग्रेस पहले कार्यकर्ता को बच्चे की तरह तैयार करती है और फिर उसी को पार्टी के बड़े नेता खा जाते हैं। कुछ की तो भ्रूणहत्या की जाती है। कुछ मेरे जैसे लोग, जिन्हें राजनीति में मौका मिलता है, उन्हें एक समय के बाद खत्म कर दिया जाता है। राहुल गांधी भी इसी चीज के शिकार हुए।

विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की मिट्टी पलीद होने का दावा करते हुए तंवर ने 22 विधानसभा क्षेत्रों का टिकट बेचे जाने का आरोप फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दुसमा (सबसे खराब स्थिति) होगी। तंवर ने कहा टिकट वितरण में पार्टी का कोई सिस्टम नहीं था। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। केवल चाय-पानी हुआ और गपशप हुई। नतीजन पार्टी में कई दशक लगाने वालों का टिकट कटा और अंतिम क्षणों में कांग्रेस में आने वालों को टिकट दे दिया गया। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में वह दुराचारी और भ्रष्टाचारी नेताओं को हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। अच्छे प्रत्याशी चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनकी मदद करेंगे।

अशोक तंवर। फाइल

उप्र कांग्रेस में असंतोष, राजेश मिश्र ने सलाहकार परिषद को ठुकराया

जागरण संवाददाता, वाराणसी: उप्र कांग्रेस कमेटी गठन के साथ ही पूर्वांचल के नेताओं में जिस असंतोष की बात कही जा रही थी, वह गुरुवार को सामने आ गई। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद डा. राजेश मिश्र ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा द्वारा बनाई गई सलाहकार परिषद को ठुकरा दिया। उन्होंने प्रियंका के राजनीतिक सलाहकार जुबेर खान को इसका संदेश भेज दिया है। साथ ही लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के प्रभार से भी मुक्त करने का अनुरोध किया है, जहां उप चुनाव होना है। डा. राजेश मिश्र का कहना है कि वह राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशों का पालन करते आ रहे हैं। आदेश पर वाराणसी लोकसभा सीट की बजाए सलेमपुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब उनको वह सलाह कैसे दे सकते हैं। इन्हीं तर्कों के साथ प्रियंका की अध्यक्षता में गठित सलाहकार परिषद से खुद को बाहर करने के लिए संदेश भेजा है। साथ ही कहा है कि लखनऊ कैंट विस क्षेत्र में हो रहे उप चुनाव में प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के सुझाव पर प्रत्याशी का चयन हुआ है। ऐसे में इस सीट के प्रभार की जिम्मेदारी उनसे अच्छा कोई नहीं निभा सकता।

लालू परिवार में पुराने वफादार बनाम नए किरदार पर मंथन

अरविंद शर्मा, पटना

- डॉ. रामचंद्र पूर्वे के दोबारा राजद अध्यक्ष बनने की संभावना

राजद का सदस्यता अभियान दो महीने चलकर गुरुवार को खत्म हो गया। पंचायत, प्रखंड एवं जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू होगी। सियासी गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चा, उत्सुकता और इंतजार प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर है। डॉ. रामचंद्र पूर्वे ही बने रहेंगे या किसी और को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। लालू परिवार में पुराने वफादार बनाम नए किरदार पर मंथन जारी है।

राजद में प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार कई हैं और रामचंद्र पूर्वे की राह में बढ़ती उम्र आड़े आ रही है। ऐसे में आलोक मेहता एवं शिवचंद्र राम का नाम तेजी से चल रहा है। सूची में कुछ ऐसे बड़े नाम भी शामिल हो चुके हैं, जो प्रतिस्पर्धा को दिलचस्प बना रहे हैं। विधान परिषद के पूर्व सभापति सलीम परवेज, पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी भी बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। हाल के दिनों में पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और विधायक कुमार सर्वजीत का नाम भी जुड़ गया है। करीब महीने भर पहले राजद की सदस्यता लेने वाले पूर्व मंत्री रमई राम भी प्रयासों में पीछे नहीं हैं। चुनाव करीब देखते हुए दर्जन भर अन्य नेता भी सक्रिय हो गए हैं। दावेदारी और उम्मीदवारी में कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन रामचंद्र पूर्वे की वफादारी सब पर भारी पड़ सकती है।

चार बार से कप्तानी कर रहे पूर्वे: राजद की चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से दो दिसंबर के पहले प्रदेश राजद के नए कप्तान का निर्वाचन हो जाएगा। डॉ. पूर्वे 2010 से ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चार बार इस पद पर रह चुके हैं। एक बार मनोनीत और तीन बार निर्वाचित। लोकसभा चुनाव का परिणाम पूर्वे के पक्ष में नहीं आया है। फिर भी दावेदारी में वे भारी नजर आ रहे हैं। पूर्वे की गिनती लालू प्रसाद के वफादार नेताओं में होती है। सत्ता और सियासत में ओहदा पाने के लिए सामाजिक समीकरण और नेतृत्व के प्रति समर्पण, दो बड़े फैक्टर अहम होते हैं। अति पिछड़े वर्ग से आने और राजद के स्थापना काल से जुड़े होने के कारण पूर्वे अभी भी लालू के हर फार्मूले पर फिट बैठते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी लालू के लिए वह अपरिहार्य बने रहे।

भाजपा प्रत्याशी से नाराज शिवसेना के 28 सभासदों व 200 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा

मुंबई, मिड डे: महाराष्ट्र की कल्याण पूर्वी विधानसभा सीट गठबंधन के सहयोगी भाजपा के हिस्से में जाने और उसके प्रत्याशी से नाराज शिवसेना के 28 सभासदों व 200 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया।

भाजपा ने इस सीट से गणपत गायकवाड़ को टिकट दिया है। सभासदों का कहना है कि गायकवाड़ यहां से दो बार से विधायक रहे, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए, मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। शिवसैनिक चाहते थे कि उनके पार्टी के नेता धनंजय बोडारे कल्याण पूर्वी से चुनाव लड़ें। शिवसैनिकों का कहना है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोडारे राजनीति में 27 साल से सक्रिय हैं और आसपास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इसलिए उन्हें ही यहां से टिकट दिया जाना चाहिए थे। उन्होंने यहां से भाजपा प्रत्याशी को टिकट दिए जाने का विरोध किया।

कल्याण डोंबीवली के शिवसैनिक लोकसभा चुनाव के दौरान भी बागी हो गए थे। तब एकनाथ शिंदे ने मध्यस्थता करते हुए शिवसैनिकों को मना लिया था। इस प्रकार लोस चुनावों में यहां से भाजपा के प्रत्याशी कपिल पाटिल की जीत हुई थी।

दाव-पेच

हर चुनाव में पांच प्रमुख खाप पंचायतों और आधा दर्जन डेरों का रहता है अहम रोल, जाट बहुल क्षेत्रों में खापों का खासा वजूद, जिसे समर्थन दिया उसकी पौ बारह

हरियाणा में गहरा है खाप-डेरों का असर

सुधीर तंवर, चंडीगढ़

- कंडेला खाप, बिनैन खाप, सर्वजाट खाप, महम चौबीसी खाप और गठवाला मलिक खाप चुनावों में अहम भूमिका अदा करती हैं
- डेरा सच्चा सौदा, डेरा समैण, संत निरंकारी मिशन और राधा स्वामी सत्संग सहित आधा दर्जन डेरों का भी है खासा प्रभाव

डेरे हों या फिर खाप पंचायतें, चुनावी जंग जीतने के लिए नेताओं ने उनके इर्द-गिर्द मंडराना शुरू कर दिया है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को पहले भले ही डेरों और खाप पंचायतों की याद न आई हो, लेकिन इन दिनों उनका डेरों और खापों के चक्कर लगाना लाजिमी है। सवाल राजनीतिक भविष्य का जो है। अगर बात बन गई और समर्थन मिला तो फिर बल्ले-बल्ले।

प्रदेश में खापों का प्रभाव जाट बहुल क्षेत्रों में ज्यादा है। प्रमुख रूप से कंडेला खाप, बिनैन खाप, सर्वजाट खाप, महम चौबीसी खाप और गठवाला मलिक खाप चुनावों में अहम भूमिका अदा करती हैं। इन पर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का फोकस बना हुआ है।

कंडेला खाप ने हालांकि अभी तक किसी को चुनाव में समर्थन पर निर्णय नहीं लिया है। जींद विधानसभा क्षेत्र में इस खाप का खासा प्रभाव माना जाता है। खाप प्रधान टेकराम कंडेला के भाजपा में आने के बाद समीकरण कुछ बदले हैं। इसके अलावा गठवाला मलिक खाप कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने वजूद का दावा करती है। इनमें गन्नौर, गोहाना, बरौदा, जुलाना, पानीपत ग्रामीण, इसराना, हांसी और सफीदों क्षेत्र प्रमुख हैं। बीते चुनाव में इस खाप के समर्थन से कई विधायक विधानसभा में पहुंचे थे।

बात करें बिनैन खाप की तो नरवाना, टोहाना और उकलाना इसके प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं। अन्य जाट क्षेत्रों में भी खाप अपना रसूख होने का दावा करती रही है। सर्व जाट खाप नवाना, टोहाना, उकलाना, बरवाला, हांसी, नारनौंद, कैथल व गोहाना क्षेत्रों में दबदबा होने का दम भरती है। जाट आंदोलन से इस खाप का उदय हुआ है। महम चौबीसी खाप दो विचारधाराओं में बंटी हुई खाप है। इसका इतिहास चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का रहा है। खाप ने अपने दम पर पंचायती उम्मीदवारों को जिताया भी है। खाप के अपने जीते उम्मीदवारों में हरस्वरूप बूरा, उमेद सिंह और प्रो. महा सिंह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त समैण बिठमड़ा खाप से जुड़े सूबे सिंह समैण भी टिकट की दावेदारी करते रहे हैं।

खाप और डेरों के पास काफी मात्रा में लोग जुड़े होते हैं जो किसी भी राजनीतिक दल को लुभा सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मौसम में यहां का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं।

पूरे प्रदेश में फैले अनुयायी

खापों के प्रभाव पर नजर डालने के बाद अगर डेरों को खंगाला जाए तो प्रदेश में डेरा सच्चा सौदा, डेरा समैण, संत निरंकारी मिशन और राधा स्वामी सत्संग सहित आधा दर्जन डेरों का खासा प्रभाव है। इनके अनुयायी व समर्थक किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हैं। डेरा सच्चा सौदा मौजूदा समय में भी अपने दम पर कई सीटों के समीकरण बदलने की कुव्वत रखता हैं। इसलिए ही चुनावी समर में नेताओं का डेरों में सुबह-शाम चक्कर काटना सामान्य हो गया है।

भाजपा ने बंगाल में दुर्गापूजा में चलाए गए जनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट मांगी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- दुर्गापूजा मंडपों के आसपास लगाए गए थे 10,000 8 बुक स्टॉल

बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान जन संपर्क अभियान के बारे में भाजपा नेतृत्व ने पार्टी की जिला इकाइयों एवं राज्य के नेताओं से रिपोर्ट मांगी है। विशेषकर यह संपर्क अभियान राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन बिल को ध्यान में रखकर चलाया गया था। भाजपा सूत्रों के अनुसार पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा था कि त्योहार के अवसर पर वे जनता से संपर्क बढ़ाएं तथा पार्टी की विचारधारा एवं नीतियों के बारे में प्रचार करें।

इस बार भाजपा ने दुर्गापूजा के मंडपों के आसपास 10,000 से अधिक स्टॉल लगाए थे। इन स्टॉलों में पार्टी की विचारधारा से जुड़ी पुस्तकें रखीं गईं थीं। यहां से जनता को एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन बिल से संबंधित जानकारियां भी दी गई।

प्रदेश भाजपा महासचिव प्रताप बनर्जी ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने सभी जिलों एवं प्रदेश नेताओं से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि किस तरह दुर्गापूजा त्योहार के माध्यम से पार्टी का जन संपर्क बढ़ाया गया।

उन्होंने अगले सप्ताह की शुरुआत तक इस बारे में पूरी रिपोर्ट मिलने की उम्मीद जताई। रिपोर्ट के आधार पर भाजपा का जनाधार बढ़ने और पार्टी की विचारधारा फैलने के बारे में पता चलेगा।

माकपा का दावा, बेहतर रही मार्क्सवादी साहित्य की बिक्री

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या शून्य पर पहुंचने के बावजूद माकपा के प्रकाशन हाउस नेशनल बुक एजेंसी (एनबीए) का इस दुर्गा पूजा मार्क्सवादी साहित्य से जुड़ी किताबों की बिक्री में बेहतर प्रदर्शन रहा है। दावा किया जा रहा है कि एनबीए के स्टॉल पर पूजा के दौरान भारी भीड़ देखी गई। एनबीए के अध्यक्ष अनिरुद्ध चक्रवर्ती ने कहा कि विभिन्न पूजा पंडालों के बाहर स्टालों पर किताबों की बिक्री और इसे लेकर लोगों में उत्सुकता देखने को मिली। उन्होंने कहा कि चीन पर बुद्धदेव भट्टाचार्य लिखित किताब के दो बांग्ला संस्करणों 'स्वर्गे नीचे महाबिश्रिंखला' (अराजकता के तहत स्वर्ग) पहले ही बिक चुकी हैं जबकि तीसरे संस्करण की छपाई की जा रही है। हालांकि, बिक्री के आंकड़े और स्टालों में बेची गई पुस्तकों की संख्या का विवरण देने से इन्कार कर दिया। एनबीए ने इस साल राज्य भर में 1,100 से अधिक पुस्तक स्टाल लगाए थे।

मतभेदों के बावजूद आगे बढ़ने पर है मोदी–चिनफिंग बैठक का फोकस

राय ▸ चीन के सरकारी मीडिया ने कहा– सहयोग की संभावनाएं तलाशेगी बैठक

भारत और चीन ने संदेश दिया है कि वे रचनात्मक बातचीत में बाधा नहीं आने देना चाहते

बीजिंग, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग शुक्रवार दोपहर भारत पहुंच रहे हैं। इसे लेकर चीन के सरकारी मीडिया का कहना है, बैठक का फोकस दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और वर्तमान मतभेदों और सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए उनसे आगे बढ़ने पर रहेगा।

चीन के सरकारी अखबार में छपे संपादकीय में कहा गया है कि अभी यह देखना बाकी है कि अगले दो दिनों में दोनों नेता क्या उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। संपादकीय के मुताबिक, 'अनौपचारिक बैठक से सिर्फ 48 घंटे पहले चिनफिंग की देश के दो दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों (भारत और नेपाल) की यात्रा की आधिकारिक घोषणा इस बात का सुबूत है कि बीजिंग और नई दिल्ली अपने शीर्ष नेताओं के बीच निजी कैमिस्ट्री के जरिये द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना चाहते हैं। चीन और भारत दोनों ने ही घोषणा की है कि बैठक होगी, लिहाजा वे आशंकाएं खत्म हो गई हैं कि दोनों नेता बैठक स्थगित कर सकते हैं। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि वे रचनात्मक बातचीत के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने देना चाहते हैं।'

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के दौरे के मद्देनजर तमिलनाडु के मामल्लपुरम में भव्य तैयारियां की गई हैं। यहां के पल्लवकालीन स्थलों को जाने वाले मार्ग पर प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। गुरुवार को द्वार के पास तैनात सुरक्षाकर्मी। एपी

विदेश उपमंत्री बोले, सफल होगी यात्रा : बैठक के बारे में चीन के विदेश उपमंत्री लुओ झाओहुई ने मीडिया को बताया कि बैठक के लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने गहन वार्ता के जरिये बेहद सावधानीपूर्वक तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा, 'अब ठोस आधार बन गया है। दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रपति चिनफिंग की भारत यात्रा पूरी तरह सफल होगी और द्विपक्षीय संबंधों में और विकास की दिशा और टोन तय करेगी। साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग के आदान-प्रदान से नई प्रगति और फलदायी परिणाम देगी। चूंकि यह अनौपचारिक बैठक है लिहाजा दोनों नेता शांत और आरामदायक माहौल में बिना पूर्व निर्धारित विषयों के विचारों का आदान-प्रदान कर सकेंगे।' इसलिए दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना भी नहीं है। बता दें कि मोदी और चिनफिंग के बीच वार्ता के दौरान ज्यादातर समय सिर्फ उनके अनुवादक ही साथ होंगे।

कश्मीर पर बोलने से बचे प्रवक्ता : चिनफिंग की यात्रा से पहले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कश्मीर मसले पर चीनी रुख के बारे में ज्यादा कुछ कहने से इन्कार कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या मोदी-चिनफिंग बातचीत में कश्मीर मसला भी उठेगा तो उन्होंने कहा, 'कश्मीर मसले पर चीन का रुख लगातार एक जैसा और स्पष्ट है। राष्ट्रपति चिनफिंग और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बारे में हम समय आने पर जानकारी देंगे।'

कांग्रेस बोली, चीन को कठोर संदेश देना जरूरी

- चिनफिंग के कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात करने पर प्रतिक्रिया
- कहा, चीन से कहें– तिब्बत–हांगकांग में चीनी दमन पर भारत की भी नजर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुलझाने के चीन के बयान पर बेहद कड़ा एतराज जाहिर करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से चीन को इसका मुंहतोड़ कूटनीतिक जवाब देने को कहा है। पार्टी ने सरकार से कहा है कि चीन को जवाब देने के लिए भारत को भी तिब्बत और हांगकांग के मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के जरिये करने की मांग उठानी चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के इस बयान 'उनकी कश्मीर पर नजर है', पर केंद्र सरकार के कठोर जवाब नहीं देने पर सवाल उठाया। तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि जब चिनफिंग ऐसी बात कह रहे हैं तो पीएमओ और विदेश मंत्रालय यह क्यों नहीं कह रहा कि हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों को जिस तरह कुचला जा रहा उस पर हमारी भी नजर है। इसी तरह, चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को भी हम देख रहे हैं। साथ ही तिब्बत में वहां के लोगों के लगातार दमन पर भी भारत की नजरें हैं। जबकि दक्षिण चीन सागर में उसकी नीतियों पर भी हमारी निगाह है। कांग्रेस नेता ने चीन की पाक परस्त नीति पर प्रहार करने के लिए इन मुद्दों पर चीन को आईना दिखाने के लिए कहा।

मनीष तिवारी ने दूसरे ट्वीट में चीन को लेकर राजग-भाजपा सरकार की नरम नीति को लेकर उसे आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कहा कि राजग-भाजपा के लोग गुलाम कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान पाकिस्तान से वापस लेने की जोर-शोर से हुंकार भरते हैं मगर इनमें कोई भी चीन से अक्साई चिन वापस लेने की बात नहीं करता। तिवारी ने पीएमओ से सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति चिनफिंग की बैठक में प्रधानमंत्री अक्साई चिन का हिस्सा वापस लेने का मुद्दा उठाएंगे?

जनमत मुद्दा

क्या भारत से संबंधों को प्रगाढ़ करने की विवशता और पाकिस्तान से संबंध बनाए रखने की जरूरत चीन को कश्मीर पर बार-बार बयान बदलने को मजबूर कर रही है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

राजदूत ने कहा, एक दूसरे के लिए खतरा नहीं भारत–चीन

मामल्लपुरम, प्रेट्र : राष्ट्रपति शी चिनफिंग के अहम भारत दौरे से पहले चीन ने कहा है कि दोनों देश एक-दूसरे के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करते और एशिया के इन दो बड़े देशों के बीच ज्यादा सहयोग क्षेत्र और उसके बाहर सकारात्मक माहौल पैदा करने में सहायक बनेगा।

भारत में चीन के राजदूत सुन वेडांग ने एजेंसी के साथ बातचीत में कहा कि चिनफिंग और मोदी के बीच होने वाली बातचीत में सहमति के नए बिंदु उभरेंगे, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों के विकास को दिशा देने वाले सिद्धांत भी होंगे। वेडांग के मुताबिक भारत और चीन दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले देश हैं।

दोनों देशों की यह जिम्मेदारी है कि वे जटिल दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा भरने की दिशा में काम करें। मोदी-चिनफिंग शिखर वार्ता द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और इसका क्षेत्रीय व वैश्विक शांति-स्थिरता में गहरा सकारात्मक असर होगा। वेडांग ने कहा, दोनों नेता अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर गहराई से विचार-विमर्श करेंगे। संरक्षणवाद सरीखी चुनौतियों से निपटने की दिशा में भारत और चीन का सहयोग अहम होगा।

मोदी के लिए चिनफिंग का तोहफा आत्मीयता और दोस्ती का प्रतीक

बीजिंग, प्रेट्र : दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए शुक्रवार को भारत पहुंच रहे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा तोहफा देने की है जो उनके बीच आत्मीयता और दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों को दर्शाता हो। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

मोदी और चिनफिंग पिछले वर्षों में कई बार मिल चुके हैं। लिहाजा उनके बीच आपसी समझबूझ बन गई है। इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच पिछले साल वुहान में पहली अनौपचारिक बैठक हो सकी थी और जिसने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में मदद की थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति चिनफिंग भारत और नेपाल के नेताओं को जो तोहफे देंगे वे उनके और चीन के साथ दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों का प्रतीक होंगे।

हालांकि मंत्रालय ने तोहफों का कोई विवरण नहीं दिया। बता दें कि वुहान बैठक के दौरान मोदी ने चिनफिंग को प्रख्यात चीनी कलाकार झू बीहांग की पेंटिंग्स तोहफे में दी थीं।

राजनाथ की अपील, फ्रांस की रक्षा कंपनियां भारत को बनाएं ठिकाना

- तीन दिवसीय यात्रा से भारत लौटे रक्षा मंत्री, बोले–बेहद सार्थक रही फ्रांस की यात्रा

पेरिस, एजेंसियां : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि फ्रांस की उनकी यात्रा बेहद सार्थक रही और इससे भारत तथा फ्रांस के द्विपक्षीय रक्षा संबंध और प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने फ्रांस की कंपनियों को रक्षा उपकरणों का निर्माण करने के लिए भारत को अपना ठिकाना बनाने का संदेश दिया।

रक्षा मंत्री फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा समाप्त करके पेरिस से नई दिल्ली पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह ने रवाना होने से पहले ट्वीट किया, 'शुक्रिया फ्रांस! मेर्सी! यह यात्रा बेहद सार्थक रही।' उन्होंने कहा, 'इस यात्रा के नतीजे भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ली और फ्रांस सरकार के आतिथ्य के प्रति मेरा आभार।'

बुधवार शाम को राजनाथ सिंह ने फ्रांस के प्रमुख रक्षा उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित किया और तकनीकों के मेल के जरिए भारत के बंदरगाहों और रक्षा मंचों को आधुनिक बनाने को कहा। उन्होंने कहा, 'फ्रांस की कंपनियां रक्षा उपकरण निर्माण के लिए भारत को अपना ठिकाना बना सकती हैं। भारत के बड़े बाजार के लिए ही नहीं बल्कि अन्य देशों को निर्यात करने के लिए भी।'

सिंह ने भारत भर में एक समान वस्तु एवं सेवा शुल्क लागू करने के महत्व को भी रेखांकित किया। स्वतंत्रता के बाद यह कर सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, 'हमने हाल ही में अपने कॉरपोरेट कर में भारी कटौती की है। रक्षा के क्षेत्र में यदि 'मेक इन इंडिया' के लिए कर को और सुसंगत करने की जरूरत पड़ी तो इसपर विचार किया जाएगा।'

रक्षा मंत्री ने फ्रांस की कंपनियों की प्रति वर्ष भारत में डिफेंस एक्सपो में उत्साह के साथ भाग लेने की भी सराहना की। सिंह ने फ्रांस की कंपनियों को अगले साल पांच से आठ फरवरी के बीच लखनऊ में आयोजित होने वाले डेफएक्सपो में भाग लेने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा, 'लखनऊ समृद्ध संस्कृति और धरोहरों वाला शहर है और फ्रांस के लोग महान संस्कृतियों का आदर करने वाले माने जाते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और नए अवसरों की भूमि भी।'

शस्त्र पूजा में कश्मीरी मुस्लिम, सिख अफसरों ने मदद की

नई दिल्ली, आइएएनएस : राफेल विमान की पूजा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मदद वायुसेना के कश्मीरी मुस्लिम और सिख अफसरों ने की थी। हिंदू रीति से शस्त्र पूजा के निवर्हन में वायुसेना की कार्यशैली की बेहतरीन मिसाल है। सर्वधर्म सम्भाव वाली वायुसेना की पूजा की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि जहां भारत में कुछ राजनीतिक दल रक्षा मंत्री पर सभी धर्मों के करदाताओं के धन को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे थे, वहीं खुद वायुसेना के अफसर एयर कोमोडोर हिलाल अहमद फ्रांस में भारतीय दूतावास के अटैची हैं।

चिदंबरम व उनके पुत्र की अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : 3500 करोड़ रुपये के एयरसेल मैक्सिस डील मामले में आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।

राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने गत 5 सितंबर को चिदंबरम व उनके बेटे को अग्रिम जमानत दी थी। आइएनएक्स मीडिया डील मामले में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआइ ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पिछले साल 25 अक्टूबर को ईडी ने एरसेल मैक्सिस घोटाले में आरोपपत्र दाखिल किया था। पटियाला हाउस की विशेष अदालत में दायर इस आरोपपत्र में चिदंबरम के अलावा कार्ति, कार्ति के सीए एस भास्करन, एयरसेल के पूर्व सीईओ वी श्रीनिवासन, मैक्सिस से अगस्तस रॉल्फ मार्शल, एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क, एयरसेल टेलिवेंचर, मैक्सिस मोबाइल सर्विस, बुमि अरमदा, बुमि अरमदा नेविगेशन को नामजद किया गया था।

अभिनेत्री नूपुर अलंकार भी हैं पीएमसी घोटाले की शिकार

मुंबई, एएनआइ : कई टेलीविजन सीरियल में काम कर चुकीं अभिनेत्री नूपुर अलंकार इन दिनों भारी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। यह बात मीडिया से खुद नूपुर ने ही साझा की। नूपुर की हालत इतनी खराब हो चुकी हैं रोज के खर्चे के लिए उन्हें पैसे जुटाने पड़ रहे हैं। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि वह अब अपना घर गिरवी रखने के बारे में भी सोच रही हैं। नूपुर अपने घर के सामान को भी बेचने पर विचार कर रही हैं।

नूपुर ने कहा, 'मेरी मां को ऑक्सीजन लगा है और ससुर की जल्द ही सर्जरी करवानी है। मुझे लोगों से विनती करनी पड़ रही है और उधार लेना पड़ा रहा है। मेरे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा। अगर सबकुछ ठीक नहीं हुआ तो मुझे अपने गहने बेचने होंगे और घर की चीजें भी बेचनी होंगी।'

इससे पहले नूपुर ने कहा था, 'मैं एक बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रही हूं। दूसरे बैंकों में भी मेरे खाते थे जिन्हें मैंने कुछ साल पहले इस बैंक में ट्रांसफर किया था। मुझे कैसे पता होगा कि मेरे परिवार के सदस्य- पति, मां, बहन, ननद, ससुर और मेरी जिंदगी भर की बचत को इस तरह फ्रीज कर लिया जाएगा।'

नूपुर अलंकार। फाइल

उन्होंने कहा कि बगैर पैसे के वह कैसे जीवनयापन करें। उन्होंने पूछा क्या अपना घर गिरवी रखना चाहिए। खुद की कमाई पर रोक क्यों है। टैक्स भरने के बावजूद इस तरह की तकलीफों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। फिल्म व टीवी अभिनेत्री नूपुर अलंकार 'अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो' और 'स्वरागिनी' जैसे सीरियलों में काम कर चुकी हैं।

गोतस्करों ने गोरक्षा दल के जिला संयोजक को मारी गोली

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

एक दुस्साहसिक वारदात में तस्करी कर गायों को ले जा रहे बदमाशों ने गोरक्षा दल के जिला संयोजक मोनू यादव को गोली मार दी। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपित गोतस्कर मुस्लिम बहुल नूंह के बताए जा रहे हैं। बुधवार देर रात गोरक्षा दल के संयोजक मोनू यादव (मोहित यादव) को सूचना मिली थी कि गोतस्कर सोहना रोड से पिकअप वाहन में गायों को लेकर निकलने वाले हैं। मोनू अपने साथियों के साथ कार में भोंडसी के नजदीक पहुंच गए। गुरुवार तड़के लगभग तीन बजे गुरुग्राम की तरफ से पिकअप आती दिखाई दी। रोकने का इशारा करने पर पिकअप को वापस गुरुग्राम की तरफ मोड़ दिया।

गोरक्षकों को उलझाने के लिए चलती पिकअप से गायों को फेंकने लगे। बादशाहपुर के नजदीक फेंकी गई दो गायों को बचाते हुए गोरक्षक तस्करों के पीछे लगे रहे। तब तक गोतस्कर गांव झाड़सा में घुस गए। गांव से पहले बख्तावर चौक पर भी उन्होंने एक गाय को पिकअप से नीचे फेंक दिया। गांव से बाहर निकलकर राजीव चौक होते ही सेक्टर-10ए इलाके में पहुंच गए। शांति नगर में उन्होंने गाड़ी की स्टेपनी कार की तरफ फेंकी। कादीपुर स्थित स्कूल के नजदीक तस्करों ने अपनी गाड़ी रोककर फायरिंग कर दी। गोली सीधे मोनू के सीने में लगी। इसके बाद गोतस्कर फरार हो गए।

मोनू यादव। फाइल फोटो

छह लोगों पर तस्करी का आरोप : गोरक्षकों ने पिकअप में भाग रहे तस्करों की पहचान नूंह के हुसैनपुर निवासी अंजुम, लियाकत, कय्यूम, इश्तियाक, दिलशाद के रूप में की। वे एक शख्स को पहचान नहीं पाए।

जुलूस निकाला : गो-तस्करी के खिलाफ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मेदांता अस्पताल से लेकर लघु सचिवालय के नजदीक तक जुलूस निकाला और आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

25 साल पुराने मामले में भाजपा विधायक को सजा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व नगरपालिका की फाइलों को नष्ट करने के मामले में बनासकांठा की स्थानीय अदालत ने गुरुवार को डीसा के भाजपा विधायक शशिकांत पांड्या को तीन माह कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि, शीघ्र ही विधायक को जमानत भी दे दी गई। मामला 25 साल पुराना है। वर्ष 1994 में श्रीप्रकाश भारतीय डीसा नगरपालिका के चेयरमैन थे। तब पांड्या ने चीफ ऑफिसर गंगाराम सोलंकी व सुप्रिंटेंडेंट के काम में बाधा पहुंचाते हुए कार्यालय में रखी फाइलों को नष्ट कर दिया था। उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 327, 477, 186 तथा 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। डीसा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमडी ब्रह्मभट्ट ने सरकारी वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए गुरुवार को भाजपा विधायक को इस मामले में तीन माह कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विधायक ने बताया कि यह उस समय का मामला है जब कांग्रेस सत्ता में थी। वे नेता विपक्ष के नाते जनसमस्या हल करने के लिए अर्जी देने गए थे। जनता से जुड़े मुद्दों पर वह आक्रामक थे। इसलिए, चीफ ऑफिसर ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाने के कुछ समय बाद जमानत दे दी।

जय श्रीराम बोलने पर बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता को गोली मारी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जय श्रीराम बोलने पर एक भाजपा कार्यकर्ता को गोली मार दिए जाने की घटना प्रकाश में आई है। उसका नाम राम प्रसाद मंडल (38) है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है।

उसे कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा ने हमले के पीछे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है। हालांकि तृणमूल ने भाजपा के आरोपों को झूठा और पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक करने का आरोप लगाया है। इस बाबत पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में सत्येंद्र सरदार, सन्यासी नस्कर, मनोरंजन सरदार, तपन नस्कर और पवित्र नस्कर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में जय श्रीराम बोलने पर भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले की घटना होती रही है। भाजपा हर बार तृणमूल पर आरोप लगाती रही है और तृणमूल नेता हर बार इन्कार करते रहे हैं। भाजपा का कहना है कि प्रशासन भी उनकी शिकायतों पर गंभीर नहीं होता है।

वारदात के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार बताया

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

दशहरे के दिन हुए इस नृशंस हत्याकांड को लेकर भाजपा व विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इस वारदात को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुत्री व कांग्रेस प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने वारदात को बर्बर करार दिया है। भाजपा सांसद कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा-'इससे ज्यादा जघन्यता क्या होगी? जहां आम आदमी सुरक्षित न हो, उस राज्य की कानून व्यवस्था को अच्छा कैसे माना जाए? ये क्या हो रहा है दीदी आपके राज में?' भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने बंगाल में 'जंगलराज' की बात कहते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा-'पुलिस ने इस मामले में अब तक जांच शुरू नहीं की है। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे साफ है कि बंगाल में कानून व्यवस्था बोलकर कोई चीज नहीं है।

विहिप ने वारदात के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे मानवता को शर्मसार करने वाला करार दिया। विहिप के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि एक ओर मां चंडी ने महिषासुर जैसे राक्षस का संहार कर पृथ्वी को भयमुक्त किया, वहीं बंगाल सरकार मानवता के दुश्मन राक्षसों पर ममता बरसा रही है। बंसल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राज्य सरकार अब हिंदुओं के धैर्य की और परीक्षा न ले। जब हिंदुओं की हत्याएं होती हैं और वह भी किसी संघ के स्वयंसेवक की तो सारा तंत्र शांत क्यों हो जाता है? मोमबत्ती गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, नागरिक समाज, कलाकार, फिल्मकार और बुद्धिजीवी तब क्या खाकर सो जाते हैं?

यह है मामला

मुर्शिदाबाद में दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, पत्नी और बेटे की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से नृशंस हत्या कर दी थी। खून से सने तीनों के शव उनके ही घर में बरामद हुए थे। प्रकाश पाल पेशे से शिक्षक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बंगाल शाखा के अनुसार प्रकाश पाल आरएसएस के सक्रिय सदस्य भी थे। करीबियों का कहना है कि राजनीतिक कारणों से बंधु प्रकाश पाल व उनके बीवी-बच्चे की हत्या की गई है।

उम्मीद है कि 'उदारवादियों' को बंगाल हत्याकांड पीड़ितों से सहानूभुति होगी : कानून मंत्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बंगाल में एक स्कूल अध्यापक और उसके परिवार की हत्या की गुरुवार को निंदा करते हुए कहा कि यदि 'उदारवादी' इसकी निंदा न भी करें, तो भी उम्मीद है कि उनके लिए यह इतना भयंकर होगा कि उन्हें पीड़ितों से सहानूभुति होगी।

प्रसाद ने ट्वीट किया, 'बंगाल में आरएसएस कार्यकर्ता, उनकी पत्नी और बच्चे की हत्या के बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। आशा करता हूं कि उदारवादी भले ही इस नृशंस हत्याकांड की सीधे निंदा न करें, लेकिन उन्हें यह इतना भयंकर तो लगेगा कि वे पीड़ित परिवार के साथ सहानूभुति रखेंगे।'

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर घर का वीडियो साझा किया जिसमें फर्श पर खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। पात्रा ने ट्वीट किया, 'चेतावनी : नृशंस वीडियो। इसने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उदारवादियों की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया। 59 उदारवादियों ने ममता को एक भी पत्र नहीं लिखा।'

गौरतलब है कि देशभर के 49 जानेमाने लोगों ने जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में भीड़हत्या की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

महायज्ञ

वेद मंत्रों के पाठ और हवन से बिड़ला मंदिर में चहुंओर अध्यात्म

विहिप, झंडेवालान मंदिर व अशोक सिंहल फाउंडेशन द्वारा बिड़ला मंदिर में कराया जा रहा चतुर्वेद स्वाहाकार महायज्ञ, दक्षिण भारत के 60 से अधिक वेद पाठियों ने किया मंत्रोच्चार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

चारों वेद के सस्वर पाठ और हवन कुंड से निकलता धुआं वहां मौजूद लोगों को अध्यात्म के रंग में रंग रहा है। गुरुवार को यहां चतुर्वेद स्वाहाकार महायज्ञ प्रारंभ हो गया है। दक्षिण भारत के 60 से अधिक वेद पाठियों ने वेदों के मंत्रोच्चार से पूरा परिसर गूंजता रहा। इसमें शामिल होने के लिए देशभर से साधु-संत आए हैं। इसका आयोजन विश्व हिंदू परिषद (विहिप), झंडेवालान मंदिर व अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा कराया जा रहा है। यह 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है।

महायज्ञ में आए जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में वैमनस्यता बढ़ रही है। प्रकृति असंतुलित हो रही है। ऐसे में यज्ञ के माध्यम से धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु व नक्षत्रों का संतुलन बनेगा और प्राणियों में सद्भावना आएगी। यज्ञ से उन्माद शिथिल होता है, उत्तेजना शिथिल होती है। यज्ञ के माध्यम से वो तत्व विकसित होते हैं जो व्यक्ति को सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक और संयमित रखते हैं। यज्ञ से पाचक रस सहज बनते हैं। यज्ञ के परिणाम यह भी देखे गए कि समूची प्रकृति में एकता आ जाती है।

श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर (बिड़ला मंदिर) परिसर में चतुर्वेद स्वाहाकार महायज्ञ में हवन करते पुरोहित। संजय

विहिप के प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद्र ने बताया कि विश्व के कल्याण के लिए यह यज्ञ है। वेद के विषय में अनेक भ्रांतियां फैली हैं जैसे महिलाएं वेद नहीं पढ़-सुन सकतीं, कोई विशेष वर्ग नहीं सुन सकता। उन्होंने बताया कि यजुर्वेद के 26वें मंडल के दूसरे अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वेदों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नारी, सेवक कोई भी श्रवण, अध्ययन और पठन कर सकता है। वेद के लेकर फैले भ्रम दूर हों इसलिए दिल्ली में ऐसा महायज्ञ पहली बार हो रहा है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी यह ऐतिहासिक है, इसमें झुग्गी बस्तियों से लेकर महलों में रहने वाले विभिन्न समाज के नेता, धर्म नेता व राज नेता को बुला रहे हैं और वे सब आ भी रहे हैं। दक्षिण के 61 आचार्य यहां आए हुए हैं जिनको वेद कंठस्थ है। सुबह 9 से 12 के सत्र में पूर्णाहुति से समय पर चारों वेद मंत्रों का पाठ के साथ आहुति हुई। अंत में सभी को प्रसाद वितरण हुआ। इस महायज्ञ में यजमान के नाते महेश भागचंदका व उनका परिवार, विहिप के संयुक्त महामंत्री कोटेश्वर समेत अन्य शामिल हुए। वहीं, परमानंद महाराज, वृंदावन से फुलडोलदास महाराज व चित्र प्रकाशानंद महाराज, नेपाल से गुरु कर्माचार्य, पंजाब से रमेश शास्त्री, महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद महाराज, उदासीन आश्रम पहाड़गंज के स्वामी राघवानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अमृतानंद, बृज के गुरु शरणानंद व महाराज रमण रीति समेत अन्य साधु-संत शामिल हुए।

आज यजमान बनेंगे भागवत : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत शुक्रवार शाम को महायज्ञ में यजमान बनेंगे। वहीं शनिवार को सुबह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी यजमान बन सकते हैं।

2023 तक राज्य अर्धसैनिक बलों की तैनाती में 65 फीसद रकम देंगे

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, अधिक रकम खर्च करेंगे राज्य
- पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष राज्यों को 15 फीसद और रकम देनी होगी

नई दिल्ली, एएनआइ : देश के अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर अपने क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करानी है तो उन्हें और अधिक रकम खर्च करनी पड़ेगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी एक पत्र के अनुसार पिछले साल के मुकाबले राज्यों को अब इस काम के लिए 10 से 15 फीसद और रकम खर्च करनी पड़ेगी। वर्ष 2023 तक तो राज्यों को मौजूदा लागत से 65 फीसद अधिक रकम खर्च करनी पड़ेगी। वर्ष 2019-2020 के बीच राज्यों को अर्धसैनिक बलों की सामान्य इलाकों में तैनाती के लिए 13.70 करोड़ रुपये देने हैं। लेकिन वर्ष 2023-2024 में इसी काम के लिए राज्यों को 22.30 करोड़ रुपये देने होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक जिन केंद्र शासित प्रदेशों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए रकम का भुगतान करने का कानूनी प्रावधान नहीं है, वहां केंद्र शासित प्रदेशों को भुगतान नहीं करना होगा। इसके अलावा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इन बलों के जवानों के लिए रुकने की उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी। साथ ही उनके पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं का पूरा ख्याल रखना होगा। सीआरपीएफ और आरएएफ जैसे बलों की तैनाती के लिए केंद्र सरकार को इसतरह की कोई भी शुल्क अदायगी नहीं करने होगी।

अत्यधिक खतरे वाली जगहों के लिए राज्यों को वर्ष 2019-2020 के दौरान 25.18 करोड़ रुपये देने होंगे। जबकि वर्ष 2023-2024 में यह रकम बढ़कर 33.78 करोड़ रुपये हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की अवधि दस दिन के लिए बढ़ जाएगी तो फिर राज्यों को उनके लिए पूरे महीने का भुगतान करना होगा।

3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी राजस्थान सरकार पढ़े-लिखे किन्नर (ट्रांसजेंडर) को। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार किन्नर श्रेणी के लिए पात्र लाभार्थी को राज्य में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री धारक होना चाहिए।

अब बेखौफ कश्मीर आएं सैलानी

- राज्य प्रशासन ने एडवाइजरी ली वापस, बिना डर घाटी आने का किया आग्रह
- राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने चार दिन पहले दिए थे निर्देश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पर्यटकों के लिए कश्मीर छोड़ने की एडवाइजरी को राज्य प्रशासन ने गुरुवार को वापस लेते हुए बेखौफ घाटी आने का आग्रह किया है। साथ ही कहा कि देशी-विदेशी पर्यटकों को जो मदद चाहिए वह दी जाएगी। वहीं, पर्यटन जगत से जुड़े लोगों ने कहा कि अगर इंटरनेट व मोबाइल सेवा बहाल करें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा।

राज्यपाल ने चार दिन पहले दिए थे निर्देश : राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने करीब चार दिन पूर्व वादी में पर्यटकों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी वापस लेने का निर्देश दिया था। संबंधित प्रशासन ने कहा था कि 10 अक्टूबर तक एडवाइजरी को वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। गृह विभाग ने नौ अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी। राज्य गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा द्वारा गत शाम जारी की अधिसूचना में कहा कि कश्मीर घूमने के इच्छुक पर्यटक बिना किसी रुकावट आ सकते हैं। अगर उन्हें किसी तरह की सेवा-सुविधा या मदद चाहिए, उन्हें प्रदान की जाएगी।

दो अगस्त को एडवाइजरी जारी की थी : दो अगस्त को ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए सरकार ने आतंकी हमले की आशंका का हवाला दिया था। इसके बाद कश्मीर में आए पर्यटक अपने घरों को लौट गए थे। पांच अगस्त को सभी को समझ आ गया था कि पर्यटकों के लिए एडवाइजरी अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले से पैदा होने वाली किसी स्थिति से सुरक्षित रखने के लिए जारी की गई है।

गुलजार होने में समय नहीं लगेगा : जम्मू-कश्मीर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर एसोसिएशन से जुड़े जावेद पंडित ने कहा कि अगस्त और सितंबर हमारे लिए बुरा रहा है। सितंबर के अंत में कुछ पर्यटक आए। अक्टूबर का पहला सप्ताह में भी थोड़ी बहुत आमद रही है, इसलिए ट्रैवल एडवाइजरी वापस लेने के बाद पर्यटकों की तादाद बढ़ने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन को मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बहाल कर देनी चाहिए। वोल्गा ट्रैवल एजेंसी के संचालक सुहेल अहमद ने कहा कि हमारा ज्यादातर काम टिकट और पैकेज बुकिंग का है। इंटरनेट न होने से टिकट बुक करना मुहाल हो चुका है, पैकेज टूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्राहक हमारे साथ फोन व इंटरनेट पर ही जुड़े होते हैं। दिवाली भी आने वाली है और इन दिनों कश्मीर में गुजरात और बंगाल के पर्यटक आते हैं। डलगेट में एक होटल चलाने वाले फिरदौस अहमद ने कहा कि मेरे होटल में 30 कमरे हैं। पांच लोग भी काम करने वाले हैं। चार अगस्त के बाद से दो अक्टूबर तक मैंने एक भी पर्यटक नहीं देखा था। जम्मू में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके जरिये मैंने बंगाल के चार पर्यटकों को कश्मीर आने के लिए किसी तरह तैयार किया था। वही पांच अक्टूबर को मेरे होटल में आकर रुके थे। वह भी आज ही लौटे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि सर्दियों में यहां पर्यटक खूब रहें।

कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील में फिर से पर्यटक दिखने लगे हैं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को पर्यटकों के लिए कश्मीर छोड़ने की एडवाइजरी वापस ले ली है। जागरण

बंद के ठेकेदारों को ठेंगा गुलजार हो उठा कश्मीर

- बाजार खुले रहे, सड़कों पर सुबह से शाम तक वाहनों की कतारें नजर आईं
- प्रशासन ने पूरी वादी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में बुधवार को भी अलगाववादियों और जिहादियों के जबरन लागू कराए जा रहे बंद को ठेंगा दिखाते हुए श्रीनगर समेत कश्मीर के प्रमुख शहरों और कस्बों में सामान्य जनजीवन बहाल होता नजर आया। सड़कों पर सुबह से शाम तक वाहनों की कतारें नजर आईं। सरकारी कार्यालय खुले। सभी प्रमुख बाजार दिनभर बंद रहे। रेहड़ी-फड़ी और फुटपाथ पर सामान बेचने वालों व उनके पास जुटे खरीदारों की भीड़ ने कहीं भी बंद दुकानों का अहसास नहीं होने दिया। इसी बीच, प्रशासन ने पूरी वादी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रखे हैं।

प्रशासन ने दो अगस्त को पर्यटकों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी को सुधरते हालात के मद्देनजर वापस ले लिया है। अब प्रशासनिक पाबंदियों के नाम पर मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ही बंद हैं। इन्हें जल्द ही हटाने की दिशा में संबंधित प्रशासन जुटा है।

अलगाववादियों व जिहादियों के बंद के फरमान के बावजूद श्रीनगर समेत वादी के सभी प्रमुख शहरों व कस्बों में सुबह-शाम दुकानें खुली नजर आईं। सिर्फ 11 बजे से शाम चार बजे तक ही दुकानें बंद रहीं। रेहड़ी-फड़ी पर सामान बेचने वाले प्रमुख बाजारों और सड़कों पर डटे रहे। उनके पास खरीदारों की भीड़ भी खूब रही। निजी वाहनों के साथ साथ तिपहिया वाहनों के अलावा टैक्सियां दिनभर सड़कों पर दौड़ती नजर आईं। वादी की सड़कों पर कई जगह सुबह ही ट्रैफिक जाम की स्थिति रही जिसे काबू करने के लिए यातायात पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सभी शिक्षण संस्थान खुले। हालात में बेहतरी से हताश आतंकियों व जिहादियों द्वारा गड़बड़ी किए जाने की आशंका के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक, कुछेक इलाकों में कुछ तत्वों ने पथराव का प्रयास किया था। उन्हें जल्द वहां से खदेड़ सामान्य स्थिति बहाल कर ली गई। कुल मिलाकर पूरी वादी में स्थिति दिनभर शांत व सामान्य ही रही है।

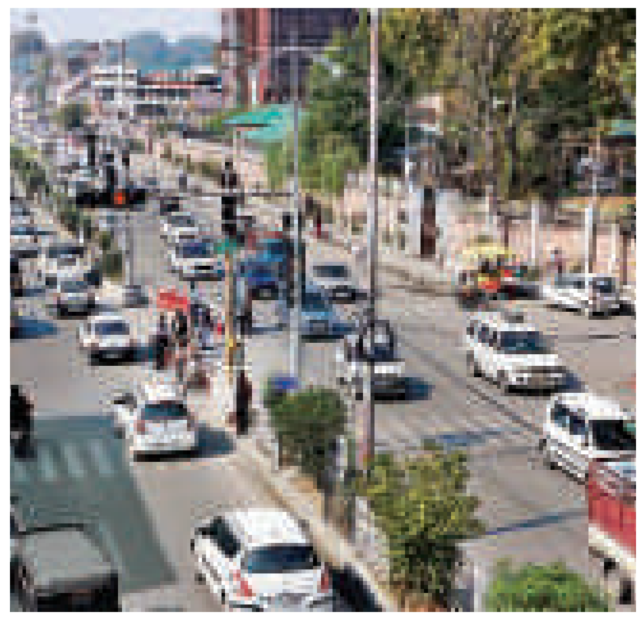

श्रीनगर में गुरुवार को बाजार खुले रहे और सड़कों पर सुबह से शाम तक वाहनों की कतारें नजर आईं। जागरण

खुशवंत सिंह लिटफेस्ट में होगी अनुच्छेद 370, कश्मीर व पाक पर चर्चा

जागरण संवाददाता, सोलन : हिमाचल प्रदेश के कसौली में शुक्रवार से 8वें खुशवंत सिंह लिटफेस्ट का आगाज होगा। तीन दिवसीय आयोजन में हिस्सा लेने के लिए अधिकतर साहित्यकार, लेखक व अन्य हस्तियां कसौली पहुंच चुकी हैं। इनमें आर्ट हिस्ट्रोरियन बीएन गोस्वामी व दूरदर्शन की एंकर मीनू तलवार, तवलीन सिंह, सादिया देहलवी व मिनी वैद आदि प्रमुख हैं। लिटफेस्ट में इस बार कश्मीर, पाकिस्तान व बलूचिस्तान, अनुच्छेद 370 जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कैफी आजमी व जलियांवाला बाग हत्याकांड शताब्दी व कारगिल युद्ध के 20 वर्ष होने पर विशेष चर्चा होगी।

लिटफेस्ट में अभिनेत्री शर्मिला टैगौर, शबाना आजमी, मनीषा कोईराला, जावेद अख्तर, कारगिल हीरो कर्नल सोनम वांगचुक, सर्जिकल स्ट्राइक हीरो लेफ्टिनेंट जनरल रि. डीएस हुड्डा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला, नयनतारा सहगल, नवतेज सरना व विवेक काटजू जैसी 50 के करीब हस्तियां शामिल होंगी। खुशवंत सिंह के बेटे व आयोजक राहुल सिंह ने बताया कि गुलशन ग्रोवर के विदेश में होने के कारण आना संभव नहीं है। वहीं जावेद अख्तर पर भी संशय है।

जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की पांच सैन्य चौकियां तबाह

नापाक हरकत ▶ पुंछ के सात सेक्टरों में गोलाबारी, दो नागरिक घायल

नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ का प्रयास नाकाम, रात तक फायरिंग जारी

जागरण न्यूज नेटवर्क, जम्मू

बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को पुंछ के सात सेक्टरों बालाकोट, बलनोई, देगवार, खड़ी करमाड़ा, शाहपुर किरनी, कसबा और गोंतरियां सेक्टर में भारी गोलाबारी की। इसमें सात घर क्षतिग्रस्त हो गए और महिला समेत दो नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में बालाकोट सेक्टर के उस पार पाक सेना की पांच चौकियां पूरी तरह तबाह हो गईं और उसके तीन सैनिक मारे गए।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह पाकिस्तानी सेना ने बालाकोट, बलनोई व देगवार सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। पाक सेना ने गोलाबारी की आड़ में आतंकियों के दल को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने का प्रयास किया, जिसे सीमा पर सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम बना दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक सेना की पांच चौकियां तबाह हो गईं और कम से कम पाक सेना के तीन सैनिक भी ढेर हो गए। इसके बाद भी पाक सेना ने देर शाम पुंछ के ही खड़ी करमाड़ा, शाहपुर किरनी, कसबा और गोंतरियां सेक्टर में भारी गोलाबारी जारी रखी। इसमें 30 वर्षीय शाहिन अख्तर व 80 वर्षीय नूर मुहम्मद घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल पुंछ में भर्ती कराया गया है। जिला आयुक्त पुंछ राहुल यादव व अन्य अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना और बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने घायलों को रेड क्रास फंड से राहत चेक भी दिए। रात तक पाक सेना रिहायशी क्षेत्रों पर मोर्टार दागती रही।

उधर, कठुआ जिले के हीरानगर में चौबीस घंटे की शांति के बाद पाकिस्तान ने बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे मन्यारी व पानसर गांवों के बीच गोलीबारी की। यह गोलाबारी रात दो बजे तक जारी रही। तहसीलदार सोहनलाल का कहना है कि प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। सभी नंबरदार उनके संपर्क में हैं। पीडब्ल्यूडी को बंकर निर्माण जल्द पूरे करवाने के लिए कहा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के भी प्रबंध किए गए हैं।

गोलाबारी के बीच स्कूलों से घर पहुंचे बच्चे

पाकिस्तानी सेना ने दोपहर को जब पुंछ के विभिन्न सेक्टरों में मोर्टार दागे तो उस समय अधिकतर सीमावर्ती स्कूलों में छुट्टी हुई थी। गोलाबारी के बीच ही अभिभावक स्कूल पहुंच गए। गनीमत यह रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और बच्चे सुरक्षित घर पहुंच गए।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पांच माह का अलग-अलग बनेगा बजट

राज्य ब्यूरो, जम्मू : 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास को गति देने के लिए सरकार अगले पांच महीने का बजट लाने वाली है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक अलग-अलग बजट होगा। यह बजट 14 अक्टूबर तक तैयार कर लिया जाएगा।

वित्त विभाग के आयुक्त डॉ. अरुण कुमार मेहता की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दो केंद्र शासित प्रदेशों का बजट एक नवंबर से पांच महीने के लिए 14 अक्टूबर तक बन जाएगा। जबकि जम्मू-कश्मीर राज्य का पहला बजट एक अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक सात महीने का रहेगा।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से कहा है कि बजट के प्रस्ताव, बजट एस्टीमेशन, एलोकेशन एंड मनेटिरिंग सिस्टम (बीईएएमएस) पोर्टल पर 11 अक्टूबर तक उपलब्ध करवा दिए जाएं। सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि इस मामले को प्राथमिकता पर करें।

तीन नेताओं की रिहाई, सात कतार में

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

ब्लॉक विकास परिषदों (बीडीसी) के गठन के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के साथ राज्य प्रशासन ने दो माह के दौरान एहतियातन हिरासत में लिए राजनीतिक लोगों की रिहाई शुरू कर दी है। कांग्रेस, पीडीपी व नेशनल कांफ्रेंस के तीन वरिष्ठ नेताओं को गुरुवार को सशर्त रिहा कर दिया गया। राज्य प्रशासन अगले एक सप्ताह में सात व नेताओं को रिहा करने जा रही है।

चार दर्जन हो चुके रिहा : अभी तक चार दर्जन नेता रिहा हो चुके हैं। इनमें पूर्व मंत्री व पीपुल्स कांफ्रेंस के महासचिव इमरान रजा अंसारी शामिल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक शोएब लोन, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व विधायक यावर मीर और नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता नूर मुहम्मद को रिहा किया। यावर मीर के पिता दिलावर मीर पूर्व मंत्री हैं। शोएब लोन उत्तरी कश्मीर में संग्रामा से विधायक रह चुके हैं। तीनों डल झील किनारे शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआइसीसी) परिसर में स्थित सेंटूर होटल में रखे थे। सेंटूर को राज्य प्रशासन ने गत अगस्त में पूरक जेल का दर्जा दिया था। सेंटूर में 30 राजनीतिक नेता बंद हैं। शोएब, नूर मुहम्मद और यावर की रिहाई पर प्रशासन ने बीती रात मुहर लगाई थी। सुबह इन्हें रिहा किया। तीनों ने बांड भरकर दिया है। बांड में तीनों ने यकीन दिलाया है कि वे कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े।

राज्य गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान सात और नेताओं को रिहा किया जा सकता है। इनमें पीपुल्स कांफ्रेंस के दो वरिष्ठ नेता जुनैद अजीम मट्टू और शेख इमरान के अलावा नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व विधायक शेख इश्फाक जब्बार शामिल हैं। शेख नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व विधायक सईद अहमद अखून के दामाद हैं। अखून को बीते माह सशर्त रिहा किया है। पीपुल्स कांफ्रेंस के महासचिव इमरान रजा अंसारी के अलावा पीडीपी के श्रीनगर इकाई के प्रधान और एमएलसी खुर्शीद आलम समेत सात नेताओं को बीते माह रिहा किया था। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जुनैद घर में नजरबंद हैं। शेख और इश्फाक सेंटूर में बंद हैं।

महबूबा की बेटी ने पूछा, किस कानून के तहत किया रिहा : कश्मीर के राजनीतिक नेताओं को सशर्त रिहा किए जाने पर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने पूछा कि अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए इन लोगों को किस कानून के तहत सशर्त रिहा किया जा रहा है?

अपनी मां के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर इल्तिजा ने लिखा, खबरें मिली हैं कि आज रिहा किए गए बंदियों से कुछ बांड भरवाए गए हैं। अपनी दिशाहीन नीतियों से सरकार हालात बिगाड़ रही है।

पीडीपी सांसद ने पीएम को लिखा पत्र, कहा-हालात जानने मंत्रियों का दल भेजें

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य नजीर अहमद लावे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कश्मीर के जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह को वादी में भेजने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के लोगों के दिलो-दिमाग जीतने के लिए एक ठोस व व्यावहारिक राजनीतिक नीति बनाने और सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की प्रक्रिया को अविलंब शुरू करने की मांग भी की। लावे अगस्त में चर्चा में आए थे, जब राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने हंगामा करते हुए संविधान को फाड़ा था।

लावे ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने खत की पुष्टि करते हुए कहा कि कश्मीर में बीते दो माह से हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन सरकार हालात ठीक होने का दावा कर रही है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को हिरासत में रखा गया है और उनकी सियासी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार की समाप्ति, लोकतंत्र की मजबूती, लोगों के लिए रोजगार और खुशहाली के बड़े दावे किए थे। यह दावे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए हमने पीएम को उनके वादों की याद दिलाते हुए एक पत्र लिखा है। पत्र में आग्रह किया है कि कश्मीरियों की स्थिति को समझने, आम लोगों से बातचीत कर उनकी भावनाओं को जानने और जमीनी स्तर से फीडबैक प्राप्त करने के लिए मंत्रियों का एक दल भेजा जाए।

मेरठ कैंट क्षेत्र से सेना ने संदिग्ध को दबोचा

जासं, मेरठ : मेरठ कैंट क्षेत्र में डोगरा मंदिर के पास घूम रहे संदिग्ध व्यक्ति को सेना की क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) ने दबोच लिया। घंटों पूछताछ के बाद उसे लालकुर्ती थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को उसने जो नाम-पता बताया, वह गलत निकला। गौरतलब है कि एक पखवाड़ा पूर्व भी सेना ने छावनी क्षेत्र में संदिग्ध युवक को पकड़ा था। बाद में पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था।

गुरुवार सुबह करीब आठ बजे सेना की क्यूआरटी को गश्त के दौरान डोगरा मंदिर के पास नशे की हालत में एक संदिग्ध व्यक्ति घूमता दिखाई दिया। सेना ने उससे घंटों पूछताछ की, लेकिन वह गुमराह करने लगा। इसके बाद लालकुर्ती थाना पुलिस ने पूछताछ की। उसने अपना नाम संजय चौहान निवासी गांव सलारपुर थाना बहादुरगढ़ (हापुड़) बताया। पुलिस ने जब ग्राम प्रधान से बात की तो उन्होंने इस नाम के व्यक्ति का गांव निवासी होने से इन्कार किया। इसके बाद उसने पिता का नाम दयाचंद चौहान बताया। फिर प्रधान से बात की तो उन्होंने इन्कार कर दिया।

बाद में उसने पिता का नाम महेंद्र और माता का नाम द्रोपदी बताया। पुलिस ने जानकारी की तो प्रधान ने बताया कि गांव में महेंद्र नाम के कई लोग हैं, लेकिन उनका संबंध संजय चौहान से नहीं है। गांव में द्रौपदी नाम की भी कोई महिला नहीं है। छावनी में संदिग्ध के पकड़े जाने की सूचना पर खुफिया विभाग के अधिकारी भी थाने पहुंचे। उन्होंने भी पूछताछ की। एएसपी धवन जायसवाल का कहना है कि संदिग्ध को सेना ने पुलिस के हवाले कर दिया है। उससे पूछताछ जारी है।

पिछले दरवाजे से नियुक्ति मामले में महबूबा के ममेरे भाई को कोर्ट से राहत नहीं

- खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में 2016 में हुई थीं चुनिंदा नियुक्तियां
- सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम साहनी ने रखा पक्ष

जागरण संवाददाता, जम्मू

खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में पिछले दरवाजे से हुई चुनिंदा नियुक्तियों के मामले में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया है। नियुक्तियों में पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का ममेरा भाई भी शामिल है।

यह याचिका उम्मीदवारों की ओर से एडवोकेट अभिनव शर्मा ने दायर की, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने बोर्ड में हुई नियुक्तियों को पहले से ही खारिज कर दिया है। लिहाजा, उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की जाए। याचिका शुभम थापा और उनके साथियों ने दायर की है। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम साहनी और उनके सहयोगी वकील भानू जसरोटिया ने जिरह में कहा कि नियुक्तियां अवैध तरीके से हुई हैं। सरकार ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नियुक्तियों में कई आला अधिकारियों और मंत्रियों की संलिप्तता सामने आ रही है। इन नियुक्तियों में महबूबा मुफ्ती का ममेरा भाई अरूत मदनी भी शामिल है।

साहनी ने डीजी सीआइडी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम के पीआरओ ने उम्मीदवारों से पांच-पांच लाख लेकर नियुक्तियां करवाईं। साहनी ने कहा कि नियुक्तियों में उच्च पदस्थ लोगों की साजिश है, जिन्होंने भर्ती नियमों को ताक पर लगा दिया। नियुक्तियों में अगर लेनदेन हुआ तो यह एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि जिस साजिश में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और डिप्टी सीएम के पीआरओ का नाम आ रहा है, तो यह मामला काफी संगीन है। लिहाजा उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत न दी जाए। कोर्ट में आइएएस अधिकारी आरके गोयल की जांच रिपोर्ट को भी पेश किया गया। राज्य सरकार में प्रधान सचिव आरके गोयल खादी इंडस्ट्री बोर्ड में हुई धांधलियों की जांच कर रहे हैं।

हाई कोर्ट के जस्टिस ताशी रबस्तान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उन्हें किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बोर्ड में आठ अक्टूबर, 2016 को विभिन्न पदों के लिए चुनिंदा नियुक्तियां हुई थीं। नियुक्तियों में हुए घोटाले के बाद सरकार ने इन्हें रद कर दिया था।

संभल से पाक और अरब जाने वालों पर खुफिया एजेंसियों की नजर

राघवेंद्र शुक्ल, संभल : अफगानिस्तान में मारे गए अलकायदा प्रमुख आसिम उमर को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। अभी भी एजेंसियां उप्र के संभल में सक्रिय हैं। जांच एजेंसियों की पाकिस्तान और अरब जाने वाले कुछ अन्य युवकों पर भी निगाह है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियां ऐसे लोगों के नाम भी तलाश कर रहीं हैं, जो संभल से बाहर गए हैं और 10-15 साल बाद भी नहीं लौटे हैं। पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

अफगानिस्तान में अमेरिकी व अफगानी सेना के संयुक्त ऑपरेशन में मारे गए संभल के रहने वाले कुख्यात आतंकी सनाउल हक उर्फ आसिम उमर को लेकर खुफिया एजेंसियों ने दूसरे दिन भी यहां डेरा डाल रखा था। ऐसे लोगों की जानकारी एकत्रित की जाती रही जो लंबे अर्से से संभल नहीं लौटे हैं। इसके अलावा अरब और पाकिस्तान जाने वालों का रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है। उनकी गतिविधियों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। दोनों ही बिंदुओं पर खुफिया एजेंसियां पुलिस के सहयोग से काम कर रही हैं।

चार साल पहले आसिफ के पकड़े जाने पर चर्चा में आया था संभल: चार साल पहले संभल से एक संदिग्ध आसिफ को दिल्ली की पुलिस टीम ने पकड़ा था। उसका नाम उस समय प्रकाश में आया था, जब आतंकी संगठन आइएस की गतिविधियों के भारत में तेज होने की आशंका पर लगातार कार्रवाई चल रही थी। तब पूरे देश में संभल का नाम आतंकी गतिविधियों को लेकर चर्चा में आया था। अब खुफिया विभाग ने मंडल के अन्य जनपदों में भी अपने तंत्र को और सक्रिय कर दिया है।

बताई हकीकत

छह दिन तक घाटी का दौरा कर लौटे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पांच सदस्यीय टीम ने बयां की वहां की जमीनी सच्चाई

कश्मीर में तेजी से सामान्य हो रहे हालात

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी में हालात असामान्य होने का दावा कर रहे कुछ राजनीतिक दलों और मानवाधिकार संगठनों से इतर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने घाटी में हालात तेजी से सामान्य होने की बात कही है। एमआरएम का एक पांच सदस्यीय दल छह दिन तक श्रीनगर से लेकर अनंतनाग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, बारामुला, कुपवाड़ा व गांदरबल समेत घाटी के कई इलाकों में गया और वहां लोगों से मुलाकात कर हालात समझने की कोशिश की। टीम डल लेक से लेकर डाउन टाउन पीरबाग व लाल चौक जैसे श्रीनगर के अंदरुनी इलाकों में भी गई। यह टीम एमआरएम के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार के निर्देश पर 28 सितंबर को घाटी पहुंची थी और 4 अक्टूबर को वापस आई है। टीम कश्मीर पर एक रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को सौंपेगी।

टीम का नेतृत्व कर रहे एमआरएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता यासिर जिलानी ने बताया कि वहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। कमोबेश सभी दुकानें खुल रही हैं। लोग बिना डर-भय के खरीदारी कर रहे हैं। सड़कों पर वाहन निकल रहे हैं। हालात यह कि प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बन जा रही है। शादी से लेकर अन्य समारोहों के आयोजन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इतना ही नहीं वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों से स्थानीय निवासियों के संबंध दोस्ताना ही है। टीम कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों से मिला तो गांदरबल में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मिला। श्रीनगर के न्यू सर सैयद कॉलोनी में तो दिल्ली से आने की जानकारी मिलने पर वहां के लोगों ने गर्मजोशी से कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें खाने-पीने की भी व्यवस्था की गई थी।

जिलानी ने बताया कि बातचीत में युवाओं में बदलाव की बयार दिखी। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह पर विश्वास दिखा। वे चाहते हैं कि वह पढ़ाई और नौकरी के लिए दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाने की जगह उन्हें यह इंतजाम अपने राज्य में ही मिले। वे स्थानीय नेताओं और वर्षों से जमे नौकरशाही से त्रस्त हैं। उनकी इच्छा है कि केंद्र उनसे सीधे संवाद बनाए।

हालांकि, वे मोबाइल सेवा बंद होने से परेशान हैं और जल्द इंटरनेट व सभी मोबाइल फोन पर बातचीत की सुविधा चाहते हैं। खुद वहां के लोगों ने बताया कि अब भी घाटी में केबल नेटवर्क से कुछ पाकिस्तानी चैनलों का प्रसारण हो रहा है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो सुनियोजित तरीके से अफवाहों को हवा देने में जुटे हैं। गांदरबल में स्थानीय लोगों से मुलाकात के बीच कुछ ऐसे ही लोग मिले। चंद लोग हैं जो आजादी की बात कह रहे हैं पर रोडमैप के सवाल पर उनके पास भी कोई जवाब नहीं है।

कश्मीर में यात्रा के दौरान कश्मीरी लोगों से सद्भावना के माहौल में मिलते मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी। सौ.: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच

...तो उप्र में बनेंगे लड़ाकू विमान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

दुनिया की जानी-मानी रक्षा उत्पाद कंपनियों को उप्र में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर संभावनाओं का 'कॉरिडोर' बनाया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा फरवरी में लखनऊ में आयोजित किए जा रहे डिफेंस एक्सपो में राफेल बनाने वाली फ्रांस की दासौ सहित तमाम कंपनियां आने को तैयार हैं। डिफेंस कॉरिडोर के प्रति जिस तरह की जिज्ञासा उन्होंने दिखाई है, उससे इन उम्मीदों को बल मिला है कि आने वाले समय में राफेल जैसे लड़ाकू विमानों का निर्माण यहां भी हो।

प्रदेश में रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इसमें 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। इसके साथ ही यहां कंपनियों की स्थापना कराने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। ऐसे में रक्षा मंत्रालय द्वारा अगले वर्ष पांच से सात फरवरी तक आयोजित किया जा रहा डिफेंस एक्सपो बड़ा माध्यम बनने जा रहा है।

पिछले दिनों लंदन में आयोजित डिफेंस एक्सपो में गए सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने लगभग दो दर्जन रक्षा उत्पादन कंपनियों के साथ वार्ता कर उन्हें डिफेंस कॉरिडोर और यहां की संभावनाओं के बारे में बताया था। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें राफेल बनाने वाली फ्रांस की दासौ, जनरल डायनेमिक्स, एयरबस सहित कई कंपनियों ने तमाम जानकारियां ली हैं। उन्हें बताया गया है कि झांसी के पास बबीना में भूमि है, जो आयुध परीक्षण के लिए आरक्षित की जा सकती है। इसके साथ ही सरकार ने तैयारी कर ली है कि इन कंपनियों के प्रतिनिधि डिफेंस एक्सपो में आते हैं तो उन्हें डिफेंस कॉरिडोर के लिए चिह्नित जिलों में ले जाकर स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा।

> 'कंपनियों को निमंत्रण तो भारत सरकार भेजेगी लेकिन, कंपनी के प्रतिनिधि लखनऊ आएंगे तो उन्हें डिफेंस कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा। हमारे पास जमीन उपलब्ध है, बेहतर संभावनाएं हैं। पूरी उम्मीद है कि निवेशक आकर्षित होंगे और डिफेंस कॉरिडोर में इकाइयां लगाएंगे।'
>
> **-अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उप्र औद्योगिक एक्सप्रेस वे प्राधिकरण**

2.80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस साल हेमकुंड साहिब के दर्शनों के लिए पहुंचे। वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद यह पहला मौका है जब इतनी अधिक रही। यह तादाद पिछले वर्ष से 51 हजार अधिक है।

मप्र में आदिवासी किसानों के नाम पर 100 करोड़ की योजना में गड़बड़ी

घोटाला ▶ विधानसभा में कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने उठाया था मुद्दा

सात विधायकों की समिति करेगी मामले की जांच

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में आदिवासी किसानों को जैविक खेती के लिए खाद सहित अन्य सामग्री देने नाम पर सौ करोड़ रुपये की योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसमें अधिकांश किसानों को सामग्री नहीं मिली। खाद में राख, मिट्टी और तरल पदार्थ के नाम पर पानी दिया गया। कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने विधानसभा में इसे आदिवासियों के नाम पर बड़ा घोटाला करार देते हुए जांच की बात उठाई थी। आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने विधायकों के आरोपों का साथ देते हुए पूरी योजना को कागजी करार दिया था। अब कृषि विभाग ने सात विधायक और कृषि व आदिम जाति कल्याण के अधिकारियों की कमेटी बनाकर जांच कराने का फैसला किया है।

सूत्रों के मुताबिक, आदिम जाति कल्याण विभाग ने 20 जिलों के आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया व भारिया किसानों को कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा के उत्पादन में सहयोग और प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व मार्केटिंग के लिए सौ करोड़ रुपए कृषि विभाग को वर्ष 2017-18 में दिए थे। विभाग का मकसद था कि जैविक खेती करने वाले आदिवासी किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

कृषि विभाग ने इस राशि का इस्तेमाल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, हरी खाद के प्रयोग के लिए सहायता, तरल जैव उर्वरक सहायता, जैव पेस्टीसाइड, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर प्रयोग के लिए सहायता एवं प्रोसेसिंग, पैकिंग मटेरियल विथ पीजीएस लोगो में करने को मिलाकर कार्ययोजना बनाई थी। तीन जुलाई 2017 को आदिम जाति कल्याण विभाग ने बायोपेस्टीसाइड को छोड़कर वर्मीकंपोस्टिंग को शामिल करते हुए योजना को मंजूरी दे दी। परियोजना संचालक (आत्मा) ने प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और हर जिले के ब्रांडनेम उत्पाद के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और न ही राशि खर्च की। सितंबर 2018 में जैविक कृषि आदान सहायता अनुदान कार्यक्रम के लिए मिले सौ करोड़ रुपए से 14 जिले के लिए लक्ष्य तय किए गए, लेकिन जमीन पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। विधानसभा में फुंदेलाल सिंह मार्को ने ध्यानाकर्षण के जरिए इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि राशि की बंदरबांट की गई। कागजों में लीपापोती कर आदिवासियों के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। अन्य विधायकों ने भी आरोपों का समर्थन करते हुए जांच की बात उठाई।

खाद में राख व मिट्टी की मात्रा अधिक होने का आरोप

सूत्रों का कहना है कि कृषि मंत्री सचिन यादव जब सदन में जवाब देने की तैयारी कर रहे थे, तब आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर बैठक में आए थे और उन्होंने इसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला करार देते हुए जांच कराने की बात कही थी। कृषि विभाग से ज्यादा तैयारी आदिम जाति कल्याण विभाग की थी, क्योंकि राशि उन्होंने ही दी थी। सूत्रों का कहना है कि एमपी एग्रो को खाद सहित अन्य सामग्री की आपूर्ति का जिम्मा सौंपा गया था। एग्रो ने निजी कंपनियों को ठेका दिया। आरोप है कि जो सामग्री वितरित की गई वो बेहद घटिया थी। खाद में राख व मिट्टी की मात्रा अधिक होने और तरल पदार्थ में खाद की जगह पानी पाया गया, जो बेअसर रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कमेटी बनाकर जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसके मद्देनजर कृषि विभाग ने विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, नीलांशु चतुर्वेदी, संजय उइके, योगेंद्र सिंह, प्रताप ग्रेवाल, सुनील सर्राफ और विजय राघवेंद्र सिंह के अलावा आयुक्त अनुसूचित जनजाति कल्याण व संचालक कृषि की समिति बना दी है। समिति पूरे मामले में अनियमितता की जांच करके रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी।

हाथियों को भगाने के लिए पटाखों के उपयोग की अनुमति किसने दी

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▶ 11 हाथी कॉरिडोर में अतिक्रमण पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक व कार्बेट नेशनल पार्क के निदेशक से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

उत्तराखंड हाई कोर्ट। फाइल फोटो

उत्तराखंड के 11 हाथी कॉरिडोर घोषित वन क्षेत्रों में अतिक्रमण का हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक व निदेशक कार्बेट नेशनल पार्क व डीएफओ रामनगर को 15 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सख्त नाराजगी जताते हुए पूछा है कि हाथियों को हाईवे पर रोकने के लिए मिर्ची खिलाने, फायरिंग व पटाखे फोड़ने जैसे पशु क्रूरता भरे कृत्य करने की अनुमति किसने दी है।

गुरुवार को हाई कोर्ट में दिल्ली की संस्था इंडिपेंडेंट मेडिकल इनिसिएटिव सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि राज्य के 11 हाथी कॉरिडोर मार्ग में अतिक्रमण कर व्यावसायिक भवनों का निर्माण किया गया है। रामनगर में 27 किलोमीटर हाईवे में तीन हाथी कॉरिडोर हैं। ढिकुली क्षेत्र का कॉरिडोर डेढ़ सौ से अधिक व्यावसायिक निर्माण की वजह से बंद हो चुका है। मोहान क्षेत्र में निर्माण होने व रात्रि में वाहनों की आवाजाही से हाथियों को कोसी तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो गई है। मलानी कोटा, चिल्किया कोटा व दक्षिणी पतली दून भी करीब-करीब बंद हो चुका है। कुछ बड़े व्यावसायिक भवनों में शादियों और पार्टी में होने वाले शोरगुल से वन्य जीवों को परेशानी हो रही है। वन महकमे द्वारा जंगलों में मानव दखलंदाजी पर अंकुश के बजाय हाथियों को हाईवे पर आने से रोकने के लिए मिर्च पाउडर व पटाखों का उपयोग किया जा रहा है। इससे हाथियों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है और वे हिंसक हो रहे हैं। पिछले एक साल में ही हाथियों के हमले के 20 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। याचिका में केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट को दरकिनार कर इन कॉरिडोर में पर्यटन गतिविधियों पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार की संस्तुतियां लागू करने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार एक हाथी रोजाना 225 लीटर पानी पीता है, जिसके लिए वह कोसी में उतरते हैं मगर वन महकमे द्वारा उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है।

न्यूज गैलरी

कोविंद ने सेना विमानन कोर को दिया प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड

नासिक, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को आयोजित एक समारोह में सेना विमानन कोर (एएसी) को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया। वह सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। नासिक रोड स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित भव्य परेड के दौरान इस सम्मान को प्रदान करने के बाद राष्ट्रपति कोविंद ने कोर के सदस्यों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, 'भारतीय सेना और राष्ट्र को आप पर गर्व है। 32 वर्ष के हो चुके इस कोर ने कई अभियानों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।' एएसी की स्थापना एक नवंबर 1986 को हुई थी। इसे दो महावीर चक्र, 16 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र व 115 सेना पदक मिल चुके हैं। कोविंद 9-13 अक्टूबर तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की यात्रा पर हैं। शुक्रवार को वह मैसूरु में जेएसएस उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी के परिसर का शिलान्यास करेंगे। (प्रेट्र)

भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां को राहत

रामपुर : भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फंसे सपा सांसद आजम खां को सेशन कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। लोकसभा चुनाव में आजम सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व नेता फैसल लाला ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि 29 मार्च को सपा कार्यालय पर आजम ने जनसभा की थी, जिसमें लोगों को जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट के खिलाफ भड़काया था। कहा था कि ये अधिकारी शहर का माहौल खराब करने के लिए भेजे गए हैं। रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद ने जिला जज के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका पर आपत्ति जताई, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता नासिर सुल्तान का कहना था कि मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। यदि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था तो फिर इसे सरकार की ओर से दर्ज किया जाना चाहिए था। मुकदमा दो वर्गों के बीच तनाव फैलाने की धारा में किया है, जबकि बयान में ऐसी कोई बात नहीं है। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने इस मामले में सांसद की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। (जासं)

आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक 16 से

रांची : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक 16 से 18 अक्टूबर तक भुवनेश्वर में होगी। 13 अक्टूबर से कोर टीम की बैठक शुरू हो जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए 12 अक्टूबर को सरसंघचालक मोहन भागवत भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। तीन दिनों की बैठक में नई शिक्षा नीति, मॉब लिंचिंग सहित कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए जा सकते हैं। इस बैठक को दिवाली बैठक के नाम से भी जाना जाता है। (जासं)

चिन्मयानंद प्रकरण : विक्रम व सचिन की जमानत अर्जी खारिज

शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपित विक्रम सिंह और सचिन सेंगर की जमानत अर्जी को जिला जज रामबाबू शर्मा ने खारिज कर दिया। वहीं, तीसरे आरोपित संजय सिंह की जमानत अर्जी पर पांच दिन बाद सुनवाई होगी। चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपित विक्रम सिंह व सचिन सेंगर के वकील प्रमोद तिवारी ने तीन अक्टूबर को दोनों की जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिस पर गुरुवार दोपहर बहस शुरू हुई। करीब एक घंटा दस मिनट तक आरोपितों के अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सिंह के बीच तर्क-वितर्क हुए। वकील प्रमोद तिवारी ने कई तर्क देते हुए जमानत के लिए पर्याप्त आधार बताए, लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि जांच जारी है। आरोपितों के कुछ अन्य साथियों के भी नाम सामने आ सकते हैं। अगर जमानत दे दी जाती है तो साक्ष्य नष्ट होने व विवेचना प्रभावित होने की आशंका है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज रामबाबू शर्मा ने आरोप गंभीर पाते हुए दोनों आरोपितों को जमानत देने से इन्कार कर दिया। (जासं)

मुसलमान अपनी मर्जी से दें राम मंदिर के लिए जमीन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ कोर्ट से बाहर अयोध्या मसले का हल चाहते हैं मुस्लिम बुद्धिजीवी

▶ इंडियन मुस्लिम फॉर पीस संस्था के बैनर तले जुटे मुस्लिम बुद्धिजीवी

मुस्लिम बुद्धिजीवी अयोध्या मसले का हल कोर्ट से बाहर चाहते हैं। इससे दोनों पक्षों की जीत होगी। बुद्धिजीवियों ने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत भी जाता है तो उन्हें यह जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए।

मुस्लिम बुद्धिजीवी गुरुवार को इंडियन मुस्लिम फॉर पीस संस्था के बैनर तले लखनऊ में एकत्र हुए। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अफसर, शिक्षाविद्, रिटायर्ड जज शामिल थे। बुद्धिजीवियों ने संकल्प पत्र पास कर उसे सुन्नी वक्फ बोर्ड व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भेजने का निर्णय लिया है।

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल व एएमयू के पूर्व कुलपति जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि लड़ाई से केवल नुकसान होता है, फायदा नहीं। अयोध्या मसले का हल कोर्ट से बाहर होना चाहिए। वर्तमान में जो हालात हैं, उसमें मुसलमान वहां मस्जिद नहीं बना पाएंगे। इसलिए यह जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए।

सीआरपीएफ के पूर्व एडीजी निसार अहमद कहते हैं कि यह पूरा मामला राजनीतिक व धार्मिक नेताओं का है। मजहब के नाम पर हमें लड़ाया जा रहा है। दंगों में आम लोग मरते हैं, बड़े लोग सुरक्षित रहते हैं। कोर्ट का जो भी फैसला आए, उसका असर अपने जीवन पर न होने दें। रिटायर्ड आइएएस अफसर अनीस अंसारी ने कहा कि ये जमीन मुस्लिम समाज के पास है जिसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए सरकार को वापस कर देना चाहिए। इसकी जगह कहीं और मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी जाए।

कार्यक्रम के सह संयोजक रिटायर्ड जज बीडी नकवी ने कहा की हम सुन्नी वक्फ बोर्ड के संपर्क में हैं। अब वहां मस्जिद नहीं है, इसलिए जमीन की अदलाबदली हो सकती है। बैठक में हृदय रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉ. मंसूर हसन, पूर्व मंत्री मोइद अहमद, रिटायर्ड आइपीएस वीएन राय, लव भार्गव सहित कई ने विचार रखे।

ये प्रस्ताव भी हुए पास

- अयोध्या में अन्य मस्जिद, दरगाह व इमामबाड़े हैं, उनके रख-रखाव की अनुमति दी जाए
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देख रेख में जितनी मस्जिदें हैं, जहां संभव हो वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए
- प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सजा तीन माह है, इसे बढ़ाकर तीन साल किया जाए

दरगाह आला हजरत ने कहा अयोध्या पर मंजूर होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बरेली : सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या प्रकरण की सुनवाई जारी है। दूसरी तरफ कोर्ट से इतर सुलह की कोशिशें भी हुईं। सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े मरकज (केंद्र) दरगाह आला हजरत ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रजा खां कादरी ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वह हमें मंजूर होगा। गुरुवार को उन्होंने 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे 101वें सालाना उर्स-ए-रजवी के संबंध में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कहीं। मार्च 2018 में आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर अयोध्या में सुलह का प्रस्ताव लेकर बरेली पहुंचे थे। उस दौरान दरगाह आला हजरत की प्रमुख शख्सियतें-दरगाह प्रमुख मौलाना सुब्हानी मियां, सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां, शहर काजी मुफ्ती असजद मियां समेत अन्य लोगों ने श्रीश्री से दूरी बना ली थी। यहां तक कि उन्हें मदरसा जामियातुर्रजा में प्रवेश भी नहीं दिया गया था।

प्रस्तावित मंदिर में स्थापित होंगे स्वर्ण जड़ित रामलला

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद भले ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद (विहिप) अपने स्तर से निर्माण की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। इस बीच रामलला की उस प्रतिमा को निर्मित कराने की तैयारी होने लगी है, जिसे रामजन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर में स्थापित किया जाना है। इस बाबत पिछले दिनों दिल्ली में जयपुर के 10 नामचीन मूर्तिकारों को बुलाकर रामलला की प्रतिमा के स्वरूप को अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह प्रतिमा संगमरमर की होगी और उस पर रामलला की गरिमा के अनुरूप सोने की परत चढ़ी रहेगी।

इतना ही नहीं, इसी प्रतिमा की अनुकृति के रूप में रामलला की पांच हजार और प्रतिमाएं तैयार कराई जा रही हैं। हालांकि ये संगमरमर के बजाए लाल बलुआ पत्थर की होंगी। मुख्य प्रतिमा की तरह ये स्वर्ण जड़ित भी नहीं होंगी। इन प्रतिमाओं को 2100 रुपये के शुल्क पर इच्छुक रामभक्त प्राप्त कर सकेंगे। इन तैयारियों के संदर्भ में विहिप नेतृत्व भले ही पूरी गोपनीयता बरत रहा हो, लेकिन वर्षों से चल रही उसकी तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। रामघाट स्थित मंदिर निर्माण न्यास कार्यशाला में हलचल साफ देखी जा सकती है। प्रस्तावित मंदिर में एक लाख 75 हजार घन फीट तराशे गए पत्थर का प्रयोग होना है। इनमें से एक लाख घन फीट से अधिक पत्थर की तराशी पूरी भी हो गई है। तराशे गए पत्थर प्रथम तल के हैं।

देशद्रोह का केस दर्ज कराने के लिए हाजी महबूब के विरुद्ध परमहंसदास पहुंचे कोर्ट

जासं, अयोध्या : बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाजी महबूब के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए तपस्वीजी की छावनी के महंत परमहंसदास ने गुरुवार को सीजेएम द्वितीय की अदालत में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। परमहंसदास ने तीन अक्टूबर को ही पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के अनुरूप कार्रवाई में विलंब होने पर उन्होंने रविवार से अनशन भी शुरू किया। मंगलवार को सीओ अमर सिंह ने त हरीर की प्राप्ति देकर उनका अनशन तो समाप्त कराया, मगर वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए।

गंगा आमंत्रण यात्रा देवप्रयाग से गंगासागर के लिए रवाना

जागरण संवाददाता, नई टिहरी: नमामि गंगे के तहत आयोजित गंगा आमंत्रण यात्रा (नौका अभियान) को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को रामकुंड देवप्रयाग से गंगा सागर (बंगाल) के लिए रवाना किया। अभियान का नेतृत्व विंग कमांडर परमवीर कर रहे हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के 32 जवान भाग ले रहे हैं। 2155 किमी के इस अभियान को 34 दिन में पूरा किया जाएगा।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी देवप्रयाग से ऋषिकेश तक नौका अभियान में शामिल हुए। यात्रा की शुभारंभ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा कि निर्मल गंगा अभियान को जनांदोलन का रूप दिए जाने की जरूरत है। गंगा में औद्योगिक व शहरी प्रदूषण रोकने के लिए युद्ध लड़ना होगा, तभी हम गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा को निर्मल बना सकेंगे। कहा कि जिन नदियों के तटों पर हमारी सभ्यताएं विकसित हुईं, वही नदियां आज प्रदूषित हैं।

नमामि गंगे अभियान के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड में स्वच्छ गंगा अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने गंगा आमंत्रण यात्रा में तीनों सेनाओं के संयुक्त रूप से भाग लेने पर खुशी जताई।

बिहार में डेंगू बेकाबू, अब तक 1276 मरीज मिले

जागरण टीम, पटना

बिहार में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक इनकी संख्या 1276 तक पहुंच गई है। अकेले पटना में डेंगू के 903 रोगी पाए गए हैं। गुरुवार को पटना में 60 नए मरीजों की पहचान हुई। इधर स्वास्थ्य विभाग ने पटना में डेंगू के प्रकोप को कम करने के लिए एक साथ कई कदम उठाए हैं। एक ओर जहां जलजमाव वाले वैसे क्षेत्र जहां से जल निकासी हो चुकी है, वहां ब्लीचिंग और चूने के मिश्रण का पैकेट घर-घर बांटने का काम शुरू किया।

मलेरिया विभाग की टीम ने पटना के विभिन्न इलाकों में सिंथेटिक पाराथ्रॉयड का घरों के अंदर छिड़काव प्रारंभ कर दिया है। इधर स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य कैंप लगाकर डेंगू और चिकनगुनिया की जांच और इलाज की सुविधा बहाल कर दी गई। यह कैंप शनिवार तक चलेंगे।

> राज्य के ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं है। लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए। इस बार डेंगू में एक विशेष बात सामने आई है कि मच्छरों के काटने से प्लेटलेट्स स्तर 50-60 हजार से नीचे नहीं जा रहा। सरकार मामले को देख रही है।
>
> **-दीपक कुमार, मुख्य सचिव, बिहार**

जमशेदपुर में भी 94 लोग डेंगू की चपेट में

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : जमशेदपुर में एक दिन में 94 मरीजों को डेंगू होने की पुष्टि हुई। गुरुवार को रिपोर्ट आते ही सिविल सर्जन डॉ. महेश्वर प्रसाद ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में इस स्थिति से निपटने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा हुई। तय हुआ कि इस मामले में लोगों को जागरूक किया जाएगा। नए मरीजों को जोड़कर पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है।

करवा चौथ स्पेशल ट्रेन रद, सिर्फ दो दंपतियों ने खरीदे थे टिकट

नई दिल्ली, प्रेट्र : करवा चौथ पर विशेष ट्रेन चलाने की योजना परवान नहीं चढ़ सकी। सिर्फ दो दंपतियों द्वारा रुचि दिखाए जाने के कारण रेलवे को इस विशेष ट्रेन को रद करना पड़ा।

अधिकारियों ने बताया कि विशेष ट्रेन 'द मैजेस्टिक राजस्थान डीलक्स' में विवाहित जोड़ों के लिए पांच दिनों का यात्रा पैकेज 'ड्रीम हॉलिडे' की योजना की गई थी। इसके तहत उन्हें राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाना था। उन्होंने बताया कि करवा चौथ स्पेशल में इसके लिए 78 सीटें आरक्षित की गई थीं, लेकिन सिर्फ दो दंपतियों ने ही टिकट खरीदे। सिर्फ विवाहित जोड़ों को ही इसमें यात्रा की इजाजत थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'सिर्फ दो दंपति ने इसकी बुकिंग की थी, इसलिए अच्छा है कि इसे रद किया जाए। हम बिना यात्री के ट्रेन नहीं चला सकते।' अधिकारियों ने बताया कि इसके पीछे अधिक किराया वजह हो सकती है। प्रति दंपती इसका किराया एसी वन में 1,02,960 रुपये और एसी टू टीयर में 90,090 रुपये था। उन्होंने बताया कि दोनों दंपतियों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे।

भाईचार का उत्सव 'अलाई-बलाई'

हैदराबाद में गुरुवार को तेलंगाना के लोकप्रिय सांस्कृतिक 'अलाई-बलाई' उत्सव पर पांरपरिक पोशाक में अपनी कला की प्रस्तुति देते कलाकार। यह सांस्कृतिक उत्सव राज्य के लोगों की जीवन शैली को दर्शाता है। उत्सव का मकसद आपसी सौहार्द व भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। एएनआइ

उपलब्धि

छोटे शहरों और कस्बों की लड़कियों में भी है बड़े मुकाम छूने का जज्बा, प्रतिस्पर्धा में महानगरीय पृष्ठभूमि की लड़कियों को पीछे छोड़ा

गोरखपुर की आयशा बनीं एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त

संजय मिश्र, नई दिल्ली

▶ ब्रिटिश उच्चायुक्त भी आयशा की प्रतिभा और हौसले से हुए चकित

▶ अधिकारियों से उनके कामकाज को लेकर पूछे सवाल

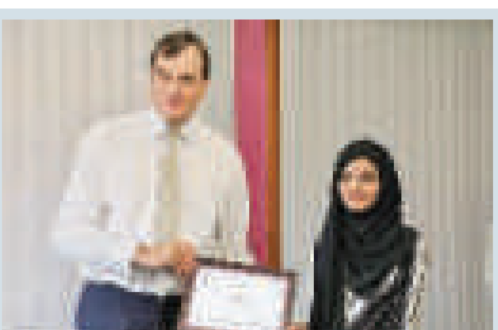

भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एसक्वीथ के साथ गोरखपुर की आयशा खान। जागरण

जब एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनीं गोरखपुर की आयशा खान ने उच्चायोग के आला अधिकारियों से उनके कामकाज को लेकर सवाल दागने शुरू किए तो भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एसक्वीथ भी हैरत में पड़ गए। दुनिया और जिंदगी के सरकारों को लेकर शायद उसकी जागरूकता और संजीदगी ही यह वजह रही कि आयशा ने महानगरीय पृष्ठभूमि की लड़कियों को मात देते हुए एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने की प्रतिस्पर्धा में बाजी मारी।

आयशा ने ब्रिटिश उच्चायुक्त के सरकारी आवास पर दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि यह कामयाबी वास्तविक सपने के सच होने जैसा है। गोरखपुर शहर के शिवपुर शहबाजगंज की रहने वाली आयशा ने कहा कि केवल महानगरों की ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों की लड़कियों में भी बड़े मुकाम छूने का जज्बा और क्षमता है। इन लड़कियों को तलाश है तो बस मौके की जो उन्हें अभी कम मिल पाते हैं।

आयशा इस लिहाज से खुद को काफी खुशकिस्मत मानती हैं कि गोरखपुर जैसे शहर की पृष्ठभूमि में भी उनके माता-पिता ने पढ़ाई लिखाई की पूरी सुविधा और आजादी दी। खासकर उनके दादा ने बेहद प्रोत्साहित किया और इसीलिए परिवार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कालेज में पढ़ने के लिए भेजने में आनाकानी नहीं की। आयशा कहती हैं कि उन्हें तो भरोसा ही नहीं था कि इतने बड़े स्तर की प्रतिस्पर्धा में उनके लिए कोई जगह भी होगी। मगर इसके नतीजों के बाद वह छोटे शहरों और गांव-कस्बों की लड़कियों से यही कहेंगी कि अपने लक्ष्य की ओर वह हौसले के साथ बढ़ेंगी तो कामयाबी की मंजिल आएगी ही।

ब्रिटिश उच्चायुक्त सर डोमिनिक ने आयशा की प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त की यह पहल काफी प्रतिस्पर्धी हो गई है। पिछले साल से तीन गुने से अधिक प्रतिभागियों के बीच सघन और कठिन चयन प्रक्रिया को पार कर आयशा ने कामयाबी हासिल की। जो यह दर्शाता है कि भारत के छोटे शहरों व कस्बों की लड़कियों में भी प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। एक दिन की उच्चायुक्त के तौर पर आयशा ने दूतावास के सारे वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से दिन का आगाज किया और उनके साथ काम करना बेहद अच्छा व दिलचस्प अनुभव रहा। कई ज्वलंत मुद्दा जैसे शिक्षा, लैंगिक समानता पर आयशा ने बेहद प्रभावी बातें की और उसकी शैली ने भी सबका मन मोहा।

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित की जाती है प्रतिस्पर्धा

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर ब्रिटिश उच्चायोग 18 से 23 साल की लड़कियों के लिए एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने की प्रतिस्पर्धा आयोजित करता है। इसकी विजेता को बकायदा उच्चायोग में पूरे दिन हाई कमिश्नर की कुर्सी पर बिठाने से लेकर काम को अंजाम देने का मौका दिया जाता है। आयशा को भी चार अक्टूबर को एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनने का मौका मिला तो उन्होंने उच्चायोग के अंदर बैठकें करने के बाद कुछ बाहरी समारोहों में भी भाग लिया। पत्रकारिता में मास्टर डिग्री कर रहीं आयशा अध्यापन या कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहती हैं।

हर्षवर्धन ने राज्यों से कहा, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाएं

▶ स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सुधार को सामाजिक आंदोलन बनाने पर दिया बल

▶ ताकि 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी के 2.5 फीसद खर्च के लक्ष्य को पा सकें

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने गुरुवार को सभी राज्यों से अपने बजट में स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ाकर इसे कम से कम आठ फीसद तक ले जाने की अपील की। ताकि 2025 तक स्वास्थ्य पर खर्च की को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक ले जाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 13वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए सभी राज्यों ने मिलकर काम करके देश को पोलियो मुक्त बनाने सहित कई मील के पत्थर कायम किए हैं। उन्होंने कहा, 'अगर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री किसी लक्ष्य के लिए एकजुट हो जाएं तो उसे पाना नामुमकिन नहीं है।'

उन्होंने राज्यों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट राशि के इस्तेमाल को बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट राशि के व्यय को 2025 तक जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य तय किया गया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी राज्यों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे और इसके तहत बजट में स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली राशि में आठ प्रतिशत का इजाफा करने की जरूरत होगी।

बैठक में 13 राज्यों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सुधार को सामाजिक आंदोलन बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को नागरिकों की सेहत में सुधार के लिए खानपान की आदतों में बदलाव का संदेश देने वाले अभियान 'ईट राइट एंड फिट इंडिया' में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 11 अक्टूबर 2019

दैनिक जागरण

जब कहने के लिए कुछ विशेष न हो तो बेहतर है कि चुप रहें

जीएसटी संग्रह में कमी

केंद्र सरकार के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संग्रह में लगातार कमी का संज्ञान लेना आवश्यक हो गया था। वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकती थी कि सितंबर में जीएसटी संग्रह घटकर 91,916 करोड़ रुपये रह गया, जो अगस्त की तुलना में 6,286 करोड़ रुपये कम है। यह लगातार दूसरा महीना है जबकि जीएसटी संग्रह घटा है। इस सिलसिले को देखते हुए ही सरकार ने एक ऐसी समिति गठित करने का फैसला किया जो जीएसटी संग्रह में कमी के कारणों पर विचार करने के साथ ही टैक्स प्रशासन में सुधार के उपाय भी सुझाएगी। इस समिति को जिस तरह 15 दिनों के भीतर अपनी पहली रिपोर्ट सौंपने को कहा गया उससे सरकार की गंभीरता का ही पता चलता है, लेकिन बेहतर होता कि इस समिति में टैक्स अधिकारियों के अलावा कारोबार जगत के भी कुछ प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता। कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि यह समिति कारोबार जगत के लोगों से विचार-विमर्श अवश्य करे। दरअसल टैक्स अधिकारियों के लिए यह जानना आवश्यक है कि व्यापारियों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? उम्मीद की जानी चाहिए कि उक्त समिति जीएसटी में सुधार के ऐसे ठोस उपाय सुझाने में सफल रहेगी जिससे यह टैक्स व्यवस्था और अधिक सुगम बनेगी।

निःसंदेह जरूरत केवल इसकी ही नहीं है कि जीएसटी व्यवस्था और अधिक सरल बने, बल्कि इसकी भी है कि टैक्स चोरी का सिलसिला थमे। यह ठीक नहीं कि जीएसटी चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। टैक्स चोरी में लिप्त लोगों को यह अहसास जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा कि यह सिलसिला अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। इसी के साथ सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदम उन कारोबारियों की परेशानी का सबब न बनें जो अपना टैक्स ईमानदारी से चुका रहे हैं। चूंकि जीएसटी संग्रह में कमी से अर्थव्यवस्था में सुस्ती का भी संकेत मिलता है इसलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि यह सुस्ती कैसे दूर हो? हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन इसे लेकर अभी भी सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि इन कदमों से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ ही जाएगी। इसमें दोराय नहीं कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने वाला एक बड़ा कदम है, लेकिन बात तो तभी बनेगी जब उद्योगपति वास्तव में सक्रिय होंगे। बेहतर होगा कि सरकार जीएसटी संग्रह बढ़ाने के उपाय करने के साथ ही इस पर भी नजर बनाए रहे कि आर्थिक गतिविधियां अपेक्षित गति से तेजी पकड़ रही हैं या नहीं?

अब स्वास्थ्य का मोर्चा

पटना में जलजमाव समेत बिहार के 15 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को त्वरित राहत दिलाने के लिए सटीक रणनीति की आवश्यकता है। एक अनुमान के मुताबिक दोबारा बाढ़ और भारी बारिश की वजह से लगभग पंद्रह लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस आपदा के दौरान बांध, सड़क, पुल-पुलिया और फसलों को हुए नुकसान का आकलन तो किया ही जा रहा है, सबसे बड़ी चुनौती पिछले दस दिनों से पानी के बीच घिरे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर है। डेंगू के मरीज तेजी से बढ़े हैं। पटना के जलजमाव वाले मोहल्लों में शिकायतें ज्यादा हैं। जिन गली-मोहल्लों में जमा पानी सड़ रहा है वहां यथाशीघ्र जलनिकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी। साथ ही संक्रामक और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग और चूने के साथ-साथ मच्छरों के लार्वा के शमन के लिए दवा का छिड़काव निर्बाध रूप से करना होगा। इस कार्य में शिथिलता न बरती जाए, इसके लिए निगरानी भी जरूरी है। डेंगू के मरीजों के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। मरीज अस्पताल तक पहुंच सकें, इसके लिए एंबुलेंस की सुलभता का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के इस मोर्चे पर सटीक रणनीति की जरूरत है, ताकि स्थिति पर नियंत्रण बना रहे। पटना के बाद भागलपुर में डेंगू की शिकायतें ज्यादा पाई गईं। हालांकि प्रायः जलजमाव प्रभावित जिलों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा डेंगू की शिकायतें मिली हैं। दूसरी ओर जलनिकासी के लिए जरूरी है कि नाले का पानी पर्याप्त मात्र में संप हाउस तक पहुंचे। भारी वर्षा के बाद भी पटना के कई संप हाउस की मशीनें पर्याप्त पानी न रहने के कारण बंद रहीं। चूंकि नालों के जहां-तहां अवरुद्ध रहने के कारण संप हाउस तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा था, इन नालों की सफाई भी यथाशीघ्र होनी चाहिए। जो क्षेत्र जलजमाव से मुक्त हो रहे हैं, वहां के कचरे की सफाई भी तत्परता के साथ की जानी चाहिए। विशेषकर फल और सब्जी मंडी में सड़े-गले फल और सब्जियों को शहर से बाहर करना होगा। बड़ी मात्र में फल और सब्जियों का नुकसान हुआ है। इसमें सर्वाधिक क्षति जलजमाव में कई दिनों तक खड़े ट्रकों में रखे फलों के सड़ जाने के कारण हुई है। जितनी जल्दी यह सूरत बदलेगी, दशहरा में मायूस हुए लोग दीपावली का उत्सव मना सकेंगे।

समावेश का संदेश देने वाला संबोधन

अद्वैता काला

विजयादशमी पर सरसंघचालक के संबोधन की मंशा भले ही स्वयंसेवकों को प्रेरित करने की हो, लेकिन उसमें समावेशन का साफ संदेश भी है

सरसंघचालक के विजयादशमी भाषण को लेकर खासी उत्सुकता रहती है। स्वाभाविक है कि इस बार भी यह कोई अपवाद नहीं था। डॉ. मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण के बाद तमाम तरह की चर्चाओं के दौर शुरू हो गए। सरसंघचालक के विजयादशमी भाषण की परंपरा बहुत पुरानी है जो प्रथम सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार के समय से चली आ रही है। पहले संबोधन में करीब 15 स्वयंसेवक शामिल हुए थे जिन्होंने समाज के भीतर काम करते हुए राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य से जुड़ने की राह चुनी थी। सरसंघचालक संघ परिवार के संरक्षक एवं मार्गदर्शक होते हैं। अपने इस वार्षिक संबोधन में वह स्वयंसेवकों के लिए प्राथमिकताओं का खाका खींचते हैं। साल दर साल इसके बिंदु भले बदल जाते हों, लेकिन मूल भाव वही रहता है। यह मूल भाव है समावेशन। इस वर्ष संघ के 94वें स्थापना दिवस पर सरसंघचालक ने ऐसे एकजुट राष्ट्र का आह्वान किया जो विविधता भरा हो और जिसमें तमाम पहचान समाहित हों। एक व्यक्ति के रूप में भी हमारी तमाम पहचान होती हैं जो भाषा, संस्कृति, लिंग और धार्मिक आधार से तय होती है, लेकिन जैसे तमाम नदियां अलग-अलग प्रवाहित होकर सागर में एकाकार हो जाती हैं वैसे ही इन सभी पहचानों को राष्ट्रवाद की एक धारा में अवश्य ही मिल जाना चाहिए।

बीते कुछ वर्षों में विशेषकर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को मिले पूर्ण जनादेश के बाद इन पहचानों को नुमाया करना और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष को तूल देने की तमाम कोशिशें हुई हैं। डॉ. भागवत ने इस गंभीर मसले पर स्पष्ट लहजे में बात रखी। उन्होंने विशेष रूप से मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा से जुड़े विमर्श की चर्चा की, जिसे कुछ निहित स्वार्थी लोग भारत को बदनाम करने के लिए गढ़ रहे हैं। सामाजिक तनाव एवं हिंसा दुर्भाग्यवश भारतीय समाज का हिस्सा रहे हैं। हालांकि बीते छह वर्षों में देश में ऐसा कोई भयावह दंगा नहीं हुआ जिसमें जान-माल की भारी हानि हुई हो। यह मोदी सरकार की खास उपलब्धि है कि देश में शांति का माहौल कायम रहा और सांप्रदायिक संघर्ष की कोई चिंगारी नहीं भड़की। हालांकि छिटपुट हिंसा के कुछ मामले जरूर सामने आए जिन्हें स्वार्थी तत्वों ने लिंचिंग का नाम दिया। भागवत ने लिंचिंग को पश्चिमी अवधारणा बताया और वह गलत भी नहीं हैं। लिंचिंग का संबंध पश्चिम खासकर अमेरिका से है जहां अमेरिकी गृहयुद्ध के आसपास ऐसी घटनाएं सामने आईं। तब दासप्रथा के समर्थक अश्वेतों को निशाना बनाकर नस्ली श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करते। ऐसे माहौल में ही इस किस्म के जघन्य अपराध अंजाम दिए जाते थे। हालांकि भारत में जहां हम सभी का मूल एक ही है तो ऐसा संदर्भ सर्वथा अनुचित है। लिंचिंग एक ऐसा अत्याचार है जहां पीड़ितों को अलग-अलग निगाह से देखा जाता है। इसकी तमाम मिसालें भी हैं। इस

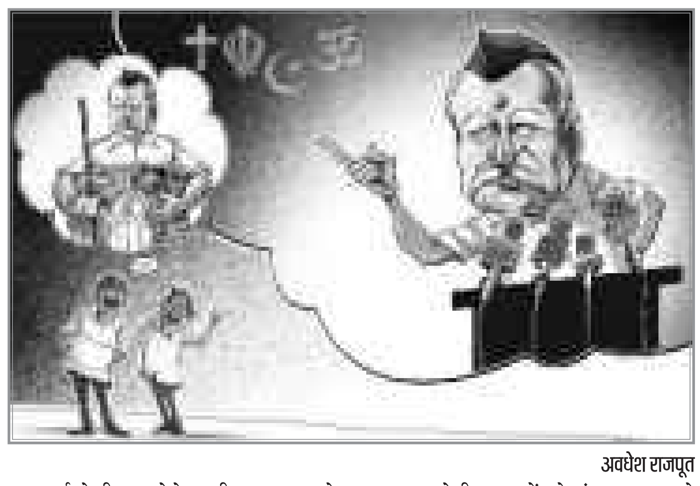

अवधेश राजपूत

साल मई से ही अब ऐसे तकरीबन 37 मामले सामने आए जहां मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमला किया, पर ये सुर्खियों में नहीं छाए। ऐसा मीडिया के पक्षपाती रुख और कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के चलते होता है जो अपने एजेंडे के चलते अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इन अपराधों को उस लहजे में परोसते हैं जिसे पश्चिम में आसानी से समझा जा सके। इस तरह वे लिंचिंग का तानाबाना बुनते हैं जिसमें पीड़ित-हमलावर की पहचान हमेशा मायने रखती है।

लिंचिंग एक भारी-भरकम शब्द है जिसका आशय एक खास तबके के लोगों के योजनाबद्ध 'सफाये' से है। जबकि तथ्य यह है कि देश में ऐसे अपराध 2014 से पहले भी होते आए हैं और यहां तक कि भारत का विभाजन भी ऐसी घटनाओं का परिणाम था। तब मुस्लिम अपने लिए अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। यह प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि ऐसे लोगों का क्या एजेंडा है जो बड़े ढीठ तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार एक तबके की गलत छवि पेश करते हैं? ऐसे लोग तब मुंह फेर लेते हैं जब वही तबका पीड़ित होता हैं। अगर हम ऐसी लड़ाइयों को बंद करना चाहते हैं तो हमें दोषारोपण की कवायद से ऊपर उठकर समस्या के मूल में जाना होगा। असल में समस्या लोगों की उस मानसिकता में है जो यह सोचते हैं कि वे कानून अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से इंसाफ कर सकते हैं। हिंसक भीड़ के ऐसे वाकये हमने अस्पतालों में भी देखे हैं। हाल में अपने एक करीबी की देखभाल के लिए मैं अस्पताल गई तो वहां ऐसे बोर्ड देखे जिसमें लोगों को अस्पताल स्टाफ के साथ हिंसक तरीके से पेश आने को लेकर हिदायत दी गई थी। यह स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया थी जिसमें लोगों ने अपने प्रियजनों की मौत के बाद डॉक्टरों और नर्सों पर हमले किए थे। हिंसक भीड़ की उस घटना का भी उदाहरण लें जिसमें असम में बच्चा चोरी की अफवाह में दो लोगों को धर लिया गया।

ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। ये मामले चिंतित करते हैं, लेकिन हिंसक भीड़ के इन मामलों को लिंचिंग नहीं कहा गया। इस तरह आप देखेंगे तो उन्हीं मामलों को लिंचिंग करार दिया गया जहां पीड़ित मुस्लिम हों। जब कोई पीड़ित हिंदू होता है तो आखिर उसे लिंचिंग क्यों नहीं कहा जाता? सभी भारतीयों को यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए, भले ही उनका मजहब कुछ भी हो। इसका जवाब इसके पीछे छिपे उस एजेंडे को उजागर करेगा जिसका मकसद दो वर्गों के बीच विभेद पैदा करना है और इस सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है।

वर्ष 2019 में पीएम मोदी को मिला जनादेश बेहद निर्णायक है। सरसंघचालक ने एकदम सही कहा कि अगर 2014 की जीत पूर्ववर्ती सरकार से जनता के मोहभंग का परिणाम थी तो यह जनादेश मौजूदा सरकार के प्रदर्शन पर मुहर लगाता है। बढ़ी सीटें यही दर्शाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस निरंतर होने वाले दुष्प्रचार को देख रहे हैं और पीएम मोदी जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, वे उसमें भरोसा जता रहे हैं। संक्षेप में कहें तो यह दुष्प्रचार कारगर नहीं रहा। दो वर्गों को बांटने के इस खतरनाक खेल से व्यापक सांप्रदायिक हिंसा नहीं भड़की। मुस्लिम भाई भी इस उकसावे में नहीं आए। ऐसे में दुष्प्रचार करने वालों का एजेंडा नाकाम हुआ और आगे भी इसकी यही परिणति होगी। हालांकि इन खतरनाक परिस्थितियों में कुछ निहित स्वार्थी एवं राजनीतिक हितों के वशीभूत लोग भारत की विकास गाथा को पटरी से उतारना चाहते हैं। एक आम भारतीय होने के नाते इस समय हमें भाईचारे और सहयोग की भावना सुनिश्चित करनी होगी। विजयादशमी के अवसर पर सरसंघचालक ने अपने संबोधन में यही संदेश दिया कि हमें समावेशन और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से उनके संबोधन की मंशा भले ही स्वयंसेवकों को प्रेरित करने की हो, लेकिन उसमें हम सभी के लिए सीख और संदेश निहित है।

(स्तंभकार जानी मानी पटकथा लेखक हैं)

response@jagran.com

इतिहास की गलती सुधारने का समय

अवधेश कुमार

देश विभाजन के वक्त पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के प्रति जिस दायित्व से भारत ने पल्ला झाड़ा था अब उसे पूरा किया जाए

पाकिस्तानी संसद ने एक विधेयक को पेश होने से पहले ही खारिज कर दिया जिसमें संविधान संशोधन के जरिये गैर मुस्लिमों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने का प्रावधान था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ईसाई सांसद डॉ. नवीद आमिर जीवा इसके लिए संविधान संशोधन कराना चाहते थे। इसकी चर्चा करते ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मानो तूफान आ गया। संसदीयकार्य राज्यमंत्री अली मुहम्मद ने इसका वरोध किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है जिसमें गैर-मुस्लिम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। कई विपक्षी सदस्यों ने भी सरकार का समर्थन किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तानी संविधान की धारा 41 में स्पष्ट लिखा है कि प्रधानमंत्री होने के लिए मुस्लिम होना अनिवार्य है। इसी तरह धारा 91 में राष्ट्रपति की अर्हता है। यानी कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन या ईसाई वहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे धर्म बदलकर मुसलमान बनना होगा।

इसके पीछे तर्क यह है कि जब देश का विभाजन ही हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ तो वहां मुसलमानों को ऐसा विशेषाधिकार स्वाभाविक है। भारत के सामने भी ऐसा मजहबी संविधान बना देने में समस्या नहीं थी। इसका उत्तर यही है कि हिंदू दर्शन में ऐसे किसी मजहबी राज्य की कल्पना ही नहीं है। जिस राजव्यवस्था का हमारे प्राचीन साहित्य में विवरण है वहां मौजूदा थियोक्रेटिक स्टेट यानी मजहबी राज्य नहीं था। इसलिए भारत वैसा हो ही नहीं सकता है। यह है दोनों देश के चरित्र में अंतर। सभी इस्लामिक गणराज्यों में ऐसे ही संविधान हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक गैर मजहबी व्यक्ति थे। उन्होंने विभाजन के बाद अपनी संविधान सभा में साफ कहा था कि यहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार होगा। पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना ने कहा था कि हम रंग और नस्ल के भेदभाव से परे देश बनाकर दिखाएंगे। जिन्ना ने भारत से दलितों की हितसाधना के लक्ष्य से पाकिस्तान गए जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया। मगर जिन्ना के जीवनकाल में ही पाकिस्तानी नेताओं का भयावह मजहबी व्यवहार दिखने लगा था।

जिन्ना के वादे के कारण लाखों हिंदू और सिखों ने स्वेच्छा से पाकिस्तान में रहना स्वीकार किया। मगर जो स्थिति बनती गई उसमें उनके लिए पाकिस्तान में अपनी

संस्कृति और परंपरा ही नहीं, बल्कि इज्जत और संपत्ति तक की रक्षा मुश्किल होती गई। जैसी हिंसा और लूट के साथ जबरन धर्मांतरण का सामना हिंदुओं को करना पड़ा, उसका विवरण रोंगटे खड़े करता है। अल्पसंख्यकों की संपत्तियों के लिए जो शत्रु संपत्ति कानून बना उसका भयंकर दुरुपयोग हुआ। संपत्तियों पर जबरन कब्जा सामान्य बात हो गई और इसके खिलाफ शिकायत के लिए कहीं कोई जगह नहीं। विडंबना देखिए कि जिन दलित हिंदुओं को विभाजन के पूर्व मुस्लिम लीग ने यह कहकर साथ लिया था कि सवर्ण हिंदू तो आपको अपना भाई मानते नहीं, लेकिन पाकिस्तान आपको बराबरी का दर्जा देगा, उनका ही सबसे अधिक उत्पीड़न किया गया।

यहां जोगेंद्र नाथ मंडल की चर्चा जरूरी है। 1940 के दशक में वह दलितों के बड़े नेता बन चुके थे, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर के विपरीत वह मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए। विधि मंत्री के साथ वह पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य भी बने, मगर वहां अपने ही लोगों के साथ मजहबी बर्बरता के सामने वह असहाय थे। इससे आजिज आकर आठ अक्टूबर, 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को उन्होंने जो लंबा पत्र लिखा वह पाकिस्तान का सच समझने के लिए पर्याप्त है।

उन्होंने लिखा कि 'पूर्वी पाकिस्तान के पिछड़े हिंदुओं के उत्थान के अपने मिशन में विफल रहने की कुंठा के चलते मैं यह कदम उठा रहा हूं। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भविष्य में पाकिस्तान हिंदुओं के लिए रहने लायक नहीं रह जाएगा। धर्मांतरण और दमन की राजनीति के कारण उनके लिए केवल अंधेरा ही रहेगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज कैसे दबा सकता हूं और कैसे पाकिस्तानी हिंदुओं को यह भरोसा दिला सकता हूं कि भविष्य में उनके साथ न्याय होगा?' यह था पाकिस्तान का सच जिसे मंडल ने व्यक्त किया। ऐसे पाकिस्तान में, जिसके निर्माताओं में से एक ने कहा कि भविष्य में यह हिंदुओं के रहने लायक नहीं रह जाएगा वहां यह कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई गैर मुस्लिम दो शीर्ष पदों पर पहुंच सकता है। मंडल हिंदू थे इसलिए अपने समुदाय के बारे में बात की। दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भी यही स्थिति थी। इसीलिए भारत में समुदायों की अदला-बदली की भी मांग जोर से उठी थी। सिख नेता मास्टर तारा सिंह इसकी सबसे बड़ी आवाज बने थे। भारत को इन मांगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हुआ अजीब।

तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खान से बात की। वह दिल्ली आए। छह दिनों की वार्ता के बाद दोनों नेताओं के बीच आठ अप्रैल, 1950 को एक समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने यहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वचन दिया। इसके बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यक समितियां गठित हुईं। यह अदूरदर्शितापूर्ण कदम था। भारत में तो अल्पसंख्यकों के लिए समस्या थी ही नहीं। समस्या पाकिस्तान में थी। इस समझौते ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को निराश्रित कर दिया। मंडल ने अपने पत्र में लिखा था कि पूर्वी बंगाल व मुस्लिम लीग ने नेहरू-लियाकत समझौते का इस्तेमाल केवल कागज के एक टुकड़े के रूप में किया। भारत सरकार उस समय अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर सकी। परिणाम सामने है। अल्पसंख्यक वहां धीरे-धीरे खत्म होते गए। जो पाकिस्तान हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों और ईसाइयों आदि के लिए तब था, आज भी वही है। इसी कारण मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार जिस नागरिकता कानून की बात कर रही है उसका मकसद समझ में आता है। भारत ने जिस जिम्मेदारी से तब पल्ला झाड़ा था कम से कम अब उस भूल का परिमार्जन होना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भक्ति है तो भगवान हैं

अगर आप खुद को एक मशीन के रूप में देखें तो आपके पास शरीर है, दिमाग है, आपके पास सब कुछ है। जिसे आप कृपा कहते हैं वह एक चिकनाई की तरह होती है। आपका इंजन कितना भी मजबूत क्यों न हो बिना इस चिकनाई के आप हर जगह अटक जाएंगे। इस पृथ्वी पर अनेक लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, क्षमतावान हैं, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर अटक जाते हैं, क्योंकि उनके पास कृपा की चिकनाई नहीं होती। कुछ लोगों के जीवन में भरपूर कृपा है और उनका जीवन आनंदमय है, जबकि कुछ लोग हर छोटी-छोटी चीज को लेकर जीवन के साथ जूझ रहे हैं। जीवन के सफर को आनंदमय बनाने के लिए कृपा प्राप्त करनी होगी और इसे पाने का सबसे आसान तरीका भक्ति है, लेकिन बुद्धि बहुत चालाक है, यह किसी की भक्त नहीं बन सकती। आप भक्ति गीत गा सकते हैं, लेकिन बुद्धि तर्क करती है, हिसाब लगाती है। एक मतलबी बुद्धि कभी भी भक्ति नहीं कर सकती।

एक भक्त किसी व्यक्ति का भक्त नहीं होता, भक्ति तो एक गुण है। भक्ति का अर्थ है खुद को किसी एक लक्ष्य को सौ फीसद सौंप देना। जब कोई व्यक्ति निरंतर एक दिशा में ऐसे केंद्रित हो जाए कि उसके विचार, भावनाएं और सब कुछ एकाग्र हो जाएं तब वह कृपा का पात्र हो जाता है, उसके ऊपर कृपा स्वाभाविक है। आप किसके प्रति समर्पित हैं या किसके भक्त हैं, मुद्दा यह नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि मैं भक्त बनना चाहता हूं, पर आपके मन में यह संदेह है कि ईश्वर है भी या नहीं, फिर आप भ्रम में हैं। जिसे मैं भक्ति कहता हूं उसकी गहराई ऐसी है कि यदि ईश्वर नहीं भी हो तो भी वह उसका सृजन कर सकती है, उसको उतार सकती है। भक्ति का अर्थ राम-राम कहना नहीं है-जो इंसान अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त है, जो अपने काम में पूरी तरह समर्पित है, वही सच्चा भक्त है। उसे भक्ति के लिए किसी देवता की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति इसलिए नहीं आई, क्योंकि भगवान हैं। चूंकि भक्ति है इसीलिए भगवान हैं। यह एक प्रकार का परस्पर भाव ही अधिक है।

सद्गुरु

शिक्षा में संगीत का महत्व

बाल मुकुंद ओझा

अब स्कूली बच्चे गीत-संगीत के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, ताकि उनको सकारात्मक वातावरण मिल सके

पठन-पाठन को संगीत फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार तरह-तरह के प्रयोग करने में जुटी है। अब स्कूली बच्चे गीत और संगीत के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, ताकि उनको सकारात्मक और आनंददायक वातावरण मिल सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इसके लिए स्कूलों को बाकायदा एक दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि लंच ब्रेक या मिड डे मील दिए जाने के दौरान स्कूलों में बच्चों की उम्र के अनुसार गीत-संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। गाने बजाने के ऐसे कार्यक्रम आवश्यकता के अनुसार पढ़ाई के दौरान भी किए जा सकते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि संगीत से बच्चों की ग्रहणशीलता बेहतर होती है। इससे ठहराव और शांति की भावना भी विकसित होती है।

जिस प्रकार हमारा मन और शरीर आत्मा के बिना अधूरे हैं उसी प्रकार जीवन भी संगीत के बिना अधूरा है। आजादी के बाद शुरू के चार दशकों में दैनंदिन गतिविधियों के साथ स्कूलों में हर सप्ताह एक दिन छात्र सभा का आयोजन कर गीत-संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे जिनमें बड़ी संख्या में छात्र उत्साह के साथ भाग लेते थे। पूरे सप्ताह छात्र उसकी तैयारियां भी करते थे। यहां तक कि अभिभावक भी घरों में बच्चों को गाने-बजाने के काम में सहयोग देते थे। गाने-बजाने के अलावा भाषण, निबंध, चित्रकला आदि का आयोजन भी होता था। धीरे-धीरे ऐसे आनंद देने वाले आयोजन घटते गए। अब सरकार एक बार फिर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली शिक्षा का बोझिल वातावरण पलटना चाहती है तो इसे स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है।

निश्चय ही गीत-संगीत को प्रभावशाली एवं उपयोगी माध्यम बनाकर पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने का यह एक अभिनव प्रयास होगा। सरकार को चाहिए कि गीत-संगीत के माध्यम से बच्चों को समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के बारे में भी जानकारी दे और चित्रकला के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने का प्रयास करे। चित्रों के माध्यम से बच्चों को उनकी धरोहर एवं संस्कृति का ज्ञान दिया जा सकता है। साथ ही उनके अंदर की कला को भी जागृत किया जा सकता है। गीत प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी छात्र-छात्राओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत की जा सकती है। यह संपूर्ण कवायद तभी पूरी होगी जब स्कूलों के पास गीत-संगीत की सभी सुविधाएं यथा कला शिक्षक और विभिन्न वाध यंत्र आदि उपलब्ध होंगे।

संगीत मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है। संगीत गायन, वादन एवं नृत्य का आकर्षक और मनमोहक समावेश है। संगीत हमारा मनोरंजन करने के साथ सुकून भी देता है। जीवन में संगीत का बहुत महत्व है। संगीत से हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। संगीत शारीरिक और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है। जीवन में खुश और व्यस्त रहने के लिए संगीत सबसे अच्छा तरीका है। जीवन में संगीत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों को भी संगीत से अथाह स्नेह है। सुख-दुख के हर क्षण में संगीत का अप्रतिम योगदान है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

मेलबाक्स

नवाचार पर देना होगा ध्यान

आर्थिक सुस्ती तोड़ने का सही उपाय शीर्षक से लिखे अपने लेख में विवेक कौल ने आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहे देश को बाहर निकालने के लिए (बीमार) सरकारी कंपनियों और उनकी (बेकार पड़ी) जमीनों को बेचने और उनसे मिले पैसों को बुनियादी ढांचे के विस्तार में लगाने की सलाह दी है, ताकि रोजगार सृजन कर उपभोक्ता मांग को बढ़ाया जा सके, लेकिन जैसा कि लेखक ने स्वयं माना है कि लोकप्रिय सरकारों के लिए एक झटके में ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन काम है। ऐसे में प्रश्न यह है कि लोगों की आय बढ़ाकर उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, ताकि निवेश का माहौल बने और उद्योगों की सेहत भी सुधरे। एक उपाय तो यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। इसके लिए जरूरत होगी नवाचार को अपनाने की और नए अनुसंधानों के ऊपर खर्च बढ़ाने की। यदि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी और वे प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होंगे तो उनकी मांग विश्व भर के बाजारों में होगी। सूचना तकनीकी और स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने अपना परचम लहराया है और अब बारी है मैन्यूफैक्चरिंग में मेहनत करने की। इस क्षेत्र में हम चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।

चंदन कुमार, देवघर

कांग्रेस को चाहिए सक्षम नेतृत्व

दैनिक जागरण के 10 अक्टूबर के अंक में संपादकीय आलेख, कांग्रेस का आत्ममंथन, में सही लिखा है कि कांग्रेस किधर जा रही है यह कांग्रेस के नेता भी नहीं जानते। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस जन हमेशा परिवार से किसी चमत्कार की आस लगाए रहते हैं। आम चुनाव में मिली पराजय के बाद आत्ममंथन करने के बजाय राहुल गांधी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर अपने दायित्व से किनारा कर गए। बेशक राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत गए, लेकिन पारिवारिक सीट अमेठी हारने से निश्चय ही उनका आत्मविश्वास डगमगा गया होगा। अमेठी में कांग्रेस की यह पहली हार नहीं है, वर्ष 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी व संजय गांधी दोनों रायबरेली व अमेठी से चुनाव हार गए थे, किंतु 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और दोनों सीटें फिर से जीत लीं। किंतु वह इंदिरा गांधी का जलवा था, अब कांग्रेस सोनिया गांधी पर निर्भर है, जब महाराष्ट्र व हरियाणा में विधान सभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है तब राहुल गांधी का विदेश यात्रा पर चले जाना उनकी राजनीतिक क्षमता पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं और अचेत कांग्रेस में प्राण फूंकना अकेले उनके बस की बात नहीं है। राहुल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका गांधी का नाम चर्चा में अवश्य रहा, किंतु पार्टी हिम्मत नहीं जुटा सकी। संभवतः प्रियंका बेहतर विकल्प हो सकती थीं। यदि कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो उसे एक सक्षम नेतृत्व की तलाश करनी ही होगी, अन्यथा उसका नाम इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

फर्जीवाड़े पर प्रहार

देश के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों से फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए इन्हें जियो टैग से जोड़ने की सरकार की योजना है। इसके लिए इनका व्यापक सर्वे होगा, ताकि इनका पूरा और सही विवरण आसानी से मिल सके। इससे किसी भी स्कूल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यदि वास्तव में ऐसा पारदर्शी सर्वे और कार्य होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार होगा। ऐसे ही सर्वे और सुधार की आज हर जगह जरूरत है। आशा है सरकार इस पर भी जल्द कुछ करेगी। स्कूल ही शिक्षा के असली मंदिर हैं, जिनके व्यापक और पारदर्शी सुधार के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

वेद मामूरपुर, नरेला

यह है जीवन

प्रेम सही अर्थ में अत्यंत सरलता का सूचक है। प्रेम वहां निवास करता है जहां शांति होती है। दिल में शांति है तो प्रेम है। मानसिक उथल-पुथल में प्रेम की कल्पना करना बेईमानी है। मनुष्यता, प्रेम व रिश्ता ये सभी एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में बाकी सबका कोई अस्तित्व नहीं है। इन तत्वों की मौजूदगी आत्मसंयम व आत्मसंतुष्टि ही होती है।

शोभित शुक्ला, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

रिजवान अंसारी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

आजकल

प्रवेश परीक्षा की गुणवत्ता का सवाल

अब आइआइटी अध्ययन में 'कमजोर छात्रों' को तीन साल बाद सम्मानपूर्वक ढंग से संस्थान छोड़ने की अनुमति देगी। इस नई व्यवस्था में कमजोर छात्रों को बीच में पढ़ाई छोड़ने पर बीएससी की डिग्री या फिर डिप्लोमा दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में जो व्यवस्था है उसमें अगर कोई विद्यार्थी सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी होती है। इससे छात्र का पिछला समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन नई व्यवस्था में छात्र की पिछली मेहनत बेकार नहीं जाएगी

हाल ही में आइआइटी काउंसिल की 53वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन सभी फैसलों में एक फैसला खासा चर्चा में है। इसके मुताबिक आइआइटी अध्ययन में 'कमजोर छात्रों' को तीन साल बाद सम्मानपूर्वक ढंग से संस्थान छोड़ने की अनुमति देगी। इस नई व्यवस्था में कमजोर छात्रों को बीच में पढ़ाई छोड़ने पर बीएससी की डिग्री या फिर डिप्लोमा दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में जो व्यवस्था है उसमें अगर कोई विद्यार्थी सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी होती है। जाहिर है कि छात्र का पिछला समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन नई व्यवस्था में छात्र की पिछली मेहनत बेकार नहीं जाएगी और वह सम्मानपूर्वक बीएससी की डिग्री या डिप्लोमा ले सकेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी विद्यार्थी अब चार साल की बीटेक डिग्री की जगह तीन साल की बीएसएसी डिग्री या डिप्लोमा लेकर आइआइटी से विदाई पा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मानें तो पिछले दो वर्षों में देश भर के 23 आइआइटी संस्थानों में 2,461 छात्र अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए और उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। ऐसी और भी कई खबरें हम लगातार अखबारों में पढ़ते रहते हैं। आइआइटी कानपुर द्वारा खराब ग्रेड के आधार पर इस साल 18 छात्रों को निकाले जाने की खबर इसी का एक पहलू है।

गौरतलब है कि आइआइटी में पढ़ना ज्यादातर छात्रों का सपना होता है। हालांकि उसके लिए प्रवेश परीक्षा को पास करना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन विडंबना तो देखिए कि जी तोड़ मेहनत कर आइआइटी में दाखिला लेने के बाद भी कोर्स को मुकम्मल करना कई छात्रों के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके लिए आइआइटी की पढ़ाई के तरीकों को दोष नहीं दिया जा सकता। गौर करें तो हर साल लगभग 13,500 छात्र इन संस्थानों में दाखिला लेते हैं। पिछले दो वर्षों में 27 हजार छात्रों ने दाखिला लिया होगा। ऐसे में अगर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों (2,461) का फीसद 10 से भी कम है तो इसका साफ मतलब है कि कुछ ऐसे छात्र भी चयनित होकर आ जाते हैं जो आइआइटी सरीखे संस्थानों के स्टैंडर्ड के काबिल नहीं होते। फिर सवाल है कि क्या आइआइटी की चयन प्रक्रिया में कोई दोष है? यह मामूली समझ की बात है कि वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रश्न की परीक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अनमने ढंग से विकल्प को चुन कर भी परीक्षा पास की जा सकती है। और इस तरीके से कोई भी कमजोर छात्र मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। सिविल सेवा में भी इस परीक्षा प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन यह प्रणाली केवल पहले चरण में अपनाई जाती है, जिसका मकसद अवांछित छात्रों की छंटनी करना है। दूसरे चरण में लिखित परीक्षा ली जाती है जिसमें उम्मीदवारों के ज्ञान की असली परख होती है। जाहिर है कि इस व्यवस्था में 'अयोग्य' उम्मादवारों के चयन की संभावना बेहद कम रहती है।

फिर सवाल है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस नई कोशिश को किस रूप में देखा जाना चाहिए? दरअसल सरकार की इस पहल पर शक करने की कोई वजह नजर नहीं आती। सरकार अपने इस कदम से कमजोर छात्रों के साथ खड़ी नजर आ रही है। गौर करें तो सरकार का यह कदम एक तीर से दो निशाना साधने जैसा है और दोनों ही सकारात्मक हैं। पहला तो यह कि अब डिग्री कोर्स में प्रवेश ले चुके छात्रों के समय को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा और उन्हें एक डिग्री के साथ घर भेजा जा सकेगा। इससे न केवल छात्र दूसरे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए भटकने से बच सकेंगे, बल्कि आइआइटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की डिग्री से भी वे वंचित नहीं रह सकेंगे।

दूसरा यह कि बीच में पढ़ाई छोड़ कर चले जाने से विद्यार्थियों पर खर्च किए जा चुके संसाधनों की बर्बादी होती है। यकीनन तीन वर्षीय बीएससी की डिग्री देने से संसाधनों की बर्बादी में कमी आएगी। हालांकि सरकार ने इस बाबत यह पहल जरूर की है, लेकिन सरकार को एक कदम और आगे जाकर सोचने की जरूरत है। अमूमन देश में शिक्षा प्रणाली और उसकी गुणवत्ता को लेकर बहस चलती रहती है, लेकिन यह कम ही देखने और सुनने को मिलता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई ठोस पहल की गई हो। इसकी एक बानगी 14 वर्षों तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा और फिर मिड-डे-मील योजना में देखी जा सकती है। यहां सरकार घर-घर तक शिक्षा पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। व्यापक पैमाने पर पैसे खर्च जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की कितनी फिक्र की जा रही है? आए दिन सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की अयोग्यता को बयान करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे होते हैं। यकीनन इसमें बुनियादी स्तर पर ही कमी देखी जा रही है। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण है।

इसी तरह सरकार को आइआइटी संस्थानों में भी चयन की प्रक्रिया को इतनी मजबूत बनाने की जरूरत है कि 'कमजोर छात्रों' के लिए कोई जगह न बन सके। इसके लिए दूसरे चरण की परीक्षा को लिखित रूप में लिए जाने की जरूरत है। जाहिर है कि उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा से पहले लिखित रूप में सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे जो कोर्स के दौरान पढ़ाई में भी उनके लिए सहायक सिद्ध होगा। यह समझने की जरूरत है कि कोर्स के दौरान भी विद्यार्थियों को लिखित रूप में ही सेमेस्टर की परीक्षाएं देनी होती हैं। हालांकि यह सच है कि लिखित परीक्षा लेने में सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे। दूसरे चरण में भी लाखों की संख्या में छात्र होते हैं, लेकिन अगर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना है तो कुछ कड़े कदम उठाने ही होंगे। यह समझने की जरूरत है कि कमजोर छात्रों को बीएससी की डिग्री देना भी गुणवत्ता से समझौता न करने का ही संकेत है। फिर कुछ कमजोर छात्रों के लिए आइआइटी की पढ़ाई को आसान न बनाना भी इसी का उदाहरण है। अन्यथा आसान बनाने से कमजोर छात्र भी कोर्स में बने रहने के लिए जरूरी अंक ले ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए जब इस स्तर पर गुणवत्ता से समझौता करना सरकार और प्रबंधन को मंजूर नहीं है तो प्रवेश परीक्षा के स्तर पर गुणवत्ता से समझौता करना भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल सरकार को इस बिंदु पर भी फिक्रमंद होने की जरूरत है।

उच्च शिक्षा में पिछड़ने की वजह

देवेंद्रराज सुथार

> अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की आर्थिक प्रगति को वहां की उच्च शिक्षा से जोड़कर देखा और समझा जा सकता है

टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2020 में दुनिया के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का एक भी विश्वविद्यालय जगह नहीं बना पाया है। इस बार शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के 6 संस्थानों को जगह मिली है। गौरतलब है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल 92 देशों के 1300 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था। सूची में शीर्ष स्थान पर कब्जा करने वाले अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की आर्थिक प्रगति को वहां की उच्च शिक्षा से जोड़कर देखा और समझा जा सकता है। इन देशों में शोध एवं अनुसंधान पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। भारत में इसके विपरीत है। यहां शोध एवं अध्ययन की गुणवत्ता महज येन-केन-प्रकारेण डिग्री हासिल करने तक ही सीमित है।

शोध से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि ब्रिक्स देशों में केवल भारत ही ऐसा देश है, जहां शोध पर कुल जीडीपी का मात्र 0.9 फीसद खर्च किया जाता है। दूसरी ओर चीन में यह 1.9 फीसद, रूस में 1.5 फीसद, ब्राजील में 1.3 फीसद तथा दक्षिण अफ्रीका में एक फीसद खर्च होता है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मूल्यांकन परिषद ने भी अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह साफ किया है कि भारत में 68 फीसद विश्वविद्यालयों और 90 फीसद कॉलेजों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता या तो मध्यम दर्जे की है या दोषपूर्ण है। इन संस्थानों के 74 फीसद डिग्रीधारी छात्र बेरोजगार हैं। भारत में 60 फीसद विश्वविद्यालयों और 80 फीसद कॉलेजों से निकले छात्रों के पास न तो तकनीकी कौशल है और न ही भाषा की दक्षता है। यही कारण है कि ऐसे छात्र उचित रोजगार नहीं पा सकते। सिर्फ कुछ आइआइटी, एनआइटी, आइआइएम और सरकारी कॉलेजों के भरोसे देश उच्च शिक्षा में तरक्की नहीं कर सकता। सरकार के पास निजी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए बेहतर कार्ययोजना होनी चाहिए।

हमने यह समझने में बहुत देरी कर दी कि अकादमिक शिक्षा की तरह अपनी नई पीढ़ी को बाजार की मांग के मुताबिक उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा देना भी हमारे लिए जरूरी है। एशिया की आर्थिक महाशक्ति दक्षिण कोरिया ने विकास के मामले में चमत्कार कर दिया है। साल 1950 तक विकास के स्तर और विकास दर, दोनों ही मामलों में दक्षिण कोरिया हमारे मुकाबले कहीं नहीं था, लेकिन आज उसकी गिनती भारत के एक पायदान आगे वाले देशों में होती है और विकास के कुछ पैमाने पर वह जर्मनी को भी पीछे छोड़ चुका है तो इसमें बड़ी भूमिका कौशल से जुड़ी शिक्षा की है। निश्चित रूप से कौशल विकास को बढ़ावा दिए बिना देश विकसित एवं आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। निःसंदेह भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनों की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा का हमारा एक विद्यार्थी लगभग 40 घंटे प्रति सप्ताह कॉलेज के लेक्चर सुनने और प्रायोगिक कार्यों वगैरह में लगा देता है।

शायद यही कारण हैं कि असीम प्रतिभाओं के होते हुए भी देश में शोध एवं अनुसंधानों की इतनी कमी है। उच्च शिक्षा में चल रहे इस घिसे-पिटे ढर्रे से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो हमें क्लास रूम शिक्षा के घंटों को कम करके 15 तक सीमित करना होगा। यह समझना होगा कि विद्यार्थी के लिए क्लास रूम शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण सीखना है। दूसरा पक्ष उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के लिए 40-45 घंटे प्रति सप्ताह पढ़ाने का भार होना है। उच्च शिक्षा का एक शिक्षक 15 घंटे में भी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता के जरिये वही पढ़ा सकता है, जो वह 45 घंटों में पढ़ाता है। शिक्षा और उद्योगों के इनपुट और आउटपुट में बहुत अंतर होता है। शिक्षा का क्षेत्र उद्योग की तरह नहीं है, जहां अधिक घंटे तक काम करके अधिक उत्पादन किया जा सके। शिक्षा में तो घंटे चाहे कम हों, काम की गुणवत्ता उत्कृष्ट होनी जरूरी है। परिणाम तभी बेहतर हो सकते हैं। अतः भारत सरकार को शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि एशिया के ही दूसरे शिक्षण संस्थानों से भारतीय विश्वविद्यालयों को कड़ी चुनौती मिल रही है। परिणाम तभी बेहतर हो सकते हैं।

खरी-खरी

वानरों की व्यथा-कथा

जगदीश ज्वलंत

बापू की प्रतिमा के चरणों को कुर्सी का पाया समझ मजबूती से पकड़ वे धार-धार रोने लगे। ऐसी अकल्पनीय, अप्रत्याशित, हृदय विदारक भावावेग की बाढ़ को बहकर आते देख डूबने के डर से तीनों बंदरों ने झट अपनी परंपरागत पोजीशन बदल ली। पहला होठों पर रखी अंगुली को हटाकर बोला-वाह! ये है असीम भक्ति। दूसरे ने आंखों पर रखी हथेलियों को हटा पहले वाले को डांटते हुए कहा-रहा न बंदर का बंदर। श्रद्धा-भक्ति नहीं, नौटंकी है ये। तीसरे ने भी हलचल देख झट दोनों कानों से अंगुली हटा ली। उसने साफ सुना कि वे विलाप करते हुए यही कह रहे थे कि-बापू, पहले इन तीनों बंदरों को हटाओ। आपके सच्चे बंदर तो हम हैं।

इधर बेचारे तीनों बंदर परेशान। यदि ये तथाकथित बहुरुपिए ऐसे ही रोते रहे तो हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। रोना ही है तो कहीं और जाके रो लें। बीते दो अक्टूबर से भूखे बैठे हैं। तीस जनवरी को एक भक्त ने गंगाजल पिलाया था। इस उम्र में अब कहां जाएं? बापू की छाया में कम से कम सुरक्षित तो हैं।

तीनों बेचारे न बुरा सुनते थे, न देखते थे, न कहते थे। किंतु आज इन मानव तनधारी बुरे वानरों को बुरी तरह बुक्का फाड़ रोते देख वे खिसिया उठे। जी तो चाहा कि उन्हें ऐसी जगह नोचें-लबूरें कि उनका विलाप गालियों में बदल जाए। किंतु तीनों सिद्धांतों के चलते मजबूर थे। तभी अकस्मात प्रजातंत्र का चौथा बंदर आ धमका। वह इन तीनों से कहा करता था कि अब समय बदल चुका है। खुद को भी बदलो। वह खुद मंत्रियों के बगीचों के फल खा-खाकर प्रगतिशील हो चुका था। आज अपने इन पिछड़े वंशजों को सचेत करने जो आ गया।

उसे लगा कि अब बापू के साथ इन तीनों का अस्तित्व भी संकट में है। बापू को तो कोई भी दल वाला अपना लेगा, लेकिन इन तीनों को कौन अपनाएगा? यही सोचकर वह इन रुदालिए, बहुरुपियों के साथ भागता हुआ उन्हें लेने यहां तक आ पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य! बेचारे तीनों कुछ तय कर पाते तभी वन-विभाग की टीम वहां आ गई। उन्हें देख चौथे ने झट ऐसी छलांग लगाई कि पकड़ से बाहर हो गया। बचे तीनों को पकड़ कर टीम दूर जंगल में छोड़ आई। अब बापू के पास उन तीनों की जगह दूसरे तीन बैठे थे। जो यही चाहते थे कि हम बैठें। तीनों उसी मुद्रा में थे। किंतु कान, आंख और मुंह खुले हुए थे। रोने का अंतिम लक्ष्य वे पा चुके थे।

ट्वीट-ट्वीट

कांग्रेस के नमूने नेताओं को देखिए जो ब्रिटेन में पाकिस्तान के लिए अभियान चला रहे हैं। आखिर नेतृत्वविहीन कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है?
विवेक रंजन अग्निहोत्री@vivekagnihotri

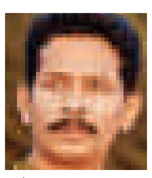

प्रत्येक मनुष्य के भीतर 'नागरिक' को कभी भी किसी राजनीतिक दल का वफादार नहीं होना चाहिए। यह अपनी आजादी गंवाने का रास्ता है।
अतुल कुलकर्णी@atul_kulkarni

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सहयोग राशि का वक्त पर भुगतान कर दिया है, लेकिन कितने शर्म की बात है कि अमेरिका ने अभी तक ऐसा नहीं किया।
निकोलस क्रिस्टॉफ@NickKristof

यह देखकर अच्छा लगा कि भारत सरकार किसी को तो समय पर भुगतान कर रही है। उम्मीद है कि वह जीएसटी रिफंड के भी वक्त से भुगतान के साथ ही उन लोगों की सेवाओं का भी भुगतान करेगी जिनकी सेवाएं वह ले चुकी है।
रूपा सुब्रमण्या@rupasubramanya

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश डायरी

जब से दादी मां का चश्मा टूट गया

देश के जनमानस में बसे श्रीराम का आसन इतना मजबूत है कि 'रोम-रोम में राम' की बात अब भी गूंजती है। वह कहावतों में हैं, लोकोक्तियों में हैं। और अगर सावन में किसी ने चश्मा नहीं पहना है तो विस्मयादि की परिस्थितियों में उसके मुंह से भी 'राम-राम' या 'हे राम' ही निकलता है। राम इस तरह मन में विराजे हुए हैं कि हर दूसरे नाम के साथ राम का नाम प्रत्यय के रूप में अटल है। राम एक लय हैं, ताल हैं राम। राग हैं राम और अस्तित्व को सिकोड़ने वाले जीवन में आस्था का ताप राम हैं। संगीत हैं राम। आदि से अंत तक की संस्कृति हैं। कौन नहीं जानता कि अंतिम यात्रा में भी एक 'राम नाम सत है' का शब्द ही गूंजता है।

गोस्वामी तुलसी दास ने तो कह ही दिया था कि होता वही है, जो राम ने रचा होता है। चार भाई, चारों सौतेले, लेकिन लेशमात्र भी कलुष नहीं। अद्भुत संगठनकर्ता। बंदरों, वन्य प्राणियों तक को संगठित कर लिया। संगठन और सहमति के प्रतीक थे राम। जिस सुप्रीम कोर्ट में राम के जन्म स्थान पर सुनवाई जारी है उसने भी राम नवमी के अवकाश काटे हैं। जिस पार्टी ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दिया है कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, उसी के बड़े नेता दशहरे पर धनुष उठाते हैं। यह राम की लीला नहीं तो क्या है।

इस बार भी राम का वनवास समाप्त होने वाला है, दीप पर्व की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। हर घर उनके आगमन की प्रतीक्षा में है। राम आते हैं, इसलिए आएंगे भी। कोई भला कहे या बुरा कहे, वह इससे ऊपर हैं। इसलिए ऊपर हैं, क्योंकि जब उन्हें वनवास का आदेश मिला, वह व्यथित नहीं थे। जब वनवास समाप्ति पर उनका राज्याभिषेक होने लगा तब वह हर्षित नहीं थे। देशभर में दशहरा की धूम हो चुकी तो अब कुल्लू में रघुनाथ जी का मेला जारी है। राम का अर्थ है सब देवताओं का मौजूद होना। राम के नाम पर सहमति। रघुनाथ जी की मूर्ति को चुराने के प्रयास बेशक किए गए हों, रघुनाथ जी सदियों से कुल्लूवासियों

के स्नेह में बंधे हुए हैं। इस सारे वातावरण में रामलीला एक संबद्ध, किंतु अलग विषय है। एक रामलीला में जाने का संयोग हुआ। कांगड़ा के फरेड़ गांव में साढ़े तीन दशक से जारी रामलीला के पंडाल में कई गांवों के लोग दर्शक बनते हैं। जिस सामुदायिकता के अभाव को निरंतर रोया जाता है, वही सामुदायिकता यहां दिखी। कोई प्रसाद का योगदान कर रहा है, कोई पुरस्कार की राशि दे रहा है। किसी के सौजन्य से चायपान का प्रबंध है। छोटे-छोटे बच्चे निश्चित अंतराल के बाद स्वयं कहते हैं कि प्रश्न पूछिए। इस प्रश्नोत्तरी के बाद पुरस्कार के रूप में कॉपी और पेंसिल भी मिलते हैं। इन बच्चों को अधिकार है कि वे किसी भी सोनाक्षी सिन्हा पर हंसें। उन्हें पता नहीं था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे। देशभर में रामलीला का मौसम है, लेकिन हिमाचल की कुछ गिनी-चुनी और विशुद्ध रूप से जज्बे के सिर पर चली रामलीलाओं में से एक इस रामलीला का रूप इसलिए विलक्षण है, क्योंकि समाज एक साथ दिखता है, जो इसे एक साथ देखता है। मोबाइल फोन के कारण मुट्ठी में सिमट आई जिंदगी की गालों पर आश्विन की हल्की ठंड जब थपकियां लगाती है, जब मैं बड़ा, वह छोटा का अहंकार घर में रख कर आते हैं लोग, जब भेड़ के ऊन से बने पट्टू में छोटे बच्चे माताओं की गोद में बैठ कर जामवंत को लंका अभियान के विषय में राम के साथ परामर्श करता देखते हैं तो यू ट्यूब की जरूरत किसे पड़ेगी? इस दौर में जब बच्चों को चुप करवाने का सबसे बड़ा जरिया मोबाइल फोन बन गया है, रामलीला जैसे परंपरागत और स्वस्थ मनोरंजन का अधिकार नई पीढ़ी को क्यों न मिले? हिमाचल में कुछ स्थानों को छोड़ कर अब रामलीला की संस्कृति संभव है दस्तावेजी फिल्मों में ही मिले। जैसे हम चेते नहीं तो कुछ दशकों के बाद अगली पीढ़ियां चित्रों में देखेंगी कि बर्फ पहले इतनी नीचे तक आती थी, कि बिल्कुल हरा पेड़ इस तरह का होता था, कि अमुक नदी में पानी पहले यहां तक आता था आदि। आग्रह यह नहीं है कि नई पौध सूचना-तकनीकी के उपकरणों अथवा औजारों का उपयोग न करे, लेकिन तकनीक से काम लेना एक बात है, तकनीक के काम आ जाना दूसरी बात। लंका कांड की यह चौपाई क्यों हमारा मार्गदर्शन न करे- नाथ न रथ नहि तन पद त्राना/ केहि बिधि जितब बीर बलवाना/ सुनहु सखा कह कृपानिधाना/जेहिं जय होइ सो स्यंदन आना। यानी हे नाथ! आपके पास न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? इस पर श्रीराम ने कहा, जिससे जय होती है, वह रथ दूसरा ही है। एक तरफ संगठित और प्रशिक्षित सेना, विमान भी और दूसरी ओर नंगे पांव श्रीराम। तकनीक का शीर्ष नहीं थे राम तो क्या थे? रामलीला को अब यह बताना चाहिए कि राम का चरित वही है, रावण बदल गए हैं। बेसहारा पशु, पर्यावरण को खतरे, आदमी का आदमी से दूर होना, सामुदायिकता की कमी और अपने अहंकार का ही कारावास स्वीकार करना नए रावण हैं जिनसे जूझना जरूरी है। रामायण और राम के चरित के साथ रिश्ता उतना ही जरूरी है जितना पत्तों की हरियाली के लिए जड़ों का मजबूत होना है। पूर्ण एहसान यूं ही नहीं कहते-

घर से रामायण का रिश्ता टूट गया
जबसे दादी मां का चश्मा टूट गया।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या आप आइएमएफ से सहमत हैं कि वैश्विक मंदी का भारत में कुछ ज्यादा असर है?

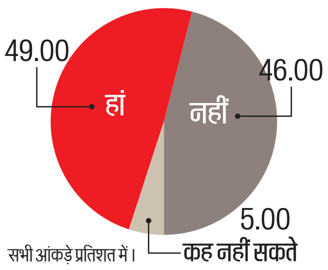

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में असंतोष के स्वर पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होंगे?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चिनफिंग जी मेहमान हैं हो खातिर भरपूर,
पर उनकी कर दीजिए गलतफहमियां दूर।
गलतफहमियां दूर न भारत बासठ वाला,
नहीं सहेगा डोकलाम सा गड़बड़झाला।
उड़ा रहे राफेल स्वयं रक्षामंत्री सिंह,
सावधान हो जायं पाक के आका चिनफिंग।
– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

डॉ. मोनिका शर्मा
सामाजिक मामलों की जानकार

सहज जीवनशैली की दरकार

तपती धरती, बढ़ते जल संकट, खत्म होते जंगल और हवा में घुलते प्रदूषण से शिकायत तो सभी को है, पर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझने की फुरसत किसी के पास नहीं

बीते दिनों अभिनेत्री कंगना रनोट ने एक साधारण सूती साड़ी पहनकर सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। यह सहज तस्वीर वायरल होने पर कंगना ने कहा कि जरूरत से ज्यादा संसाधनों का उपयोग करने वाली आज की पीढ़ी एक आम साड़ी पर गौर कर रही है। कंगना ने फैशन और फिल्मी दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक पीढ़ी के रूप में संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। हमें विचारशील होना होगा। लोग हमारे आम परिधानों पर भी गौर करते हैं। इन चीजों को प्रोत्साहित किए जाने की दरकार है।

हम ऐसे उत्पाद तब लेना पसंद करते हैं, जब वे फैंसी स्टोर में आते हैं, लेकिन किसानों, बुनकरों और शिल्पकारों को नहीं देखते, जो इन चीजों को तैयार करते हैं। कुछ समय पहले कावेरी कॉलिंग कैंपेन से जुड़ने के अवसर पर भी कंगना ने कहा था कि पर्यावरण को फैशन और ग्लैमर उद्योग से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जो कपड़े और जूते मॉडल पहनते हैं उनमें से बहुत आगे काम में नहीं लिए जाते हैं। उन्हें जला दिया जाता है जिससे बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। इसीलिए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों पर बेहतर दिखने का दबाव कम होना चाहिए। इससे न केवल सिंथेटिक और चमड़े से बने कपड़ों का प्रयोग कम होगा, बल्कि हाथ से बुने कपड़ों को बढ़ावा भी मिलेगा।

यह एक वैश्विक चिंता है कि हम संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में जीवनशैली में आए बदलावों से प्राकृतिक संसाधन ही नहीं रीते, बल्कि हमारी सोच और समझ भी रीत गई है। सजावटी-दिखावटी सी आज की दुनिया में बुनकरों और किसानों की मेहनत की अनदेखी ही नहीं, जलवायु परिवर्तन का मसला भी हमारी जीवनशैली से ही जुड़ा है। ऐसी बातों और हालातों का हमारी सोच और सजगता से ही वास्ता है। जल संसाधनों की कमी की बात हो या पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की, जरूरतों पर इच्छाएं भारी पड़ रही हैं। यही इच्छाएं प्रकृति के लिए भी बोझ बन गई हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्लोबल फुट प्रिंट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई के महीने तक हमने 2019 के लिए धरती के समस्त संसाधनों का इस्तेमाल कर लिया है। यानी साल भर के लिए तय संसाधनों को आधे साल में ही खत्म कर दिया है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि मानव जाति प्राकृतिक संसाधनों का 1.75 गुना दोहन कर रही है। चिंतनीय है कि प्रकृति जिस अनुपात में प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण करती है, उसके अनुपात में हम संसाधनों का दोहन बहुत तेजी से कर रहे हैं। इस अंधाधुंध दोहन के चलते हम आज 1.7 पृथ्वी जितना संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं जो करीब 10 साल बाद बढ़कर दो पृथ्वियों जितना हो जाएगा। कुल मिलाकर भोगवादी संस्कृति वाली इंसानी आदतें कुदरत को तो कुपित करने का काम कर ही रही हैं, तेजी से हो रहा संसाधनों का क्षरण खुद मानवीय जीवन के लिए भी संकट पैदा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य से जुड़े खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

भारत में भी संसाधनों के दोहन की स्थितियां बेहद चिंतनीय हैं। अगर इसी गति से प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग जारी रहा तो हमें अपनी मांग पूरी करने के लिए 2.5 देशों जितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। असीमित मानवीय जरूरतों और गतिविधियों ने धरती, जल और वायु सभी को प्रदूषित कर दिया है। जहां पेड़-पौधों के पूजन की परंपरा रही है वहां पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक देश के हर हिस्से में प्राकृतिक ससाधनों का जमकर दोहन हो रहा है। साफ है कि पर्यावरण सहेजने के लिए जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा होने जरूरी हैं। महात्मा गांधी के मुताबिक पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं।

वन्यजीवन पर मानवीय गतिविधियों के भयानक असर से जुड़ी बीते साल आई लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1970 के बाद मानवीय गतिविधियों के कारण जीव-जंतुओं की कुल संख्या 60 प्रतिशत कम हुई है। इतना ही नहीं कार्बन, खाद्य पदार्थ, जंगल, जैव विविधता और जल जैसे धरती के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी विचारणीय है। अगर पेड़ों के घटने की रफ्तार इसी गति से जारी रही तो वर्ष 2050 तक विश्व मानचित्र से भारत के क्षेत्रफल के बराबर जंगल समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में लाखों के परिधान पहन चर्चा में आने के बजाय आम पोशाक पहनकर इस संवेदनशील विषय पर सार्थक बात कहने का कंगना का यह अंदाज गौर करने लायक है। क्योंकि सहज और सरल रहन-सहन अपनाकर ही धरती के संसाधनों को बचाया जा सकता है।

विडंबना ही है कि तपती धरती, बढ़ते जल संकट, खत्म होते जंगल और हवा में घुलते प्रदूषण के जहर से शिकायत तो सभी को है, पर पर्यावरण के बिगड़ते हालातों के प्रति जिम्मेदारी समझने की फुरसत किसी के पास नहीं। जबकि कुदरत के बिगड़ते मिजाज और रीत रहे संसाधनों का मुद्दा समग्र समुदाय से जुड़ा है जिसे उचित योजनाओं के साथ-साथ धरती पर उपलब्ध संसाधनों का संयमित उपभोग और सही जीवनशैली ही प्रभावी रूप से संबोधित कर सकती है। ऐसे में इस जिम्मेदारी का सबसे पहला पड़ाव प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने का ही है। दुखद है कि हम प्रकृति से लेना तो सीख गए हैं, पर उसे कुछ भी लौटाने की समझ ही गुम है। निःसंदेह प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती है, पर इंसान तो सब कुछ छीनने में लगा है। यह व्यवहार प्रकृति के बिगड़ते संतुलन के लिए ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बड़ी चिंता का विषय बन गया है। सब कुछ होकर भी कुछ कमी सी लगने की आदत आज एक बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है, जिसके चलते जिंदगी के प्रति एक निराशा की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में सहज जीवनशैली अपनाकर हम मन का सुकून ही नहीं, प्रकृति के फीके पड़ रहे रंगों को भी सहेज सकते हैं।

800 लोग अब कर सकेंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्मारती। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने ऑनलाइन बुकिंग के लिए सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 800 कर दी है। इससे मंदिर समिति को 80 हजार रुपये प्रतिदिन की आय होगी।

बारिश की बूंदें सहेजेगी ये ईंट, बढ़ेगा भूजल स्तर

आइआइटी बीएचयू ने बनाया पोरस पेवर ब्लॉक, सड़कों पर बहने वाला पानी पहुंचेगा जमीन में

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पोरस पेवर ब्लॉक के साथ आइआइटी बीएचयू के छात्र। जागरण

मुहम्मद रईस, वाराणसी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आइआइटी), बीएचयू, वाराणसी ने बारिश की बूंदों को सहेजने का बेहतरीन उपाय ढूंढ निकाला है। गलियों में बिछाई जा सकने वाली ये ईंट आवागमन में सुविधाजनक होने के साथ ही बारिश की बूंदें भी सहेजेगी।

वर्षा का जल सड़कों-गलियों से होता हुआ यूं ही व्यर्थ बह जाता है। इन ईंटों से अब इस समस्या से निजात मिलेगा। भूजल स्तर बढ़ाने में इसे अहम माना जा रहा है।

जल संरक्षण

सड़कों के मलबे से बनने वाली इस ईंट को पोरस पेवर ब्लॉक का नाम दिया गया है। बनारस हिंदू विवि (बीएचयू) स्थित आइआइटी के शोधार्थियों का कहना है कि कंक्रीट के जंगल में परिवर्तित हो चुके महानगरों के लिए तो यह ईंट वरदान साबित होगी। संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. निखिल साबू के निर्देशन में शोध छात्रों ने खराब सड़कों से निकले मलबे, सीमेंट और सुपर प्लास्टिसर्जर लिक्विड का प्रयोग कर पोरस पेवर ब्लॉक (ऐसा ब्लाक जिससे पानी छन जाता हो) तैयार किया है। हालांकि पोरस ब्लॉक पहले भी तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन पेवमेंट मैटेरियल यानी सड़कों की खराब गिट्टियों का पहली बार इस तरह प्रयोग किया गया है। इन ईंटों से प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी काफी हद तक रोकी जा सकेगी।

डॉ. निखिल ने बताया कि पहले गिट्टियों की सतह, उसके ऊपर बालू की परत बिछाने के बाद ब्लॉक को लगाना होगा। इसका स्वरूप थोड़ा ढालू बनाने पर बारिश का पानी पूरी तरह छनकर एक किनारे आ जाएगा।

फुटपाथ, पार्किंग, फ्लोर और गलियों में हो सकेगा उपयोग

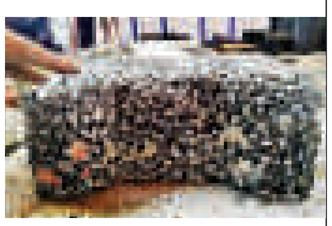

पोरस पेवर ब्लॉक। जागरण

नालियों के जरिए इस पानी को कहीं भी संचित किया जा सकता है। सिंचाई में प्रयोग के साथ ही ट्रीटमेंट के बाद इसका प्रयोग पेयजल के रूप में भी किया जा सकेगा।

गलियों, पाथवे, फुटपाथ के अलावा शोधार्थी अब सड़कों में प्रयोग के लिए ब्लॉक की मजबूती बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके तहत अगले दो माह में अलग-अलग तरह के 500 ब्लॉक तैयार किए जाएंगे। इससे सड़कों के लिहाज से भार वहन करने वाले ब्लॉक के सही फार्मूले की पहचान होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी ने इसके लिए करीब 2000 किलोग्राम पेवमेंट मैटेरियल विभाग को उपलब्ध कराया है।

वर्षाजल संचयन में बेहद कारगर : आइआइटी बीएचयू के मुताबिक सड़कों-गलियों में इसे बिछाकर वर्षा के बूंदों को सहेजा जा सकेगा। यही नहीं इन ईंटों को यदि उद्यानों, बाजारों, सोसाइटी, सड़कों के फुटपाथ और गलियों में बिछाया जाए तो यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तौर पर काम करेंगी। इससे वर्षा जल का बहुत बड़ा हिस्सा संचित किया जा सकता है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

जज्बा, तकनीक और तदबीर से सिरमौर बन सकते हैं हिमाचल व कश्मीर

विजय गुप्ता, सैन फ्रांसिस्को

देश में व्यावसायिक और आधुनिक ढंग से बागवानी व प्रोसेसिंग की जरूरत

अमेरिका से करोड़ों रुपये का अखरोट आयात होता है

कैलिफोर्निया में अखरोट के नए बाग लगाए जा रहे हैं। जागरण

सेब ने कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड को बागवानी का सिरमौर बना दिया है। अगर अखरोट पर भी ये तीनों राज्य ध्यान दें तो देश में तो एक बड़ा बाजार इनके स्वागत को तैयार है। हर साल अमेरिका से भारत करोड़ों रुपये का अखरोट आयात करता है। अगर ये तीनों राज्य अखरोट का व्यावसायिक उत्पादन करें, बाग लगाने से लेकर प्रोसेसिंग व मार्केटिंग पर भी ध्यान दें तो दुनिया में धाक जमा सकते हैं। जलवायु व जमीन के लिहाज से तीनों राज्य कैलिफोर्निया की बराबरी में हैं।

भारत में अभी जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के अलावा उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी अखरोट होता है। हालांकि, कुल रकबा केवल 68 हजार हेक्टेयर के करीब है, जिसमें हर साल लगभग 72 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। कुल उत्पादन में लगभग 80 फीसद अकेले कश्मीर का योगदान है। फिर भी देश की जरूरत को घरेलू अखरोट केवल 20 फीसद ही पूरा कर पाता है।

कश्मीर और हिमाचल में उगाया जाने वाला कागजी अखरोट भी उच्च गुणवत्ता का है, लेकिन वह वैश्विक स्तर पर अमेरिका की तरह का प्रचार नहीं पा सका है। अमेरिका ने सेब के साथ-साथ अखरोट की बागवानी व उसका बाजार बढ़ाने पर पिछले तीन दशकों (तीस वर्षों) में लगातार काम किया है। यही वजह है कि आज वह चीन के बाद सबसे बड़ा अखरोट उत्पादक देश बन गया है। निर्यात में पहले स्थान पर है। नए व उच्च गुणवत्ता के बाग लगाए जा रहे हैं। कई नई किस्में ईजाद की जा चुकी हैं। यही वजह है कि पिछले 10 साल में कैलिफोर्निया में अखरोट का उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है।

तदबीर से बदली तस्वीर : कैलिफोर्निया वालनट कमीशन की सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर पामेला ग्रेविएट ने कहा कि कश्मीर का जलवायु, तापमान, बारिश, चीलिंग आवर्स, मिट्टी भी कैलिफोर्निया की तरह की हो सकती है। लेकिन हमने लगातार रिसर्च के उपरांत नई किस्में तैयार की हैं। भारत में अखरोट के बड़े बाग नहीं हैं, जैसे हमने पिछले दो दशकों में तैयार कर दिए हैं। अखरोट की अच्छी फसल के लिए साल भर काम होता है। तोड़ने से लेकर अखरोट को धोने, सुखाने, तोड़कर गिरी निकालने और बाजार में पहुंचाने तक उच्चस्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि हमारे अखरोट की गिरी भारतीय गिरी से ज्यादा बेहतर रंग, खुशबू और स्वाद वाली है। वह कभी कसैले स्वाद की नहीं होती, क्योंकि हम नमी का पूरा ध्यान रखते हैं। यह तीन साल तक ताजा रह सकती है।

अच्छा करेंगे काम तो लहलहाएंगे बागान : जिस तरह से कैलिफोर्निया वालनट कमीशन अखरोट के उत्पादन, नई तकनीकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन, उसकी खपत बढ़ाने के लिए नए प्रयोग और वैश्विक स्तर पर प्रचार कर रहा है, उस तरह के प्रयास तो इन दो राज्यों में सेब के लिए भी नहीं किए जाते हैं। सेब को यहां बागवानी व अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। अच्छी प्रजाति के पौधों की नर्सरी विकसित करने, रूटस्टाक्स क्लस्टर तैयार करने, परागण में आने वाली समस्याओं को समझने और निदान करने की दिशा में भारत के बागवानी विशेषज्ञों को काम करने की जरूरत है।

अब दे रहे ध्यान : डॉ. जेएस चंदेल

डॉ. वाइएस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, हिमाचल के फल विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. जेएस चंदेल मानते हैं कि भारत में अखरोट की कम किस्में हैं। वह कहते हैं कि अब इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। कुछ किस्में आयात भी की गई हैं। उनका आकलन किया जा रहा है।

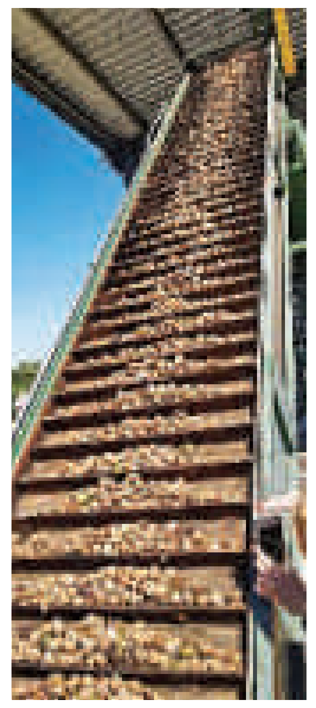

कैलिफोर्निया में अखरोटों की आधुनिक मशीनों से ग्रेडिंग, वाशिंग व ड्राईंग की जाती है। जागरण

निर्माण क्षेत्र में क्रांति के लिए तैयार एफआरपी

जागरण विशेष ▸ स्टील से हल्का और ज्यादा टिकाऊ है फाइबर रिइनफोर्स्ड पॉलीमर

रेल बोगी, बिजली के खंभे, रासायनिक टैंक व ओवरब्रिज तैयार करने में जुटी टाटा स्टील कंपनी

निर्मल प्रसाद, जमशेदपुर

पुल, ओवरब्रिज और अन्य ढांचागत निर्माण लोगों की जरूरत और विकास जुड़े हैं, लेकिन इनके निर्माण में लगने वाला समय भी एक बड़ी समस्या रहा है। सुदूर इलाकों में पुल व पुलिया निर्माण में एक से डेढ़ साल तक का समय लग जाता है। साथ ही बालू, सीमेंट, गिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी खूब दोहन होता है।

इसे ध्यान में रखकर टाटा स्टील के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग ने फाइबर रिइनफोर्स्ड पॉलीमर (एफआरपी) और ग्राफीन (जंगरोधी रसायन) की मदद से एक ऐसा उत्पाद तैयार किया है जो बेहद हल्का होने के साथ काफी टिकाऊ भी है। कंपनी ने जमशेदपुर स्थित कंपनी परिसर और शावक नानावटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इससे दो पैदल पुल तैयार किए हैं। दोनों पुल तीन माह से भी कम अवधि में तैयार किए गए हैं।

कंपनी इस नए उत्पाद का पेटेंट भी करा चुकी है। इस धातु से रेल की बोगियां, रासायनिक टैंक समेत धातु से बनने वाले तमाम उपकरण कम समय और कम लागत में बन जाएंगे। साथ ही इससे पुल, पुलिया और ओवरब्रिज का बनना निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। टाटा स्टील (जमशेदपुर) के प्रवक्ता का कहना है कि औद्योगिक, इलेक्ट्रिक और कंप्यूटर क्रांति के बाद हम नए उत्पाद के क्षेत्र में चौथी क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। हम एफआरपी और ग्राफीन की मदद से उत्पादों को रिसाइकिल कर नए उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जो काफी टिकाऊ है और जल्द तैयार भी हो जाता है।

झारखंड के जमशेदपुर में शावक नानावटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रिइंफोर्स्ड पॉलिमर कम्पोजिट (एफआरपी) और ग्राफीन से तैयार पैदल पुल। जागरण

कई स्टील उत्पादों पर भी चढ़ाया जा रहा ग्राफीन का लेप : कंपनी प्रबंधन का दावा है कि यह स्टील की तरह मजबूत तो होगा ही, लेकिन बहुत हल्का भी होगा। इसे किसी भी आकार में बदला जा सकता है। यह स्टील की तुलना ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करने में सक्षम भी होगा। टाटा स्टील ने ग्राफीन के उत्पाद का बाजार तैयार करने के लिए जमशेदपुर में छोटे पैमाने पर एक प्लांट स्थापित किया है। कंपनी अपने कुछ स्टील उत्पाद पर ग्राफीन का लेप लगा रही है जो उसके जीवनकाल को बढ़ाने में मदद करता है। टाटा स्टील में इस्तेमाल किए जाने वाले ग्राफीन मिश्रित प्लास्टिक और अन्य उत्पाद मौजूदा उत्पादों की तुलना में दोगुना चलते हैं। साथ ही ज्यादा दबाव झेलने में सक्षम भी हैं।

कम समय के कारण लागत भी कम : ग्राफीन एक प्रकार का केमिकल है। इसे जंगरोधी माना जाता है। यह महंगा उत्पाद है। टाटा स्टील प्रबंधन का मानना है कि बालू, गिट्टी और सीमेंट से बनने वाले पुल व पुलिया की तुलना में एफआरपी से बने पुल-पुलिया का निर्माण जल्दी संभव है।

इसमें मानव श्रम का इस्तेमाल कम होता है। इस कारण लागत में कमी आ जाती है। टाटा प्रबंधन ने फिलहाल प्रायोगिक तौर पर इसका निर्माण शुरू किया है। प्रबंधन का कहना है कि यह धातु भी कम कीमत में ही उपलब्ध होगी। लेकिन जब यह बाजार के लिए तैयार होगा तभी बताया जा सकता है कि परंपरागत पुल व एफआरपी पुल निर्माण की लागत पर सही-सही कितना अंतर आएगा।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

अब पता चलेगी उत्तराखंड में मौजूद गुलदारों की संख्या

केदार दत्त, देहरादून : उत्तराखंड में गुलदारों की वास्तविक संख्या कितनी है अब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद इससे पर्दा उठेगा। 2015 के बाद अगले साल प्रदेश में होने वाली वन्यजीव गणना में स्पष्ट होगा कि इनकी संख्या बढ़ी है या घटी अथवा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गुलदार हैं। फिर इसके आधार पर संबंधित क्षेत्रों में गुलदार-मानव संघर्ष थामने को कार्ययोजना तैयार कर धरातल पर उतारी जाएगी। राज्य में वन्यजीवों की गणना हर साल हो, इसके लिए प्लान भी तैयार किया जा रहा है।

वन्यजीवों के हमलों को देखें तो गुलदारों ने पहाड़ से लेकर मैदान तक नींद उड़ाई हुई है। आए दिन इनके हमलों की घटनाएं सुर्खियां बन रही हैं। स्थिति ये हो चली है कि गुलदार घरों के भीतर तक धमकने लगे हैं। ये ऐसे घूम रहे,

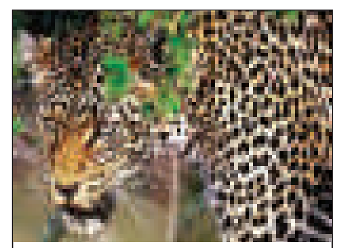

राज्य में गुलदार

गणना वर्ष	संख्या
2003	2092
2005	2105
2008	2335

मानो पालतू जानवर हों। सूरतेहाल, राज्यवासी खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं। वन्यजीवों के हमलों में करीब 85 फीसद घटनाएं गुलदारों की हैं। ऐसे में माना जा रहा कि हर परिस्थिति में खुद को ढालने वाले गुलदारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इनके बढ़ते हमलों के पीछे ये बड़ा कारण बताया जा रहा। हालांकि, ये बात अलग है कि राज्य में वर्ष 2008 के बाद से अब तक गुलदारों की गणना ही नहीं हुई है। तब इनकी संख्या 2335 थी। इसके बाद इनकी वास्तविक संख्या व सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्रों का पता न चलने से गुलदार-मानव संघर्ष थामने को ठोस पहल नहीं हो पा रही है।

अब गुलदारों की वास्तविक संख्या का जल्द ही पता चल जाएगा। राज्य में अगले साल वन्यजीवों की गणना के लिए कसरत शुरू कर दी गई है। इसमें मुख्य फोकस गुलदारों की गणना, सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्रों पर रहेगा।

राज्य स्तर पर वन्यजीव गणना में निरंतरता बनाए रखने को कदम उठाए जा रहे हैं। अगले वर्ष प्रदेशभर में वन्यजीवों की गणना की जाएगी। इसमें गुलदार समेत दूसरे वन्यजीवों की सही संख्या सामने आएगी। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही कि गणना का कार्य हर साल हो।

– राजीव भरतरी, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड

'एपल मैन' ने दी चमोली की नीती घाटी को नई पहचान

रणजीत सिंह रावत, जोशीमठ (चमोली)

जेठ के उमसभरे दिन हों या सावन-भादौ की झमाझम पड़ती बौछारें अथवा पौष की हाड़ कंपाने वाली ठंड, भारत-चीन सीमा से लगी चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक की रोंग्पा-नीती घाटी के जेलम गांव में एक बुजुर्ग आपको सेब के बागीचों की रखवाली करते मिल जाएगा। 74-वर्षीय इस शख्स का नाम है इंद्र सिंह बिष्ट, लेकिन घाटी में लोग इन्हें 'एपल मैन' के नाम से ज्यादा जानते हैं। इंद्र सिंह की हाड़तोड़ मेहनत का ही नतीजा है कि वह हर साल सेब बेचकर सात से आठ लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर घाटी के अन्य काश्तकार भी बागवानी के प्रति प्रेरित हो रहे हैं।

चमोली की नीती घाटी के जेलम गांव निवासी इंद्र सिंह बिष्ट, जिन्हें लोग एपल मैन के नाम से जानते हैं। जागरण

इंद्र सिंह को सेब के इस बागीचे को तैयार करने में दस साल लगे। इस अवधि में तमाम विपरीत परिस्थितियां भी उनका हौसला नहीं डिगा पाईं। इंद्र सिंह के संघर्ष की कहानी पिछली सदी के नौवें दशक से शुरू होती है। वर्ष 1988 में उन्होंने यहां-वहां से कर्ज लेकर 20 हजार रुपये का इंतजाम किया।

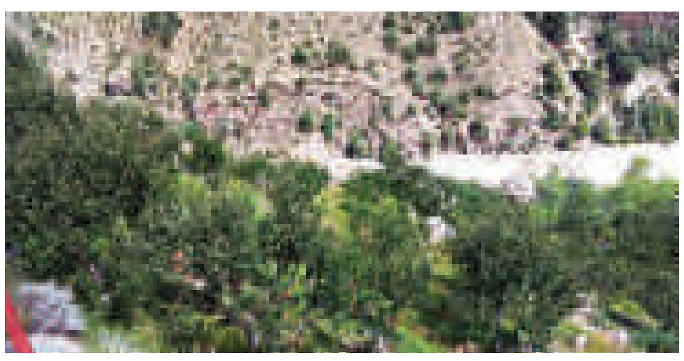

चमोली की नीती घाटी के जेलम गांव में इंद्र सिंह बिष्ट का लगाया हुआ एपल गार्डन। जागरण

इस राशि से उन्होंने जेलम गांव में बंजर पड़ी भूमि पर सेब के सौ पौधे लगाए। तब ग्रामीणों ने उनकी इस पहल का मखौल उड़ाते हुए कहा था कि यहां सेब के पौधे कैसे हो सकते हैं। लेकिन, इंद्र सिंह ने हार नहीं मानी और ठीक दस साल तक इन पौधों की बच्चों की तरह परवरिश की। आज उनकी दो हेक्टेयर भूमि पर 400 से अधिक सेब, नाशपाती व बादाम के पेड़ लहलहा रहे हैं।

बकौल इंद्र सिंह, 'ये दस साल मेरे जीवन के सबसे संघर्षमय साल थे। वर्ष 1998 में मुझे पहली खुशी तब मिली, जब सेब के पेड़ों ने फल देना शुरू किया। फिर तो मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज 31 साल बाद मेरे पास अच्छा-खासा मुनाफा देने वाला सेब का एक भरा-पूरा बागीचा है। सीजन से पहले ही मेरे पास सेब की डिमांड आ जाती है। कभी-कभी तो मैं डिमांड पूरी भी नहीं कर पाता।'

शीतकाल के दौरान भी अकेले ही करते हैं बागीचे की देखभाल : इंद्र सिंह इस काम में पुत्रों की भी मदद नहीं लेते। उन्हें सभी कार्य स्वयं ही करने में आनंद आता है। शीतकाल में जब भोटिया जनजाति के लोग माइग्रेशन कर चमोली जिले के निचले इलाकों में छह महीने के प्रवास पर आ जाते हैं, तब भी इंद्र सिंह गांव में ही डटे रहते हैं। कहते हैं, शीतकाल में जंगली जानवर सेब के पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वह इस अवधि में भी गांव में ही रहकर बागीचे की देखभाल करते हैं।

सेब की छह प्रजाति की हैं विकसित : इंद्र सिंह ने अपने बागीचे में सेब की रॉयल डेलिसस, रेड डेलिसस, गोल्डन डेलिसस, राइमर, स्पर और हेरिसन प्रजाति विकसित की हैं। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाली नाशपाती और बादाम के पेड़ भी उनके बागीचे में हैं, जो उन्हें अच्छी-खासी आमदनी देते हैं।

74 वर्ष की उम्र में सेब के उत्पादन से कर रहे हर साल सात से आठ लाख रुपये की कमाई

इंद्र सिंह पूरी नीती घाटी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। जेलम में जो सेब पैदा होता है, उसकी मिठास व गुणवत्ता का कोई जवाब नहीं। वह सेब के पेड़ों पर रसायनों का छिड़काव भी नहीं करते। जेलम का सेब पूरी तरह जैविक सेब है। इंद्र सिंह से प्रेरणा लेकर नीती घाटी के कई लोग सेब उत्पादन करने लगे हैं।

– डीपी डंगवाल, उद्यान निरीक्षक, तपोवन (चमोली)

छग में बाघों को बसाने के लिए 19 गांव खाली कराने की तैयारी

श्रीशंकर शुक्ला, रायपुर

छत्तीसगढ़ में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए वन विभाग ने पन्ना अभयारण्य की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। वन विभाग ने बाघों के वास स्थल को और विकसित करने के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया के लिए शासन को पत्र लिखा है। अचानकमार से कुल 19 गांवों के लोगों को विस्थापित किया जाना है। विस्थापित होने वाले 3,634 परिवारों को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तय मानक के अनुसार राशि या फिर खेतीबाड़ी करने के लिए जमीन और मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। उल्लेखनीय कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में बाघों की गणना के बाद संख्या जारी की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंतनीय मिली। यहां बाघों की संख्या 46 से घटकर 19 पहुंच गई है। घों की संख्या बढ़ाने में मदद के लिए मध्यप्रदेश के एपीसीसीएफ दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। उन्होंने जंगलों में जाकर बारीकी से अध्ययन कर अचानकमार के 626 किलोमीटर के अंतर्गत कोर इलाके के अंतर्गत आने वाले गांवों को पुनर्वास करने की बात कही थी। उसके बाद वन विभाग ने गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वन विभाग बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश से बाघों को लाने की तैयारी कर रहा है। मध्यप्रदेश से बाघों को लाकर जंगल में ब्रीडिंग कराई जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पन्ना अभयारण्य, बांधवगढ़ या कान्हा से बाघ लाने की योजना विभाग बना रहा है।

प्रदेश में बाघों की संख्या वर्ष वार

वर्ष	संख्या
2006 में	26
2010 में	26
2014 में	46
2018 में	19

प्रत्येक परिवार को मिलेगा मुआवजा : वन ग्रामों का व्यवस्थापन राष्ट्री व्याघ्र संरक्षण, प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार पात्र परिवार को 10 लाख रुपये दिया जाना है। यदि परिवार पैसा नहीं चाहता है तो दूसरे विकल्प के रूप में प्रत्येक परिवार को एक मकान, 02 हेक्टेयर कृषि भूमि, 50 हजार इंसेटिंव की राशि मिलेगी। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने पर विस्थापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बदलती तस्वीर

कभी हाथों में थी बंदूक, अब स्वावलंबन की बनीं मिसाल

मुख्यधारा में लौटी आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने शुरू की मशरूम की खेती, बनीं परिवार का सहारा

मनोज चेलक, राजनांदगांव

जिन हाथों में कभी बंदूक गरजती थी, आत्मसमर्पण के बाद आज उन्हीं हाथों से पूर्व महिला नक्सली मशरूम का उत्पादन कर समाज के सामने मिसाल पेश कर रही हैं। लाल आतंक की दुनिया से त्रस्त होकर मुख्यधारा से जुड़ने के बाद ये महिला नक्सली समाज को यह दिखा रही हैं कि वे वक्तके साथ खुद को ढालना जानती हैं। वे भी एक आम इंसान हैं, जो मेहनत की रोटी कमाना चाहती हैं। खास बात यह कि उनके द्वारा पैदा किया जा रहा मशरूम पुलिस विभाग के लोग ही खरीद ले रहे हैं। इससे अभी उनके सामने बाजार का संकट नहीं है। हालांकि, विभाग इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है कि उत्पादन बढ़ते ही वे बाजार भी तैयार कर लेंगे।

उर्मिला साहू (2011 में सरेंडर), सुनीता पद्दा (2012 में सरेंडर), कमला कुरामे (2014 में सरेंडर), सुशीला, शिल्पा, मीना (2019 में सरेंडर) आदि कभी नक्सली थीं। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन नक्सल संगठन में रहते हुए उन्होंने आतंक फैलाने से परहेज नहीं किया। अंततः उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, उन्होंने संगठन में देखा कि वहां भी न्याय नहीं है। इतना ही नहीं, नक्सली लीडर की प्रताड़ना भी भारी पड़ने लगी। इन्होंने मुख्यधारा में लौटना ही मुनासिब समझा। आज ये महिलाएं समाज की अन्य महिलाओं की तरह न सिर्फ सम्मान की जिंदगी जी रही हैं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार को आर्थिक सुदृढ़ता भी प्रदान कर रही हैं। इन महिलाओं का मकसद है मेहनत की रोटी खाना।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मशरूम उत्पादन करने वाली आत्मसमर्पित महिला नक्सली। नईदुनिया

अच्छी छवि बनाना थी चुनौती : आत्मसमर्पित नक्सली उर्मिला साहू ने बताया कि मुख्यधारा में लौटने के बाद समाज के सामने अच्छी छवि बनाना और अपने पैरों पर खड़े होना बड़ी चुनौती थी। पुलिस विभाग ने इसमें सभी की खूब मदद की। आज उनकी बदौलत ही हम आमदनी कर परिवार की ताकत बने हुए हैं।

आत्मविश्वास बढ़ा : सुनीता और कमला ने बताया कि मशरूम उत्पादन से फिलहाल बड़ी आमदनी नहीं हो रही है, लेकिन इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्होंने बताया कि समाज हमें उम्मीदों से ज्यादा दे रहा है।

पहले प्रशिक्षण दिया, फिर जगह : एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया कि पहले इन महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। फिर पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे वाली जगह दे दी गई, जहां ये मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। मशरूम की फसल बीज डालने के करीब 22 दिन बाद बाजार में बेचने लायक तैयार हो जाती है। इस बार उत्पादन कम कर रहे हैं, इसलिए रोजाना तीन से पांच किलोग्राम तक मशरूम निकल रहा है। यह 200 रुपये प्रति किलो की दर से बिकता है। अभी तो विभाग के लोग ही सब खरीद लेते हैं। उत्पादन बढ़ते ही इनके लिए हम बाजार की व्यवस्था भी कर देंगे।

सरेंडर नक्सली मशरूम का उत्पादन कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। हम उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का हर प्रयास करेंगे। मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों का पुलिस पूरा सहयोग कर रही और आगे भी करती रहेगी।

– कमलोचन कश्यप, एसपी राजनांदगांव

कुरान व हदीस के साथ बच्चों को दे रहे गोसेवा की तालीम

नईदुनिया, भोपाल

गोसेवा के नाम पर विरोध और हिंसा की घटनाएं अपनी जगह हैं और खामोशी से उनकी सेवा का मुकाम अलग है। गोसेवा का अलहदा अंदाज मध्य प्रदेश के एक मदरसे में दिखता है। भोपाल रेलवे स्टेशन से करीब 25 किलोमीटर दूर ग्राम तूमड़ा में जामिया इस्लामिया अरबिया मदरसे में गायों का पालन-पोषण किया जा रहा है।

मदरसे में करीब 200 बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा के साथ गोसेवा की तालीम भी दी जा रही है। वर्ष 2003 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुफ्ती अब्दुल रज्जाक ने मदरसे में गोशाला शुरू की थी। करीब 60 एकड़ में फैले मदरसा परिसर में गोशाला के लिए टीन का शेड तैयार किया गया। शुरुआत एक गाय से हुई, लेकिन अब यहां 20 गाय हैं। जर्सी व देसी नस्ल की इन गायों की देखरेख के लिए दो कर्मचारी नियुक्त हैं। बच्चों को भी गोसेवा की तालीम दी जाती है और वे भी इन देखरेख करते हैं। मदरसा संचालक मौलाना मोहम्मद अहमद ने बताया कि पिता मुफ्ती अब्दुल रज्जाक इंसानों के साथ जानवरों से भी मोहब्बत करने की सीख देते हैं। वे 95 साल की उम्र में आज भी गोशाला में गायों को देखने आते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसे के करीब 13 शिक्षक बच्चों को गोसेवा के साथ कंप्यूटर की तालीम भी दे रहे हैं। यहां बच्चों को उर्दू के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाती है। गोसेवक मोहम्मद एजाज बताते हैं कि एक मदरसा मोती मस्जिद के पास है तो दूसरा तूमड़ा गांव में। दोनों में करीब 700 बच्चे हैं। गोशाला का सारा दूध यही बच्चे पीते हैं।

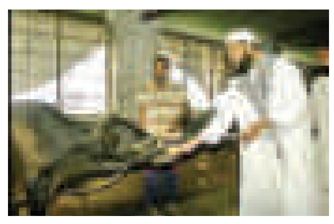

मदरसे में गाय को रोटी खिलाते मुफ्ती जियाउल्ला कासमी। जागरण

दैनिक जागरण
सबरंग

प्लान वीकेंड के

नई दिल्ली, शुक्रवार, 11 अक्टूबर, 2019

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

...जब छात्र के सपने में पूरी हुई बाबर की औलादों की तलाश

- दिल्ली कार में बैठकर नहीं बाइक पर बैठकर दिखती है
- अभिनेता टॉम ऑल्टर की दूसरी पुण्यतिथि पर हुआ नाटक का मंचन
- बाबर की औलादें नाटक के 52 शो में मुख्य भूमिका में दिखे थे टॉम ऑल्टर

दर्शकों के भाव से अभिव्यक्ति से स्पष्ट हो रहा था कि वे आज भी 'बाबर की औलादें' नाटक को टॉम ऑल्टर की याद में देखने आए हैं। खचाखच भरा ऑडिटोरियम इस बात की गवाही देने के लिए काफी था। दर्शक चाहते थे कि नाटक के बहाने ही एक बार टॉम की स्मृतियां भी दिख जाएं। वही हुआ भी एक स्क्रीन पर टॉम द्वारा अब तक 52 बार नाटक 'बाबर की औलादें' के मंचन से जुड़ी ऑल्टर की तस्वीरें देखने को मिल रही थीं। सबरंग के इस अंक में टॉम की स्मृतियां और नाट्य मंचन प्रस्तुति से रूबरू करा रहे हैं **संजीव कुमार मिश्र :**

नाट्य मंचन

ऑडिटोरियम में यूं तो मंचन बाबर की औलादें नाटक का हो रहा था लेकिन दर्शकों में टॉम ऑल्टर के प्रशंसकों का उत्साह ज्यादा दिख रहा था। स्टेज से सटे स्क्रीन पर ऑल्टर का चेहरा उभरा तो दर्शक अपने आपको रोक नहीं पाए। तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। पद्मश्री टॉम ऑल्टर मानों दर्शकों से बातें कर रहे थे। यह नाटक ऑल्टर के पसंदीदा नाटकों में से एक था। इसके 52 शो में वो खुद बतौर लीड रोल दर्शकों से मुखातिब हुए थे। अवसर भी ऐसा था जहां 29 सितंबर को ऑल्टर की दूसरी पुण्य तिथि थी तो 10 अक्टूबर को बाबर की औलादें का प्रीमियर हुए 9 साल भी पूरे हो गए।

नाटक शुरू होता है तो स्क्रीन के एक कोने में ऑल्टर बैठे दिखते हैं। उनके साथ युवा है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। दरअसल, यह युवा दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है। छात्र, मुगल खासकर बहादुर शाह जफर पर रिसर्च करना चाहता है। बस इसी इच्छा से डीयू प्रशासन से बहादुर शाह की कब्र पर जाने की इजाजत मांग लेता है लेकिन प्रशासन को यह बात समझ नहीं आती कि आखिर रिसर्च करने के लिए कब्र पर जाने की क्या जरूरत है? किसी और स्मारक पर जाकर रिसर्च पूरी करने की हिदायत दी। लेकिन अब कहते हैं न जब आपकी इच्छाओं में छटपटाहट होती है तो सपने भी उन्हीं चीजों के आने शुरू हो जाते हैं। उस छात्र के साथ भी वैसा हो गया और बहादुर शाह जफर उसके सपने में आने लगे।

निर्देशक डॉ एम सईद आलम बताते हैं कि ये दोनों एक तरह के नाटक के सूत्रधार थे। टॉम वाला दृश्य हमने स्क्रीन पर दिखाया। दरअसल, इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि जब बहादुर शाह का रोल होता था तो स्टेज पर कोई नहीं होता था। और जब स्टेज पर कोइ पात्र होता था तो बहादुर शाह नहीं होते थे। करीब 8-10 सीन बहादुर शाह के थे। छात्र, सपने में रंगून में बहादुर शाह से बात करता है। वह उनसे 1857 की क्रांति को लेकर सवाल पूछता है। लेकिन छात्र का मुख्य सवाल बाबर और बाबर की औलादों के बारे में था। वो बहादुर शाह से पूछता है कि बाबर की औलादें भारतीय थीं या नहीं? सवाल के जवाब में बहादुर शाह छात्र को पूरा मुगल इतिहास ही बता देते। वो बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के मुगल बादशाहों के बारे में बताते हैं और अंत में यह भी बता देते हैं कि मैं विदेशी था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि कोई विदेशी भारत में आकर बस जाए तो क्या वो विदेशी कहलाएगा? वो छात्र से कहते हैं कि तुमने पूरा इतिहास समझ लिया। अब ये तुम तय करो कि भारतीय थे या नहीं? 1857 में जब अंग्रेजों से लोहा लेना था तो जिस शासक को शहंशाह चुना गया वो बहादुर शाह जफर ही थे। यानी, इस समय तक लोगों ने बहादुर शाह जफर को भारतीय मान लिया था। नहीं तो कोई क्यों एक विदेशी शासक को भगाने के लिए दूसरे विदेशी का सहारा लेता क्या?

नाटक में बहुत तटस्थता से मुगल बादशाहों का आकलन किया गया है। जैसे, एक दृश्य है जिसमें कहा जाता है कि अकबर बहुत बड़ा सेक्युलर है? तो फिर क्यों नहीं उसने अपनी बहन, बेटियों की शादी किसी हिंदु से की। क्यों सिर्फ हिंदु राजाओं की बेटियों आदि से शादी की। दरअसल यह सेक्युलरवाद से ज्यादा युद्ध से बचने की जुगत थी। युवक से बातचीत के दौरान बहादुर शाह को लगता है कि बहुत अनर्थ हो गया। वो युवक से कहते हैं कि तुम वापस जाओ। तुम 150 साल पीछे नहीं आ सकते। हालांकि, जब छात्र वापस जा रहा होता है तो बहादुर शाह उससे एक गुजारिश करते हैं। कहते हैं, भारत में जाकर लोगों से कहना कि वो मुझे हिंदुस्तान का आखिरी मुगल बादशाह ना कहें बल्कि लोकतांत्रिक भारत का पहला बादशाह कहें। क्योंकि मैं सर्वसम्मति से बादशाह घोषित किया गया था। इसके बाद सपने में ही छात्र से कहते हैं कि तुम वापस जाओ। हम दोनों को अपनी दरो-दयार में रहना चाहिए। मुगल विदेशी थे? उसकी औलादें भारतीय थीं या विदेशी? इसका निर्णय इतिहासकार व लोग करेंगे। और इसी के साथ पर्दा गिर जाता है।

चाय...चुटकुले और टॉम

नाटक में गंभीर अभिनय से इतर टॉम निजी जिंदगी में हंसमुख थे। वो चाय पीते समय चुटकुले सुनाते थे। क्रिकेट पर तो घंटो बातें करते थे। राजनीति पर भी बातचीत पसंद थी। स्टेज पर वक्त गुजारना उन्हें पसंद था। कहते थे, यदि पांच-छह घंटे स्टेज पर गुजार लें तो एक्टिंग बहुत ही नेचुरल होती है। हमेशा हंसते रहने वाले टॉम नाटक शुरू होने के 20 मिनट पहले सीरियस हो जाते थे। ग्रीन रूम में जाते एवं फिर स्टेज पर दमदार अभिनय करते। दिल्ली में बाइक पर घूमना उन्हें पसंद था। कहते थे, दिल्ली की खूबसूरती को बाइक पर बैठकर देखने में जो मजा है वो कार में बैठकर नहीं आता। निजामुद्दीन में उन्हें जायके का आनंद उठाना पसंद था। सनद रहे कि 2017 में कैंसर की वजह से टॉम का निधन हो गया था।

शानदार व्यक्तित्व के धनी थे ऑल्टर : ऑल्टर से जुड़ी यादें दर्शकों के जेहन में ताजा हो आ आती हैं। बकौल डॉ एम सईद आलम, यह बाबर की औलादें नाटक का 59वां शो था। 58वें शो में बहादुर शाह जफर का किरदार एम सईद आलम ने ही निभाया था। बकौल सईद बाबर की औलादें का प्रीमियर 10 अक्टूबर, 2010 को फिक्की ऑडिटोरियम में हुआ था। जब पहली बार टॉम को बाबर की औलादें नाटक में बहादुर शाह जफर का रोल ऑफर किया गया था तब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? यह पूछने पर निर्देशक एम सईद कहते हैं कि यहां उल्टा हुआ था। हुआ यूं कि सलमान खुर्शीद रोल ऑफर करने के लिए टॉम ऑल्टर के पास पहुंचे। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और हामी भर दी लेकिन एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि नाटक का निर्देशक मैं यानी डॉ एम सईद आलम ही करेंगे। यानी, टॉम की वजह से मुझे इसके निर्देशन का मौका मिला। टॉम इस रोल के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। उनकी उर्दू पर जबरदस्त पकड़ थी। धारा प्रवाह बोलते थे। बेहतरीन शायरी की समझ थी। ऐसे ही अभिनेता की तो तलाश की जा रही थी। हां, एक चीज जो बहुत कम लोगों को पता है वो यह कि बहादुर शाह जफर बहुत गोरे नहीं थे जबकि टॉम बिल्कुल श्वेत थे। बाकि टॉम शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। हमेशा हंसते, मजाक करते रहना उनकी आदत थी। वे मुझे कहते कि मैं जानबूझकर उन्हें ऐसा रोल देता हूं जिसमें मेकअप का पैसा बचे। दरअसल, वे बहादुर शाह का रोल कर रहे थे। दाढ़ी सफेद थी, बाल उनके नेचुरल थे ही। इस तरह मेकअप पर बहुत ध्यान नहीं देना होता था।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने इंग्लिश प्रोडक्शन भी किया। हालांकि वो रोमन से बहुत चिढ़ते थे। कहते थे रोमन में सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ी जा सकती है। इसलिए वो स्क्रिप्ट सिर्फ उर्दू में पढ़ते थे। मुझे इसके लिए विशेष रूप से एक प्रति उर्दू में तैयार करानी पड़ती थी। हालांकि अंग्रेजी शो उन्हें खुद पसंद नहीं आया। वे कहते थे, बड़ा अजीब लगता है। शहंशाह के सिर पर ताज है, वो बादशाहों के ड्रेस में है लेकिन जुबां अंग्रेजी बोले। हां, यदि विदेश में शो हो तो अंग्रेजी ठीक है, दिल्ली में बाबर की औलादें अंग्रेजी में नहीं जंचता।

इस बार यहां चलें

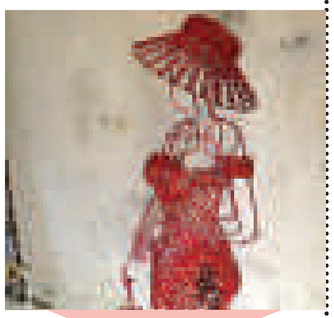

नवीनतम लोककला

डीकोडिंग पैट्रिआर्कल कोड्स आर्टिस्ट गोपाल नाम जोशी के सहयोग से अपनी नवीनतम लोक कला परियोजना शुरू कर रहा है। जिसमें घटना, प्रदर्शनी और वार्तालापों की एक श्रृंखला संभव समाधान की ओर मुद्दे के साथ आगे बढ़ती है को दर्शाया गया है। यह विभिन्न कॉलेजों और कार्यक्रम स्थल पर आयोजित की जा रही है।
- **कहां** : इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड।
- **कब** : 5-20 अक्टूबर, सुबह 11 से शाम छह बजे तक।
- **प्रवेश**–निश्शुल्क

पत्ते खुल गए

राकेश बेदी द्वारा लिखित एक दम मौलिक, मजेदार और बेहद सधे अभिनय वाला मास्टर पीस, 'पत्ते खुल गए' मध्यवर्गीय समाज की विसंगतियों को बेहद मजेदार अंदाज में उजागर करता है। दिल को गुदगुदाने वाली इस कॉमेडी में बॉलीवुड के ग्लैमर का भरपूर तड़का है। इसमें अनंत महादेवन, रूपाली गांगुली, किश्वर मर्चेंट, अविजीत दत्त, ज्योति सिंघल और राकेश बेदी का अभिनय देखने को मिलेगा।
- **कहां** : कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस। • **कब** :12 अक्टूबर, शाम चार बजे एवं शाम सात बजे। • **प्रवेश** : टिकट 399 से शुरू, ऑनलाइन बुकिंग द्वारा।

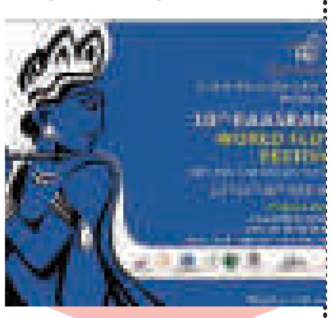

विश्व बांसुरी महोत्सव

10वां रसरंग विश्व बांसुरी महोत्सव का आगाज होने वाला है। इसमें आनंजनेय जोशी, पंडित चेतन जोशी, पंडित आशीष सेन गुप्ता, पंडित अजय प्रसन्ना, दर्पण राम, दिग राम समेत कई अन्य प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति होगी। शांति को समर्पित यह महोत्सव विश्व बंधुत्व और शांति के अग्रदूत के रूप में आयोजित हो रहा है।
- **कहां** : नेहरु पार्क, चाणक्यपुरी।
- **कब** : 11 से 13 अक्टूबर, शाम छह बजे से। • **प्रवेश** : आमंत्रण द्वारा।

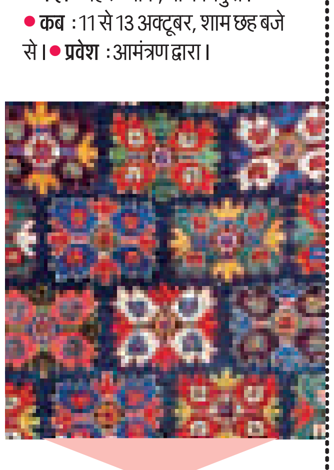

कालीन की कहानियां

प्राचीन सिल्क रोड की कालीन कहानियां प्रदर्शनी के जरिए दर्शकों के सम्मुख रखी जाएगी। ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान की 19 वीं और 20 वीं शताब्दी की जनजातीय बुनाई का संग्रह कलाकृतियों के जरिए दर्शाया गया है। कालीन के जरिए विभिन्न समाज का अध्ययन किया गया है।
- **कहां** : विजुअल आर्ट गैलरी, इंडिया हैबिटेट सेंटर। • **कब** : 7-13 अक्टूबर, सुबह 11 से शाम छह बजे तक। • **प्रवेश** : निश्शुल्क।

अवध को जियेगी दिल्ली करीब से

कला उत्सव

दिल्ली हमेशा कुछ नए की तलाश में रहती है। मनोरंजन के लिए भी हर सप्ताह कुछ नया और रचनात्मक तलाशती है। इस वीकेंड कुछ ऐसा ही खास आयोजन इंडिया इंटरनेशन सेंटर में होने जा रहा है। जहां इस 16वें आर्ट फेस्टिवल में अवध की कला-संस्कृति दिल्ली वालों के दिल में बड़ी संजीदगी के साथ उतर जाएगी। फेस्टिवल में कला जगत की प्रसिद्ध हस्तियां तो शिरकत करेंगी ही युवा कलाकारों की प्रस्तुति देख मन प्रसन्न हो जाएगा। पांच दिवसीय फेस्टिवल का आगाज 11 अक्टूबर यानी आज से होगा।

जानें कला की बारीकियां : एक साथ एक ही जगह पर विविध कलाओं को देखने, उनकी बारीकियों को जानने का वाकई अद्भुत अवसर मिल रहा है। यहां दर्शक नृत्य, संगीत (भारतीय, पश्चिमी शास्त्रीय और जैज), थिएटर, लोक कला, पेंटिंग, इंस्टॉलेशन और फोटोग्राफी प्रदर्शनी के जरिये काफी कुछ सीख सकेंगे। फेस्टिवल की पहली प्रस्तुति मैजिक इन मूवमेंट होगी। जिसमें रुद्राक्ष फाउंडेशन, भुवनेश्वर के पुरुष कलाकार ओडिशी नृत्य प्रस्तुत करेंगे। अन्य प्रस्तुतियों की बात करें तो बोसा नोवा टू सांबा में गीत-कहानियां और थिएटर होगा। फेस्टिवल का समापन कार्नेटिक कंसर्ट से होगा। थोदुर मदाबुसी कृष्ण कर्नाटक संगीत गायक हैं। दिल्ली वाले हमेशा ही इन्हें सुनना चाहते हैं।

अवध की विरासत से हों रूबरू : फेस्टिवल का खास आकर्षण लखनऊ आधारित प्रस्तुति है। इसके तहत अवध से चांद वर्क नाम से प्रदर्शनी लगेगी। जिसमें लखनऊ की धनी समधर्मी संस्कृति, भूत एवं वर्तमान की समृद्ध और ऐतिहासिक विरासत को दर्शकों से रूबरू कराया जाएगा। यह प्रदर्शनी दो हिस्सों में बंटी होगी। पहला हिस्सा फोटोग्राफ, आर्टक्राफ्ट, आर्काइवल टेक्सटाइल, किताब, विविधता का जश्न मनाते पत्रों, लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों को समेटे होगी। जबकि हुस्न-ए-कारीगरी-ए-अवध में शिल्प परंपरा से ना केवल रूबरू कराया जाएगा, कलाकारों की लाइव प्रस्तुति भी देख सकेंगे। इसमें शिल्प परंपरा के तहत शिल्पकारों की भी बात होगी। उन कलाकारों का भी जिक्र होगा, जिन्होंने कला को सहेजा है। जिन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया एवं घर घर तक पहुंचाया है। शिल्प प्रदर्शन के तहत टुकड़ी का काम, चिकनकारी, मूर्तिकार, कैलिग्राफी को बनाकर कलाकार दर्शकों को इनकी बारीकियां भी बताएंगे। प्रदर्शनी का एक अहम पहलू लखनऊ की नारीवादी लेखिकाओं पर होगा। फेस्टिवल में सोज ख्वानी की प्रस्तुति होगी।

और मिलेगा विशेष जायका भी : अवधी कला संस्कृति बिना जायके के अधूरी है। इसलिए अवधी बावर्ची खाना भी यहां दर्शकों के लिए हाजिर होगा। जिसे लखनऊ के प्रसिद्ध नेमत खाना द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य प्रदर्शनी भी दर्शकों को पसंद आएगी। यह प्रदर्शनी इंडियन आर्ट फ्रॉम 20 सेंचुरी शीर्षक से लगेगी। इसमें प्रगतिशील कलाकारों के बारे में बताया जाएगा। इसे विजय कौशिक एवं गोगी सरोज ने क्यूरेट किया है। प्रदर्शनी बांबे प्रोग्रेसिव ग्रुप के कलाकारों से दर्शकों का परिचय करवाएगी।

–संजीव कुमार मिश्र

- **कहां** : इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोदी रोड।
- **कब** : 11-15 अक्टूबर, सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

जी भर सुनें किस्से-कहानियां

कहानी समारोह

किस्से कहानियों का दौर चल रहा हो और उसमें अपने देश के साथ पोलैंड, स्वीडन, रोमानिया सरीखे देशों की दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलें। वह भी बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी में, वाकई बेहद ज्ञानवर्धन के साथ उत्साह भरा सप्ताहांत बीतेगा। मतलब आप तीन दिन जी भर किस्म-किस्म की ऐतिहासिक कथाएं सुन सकेंगे। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर किस्से कहानियों की महफिल सजने जा रही है। नौवें कथाकार अंतरराष्ट्रीय कहानी समारोह का आगाज शुक्रवार यानी आज से होगा। जिसमें विदेशी कहानीकार तो होंगे ही भारतीय सिनेमा जगत के जाने-माने अभिनेताओं से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा।

किस्से संग लोक संगीत का भी आनंद : सुंदर नर्सरी में आयोजित होने वाले इस कथाकार समारोह में भारत, पोलैंड, आस्ट्रेलिया, स्वीडन, रोमानिया, मंगोलिया, लुथिनिया और यूनाइटेड किंगडम की कहानियां सुनाई जाएंगी। समारोह इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसमें विदेशी कहानीकार भारतीय कहानियां सुनाएंगे। फेस्टिवल में पोलैंड के तातर फोक सिंगर पहली बार भारत में प्रस्तुति देंगे। पोलिश फोक सिंगर सिछा एवं पैलगा भी वहां के लोकगीत सुनाने आएंगे। इतना ही नहीं किस्से कहानियों के इस मंच पर पहली बार आदिवासी कहानीकार अंकल लैरी वॉल्श भी हिस्सा लेंगे।

बॉलीवुड सितारों से जानेंगे पर्दे के पीछे की कहानी : पहले दिन यूके की कहानीकार एमिली काली : प्राचीन भारत की कहानी सुनाएंगी। इसी दिन किस्से कहानी और अदाकारी का एक खास सेशन होगा जिसमें मोहित चौहान, अभिनेता मनोज वाजपेयी संग बातचीत करेंगे। इसके अलावा पोलैंड की एमिला लाइट बैरियर कहानी सुनाएंगी। जबकि दूसरे दिन यानी शनिवार को परंपरागत पोलिश बैंड की प्रस्तुति होगी। साथ ही अंकल लैरी वॉल्श अपनी जुबानी कहानी सुनाएंगे। इसी दिन अमृता त्रिपाठी भारत के कहानीकारों पर बातचीत भी करेंगी। जिससे दर्शकों को काफी कुछ जानने का मौका भी मिलेगा।

अब तक आप रामलीला मंच और टीवी पर रामायण की कहानी देखते आए हैं। इस फेस्टिवल में कठपुतली कला के जरिए दर्शकों के बीच रामायण प्रस्तुत की जाएगी। तीसरे दिन पोलैंड की जेंजी जुफा पोलिश कहानियां सुनाएंगी। वहीं रश्मी मन और रुचिता की बातचीत के जरिए दर्शक हरियाणवी लोक कथाओं को जान पाएंगे। किस्से कहानी और सिनेमा सेशन में फिल्म निर्माता इम्तियाज अली दर्शकों से फिल्मी कहानियों के पीछे की कहानियां बताएंगे।

–संजीव कुमार मिश्र

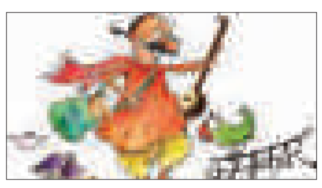

- **कहां** : दिल्ली हेरिटेज पार्क, सुंदर नर्सरी
- **कब** : 11-13 अक्टूबर, शाम पांच से रात दस बजे तक।
- **प्रवेश** : ऑनलाइन बुकिंग द्वारा। टिकट 100 रुपये।
- **नजदीकी मेट्रो स्टेशन** : निजामुद्दीन और जंगपुरा।

वत्सला के किचन में है स्वीट मैजिक

जायका

पेस्ट्रीज, केक और ब्राउनी की सोंधी खुशबू ही मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। इसे बनाने, सजाने और परोसने का तरीका हर किसी के लिए आसान नहीं। इसके लिए तो पाक कला में महारथ हासिल करने के साथ ही क्रिएटिव भी होना पड़ता है। क्योंकि इसका स्वाद पहले आंखों से चखा जाता है फिर बात जुबां तक पहुंचती है। इसका स्वाद लाजवाब होगा तभी बेकिंग कला जगत में पहचान बना पाएंगे। यह सब कुछ शौक से ही संभव है। अपने इन्हीं शौक और हुनर की वजह से वत्सला बेकरी प्रोडक्शन के क्षेत्र में आज एक पहचान बन गई हैं। कारपोरेट सेक्टर में काम करने के बावजूद वत्सला ने स्वाद की दुनिया से नाता नहीं तोड़ा और धीरे-धीरे पूरी तरह से इसी क्षेत्र में उतर गईं। उन्होंने बेकिंग में देसी-विदेशी प्रशिक्षण लिए और फिर होममेड बेकिंग करने लगीं।

बिना प्रिजर्वेटिव बनती हैं डिशेज : आमतौर पर पैकेज्ड फूड को स्वास्थ्यवर्द्धक नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें रंग और प्रिजर्वेटिव का मिश्रण होता है। वत्सला ने सोचा कि आखिर ये चीजें स्वास्थ्यवर्धक क्यों नहीं हो सकतीं। इसके लिए उन्होंने काफी प्रयोगों किए और उन्हें सफलता भी मिली कि बिना रंग और प्रिजर्वेटिव के भी बेकरी आइटम्स बनाए जा सकते हैं।

शेफ वत्सला

केक के साथ राजमा-चावल : आप अपना पसंदीदा केक मांगें और प्लेट में राजमा चावल, छोले-भटूरे, तंदूरी चिकन और चाउमीन आ जाए तो क्या कहेंगे। जी हां, वत्सला के किचन 'स्वीट मैजिक' में कुछ ऐसा ही जादू होता है। जादू इसलिए क्योंकि आपको घरेलू इंडियन व चाइनीज भोजन में केक का स्वाद मिलेगा। दरअसल केक व पेस्ट्री को वत्सला यह डेकोरेटिव ट्विस्ट देती हैं। उनका कहना है कि उनके इस प्रयोग को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं।

बार्बी केक

राजमा चावल केक

स्वास्थ्य से भरपूर ग्रेन्यूला : इन दिनों लोग अनाज और सूखे मेवे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में वत्सला ने इन्हीं चीजों से बेकरी आइटम बनाना शुरू किया। उनकी रसोई में चार प्रकार के ग्रेन्यूला बनते हैं, जिनमें मेवे, सूखे मेवे और फलों के बीज होते हैं, जो रक्तचाप, थायराइड आदि बीमारियों में रामबाण हैं। इसके अलावा ट्रेल मिक्स ग्रेन्यूला भी हैं जो सब्जियों के बीज, मेवे और बैरीज से बनाए जाते हैं। यह ग्रेन्यूला दूध के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जाता है।

खूबसूरत पैकिंग पर भी देती हैं जोर : जब तक कोई चीज आंखों को न भाए हम उसे खाने को तत्पर नहीं होते। इसलिए वत्सला बेकिंग के साथ फूड डेकोरेशन पर भी ध्यान देती हैं। खासकर फेस्टिव सीजन में वे पैकिंग को लेकर बहुत सारे प्रयोग करती हैं। इसके लिए उन्होंने क्राफ्ट भी सीखा है। वे इन बेकिंग प्रोडक्ट्स को बड़ी ही खूबसूरती से पैक करती हैं। यह देखने में ही इतना खूबसूरत होता है कि बिना खाए रहा नहीं जाता। पैकिंग पर्यावरण अनुकूल हो इसके लिए वह सजावट में बायोडीग्रेडेबल और रीसाइकल होने वाले पदार्थों का उपयोग करती हैं।

ब्राउनी का हेल्दी स्वाद : चॉकलेट ब्राउनी तो सभी को पता है लेकिन वत्सला की रसोई से निकली ब्राउनी कई रंग लिए हुए होती है। व्हिस्की, रम, अलग-अलग प्रकार के फ्रूट फ्लेवर और ओरयो फ्लेवर में वह ब्राउनी बनाती हैं। वत्सला का कहना है कि अच्छी क्वालिटी की होम मेड सामग्री से प्रिपरेशन हो तो इसमें स्वाद और स्वास्थ्य दोनों होता है।

– प्रियंका दुबे मेहता

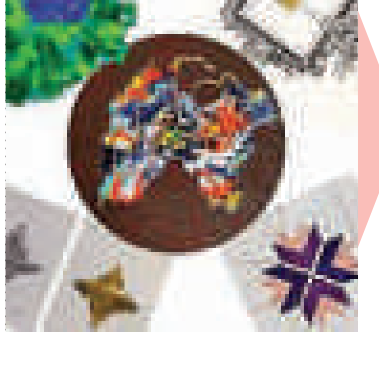

सफर के जरिए जिंदगी

जब आप सफर करते हैं तो मन में अनेकों विचार आते हैं। सफर के अनुभव कई बार जिंदगी का रुख एवं मकसद बदल देते हैं। हरलीन कौर की यह प्रदर्शनी सफर के जरिए जिंदगी को जीने एवं समझने की कोशिश है। उनकी यह प्रदर्शनी जनवरी 2019 तक की विभिन्न यात्राओं की कलात्मक अभिव्यक्ति है।
- **कहां** : गैलरी आर्टिक्यूलेट, बी70 द बेसमेंट, गुलमोहर पार्क। • **कब** : 11 से 14 अक्टूबर, सुबह दस से शाम छह बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

के थ्री, कभी भी आइए

नार्थ इंडियन, चाइनीज, इटैलियन और मोमोज यदि आप खाने के शौकीन हैं तो के थ्री एक बेहतर ठौर हो सकता है। यह साफ सुथरी, शांत जगह आपको पसंद आएगी। मद्धम संगीत आपके दिल को छू लेगा। वैसे यहां का पास्ता, पिज्जा, सलाद, बिरयानी, दाल मखनी, ब्रेकफास्ट बफेट और बटर चिकन लोग खूब पसंद करते हैं।
- **कहां** : एयरोसिटी, दिल्ली।
- **कब** : 24 घंटे।
- **शुल्क** : 3500 रुपये, प्रति दो व्यक्ति।

पा पा या

एशियन, चाइनीज, थाई, जापानी जायका आप एक ही छत के नीचे ढूंढ रहे हैं तो पा पा या का रुख कर सकते हैं। यहां सप्ताहांत लोग बेहतरीन जायके का स्वाद चखने बड़ी संख्या में आते हैं। एशियन खाना यहां का लाजवाब है। वहीं तुना सुशी, वाटरमेलन जूस जरूर ट्राई करें।
- **कहां** : सलेक्ट सिटी वॉक, साकेत।
- **कब** : दोपहर 12 से रात एक बजे तक।
- **शुल्क** : 2500 रुपये, प्रति दो व्यक्ति।

आइओबी ने ब्याज दरें घटाईं

चेन्नई, प्रेट्र : सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता इंडियन ओवरसीज बैंक (आइओबी) ने खुदरा लोन के लिए ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की है। नई दरें पहली नवंबर से प्रभावी होंगी। एक बयान में बैंक ने कहा कि खुदरा सेग्मेंट यानी हाउसिंग, व्हीकल, एजुकेशन और एमएसएमई लोन के लिए 25 आधार अंकों की कटौती की है। इसके साथ ही बैंक ने रेपो रेट लिंक्ड कर्ज दरों को भी 8.25 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत कर दिया है।

वित्तीय सेवा क्षेत्र में अस्थिरता के बावजूद हमने दूसरी तिमाही में भी सकारात्मक विकास बरकरार रखा है। चुनौतियां आगे भी हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि लंबी अवधि में कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी।

— राजेश गोपीनाथन, सीईओ, टीसीएस

सेंसेक्स	37,880.40	▼ 297.55
निफ्टी	11,234.55	▼ 78.75
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 39,375	▲ ₹3
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 47,120	▼ ₹24
डॉलर	₹ 71.07	(बदलाव नहीं)
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 58.87	

मंदी दूर करने को दे रहे सेक्टर-केंद्रित मदद : सीतारमण

मुंबई, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती से पार पाने के लिए सरकार सेक्टर-केंद्रित मदद लगातार मुहैया करा रही है। हालांकि उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि अर्थव्यवस्था में मंदी है या नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों को मदद की जरूरत है, उन्हें मदद दी जा रही है।

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 6.1 प्रतिशत रह जाने का अनुमान जताया है। गुरुवार को ही अग्रणी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपने संशोधित अनुमान में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 5.8 प्रतिशत रह जाएगी। हालांकि पिछले करीब दो महीनों के दौरान सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने, रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने और खपत बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।

पिछले महीने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा कर सरकार ने देश के कारोबारी जगत की बरसों पुरानी मांग पूरी की थी। इसके तहत देश में कॉरपोरेट टैक्स की अधिकतम दर 25.17 प्रतिशत रह गई है। इन्हीं कदमों के तहत देशभर के सरकारी बैंकों को देशभर में लोन मेला आयोजित करने को कहा गया है। इसका मकसद त्योहारी सीजन में जरूरतमंद ग्राहकों को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराना है।

वजह ▸ देश की इकोनॉमी पर लंबी अवधि तक दबाव डालने वाले कुछ कारक बरकरार

मूडीज ने भारत का जीडीपी विकास दर अनुमान घटाकर 5.8 फीसद किया

इससे पहले 6.2 प्रतिशत का अनुमान लगाया था एजेंसी ने

नई दिल्ली, प्रेट्र : अग्रणी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज को चालू वित्त वर्ष (2019-20) में भारत की विकास दर छह प्रतिशत से भी नीचे रहने का अनुमान है। एजेंसी ने गुरुवार को भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का विकास दर अनुमान घटाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 6.2 प्रतिशत रखा गया था। एजेंसी का कहना है कि लंबी अवधि तक असर डालने वाले कुछ कारकों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती कुछ ज्यादा खिंचने के आसार हैं। पिछले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने भी मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया था।

मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुस्ती का असल कारण निवेश में कमी है, जिसने बाद में रोजगार सृजन में कमी और ग्रामीण इलाकों में वित्तीय संकट के कारण खपत पर भी असर दिखाया। एजेंसी ने कहा, 'नरमी के कई कारण हैं और इनमें से अधिकांश घरेलू एवं कुछ दीर्घकालिक असर वाले हैं। वृद्धि दर बाद में तेज होकर 2020-21 में 6.6 फीसद और मध्यम अवधि में करीब सात फीसद तक पहुंच सकती है।' एजेंसी के मुताबिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) सेक्टर में नकदी की कमी भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर को सुस्त करने में जिम्मेदार रही है।

मध्यम अवधि में सात फीसद तक विकास दर का अनुमान लगाया है एजेंसी ने। प्रतीकात्मक

आठ प्रतिशत ग्रोथ की उम्मीद कम : मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'हम अगले दो साल जीडीपी की वास्तविक वृद्धि और महंगाई में धीमे सुधार की उम्मीद करते हैं। हमने दोनों के लिए अपना पूर्वानुमान घटा दिया है। दो साल पहले की स्थिति से तुलना करें तो जीडीपी वृद्धि दर आठ प्रतिशत या उससे ऊपर रहने की उम्मीद कम हो गई है।'

राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी का जोखिम : मूडीज ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और कम जीडीपी वृद्धि दर के कारण राजकोषीय घाटा सरकार के लक्ष्य से 0.40 प्रतिशत अधिक होकर 3.70 प्रतिशत पर पहुंच जाने की आशंका व्यक्त की। मूडीज ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से वास्तविक जीडीपी में पांच प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह कम है। हालिया वर्षों में महंगाई दर में अच्छी गिरावट के कारण सांकेतिक जीडीपी की वृद्धि दर पिछले दशक के करीब 11 प्रतिशत से गिरकर 2019 की दूसरी तिमाही में करीब आठ प्रतिशत पर आ गई है। वर्ष 2012 के बाद से निजी निवेश अपेक्षाकृत नरम रहा है, लेकिन जीडीपी में करीब 55 प्रतिशत योगदान देने वाला उपभोग शानदार रहा है।'

मूडीज के अन्य प्रमुख अनुमान

- चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका
- 2020-21 में आर्थिक विकास दर बढ़कर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान
- मध्यम अवधि में जीडीपी वृद्धि दर करीब सात प्रतिशत रह सकती है

अन्य एजेंसियों का अनुमान

इससे पहले एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 50 आधार अंक घटाकर 6.5 प्रतिशत रखा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) ने भी चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान में 1.3 प्रतिशत की बड़ी कमी करते हुए उसे 5.9 प्रतिशत रखा था। प्रमुख ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) और फिच ने भी भारत की विकास दर को लेकर पूर्वानुमान में कटौती की है। एसएंडपी ने चालू वित्त वर्ष में देश का संशोधित विकास दर अनुमान 6.3 प्रतिशत, जबकि फिच ने 6.6 प्रतिशत कर दिया था।

जीएसटी राजस्व बढ़ाने पर सुझाव के लिए समिति गठित

- 15 दिनों के भीतर जीएसटी सचिवालय को पहली रिपोर्ट सौंपेगी समिति
- कई राज्यों और केंद्र सरकार के शीर्ष जीएसटी अधिकारी होंगे समिति के सदस्य

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : उम्मीद से कम जीएसटी संग्रह से चिंतित सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस समिति को जीएसटी का संग्रह बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में लाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए उपाय सुझाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा यह समिति जीएसटी में संरचनात्मक बदलावों के बारे में सुझाव देगी। इस समिति में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब के जीएसटी कमिश्नरों के अलावा प्रिंसिपल जीएसटी कमिश्नर और संयुक्त सचिव (राजस्व) भी शामिल किए गए हैं। अन्य राज्यों से भी इस बारे में अपने सुझाव देने और समिति में शामिल होने का आग्रह किया गया है।

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि समिति विस्तृत सुधारों पर विचार करेगी, ताकि सुझावों की व्यापक सूची उभरकर आ सके। आदेश में कहा गया है कि कानून में नीतिगत उपायों और संबंधित बदलावों की जरूरत है। आदेश के मुताबिक समिति 15 दिन के भीतर जीएसटी सचिवालय में पहली रिपोर्ट सौंप देगी। आंकड़ों के बेहतर विश्लेषण और प्रशासनिक समन्वय के जरिये अनुपालन की बेहतर निगरानी पर सुझाव देना भी समिति की जिम्मेदारी होगी।

गौरतलब है कि पिछले महीने जीएसटी संग्रह घटकर 91,916 करोड़ रुपये रह गया, जो 19 महीनों का निचला स्तर है। अगस्त में भी जीएसटी का संग्रह घटा था। इससे अर्थव्यवस्था में सुस्ती और ग्राहक मांग में कमी का अंदेशा और मजबूत हुआ। सरकार चालू वित्त वर्ष में केवल एक बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी राजस्व हासिल कर पाई है।

चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने हर महीने 1.13 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह का अनुमान लगाया था। हालांकि अप्रैल में प्राप्त 1,13,865 करोड़ रुपये के बाद अब तक किसी भी महीने में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये को पार नहीं कर पाया है। इसकी एक वजह इसी वर्ष कई मदों में जीएसटी के रेट में कटौती को भी बताया जा रहा है।

ग्रोथ रेट पर बिगड़ा बाजारों का मूड

- 297.55 अंक फिसलकर 37,880.40 पर आया सेंसेक्स
- दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों की भी बहुत दमदार शुरुआत नहीं

मुंबई, प्रेट्र : लगातार कई सत्रों की गिरावट के बीच बुधवार को बड़ी छलांग लेने वाले घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को फिर से नकारात्मक जोन में चले गए। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 297.55 अंक यानी 0.78 प्रतिशत लुढ़ककर 37,880.40 अंक के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 78.75 अंकों यानी 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 11,234.55 अंक पर स्थिर हुआ।

जानकारों का कहना था कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत का जीडीपी विकास दर अनुमान छह फीसद से भी नीचे कर दिया, जिसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में तेज बिकवाली हावी हो गई। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) के वित्तीय नतीजों की बहुत दमदार शुरुआत नहीं होने के चलते निवेशकों में निराशा दिखी।

इंडसइंड बैंक का शुद्ध लाभ भले ही पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 52 प्रतिशत से ज्यादा उछला, लेकिन उसके फंसे कर्ज (एनपीए) में बढ़ोतरी होने से निवेशक मायूस हुए। वहीं, देश की सबसे बड़ी आइटी कंपनी टीसीएस का मुनाफा जरूर बढ़ा, लेकिन वह विश्लेषकों के अनुमान को पार नहीं कर पाया।

सेंसेक्स पैक में सबसे ज्यादा 6.15 प्रतिशत की गिरावट इंडसइंड बैंक के शेयरों में ही हुई। यस बैंक, टाटा मोटर्स, वेदांता, आइसीआइसीआइ बैंक, एसबीआइ, एचडीएफसी बैंक व टाटा स्टील के शेयर भी 5.21 प्रतिशत तक फिसल गए। हालांकि भारती एयरटेल के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.05 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। उसके साथ-साथ आरआइएल, एचयूएल, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, सन फार्मा, एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो के शेयरों में 2.76 प्रतिशत तक के उछाल ने सेंसेक्स को और बड़ी गिरावट से रोक लिया।

प्रतीकात्मक

इन शेयरों में रही बड़ी हलचल

एयरटेल : एनएसई पर एयरटेल के शेयर गुरुवार को इंट्रा-डे में 7.19 प्रतिशत उछलकर 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छू गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर एनएसई पर 4.35 प्रतिशत के उछाल के साथ 375.05 रुपये पर बंद हुए। बीएसई पर भी कंपनी के शेयर 5.05 प्रतिशत उछाल के साथ 377.40 रुपये पर बंद हुए।

वोडाफोन : वोडाफोन आइडिया के शेयर बीएसई पर 5.82 प्रतिशत चढ़कर 6.18 रुपये, जबकि एनएसई पर 5.13 प्रतिशत उछलकर 6.15 रुपये के भाव पर बंद हुए। रिलायंस जियो द्वारा बुधवार को प्रतिस्पर्धी नेटवर्क पर कॉल करने वाले अपने ग्राहकों से छह पैसा प्रति मिनट शुल्क लेने की घोषणा का फायदा एयरटेल और वोडाफोन के शेयरों में दिखा।

डीएचएफएल : एडलवाइज असेट मैनेजमेंट ने डीएचएफएल से अपने बकाया रकम की वसूली के लिए बुधवार बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके चलते गुरुवार को डीएचएफएल के शेयर करीब 10 प्रतिशत टूटकर लोअर सर्किट तक गिर गए। कंपनी के शेयर बीएसई पर 9.98 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23.45 रुपये के भाव पर बंद हुए। एनएसई पर भी कंपनी के शेयर 9.96 प्रतिशत टूटकर 23.50 रुपये पर स्थिर हुए। कंपनी के शेयर चार अक्टूबर से लगातार गिर रहे हैं और अब तक करीब 25 प्रतिशत टूट चुके हैं।

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस : आरबीआइ द्वारा बुधवार को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय प्रस्ताव को नकारने के बाद गुरुवार को दोनों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई। बीएसई पर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 18.85 प्रतिशत गिरकर 195 रुपये पर बंद हुए। एनएसई पर कंपनी के शेयरों का बंद भाव 19.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 193.60 रुपये रहा। कंपनी के बाजार पूंजीकरण में गुरुवार को 1,900 करोड़ रुपये से ज्यादा की गिरावट आई।

आइएमसी में 5-जी उपकरण प्रदर्शित करेगी हुआवे

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीन की टेलीकॉम कंपनियों हुआवे और जेडटीई को भारतीय मोबाइल कांग्रेस (आइएमसी) में 5-जी उपकरणों के प्रदर्शन की अनुमति मिल गई है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरवार को बताया कि दूरसंचार विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। आइएमसी का आयोजन 14-16 अक्टूबर को होना है।

आइएमसी के लिए मंजूरी मिलने का हुआवे ने स्वागत किया है। कंपनी ने कहा कि इससे एक सकारात्मक संदेश मिला है। इससे कंपनी के साथ काम करने को लेकर भारतीय उद्योग जगत का विश्वास भी बढ़ा है। कंपनी को भरोसा है कि उसे भारत में 5-जी के परीक्षण के लिए भी अनुमति मिल जाएगी।

हुआवे इंडिया के सीईओ जे. चेन ने कहा कि कंपनी दो दूरसंचार सेवा कंपनियों के साथ मिलकर 5-जी संभावनाओं का प्रदर्शन करेगी। सूत्रों ने बताया कि संभावित दो कंपनियां भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हो सकती हैं। कंपनी के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि आइएमसी के दौरान प्रदर्शन के लिए सभी को बिना भेदभाव बराबरी से स्पेक्ट्रम मिलेगा।

टीसीएस को दूसरी तिमाही में 8,042 करोड़ रुपये का लाभ

- शेयरधारकों को पांच रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा
- **40** रुपये प्रति शेयर का विशेष लाभांश देने का भी एलान

मुंबई, प्रेट्र : देश की सबसे बड़ी आइटी कंपनी टीसीएस ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) में 8,042 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के दौरान हासिल 7,901 करोड़ रुपये के मुकाबले 1.8 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2019) के मुकाबले दूसरी तिमाही में टीसीएस का मुनाफा घटा है। पहली तिमाही में कंपनी को 8,153 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में टाटा ग्रुप की इस प्रमुख कंपनी को 38,977 करोड़ रुपये की आय हुई, जिसमें सालाना आधार पर छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। टीसीएस ने शेयरधारकों को पांच रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश और 40 रुपये प्रति शेयर के विशेष लाभांश का भी एलान किया है। नतीजों की घोषणा के बाद टीसीएस के सीईओ और एमडी राजेश गोपीनाथन ने कहा कि वित्तीय सेवा क्षेत्र में अस्थिरता के बावजूद दूसरे वित्त वर्ष का अंत हमने सकारात्मक विकास दर के साथ किया। मध्यम और लंबी अवधि में हम अपनी सेवाओं की मांग में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।

इंडसइंड बैंक का मुनाफा 52 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई, प्रेट्र : निजी क्षेत्र के कर्जदाता इंडसइंड बैंक का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) में 52.2 प्रतिशत बढ़कर 1,400.96 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 920.34 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। हालांकि इस दौरान बैंक की असेट क्वालिटी खराब हुई और फंसा कर्ज (एनपीए) बढ़ा है। फंसे कर्ज के लिए बैंक की प्रोविजनिंग भी बढ़ी है। यही वजह रही कि बीएसई पर इंडसइंड बैंक के शेयर 80.55 रुपये यानी 6.15 प्रतिशत गिरावट के साथ 1,228.95 रुपये पर बंद हुए।

टीसीएस के कुछ अन्य प्रमुख आंकड़े

- ऑपरेटिंग आय 4.20 प्रतिशत घटकर 9,361 करोड़ रुपये रही
- प्रति शेयर अर्निंग 20.66 से बढ़कर 21.43 प्रतिशत हुई
- कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या 11.60 प्रतिशत रही
- दूसरी तिमाही में कुल 14,097 नए कर्मचारी जुड़े
- 30 सितंबर तक कर्मचारियों की कुल संख्या 4,50,738 रही

सोना स्थिर, चांदी में थोड़ी नरमी

- सोना तीन रुपये सुधरा, चांदी 24 रुपये फिसली
- ट्रेड वार और अन्य परिस्थितियों के चलते नहीं दिखे ग्राहक

नई दिल्ली, प्रेट्र : सराफा बाजार में खरीदारी के प्रति निवेशकों की उदासीनता के चलते सोने के भाव में गुरुवार को तीन रुपये की बेहद मामूली बढ़ोतरी हुई। इस बढ़त के बाद सोने का भाव 39,375 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि चांदी के भाव में 24 रुपये की गिरावट आई, जिसके बाद यह 47,120 रुपये प्रति किलोग्राम की रह गई।

एचडीएफसी सिक्युरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा कि दुनियाभर की निगाहें अमेरिका और चीन की गुरुवार देर शाम शुरू हो चुकी दो दिवसीय कारोबारी वार्ता पर टिकी हुई हैं। इस वार्ता से जुड़ी हर खबर, हर ट्वीट पर निवेशकों की निगाहें रहेंगी। पटेल ने कहा कि अमेरिका-चीन की इस कारोबारी वार्ता पर अनिश्चितताओं को देखते हुए निकट भविष्य में सोने के भाव में तेजी दिख सकती है। निवेशकों की नजर ब्रेक्जिट के अलावा घरेलू बाजार में विभिन्न आंकड़ों पर भी रहेगी। इस बीच, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में लगातार दूसरे महीने निवेशकों की सकारात्मक दिलचस्पी दिखी। सितंबर में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में 44 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया। उससे पहले अगस्त में उन्होंने 145 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था। पिछले वर्ष नवंबर के बाद इस वर्ष अगस्त में पहली बार निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ को निवेश का डेस्टिनेशन बनाया। पिछले वर्ष नवंबर से पहले अक्टूबर, 2016 में निवेशकों ने 20 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

सितंबर में जेम्स व ज्वैलरी का निर्यात छह फीसद घटा

मुंबई, रायटर : जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष सितंबर में जेम्स एंड ज्वैलरी का निर्यात 6.2 फीसद गिरकर 330 करोड़ डॉलर (करीब 23,100 करोड़ रुपये) मूल्य का रह गया। वहीं, कट एंड पॉलिश्ड डायमंड का निर्यात 17.6 फीसद गिरकर 194 करोड़ डॉलर (करीब 13,580 करोड़ रुपये) मूल्य का रह गया।

कृषि सम्मान निधि योजना में शामिल नहीं होगा बंगाल

जागरण संवाददाता, कोलकाता : केंद्र के साथ बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की टकराव एक बार फिर उभर कर पटल पर आ गई है। इस बार मामला किसानों से जुड़ी परियोजना का है। ममता सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की तरह प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में शामिल होने से इन्कार कर दिया है। इस कारण किसानों को प्रति वर्ष तीन किस्तों में मिलने वाली 6 हजार की राशि का लाभ नहीं मिल सकेगा। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में किसानों के लिए पहले से ही कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है और सरकार कृषक बंधु परियोजना पर अमल कर रही है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना में बंगाल के शामिल नहीं होने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अभी इस योजना से देश में 6 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। लेकिन ममता सरकार के योजना में शामिल नहीं होने से बंगाल के किसान इस योजना का लाभ पाने से वंचित हुए हैं। देश में अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के साथ किसानों के आधार कार्ड संयुक्त करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।

राज्य के कृषि निदेशक प्रदीप मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार के इस तरह की योजना घोषणा करने से पहले बंगाल में कृषक बंधु योजना चालू है। कृषक बंधु योजना के तहत राज्य में किसानों को प्रति वर्ष पांच हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य सरकार किसानों के लिए अपनी ही योजना चलाएगी। केंद्र की योजना से देश में पांच प्रतिशत किसानों को भी लाभ नहीं मिला है।

मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में जेनरेटर से होगी बिजली आपूर्ति

नईदुनिया, इंदौर

बिजली कटौती से डरी मध्य प्रदेश सरकार 'किरकिरी होने का' जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए मैग्नीफिसेंट मध्य प्रदेश (इन्वेस्टर समिट) के मुख्य आयोजन के लिए जेनरेटर की व्यवस्था की गई है। मुख्य आयोजन 18 अक्टूबर को इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के मुख्य सभागार में होगा। यहां जेनरेटर से बिजली आपर्ति की जाएगी। आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने आए मुख्य सचिव सुधीरंजन मोहंती ने यह व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

आयोजन में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही कुछ उद्योगपति भी अपनी बात रखेंगे। दो घंटे के समारोह में बिजली की आपूर्ति लाइन की जगह जेनरेटर से की जाएगी, जिससे लोड के कारण बिजली बंद होने की थोड़ी भी आशंका न रहे। आयोजन स्थल के अन्य भागों में बिजली की आपूर्ति विद्युत लाइन से की जाएगी। कंपनी ने दो फीडर से बिजली लेने की व्यवस्था की है। आयोजन के दौरान बिजली के किसी खंभे से छेड़छाड़ न हो, इसलिए खंभों के आसपास बिजलीकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 50 से ज्यादा कर्मचारी बिजली व्यवस्था पर नजर रखेंगे।

- राज्य सरकार को अपने ही विभाग पर नहीं है भरोसा

इन मौकों पर हुई थी बिजली गुल

- लोकसभा चुनाव के दौरान जब मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बूथ पर वोट डालने गए थे, तब थोड़ी देर के लिए बिजली बंद हो गई थी।
- ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह इंदौर में बिजली कंपनी के इंजीनियरों के अधिवेशन में शामिल होने एक होटल में गए थे, तब भी बिजली बंद हो गई थी और मोबाइल के टॉर्च से कुछ देर के लिए रोशनी करनी पड़ी।
- इंदौर के कांग्रेस कार्यालय में दो मंत्रियों की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान बिजली बंद हो गई थी। इसके बाद बैठक एक होटल में करनी पड़ी थी।
- भोपाल में बिजली मंत्री की पत्रकारवार्ता के दौरान ही बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई थी।

जीजीएस रिफाइनरी बनाएगी बीएस-6 फ्यूल

साहिल गर्ग, बठिंडा

- प्रोजेक्ट दिसंबर तक होगा पूरा, देशभर में होगी सप्लाई
- केंद्र सरकार ने देश की सभी रिफाइनरियों को दिए हैं बीएस-6 फ्यूल बनाने के आदेश
- अप्रैल, 2020 से सिर्फ बीएस-6 वाहन ही बेच सकेंगी कंपनियां

बठिंडा की गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी में पॉल्यूशन कम करने वाले बीएस-6 फ्यूल के उत्पादन पर काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सिर्फ बीएस-6 वाहनों को अगले वर्ष पहली बेचने का आदेश जारी किया हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बीएस-6 ग्रेड फ्यूल को तैयार करने के लिए देश की रिफाइनरियों को निर्देश दिए हैं। इन सबमें बठिंडा की गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी इस पर तेजी से काम कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि यहां पर बीएस-6 फ्यूल को तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट लगाने के अलावा पूरी योजना बना ली गई है। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां से देशभर में बीएस-6 फ्यूल की सप्लाई होगी। फिलहाल बठिंडा की रिफाइनरी ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है।

यह है बीएस-6 ग्रेड फ्यूल : बीएस-4 से सीधा बीएस-6 ग्रेड फ्यूल का मतलब है कि ईंधन में सल्फर की मात्रा को कम किया जाना है। अभी बीएस-4 पेट्रोल और डीजल में सल्फर की मात्रा 50 पीपीएम यानी पार्ट्स प्रति 10 लाख है। बीएस-6 ग्रेड फ्यूल में सल्फर की मात्रा महज 10 पीपीएम रहना है। दूसरी तरफ बीएस-6 फ्यूल के साथ थोड़ा बहुत रेट भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन तेल कंपनियों का कहना है कि फिलहाल इसको लोगों से नहीं वसूला जाएगा।

आप पर क्या होगा असर : बीएस-6 ईंधन को ग्राहक अपने मौजूदा बीएस-3 व बीएस-4 ईंधन के अनुकूल बने वाहनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फायदेमंद भी है। ईंधन में सल्फर की मात्रा जितनी कम होगी, वह उतना ही कम जलेगा। कम सल्फर वाला पेट्रोल कम पॉल्यूशन पैदा करेगा। इतना ही नहीं, सल्फर की मात्रा कम होने से पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा भी धुएं में कम होगी। एक अनुमान के मुताबिक बीएस-4 के अनुरूप बनी डीजल कार को अगर बीएस-6 ईंधन पर चलाया जाए तो औसतम 50 पर्सेंट तक कम पीएम उत्सर्जित होगा।

अभी ऐसे हो रही ईंधन की सप्लाई : पंजाब के अलावा जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों व उत्तर भारत में बीएस-4 फ्यूल की सप्लाई हो रही है।

दिसंबर तक लग जाएगा रिफाइनरी का प्रोजेक्ट। प्रतीकात्मक

इससे होगा यह फायदा

- हवा में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। हवा में जहरीले तत्व कम हो सकेंगे।
- बीएस-4 के मुकाबले बीएस-6 में प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ काफी कम होंगे
- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पीएम के मामले में बीएस-6 ग्रेड का डीजल काफी अच्छा होगा

बीएस-5 क्यों लागू नहीं हुआ

इसकी एक वजह ये है कि बीएस-5 और बीएस-6 ईंधन में जहरीले सल्फर की मात्रा बराबर होती है। जहां बीएस-4 ईंधन में 50 पीपीएम सल्फर होता है, बीएस-5 व बीएस-6 दोनों तरह के ईंधनों में सल्फर की मात्रा 10 पीपीएम ही होती है। इसलिए सरकार ने बीएस-4 के बाद सीधे बीएस-6 लाने का फैसला किया।

141 देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सूचकांक नक्शे में। इनका मूल्यांकन दर्जनों श्रेणियों के 100 से अधिक मापदंडों के आधार पर होता है।

तुर्क बनाम कुर्द लड़ाके और अमेरिका

उत्तरी-पूर्वी सीरिया और तुर्की की सीमा वाले इलाके से अमेरिकी सैनिकों को हटाने के फैसले के बाद से तुर्की की सेना ने कुर्द नेतृत्व वाले सैन्य बलों के खिलाफ हवाई हमला शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि तुर्क और कुर्द सदियों से एक-दूसरे के लिए लड़ते आए हैं। कुर्द लड़ाकों ने दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की मदद नहीं की थी। उनके इस बयान को वैश्विक कूटनीति के जानकार और अमेरिकी विपक्ष तुर्की को हरी झंडी देने के संकेत के तौर पर देख रहा है। हालांकि ये वही कुर्द लड़ाके हैं, जो सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देते रहे हैं।

कौन हैं कुर्द

तुर्की में दो नस्लीय पहचानें हैं– तुर्क और कुर्द। ज्यादातर कुर्द सुन्नी मुस्लिम हैं। कुर्द आबादी लगभग 20 फीसद है। पहले वे सांस्कृतिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। मगर अब कई सालों से वे आजादी की मांग कर रहे हैं। वे कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। कुर्द मांग करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के आत्मनिर्णय के अधिकार पर उन्हें भी अलग कुर्दिस्तान बनाने का हक मिले। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था। तभी से उत्तरी इराक में कुर्दिस्तान लगभग स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम कर रहा है।

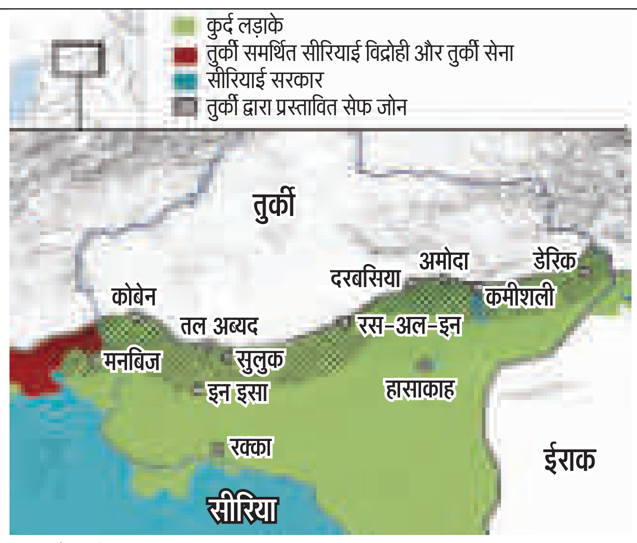

कहां है बसेरा : मध्य-पूर्व के नक्शे में नजर डालें तो तुर्की के दक्षिण-पूर्व, सीरिया के उत्तर-पूर्व, इराक के उत्तर-पश्चिम और ईरान के उत्तर पश्चिम में ऐसा हिस्सा है, जहां कुर्द बसते हैं।

कुर्द अमेरिका के प्रमुख सहयोगी

सीरिया में इस्लामिक स्टेट को हराने में कुर्द लड़ाके अमेरिका के प्रमुख सहयोगी रहे हैं। कुर्द लड़ाके अपने नियंत्रण वाले इलाकों मे बनी जेलों में बंद हजारों इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों और उनके रिश्तेदारों की निगरानी करते हैं।

तुर्की की चिंता

तुर्की की चिंता है कि उसके बगल में कुर्द राष्ट्र बना तो उसके लिए अपने यहां रह रही कुर्द आबादी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका ने सीरिया में तथाकथित इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए जिस कुर्द संगठन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) की सहायता ली, आज वह उसी को खत्म कर देने पर तुला हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगान ने कहा कि उनकी सेना कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाकर एक सेफ-ज़ोन तैयार कर रही है। कुर्द लड़ाकों को लेकर तुर्की की चिंताएं उस समय चरम पर पहुंच गईं, जब उन्होंने सीरिया में आइएस से छुड़ाए इलाके को अलग देश बनाने की कोशिश की। तुर्की में इस बात को लेकर भी बेचैनी है कि तुर्की के दक्षिणी हिस्से में कुर्द लड़ाके जिस अलग कुर्द देश का गठन करना चाहते हैं, उसे लेकर यूरोपीय संघ और अमेरिका स्पष्ट रुख नहीं जता रहे।

आइएस के लौटने का खतरा

कुर्द समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) का कहना है वो अपनी सात जेलों में आइएस के 12,000 से ज्यादा संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में रखे हुए है। वहीं कई हजार तुर्की से लगी सीमा के करीब छिपे हुए हैं। ऐसे में यदि युद्ध बढ़ा तो तुर्की इन आतंकियों का इस्तेमाल कुर्द लड़ाकों के खिलाफ कर सकता है।

न्यूज गैलरी

सीरिया में पकड़े गए आइएस आतंकी हमारे कब्जे में : ट्रंप

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में पकड़े गए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के दो आतंकी अमेरिकी सेना के कब्जे में हैं। उन्हें सीरिया से बाहर सुरक्षित ठिकाने में रखा गया है। ट्रंप ने बुधवार रात को एक ट्वीट में यह जानकारी दी। ब्रिटिश नागरिक अल शफी अलशेख और अलेक्सांदा कोटे आइएस की खतरनाक इकाई बीटल्स के सदस्य रहे हैं। यह इकाई पश्चिमी देशों के नागरिकों के अपहरण और कत्लेआम के लिए कुख्यात रही है। बीटल्स से जुड़ा एक अन्य ब्रिटिश आतंकी मुहम्मद एमवाजी उर्फ जिहादी जॉन 2015 में सीरिया में अमेरिकी हमले में मारा गया था। (आइएएनएस)

ट्रंप ने कहा, मारा जा चुका अलकायदा आतंकी इब्राहिम

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अलकायदा के लिए बम बनाने वाला आतंकी इब्राहिम हसन अल असिरी मारा जा चुका है। माना जाता है कि वह वर्ष 2009 में अमेरिका जाने वाले विमान में बम लगाने की कोशिश समेत कई अन्य वारदातों का मास्टर माइंड था। उसने सऊदी अरब के प्रिंस मुहम्मद बिन नाएफ को मारने के लिए अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को ही आत्मघाती हमलावर बना दिया था। (रायटर)

ईयू से अलगाव से तीन हफ्ते पूर्व शर्तों पर चर्चा

लंदन : ब्रेक्जिट पर बने गतिरोध को दूर करने की दिशा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वारेडकर से वार्ता की। वार्ता में पिछले सप्ताह ब्रिटेन की ओर से यूरोपीय यूनियन (ईयू) को दिए समझौता प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस नए प्रस्ताव से आयरलैंड सहमत नहीं है। वह समझौता प्रस्ताव में ज्यादा लाभकारी प्रावधानों की मांग कर रहा है। 17-18 अक्टूबर को होने वाली ईयू समिट से पहले इस वार्ता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन चलता है। समझौता प्रस्ताव की शर्तों पर विचार के लिए यह बैठक ईयू से ब्रिटेन के अलगाव के लिए निर्धारित 31 अक्टूबर से महज तीन सप्ताह पहले हुई है। (रायटर)

ब्रिटेन में एमक्यूएम संस्थापक पर भड़काऊ भाषण का केस

लंदन : ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तान के मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के संस्थापक अल्ताफ हुसैन पर पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। हुसैन पर 22 अगस्त, 2016 को पाकिस्तान की जनता को संबोधित करने के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। ब्रिटिश पुलिस का कहना है कि अल्ताफ का भाषण आतंक रोधी कानून के दायरे में आता है। (आइएएनएस)

आरोप हटाने की मांग वाली मुशर्रफ की याचिका खारिज

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने मुल्क के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आतंकवाद के आरोपों को हटाने की मांग की थी। पूर्व सेना प्रमुख ने इसके साथ ही उन पर चल रहे केस को आतंकवाद रोधी अदालत से सत्र अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी। (प्रेट्र)

वैश्विक विरोध के बावजूद तुर्की के कुर्दों पर हमले जारी

बड़ा मामला ▶ नौ माह के बच्चे समेत छह मरे, 60 हजार ने घर छोड़ा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्दों की वफादारी से पल्ला झाड़ा

अमेरिकी संसद में चल रही प्रतिबंध की तैयारी, यूरोपीय यूनियन ने जताया विरोध

इस्तांबुल, रायटर : अंतरराष्ट्रीय निंदा को दरकिनार करते हुए तुर्की ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सीरिया के कुर्द नियंत्रण वाले इलाकों पर हवाई और जमीनी हमले जारी रखे। हमलों में नौ महीने के बच्चे मुहम्मद उमर समेत छह लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। 60 हजार से ज्यादा लोगों के जान बचाकर भागने की खबर है। तुर्की के कदम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने क्षेत्र में फिर से अस्थिरता का दौर शुरू होने की आशंका जताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने असमंजस भरे बयान में कहा है कि आतंकी संगठन आइएस से लड़ाई में कुर्दों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। जबकि सीरिया ही नहीं इराक में भी कुर्द वर्षों तक अमेरिकी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। ट्रंप ने तुर्की की कार्रवाई को बुरे विचार का फैसला बताते हुए उससे खुद को अलग बताया है। इस बीच तुर्की पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

राष्ट्रपति ट्रंप भले ही असमंजस में हों लेकिन यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब और मिस्र ने तुर्की की कार्रवाई को लेकर विरोध जताया है। जवाब में तुर्की के राष्ट्रपति रीसेप तैयप एर्दोगन ने कहा है कि तुर्की की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले ईमानदार नहीं हैं। उन्होंने धमकी दी कि यूरोपीय यूनियन का विरोधी रुख बना रहा तो वह सीरियाई शरणार्थियों को यूरोपीय देशों के लिए जाने का रास्ता दे देंगे। नाटो के अकेले मुस्लिम सदस्य देश तुर्की ने कहा है कि वह कुर्द आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही दसियों लाख सीरियाई शरणार्थियों की वापसी के लिए हालात तैयार कर रहे हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इससे इलाके में फिर से टकराव शुरू होने का खतरा लग रहा है। सीरिया की सीमा से अमेरिकी सैनिकों के हटने के तत्काल बाद ही तुर्की ने कुर्दों पर हमले शुरू किए हैं। ट्रंप प्रशासन के रुख के खिलाफ जाकर सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी ने कुर्दों के खिलाफ तुर्की की कार्रवाई पर विरोध जताया है। पार्टी ने ट्रंप को कुर्दों की वफादारी की याद दिलाई है।

हजारों आइएस आतंकियों के भागने का खतरा : तुर्की के हमलों से सीरिया में स्थित कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की जेल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इस जेल में 60 देशों के हजारों दुर्दांत आइएस आतंकी और अपराधी बंद हैं। इन जेलों में आइएस आतंकियों के रिश्तेदार भी बंद हैं। हमले के बीच अगर जेल से आतंकी और अपराधी भाग निकलते हैं तो पूरे क्षेत्र के लिए यह बेहद खतरनाक होगा। फिलहाल जेल की सुरक्षा के बारे में कोई बयान नहीं आया है।

सुरक्षा परिषद ने किया विचार : ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत पांच देशों की मांग पर गुरुवार को बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया के हालात पर चर्चा हुई। परिषद को भेजे पत्र में तुर्की ने अपनी कार्रवाई को संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण बताया है। 22 देशों की अरब लीग ने हालात पर चर्चा के लिए शनिवार को बैठक बुलाई है। रूस ने कहा है कि वह सीरिया और तुर्की की सरकारों के बीच वार्ता कराने के प्रयास कर रहा है जिससे टकराव की स्थिति खत्म हो।

तुर्की के हमले के जवाब में गुरुवार को सीरिया से कुर्दों ने भी तुर्की के सीमावर्ती कस्बे अक्साकले में मोर्टार दागे। इस दौरान अपने मासूम बच्चों के साथ जान बचाकर भागतीं महिलाएं। एपी

कार्रवाई पर भारत ने दी सख्त प्रतिक्रिया

जयप्रकाश रंजन, मामल्लपुरम

कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले तुर्की को भारत ने गुरुवार को उसी के अंदाज में कूटनीतिक जवाब दिया। तुर्की की तरफ से पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्दों के इलाकों में किए जा रहे हमले पर भारत ने न सिर्फ कड़ा एतराज जताया है बल्कि उसे सीरिया के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करार दिया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि तुर्की के इन हमलों को पाकिस्तान ने जायज ठहराया है और इसे तुर्की का आंतरिक मामला करार दिया है।

सनद रहे कि पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में तुर्की ने जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया था। तुर्की के राष्ट्रपति रीसेप तैयप एर्दोगन ने अपने भाषण में कश्मीर का उल्लेख किया था। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया- 'भारत तुर्की की तरफ से सीरिया के एक हिस्से में किए जा रहे अकारण सैन्य कार्रवाई से काफी चिंतित है। तुर्की की इस कार्रवाई से उस इलाके की स्थिरता पर काफी उल्टा असर पड़ेगा और यह आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के खिलाफ है। इससे बड़ा मानवीय संकट पैदा होने का भी खतरा है। हम तुर्की से आग्रह करते हैं कि वह संयम बरते और सीरिया की भौगोलिक संप्रभुता और अखंडता का आदर करे। हम सभी मामलों का शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाने का भी आग्रह करते हैं।' उल्लेखनीय बात यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में तुर्की की कार्रवाई की खूब प्रशंसा की गई है। इसमें कहा गया है- 'पाकिस्तान की तरफ से तुर्की भी आतंकवाद का शिकार देश है। तुर्की अपने इलाके में शांति बहाली की कोशिश कर रहा है और उसे अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करने का पूरा अधिकार है।' सनद रहे कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन चीन, मलेशिया के अलावा तुर्की भी कर रहा है। तुर्की ने भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों का लिहाज रखना भी बंद कर दिया है और उसी भाषा में बात कर रहा है जो पाकिस्तान को पसंद है।

सूत्रों का कहना है कि भारत ने अब यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि तुर्की भी भारत से अब ज्यादा कूटनीतिक सहयोग की उम्मीद नहीं करे। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब कुर्दों के इलाकों पर तुर्की के हमले का मुद्दा उठेगा तो निश्चित तौर पर भारत का रुख उसके समर्थन वाला नहीं होगा। तुर्की पिछले दो दिनों से पूर्वोत्तर सीरिया के उस इलाके पर जबरदस्त हमले किए हैं। उनमें बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने की सूचनाएं सामने आ रही है। वहां के नागरिक शहर छोड़कर दूसरे इलाकों की ओर भाग रहे हैं। इससे एक तरफ तो इस्लामिक आतंकवाद को नए सिरे से बढ़ावा मिलने की आशंका है, वहीं इससे मानवीय संकट भी पैदा होने की बात कही जा रही है। दुनिया भर के देशों में तुर्की के इस रवैये की निंदा की जा रही है।

अमेरिका ने भ्रष्टाचार के कारण द. अफ्रीका के गुप्ता परिवार पर लगाया प्रतिबंध

वाशिंगटन, प्रेट्र : दक्षिण अफ्रीका के हाई प्रोफाइल गुप्ता परिवार पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने का एलान किया है। भारतीय मूल के गुप्ता परिवार पर दक्षिण अफ्रीका में अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार नेटवर्क खड़ा कर देने का आरोप है। आरोप है कि गुप्ता परिवार रिश्वतखोरी, सरकारी ठेके हड़पने और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग जैसे मामलों में लिप्त रहा है।

अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता, राजेश गुप्ता और उनके सहयोगी सलीम एसा का नाम प्रतिबंधित सूची में डाला है। दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार के कई आरोपों के बाद गुप्ता परिवार दुबई में बस गया है। अमेरिकी मंत्रालय ने कहा कि अजय इस परिवार का मुखिया है, जिसने भ्रष्ट कारोबारी रणनीति बनाई और वित्तीय मामलों को अपने नियंत्रण में रखा। अतुल को गुप्ता परिवार के ऐसे सदस्य के रूप में जाना जाता है, जिसके संबंध भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों से रहे हैं। वहीं राजेश ने दक्षिण अफ्रीका के बड़े राजनेताओं के बेटों से संबंध मजबूत किए और दक्षिण अफ्रीका के ऐसे प्रांत में कारोबार बढ़ाने का प्रयास किया, जहां खूब भ्रष्टाचार था। सलीम एसा इस परिवार का कारोबारी सहयोगी था। वह भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क को चलाने के लिए पैसा और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराता था।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधों की घोषणा का यह कदम दर्शाता है कि अमेरिका सरकार दक्षिण अफ्रीका में कानून व जवाबदेही के समर्थन में प्रतिबद्ध है। गुप्ता परिवार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है।

बिडेन ने भी की ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग

▶ कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए ट्रंप पर महाभियोग जरूरी

▶ अमेरिकी राष्ट्रपति का जवाब, भ्रष्टाचार में रंगे हैं बिडेन के हाथ

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति तथा डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार जो बिडेन ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की है। पहली बार यह मांग उठाते हुए बिडेन ने कहा कि ट्रंप अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और उन्होंने पद की शपथ का उल्लंघन किया है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को 25 जुलाई को फोन कर बिडेन से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के सौदों की जांच कराने का दबाव डाला था। बिडेन की पार्टी ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच शुरू की है।

डेमोक्रेट सदस्यों का कहना है कि ट्रंप ने यूक्रेन में अमेरिकी सैन्य सहायता रोककर वहां के राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य किया। ट्रंप ने इन आरोपों से इन्कार करते हुए महाभियोग की जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताया है। बुधवार को न्यू हैंपशायर में एक चुनावी रैली के दौरान बिडेन ने कहा, 'अमेरिका के इतिहास में कभी किसी राष्ट्रपति ने ऐसा अकल्पनीय व्यवहार नहीं किया। अपने बयानों और कामों से ट्रंप ने खुद को दोषी साबित किया है। उन्होंने न्याय प्रक्रिया में बाधा डालकर और कांग्रेस की जांच में सहयोग न करके खुद को दोषी ठहरा दिया है।' पहली बार ट्रंप पर सार्वजनिक रूप से महाभियोग चलाए जाने का समर्थन करते हुए बिडेन ने कहा, 'अमेरिकी जनता साफ देख सकती है कि ट्रंप ने पद की शपथ का उल्लंघन किया, राष्ट्र को धोखा दिया और महाभियोग लायक काम किए। हमारे संविधान, लोकतंत्र और बुनियादी एकता बचाने की खातिर उन पर जरूर महाभियोग चलाया जाना चाहिए।' बिडेन के बयान पर ट्रंप ने भी पलटवार करते हुए उन्हें भ्रष्टाचारी बताया। व्हाइट हाउस में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हमने बिडेन को भ्रष्टाचार के साथ पकड़ा है। ट्रंप ने बिडेन के बेटे पर भी यूक्रेन में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। ट्रंप ने दावा किया कि बिडेन के राष्ट्रपति बनने की कोई संभावना नहीं है।

जेलेंस्की ने कहा-ट्रंप ने नहीं किया ब्लैकमेल

कीव, रायटर : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को यहां कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिडेन के खिलाफ जांच को लेकर जुलाई में फोन पर बात और सितंबर में मुलाकात के दौरान उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ट्रंप से फोन पर बात के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी थी। जेलेंस्की के अनुसार, देश के रक्षा मंत्री ने बाद में उन्हें इसकी जानकारी दी थी।

उत्तर कोरिया की धमकी फिर शुरू करेंगे परमाणु हथियारों का परीक्षण

सियोल, एपी : उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव फिर गहरा रहा है। अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों को अपने खिलाफ उकसाने का आरोप लगाते हुए उत्तर कोरिया ने गुरुवार को परमाणु हथियारों और लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण फिर से शुरू करने की धमकी दी।

उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से यह धमकी एक ऐसे समय आई है जब स्वीडन में अमेरिका के साथ उसकी बातचीत में इस सप्ताह गतिरोध उत्पन्न हो गया है। सात महीनों में दोनों देशों के बीच यह पहली बातचीत हो रही थी। उत्तर कोरिया ने कहा है कि बातचीत इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि अमेरिका की ओर से कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया गया। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, हमारे धैर्य की एक सीमा है। यूरोप के देशों का जैसा रुख है उसे देखते हुए हम अमेरिका के साथ विश्वास बहाली के अपने कदमों के तहत निरस्त्रीकरण के वादे पर फिर से विचार कर रहे हैं।

कुछ प्रेक्षकों का कहना है कि उत्तर कोरिया की धमकी अमेरिका पर दबाव डालने की रणनीति है ताकि वाशिंगटन को कुछ रियायतों के लिए मजबूर किया जा सके। उत्तर कोरिया को गत मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की निंदा रास नहीं आई। उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल के साथ ही कुछ अन्य हथियारों का परीक्षण भी हाल के समय में किया है, जिसमें पहला अंडर-वाटर मिसाइल टेस्ट भी शामिल है।

मुकरा पाकिस्तान, करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन की तिथि अभी तय नहीं

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अपनी पूर्व की घोषणा से पीछे हटते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि बहुप्रतीक्षित करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए अभी कोई तिथि तय नहीं की गई है। हालांकि उसने यह आश्वासन दिया है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर इसे अगले महीने 'समय पर' शुरू कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि एक महीने पहले कॉरिडोर परियोजना के प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी ने करतारपुर साहिब के लिए नवंबर से भारतीय सिख श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दिए जाने की घोषणा की थी। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने गुरुवार को साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'प्रधानमंत्री (इमरान खान) के वादे के मुताबिक, करतारपुर कॉरिडोर पर काम समय पर पूरा हो जाएगा। इसका उद्घाटन समय पर होगा लेकिन इसके शुरू होने के लिए मैं कोई तिथि नहीं दे सकता क्योंकि अभी तक इसकी तिथि तय नहीं की गई है।'

उन्होंने आश्वासन दिया कि कॉरिडोर को सिखों के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर 12 नवंबर को खोल दिया जाएगा। प्रस्तावित कॉरिडोर करतारपुर में दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक के साथ जोड़ेगा और भारतीय श्रद्धालु वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे। उन्हें करतारपुर साहिब जाने के लिए केवल परमिट हासिल करना होगा।

करतारपुर साहिब की स्थापना 1522 में गुरु नानक देव ने की थी। लाहौर से करीब 125 किलोमीटर दूर नारोवाल में प्रस्तावित करतारपुर कॉरिडोर की 16 सितंबर को पाकिस्तानी और विदेशी पत्रकारों की यात्रा में परियोजना निदेशक आतिफ माजिद ने कहा कि कॉरिडोर का 86 फीसद काम पूरा हो गया है और नौ नवंबर को इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा।

विश्व आर्थिक मंच ने पाक को तीन पायदान नीचे उतारा

इस्लामाबाद, एपी : अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम) ने अपने वार्षिक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक में पाकिस्तान को और तीन पायदान नीचे ला दिया है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान की अब डब्ल्यूईएफ में रैंक 110वीं हो गई है। दावोस में स्विस स्की रिजार्ट में वैश्विक रैंकिंग देने वाली इस संस्था के सूचकांक का मानक उत्पादकता और दीर्घकालीन आर्थिक विकास है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग कम कर दी है। इसका कारण प्रेस की आजादी, शासन व्यवस्था, खोज, भ्रष्टाचार, जीवन में आशावादिता, उत्पादकता और मानव विकास जैसे प्रमुख बिंदुओं पर पाकिस्तान का और अधिक पिछड़ जाना है। हालांकि इस देश ने कुछ क्षेत्रों में सुधार भी किया है, जैसे- बजट में पारदर्शिता और संगठित अपराधों में कमी।

पाक की किरकिरी, रद करनी पड़ी उच्चायुक्त की नियुक्ति

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के लिए यह कूटनीतिक शर्मिंदगी का मामला है। उसे श्रीलंका में अपने उच्चायुक्त की नियुक्ति रद करनी पड़ी है। यही नहीं, इस प्रकरण से सेवानिवृत्त सैन्य अफसरों की राजदूत के रूप में नियुक्ति को लेकर घरेलू राजनीतिक मतभेदों की कलई भी खुल गई। विदेश विभाग ने 30 सितंबर को बताया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई नियुक्तियां की हैं। इनमें सेवानिवृत्त मेजर जनरल साद खट्टक की श्रीलंका में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति भी शामिल थी। लेकिन जनरल साद की नियुक्ति पर रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने आपत्ति कर दी। इसके बाद सरकार को उनकी नियुक्ति रद करनी पड़ी। डॉन अखबार में छपी खबर के मुताबिक इस नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान सरकार ने जब तक अपना मन बदला तब तक श्रीलंका सरकार से उसकी सहमति का आग्रह किया जा चुका था। कूटनीतिक परंपरा के तहत जिस देश में किसी राजदूत या उच्चायुक्त की नियुक्ति की जानी होती है उसकी सहमति आवश्यक होती है।

आतंकी फंडिंग का मामला

भारत ने कहा, वित्तीय सहायता से आतंकवादियों को अपनी गतिविधि अंजाम देने में मदद मिलती है, आतंकियों को आपराधिक मुकदमे से बचाना निंदनीय है

यूएन- एफएटीएफ के बीच सहयोग की अपील

संयुक्त राष्ट्र : भारत ने अन्य देशों द्वारा आतंकियों और आतंकी समूहों को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष वित्तीय मदद की निंदा करते हुए कहा है कि इसी से उनको अपनी गतिविधि अंजाम देने में मदद मिलती है। पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए भारत ने यह भी कहा है कि आतंकियों को आपराधिक मुकदमे से प्रतिरक्षा दिया जाना भी निंदनीय है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन में प्रथम सचिव/कानूनी सलाहकार येडला उमाशंकर ने बुधवार को महासभा की छठी समिति की 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद उन्मूलन के कदम' पर बैठक को संबोधित किया। उहोंने आतंकी फंडिंग रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) और संयुक्त राष्ट्र के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

उमाशंकर ने कहा कहा, 'राज्यों की ओर से आतंक को पैदा करने वाले संसाधनों के प्रवाह को रोकने की जरूरत है। इसके लिए लिए उपक्षेत्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करने होंगे। आतंक की वित्तीय मदद से लड़ने और उसे रोकने के लिए वैश्विक मानक तय करने में एफएटीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है और संयुक्त राष्ट्र को ऐसी संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए।'

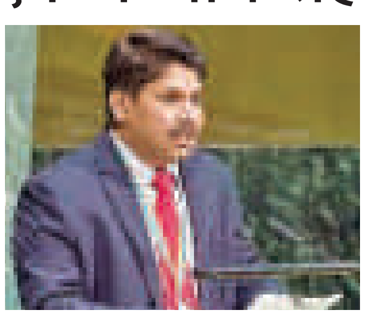

येडला उमाशंकर। फाइल

भारत की टिप्पणी उस पृष्ठभूमि में आई है जिसमें पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक निरोधी समिति से अनुरोध किया था कि मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को बुनियादी खर्चे के लिए वह उसके बैंक खाते से पैसा निकालने की इजाजत दे। सईद को संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2008 में सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 के तहत आतंकी घोषित कर रखा है। उसे पाकिस्तान में आतंकी फंडिंग के एक मामले में इस वर्ष 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक, किसी भी देश को आतंकी घोषित किए गए लोगों के सभी आर्थिक स्रोतों, अन्य वित्तीय संपत्तियों तथा कोषों पर रोक लगानी होती है।

उमाशंकर ने कहा, 'संरा महासभा में बीते एक दशक से वैश्विक आतंक निरोधी रणनीति (जीसीटीएस) को लेकर चर्चा हो रही है लेकिन जमीन पर इसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से बनाई गई प्रतिबंध समिति की धुंधली कार्य प्रणाली और फैसले लेने पर राजनीति हावी होने के कारण चयनित रूप से निशाना साधने का औजार बनकर रह गई है।'

उन्होंने भारत के इस दृढ़ विश्वास को दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआइटी) आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूत कानूनी आधार देगा और आतंक निरोधी प्रयासों में बहुपक्षीय तथा सामूहिक पैमाने का होना सभी सदस्य देशों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को आतंकवाद को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति को अपनाना और लागू करना होगा।

पाकिस्तान ने एफएटीएफ बैठक के लिए अनुपालन रिपोर्ट तैयार की

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

पाकिस्तान ने मनी लांड्रिंग निरोधक निगरानी संस्था एफएटीएफ की पेरिस में होने वाली बैठक के लिए अनुपालन रिपोर्ट तैयार की है। पाक के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद यह फैसला होगा कि वह ग्रे लिस्ट में ही बना रहता है या उसे काली सूची में डाला जाएगा या फिर उसे क्लीन चिट मिल जाएगी। एशिया पेसिफिक समूह (एपीजी) की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात की संभावना अधिक है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा क्योंकि देश को उस सूची में डालते समय संस्था ने जो 40 अनुशंसाएं की थी उनमें से पाकिस्तान ने केवल एक का ही पालन किया है। आर्थिक मामलों के मंत्री हमाद अजहर के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल 13 अक्टूबर को फ्रांस रवाना होगा। पाकिस्तान के मामले को 14 तथा 15 अक्टूबर को देखा जाएगा। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि बीते एक वर्ष में उन्होंने खासी प्रगति की है।

दम घुटने से हुई थी पाकिस्तान में हिंदू डेंटल छात्रा की मौत

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान में पिछले महीने हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध हालात में मृत मिली हिंदू डेंटल छात्रा की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि नमृता कुमारी की मौत फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण हुई थी। नमृता लरकाना स्थित बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से डेंटल सर्जरी की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। गत 16 सितंबर को उसका शव हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला था। पुलिस ने इसे खुदकशी का मामला बताया था। लेकिन नमृता के परिजनों और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि यह हत्या का मामला है।

लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज द्वारा तैयार मेडिकल रिपोर्ट बुधवार को लरकाना पुलिस को सौंप दी गई। इसमें कहा गया है कि नमृता के हृदय, किडनी, फेफड़े और लिवर में किसी तरह की कोई असामान्यता नहीं थी। लिहाजा यह अप्राकृतिक मौत का मामला नहीं है।

सिंध में एक और हिंदू लड़की का अपहरण

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक और हिंदू लड़की के अपरहरण का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों का आरोप है कि लड़की का जबरन धर्मांतरण करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जबरदस्ती उठा ले गए थे।

यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन को मुद्दा बनाते हुए सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं। मुल्क में हर साल 12 से 28 साल तक की करीब एक हजार हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कुबूल कराया जा रहा है।

ये भी जानिए
विराट कोहली की कप्तानी में सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हैं, जिनके नाम 227 विकेट हैं। इसके बाद रवींद्र जडेजा का नंबर आता है, जो कोहली की कप्तानी में 149 टेस्ट विकेट ले चुके हैं।

निडर मयंक का हल्ला बोल

- सहवाग के बाद लगातार दो टेस्ट में शतक लगाने वाले भारतीय ओपनर बने मयंक
- भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए तीन विकेट पर 273 रन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी में परिपक्वता साफ झलकती है। यह उनकी कड़ी मेहनत का फल है जो उन्होंने लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट में की है और भारतीय टीम की जर्सी पहनने का इंतजार बड़े धैर्य के साथ किया। विशाखापत्तनम टेस्ट में दोहरा शतक जमाने के बाद पुणे में गुरुवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हुए दूसरे टेस्ट के पहले दिन मयंक ने शतक लगाकर बता दिया है कि वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मयंक के शतक की बदौलत भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 273 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। कप्तान विराट कोहली 63 और अजिंक्य रहाणे 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

अच्छे प्रदर्शन का मिला था इनाम : घरेलू सत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ही मयंक को पिछले साल भारत में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में राष्ट्रीय टीम में चुना गया था। वह हालांकि पदार्पण नहीं कर सके। इसके लिए उन्हें बॉक्सिंग-डे टेस्ट का इंतजार करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला और तब से वह टीम के नियमित सलामी बल्लेबाज बन गए। अब तक विदेशी जमीन पर ही बल्लेबाजी करने वाले मयंक को जब इस सीरीज के जरिये घर में खेलने का मौका मिला तो वह एक निडर हीरो की तरह सामने आए। यह भी संयोग ही है कि वीरेंद्र सहवाग को अपना आदर्श मानने वाले मयंक ने इस शतक के साथ ही सहवाग की बराबरी कर ली। वह सहवाग के बाद लगातार दो टेस्ट में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज बने।

मानसिकता में किया बदलाव: 2014-15 घरेलू सत्र में खराब प्रदर्शन के बाद वह कर्नाटक की टीम से बाहर रहे थे। मयंक ने यहां से अपने खेल के अलावा अपनी मानसिकता को बेहतर रखने के लिए काम किया। उनकी यह मेहनत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिखी। 28 वर्षीय मयंक ने 195 गेंद में 108 रनों की पारी खेली और इस दौरान 16 चौके और दो छक्के लगाए। मयंक स्पिनर केशव महाराज की गेंद पर दो लगातार छक्के लगाकर अपने शतक के करीब पहुंचे और फिर वर्नोन फिलेंडर की गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। अग्रवाल का स्कोर कार्ड उनकी इस खूबसूरत पारी का गवाह है। उन्होंने बाउंड्री से 18 गेंद में 74 रन बनाए, जबकि बाकी के 37 रन 177 गेंद में बनाए। खास बात यह रही कि खेल के शुरुआती घंटे में अग्रवाल ने वर्नोन फिलेंडर (0/37) और कैगिसो रबादा (3/48) पर ज्यादा जल्दी नहीं दिखाई। उन्होंने समझदारी से तीसरे तेज गेंदबाज का इंतजार किया। एनरिक नोर्टजे (0/60) 13 ओवर में कोई विकेट नहीं निकाल सके। नोर्टजे को मयंक ने अच्छे से परेशान किया। वह छोटी गेंद डालते तो मयंक पुल शॉट खेल देते। वह लंबी गेंद रखते तो मयंक शानदार कवर ड्राइव खेल देते।

रबादा का जलवा : दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज रबादा एक मात्र गेंदबाज रहे जिन्हें टेस्ट के पहले दिन विकेट मिले। उन्होंने दिन की शुरुआत में पहले एक शानदार आउट स्विंग गेंद से रोहित शर्मा (14) को विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच कराया। हालांकि रबादा बदकिस्मत रहे जब शॉर्ट लेग में खड़े तेंबा बावुमा ने चेतेश्वर पुजारा (59) का कैच लपकने का मौका गंवा दिया। पुजारा ने इसके बाद मयंक के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 138 रनों की अहम साझेदारी की। रबादा ने ही आखिरकार पुजारा का विकेट लेकर इस साझेदारी को तोड़ा, लेकिन तब तक पुजारा अपने टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक लगा चुके थे। रबादा ने ही मयंक को पवेलियन भेजा।

कोहली ने संभाली कमान: पिछले कुछ समय से फॉर्म से जूझ रहे कप्तान कोहली ने आखिरकार लय पाई। मयंक और पुजारा के आउट होने के बाद कोहली ने जिम्मेदारी से भरी पारी खेली। वह अब अपने शतक की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। कोहली ने 105 गेंद में 10 चौके लगाए और 63 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। वह रहाणे के साथ चौथे विकेट के लिए 75 रनों की अटूट साझेदारी कर चुके हैं।

स्कोर बोर्ड

टॉस : भारत (बल्लेबाजी)

भारत (पहली पारी) 273/3 (85.1 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
मयंक का. डुप्लेसिस बो. रबादा	108	195	16	02
रोहित शर्मा का. डिकॉक बो. रबादा	14	35	01	00
पुजारा का. डुप्लेसिस बो. रबादा	58	112	09	01
विराट कोहली नाबाद	63	105	10	00
अजिंक्य रहाणे नाबाद	18	70	03	00

अतिरिक्त : (लेबा-6, नोबा-6) 12, **कुल** : 85.1 ओवर में तीन विकेट पर 273 रन, विकेट पतन : 1-25 (रोहित, 9.6), 2-163 (पुजारा, 50.6), 3-198 (मयंक, 60.6)

गेंदबाजी : फिलेंडर 17-5-37-0, रबादा 18.1-2-48-3, नोर्टजे 13-3-60-0, महाराज 29-8-89-0, मुथुस्वामी 6-1-22-0, डीन एल्गर 2-0-11-0

अर्धशतकीय पारी खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा। एपी

भारतीय ओपनरों के एक सीरीज में चार शतक

बनाम	वर्ष	ओपनर (शतक)
वेस्टइंडीज	1970	सुनील गावस्कर (4)
वेस्टइंडीज	1978	सुनील गावस्कर (4)
श्रीलंका	2009	सहवाग (2), गंभीर (2)
द. अफ्रीका	2019	रोहित (2), मयंक (2)

रबादा टेस्ट क्रिकेट में अपनी लय दोबारा पा रहे हैं : विंसेंट बर्न्स

पुणे, प्रेट्र : दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी कोच विंसेंट बर्न्स का मानना है कि उनके प्रमुख तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा ने दूसरे टेस्ट में भोजनकाल के बाद जिस तरह का स्पैल डाला उससे साफ है कि वह टेस्ट क्रिकेट में अपनी लय दोबारा पा रहे हैं। बर्न्स ने कहा कि रबादा को गेंदबाजी करते देखना शानदार था, खास तौर पर भोजनकाल के बाद। मुझे लगता है कि रबादा ने विशाखापत्तनम में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। गुरुवार को उन्होंने संकेत दिए कि वह दोबारा से शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के विकेट पर तेज गेंदबाजों के लिए संयम बेहद जरूरी होता है। रबादा ने इसी संयम से चेतेश्वर पुजारा का विकेट लेकर दिखाया। हम इस दौरे पर अपनी मजबूती के साथ गेंदबाजी करना चाहते हैं। रणनीति यही है कि विकेट पर संयम बरता जाए। हमने ठीक जगह पर गेंदबाजी की और उन्होंने गलती की। पुजारा एक समय अच्छी तरह से सेट हो चुके थे और रबादा ने सही जगह पर गेंद डाली और वह विकेट लेने में कामयाब रहे।

मयंक ने घरेलू क्रिकेट से बड़ी पारियां खेलने का हुनर सीखा : पुजारा

पुणे, प्रेट्र: भारत के अनुभवी टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि घरेलू क्रिकेट में 2017 में एक ही सत्र में 1000 रन पूरे करने वाले मयंक अग्रवाल ने बड़ी पारियां खेलने का हुनर घरेलू क्रिकेट से सीखा है। नए ओपनर अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में दोहरा शतक जमाने के बाद दूसरे टेस्ट के पहले दिन शतक जड़ा।

पुजारा ने कहा कि अग्रवाल अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में काफी रन बनाए हैं। इससे उन्हें काफी मदद मिली। 90 के पास पहुंचने पर नर्वस होने की बात है तो वह इस मामले में निर्भीक हैं। उन्हें पता है कि पचासे को बड़ी पारियों में कैसे बदलना है। शतक पूरा करने पर वह बड़ी पारी खेलने में भी माहिर हैं। स्वयं बड़ी पारियां खेलने में माहिर पुजारा ने साझेदारी के दौरान अग्रवाल को क्या टिप्स दिए, यह पूछने पर उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट से बड़े स्कोर बनाने की आदत डल जाती है। मुझे उन्हें ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ा। हम उनकी रणनीति पर ही बात कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में खामी होने पर मैं सिर्फ इतना कहता था कि शरीर के पास खेलो।

पुजारा ने कहा, रबादा ने मुझसे छींटाकशी करने की कोशिश की: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा ने भारतीय पारी के दौरान चेतेश्वर पुजारा से छींटाकशी करने की कोशिश की। इस पर पुजारा ने कहा कि वह मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अपने ही जोन में था। रबादा ने पुजारा को आउट करने के बाद कुछ कहा था, क्योंकि वह तेंबा बावुमा के कैच छोड़ने की वजह से उन्हें शून्य पर आउट नहीं कर पाए थे। पुजारा ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि वह क्या कह रहे थे, लेकिन वह उनमें से एक हैं जो हमेशा बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ कहना पसंद करते हैं। यदि आप अपने जोन में होते हो तो आप मुश्किल से सुन पाते हो। बल्लेबाज होने के नाते आपको ऐसा करना भी चाहिए। ऐसे में जब आप अपने जोन में होते हो तो चूक जाते हो कि कोई क्या कह रहा है।

06 टेस्ट में मयंक अग्रवाल ने पहली पारी में पांच बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि दूसरी पारी में अब तक वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं

09 लगातार टॉस एशिया में द. अफ्रीका टीम ने टेस्ट में गंवाए हैं, जबकि छह लगातार टॉस फाफ डुप्लेसिस घर के बाहर टेस्ट में हार चुके हैं

50 टेस्ट में कप्तानी करने वाले कोहली दूसरे भारतीय हैं। महेंद्र सिंह धौनी ने 60 टेस्ट में कप्तानी की थी

शतकीय पारी के दौरान शॉट लगाते हुए मयंक अग्रवाल • एएफपी

दिल्ली ने चखाया ओडिशा को हार का मजा

विजय हजारे ट्रॉफी

वडोदरा, प्रेट्र : दिल्ली ने अपने तीन बल्लेबाजों के अर्धशतक की मदद से गुरुवार को यहां खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड-9 के मैच में ओडिशा को 63 रनों से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अनुज रावत (69), नीतीश राणा (56) और कप्तान ध्रुव शौरी (51) के अर्धशतकों की मदद से छह विकेट पर 299 रन का स्कोर बनाया और फिर ओडिशा को निर्धारित 50 ओवर में आठ विकेट पर 236 रन पर रोक दिया। ओडिशा के लिए कप्तान शुभ्रांशु सेनापति ने सर्वाधिक 77, राजेश मोहंती ने नाबाद 39 और अभिषेक राउत ने नाबाद 32 रन बनाए। सेनापति ने 77 गेंदों का सामना किया, जिसमें उसने आठ चौके और दो छक्के लगाए। दिल्ली की ओर से मनन शर्मा ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए।

बंगाल ने बिहार को दी मात
जयपुर, प्रेट्र : कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (नाबाद 112) के शानदार शतक की मदद से बंगाल ने गुरुवार को यहां खेले गए राउंड-12 के मैच में बिहार को नौ विकेट से हरा दिया। बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 216 रन का स्कोर बनाया, जिसे बंगाल ने ईश्वरन के शतक की मदद से 40.2 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। ईश्वरन ने 122 गेंदों पर नाबाद शतकीय पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया। उनके अलावा अभिषेक रमन ने 96 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से नाबाद 61 और श्रीवत्स गोस्वामी ने 23 रनों का योगदान दिया। इससे पहले बिहार ने बाबुल कुमार (93) और मुहम्मद रहमतउल्लाह (53) के अर्धशतक के सहारे सात विकेट पर 216 रन का स्कोर बनाया। बंगाल की ओर से आकाश दीप ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए।

हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को दी शिकस्त
वडोदरा, प्रेट्र : मयंक डागर (4/19) की शानदार गेंदबाजी के दम पर हिमाचल प्रदेश ने गुरुवार को यहां खेले गए राउंड-9 के मैच में हरियाणा को 84 रनों से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 214 रन का स्कोर बनाया और फिर हरियाणा को 38.2 ओवर में 130 रन पर ऑल आउट कर दिया। हिमाचल के लिए अमित कुमार ने 47, प्रियांशु खंडुरी ने 42, आयुष जयसवाल ने 28 और ऋषि धवन ने 22 रनों का योगदान दिया। हरियाणा की तरफ से कप्तान अमित मिश्रा और युजवेंद्रा सिंह चहल ने दो-दो विकेट लिए।

बीसीसीआइ की शीर्ष परिषद का हिस्सा होंगी रंगास्वामी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत की पूर्व महिला कप्तान शांता रंगास्वामी बीसीसीआइ की शक्तिशाली शीर्ष परिषद का हिस्सा होंगी, जिनका भारतीय क्रिकेटरों के संघ (आइसीए) में निर्विरोध चुना जाना तय है। नामित उम्मीदवारों की अंतिम सूची में रंगास्वामी आइसीए की प्रतिनिधि होने के नाते बीसीसीआइ की नौ सदस्यीय शीर्ष परिषद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने इस परिषद की अनुशंसा की है।

आइसीए अध्यक्ष और आइपीएल संचालन परिषद में इसके प्रतिनिधि के निर्विरोध निर्वाचित होने से तीन दिवसीय चुनाव में पुरुष प्रतिनिधि के लिए मुख्य मुकाबला पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद और अंशुमन गायकवाड़ के बीच है। तीसरे पूर्व क्रिकेटर सौराष्ट्र के राकेश ध्रुवे हैं।

अशोक मलहोत्रा और सुरेंदर खन्ना का आइसीए अध्यक्ष और आइपीएल संचालन परिषद प्रतिनिधि के तौर पर निर्विरोध चुना जाना तय है। ऑनलाइन होने वाले चुनाव में 1267 आइसीए सदस्य भाग लेंगे, जिसका नतीजा मंगलवार को निकलेगा।

अंशू दानी और हितेश मजूमदार सचिव पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, जबकि कोषाध्यक्ष के लिए किशोर कुमार और वी कृष्णास्वामी के बीच मुकाबला होगा।

विश्व चैंपियनशिप की सबसे सफल मुक्केबाज बनीं मेरी, सेमीफाइनल में पहुंच आठवां पदक किया पक्का

सुपर मॉम मेरी कॉम से बढ़कर कोई नहीं

उलान-उदे (रूस), प्रेट्र: छह बार की चैंपियन एमसी मेरी कॉम (51 किग्रा) ने सटीक पंच और अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए महिला विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। 36 वर्षीय और तीन बच्चों की मां मेरी कॉम ने एकतरफा अंदाज में कोलंबिया की वालेंशिया विक्टोरिया को 5-0 से शिकस्त दी।

सुपर मॉम मेरी कॉम ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। वह विश्व चैंपियनशिप के इतिहास की सबसे सफल मुक्केबाज बन गईं और अपना आठवां पदक भी पक्का किया। पदकों की संख्या के आधार पर वह पुरुष और महिला दोनों में सबसे सफल हैं। पुरुष वर्ग में क्यूबा के फेलिक्स सावोन ने सर्वाधिक सात पदक (छह स्वर्ण, एक रजत) जीते हैं। मेरी कॉम के नाम अभी तक छह स्वर्ण और एक रजत पदक है, लेकिन वह 51 किग्रा में पहली बार पदक जीतेंगी। इस साल उन्होंने गुवाहाटी में इंडिया ओपन और इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट ओपन में स्वर्ण पदक जीता था। वह राज्यसभा सदस्य भी है। तीसरी वरीयता प्राप्त मेरी कॉम का शनिवार को सामना दूसरी वरीयता प्राप्त तुर्की की बुसेनाज साकिरोग्लू से होगा।

मुकाबले की विजेता घोषित होते समय भारत की दिग्गज मुक्केबाज मेरी कॉम • प्रेट्र

"प्री-क्वार्टर फाइनल की तुलना में यह मैच आसान था। मैं हमेशा से कहती आई हूं कि मैं अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ कोशिश करूंगी, लेकिन नतीजे मेरे हाथ में नहीं हैं। मेरी कोशिश स्वर्ण जीतने की है।
एमसी मेरी कॉम, भारतीय महिला मुक्केबाज

मेरी कॉम ने पदक पक्का कर लिया है। वह पहले ही विश्व चैंपियनशिप के छह स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। वह एक दिग्गज मुक्केबाज हैं। हमें उम्मीद है कि वह स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल करेंगी।"
किरण रिजिजू, केंद्रीय खेल मंत्री

विश्व चैंपियनशिप में मेरी कॉम के पदक

2001	स्क्रेंटन
2002	एंटाल्या
2005	पोडॉल्स्क
2006	नई दिल्ली
2008	निंग्बो सिटी
2010	ब्रिजटाउन
2018	नई दिल्ली
2019	उलान-उदे ?

05 स्वर्ण पदक और एक रजत पदक 36 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम एशियन चैंपियनशिप में भी अपने नाम करने में सफल रही हैं

2012 लंदन ओलंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक में उनका यह एकमात्र पदक है

01 स्वर्ण पदक मेरी कॉम ने 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में अपने नाम किया था, जबकि 2010 ग्वांग्झू में कांस्य हासिल कर पाई थीं

2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरी कॉम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था और यह उनका इन गेम्स में एकमात्र पदक है

मंजू, लवलीना और जमुना अंतिम-चार में

उलान-उदे (रूस), प्रेट्र: भारतीय खिलाड़ी मंजू रानी (48 किग्रा), पिछले सत्र की कांस्य पदक विजेता और तीसरी वरीयता प्राप्त लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा) और जमुना बोरो (54 किग्रा) भी गुरुवार को महिला विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गईं और अपना-अपना पदक पक्का कर लिया। हरियाणा की रानी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त और पिछली बार की कांस्य पदक विजेता दक्षिण कोरिया की किम हयांग मि को 4-1 से मात दी। वहीं, असम राइफल्स की बोरो ने जर्मनी की उर्सुला गोटलोब को इसी अंतर से हराया। इसके अलावा बोरगोहेन ने पोलैंड की छठी वरीयता प्राप्त कैरोलिना कोजेवस्का को 4-1 से मात दी। रानी का सामना अब थाइलैंड की सी रकसात से होगा। वहीं, बोरो शीर्ष वरीय एशियन गेम्स की पूर्व कांस्य पदक विजेता हुआंग सियाओ वेन से भिड़ेंगी। बोरगोहेन की टक्कर चीन की यांग लियू से होगी, जिन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त चेन निएन चिन को हराया। दो बार की कांस्य विजेता कविता चहल (81 किग्रा से ज्यादा) बेलारूस की कैटसियारिना कावालेवा से 0-5 से हार गईं।

आठ संघों पर बीसीसीआइ एजीएम में भाग लेने पर रोक लगी

38 में से अब 30 ही राज्य संघ ले सकेंगे एजीएम में हिस्सा, उप्र, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मणिपुर, सेना, रेलवे, विश्वविद्यालय को लगा झटका

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: बीसीसीआइ की 38 में से आठ राज्य इकाइयों के मुंबई में 23 अक्टूबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने पर गुरुवार को रोक लगा दी गई है, क्योंकि उन्होंने संविधान में संशोधन का अनुपालन नहीं किया।

बीसीसीआइ के निर्वाचन अधिकारी एन गोपालस्वामी द्वारा अंतिम मतदाता सूची जारी करने के बाद एजीएम में भाग लेने वालों पर स्थिति स्पष्ट हो गई। एजीएम के दौरान अगर पदाधकारियों के लिए चुनाव होता है तो मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, रेलवे, सेना और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के पास मतदान का अधिकार नहीं होगा। तीन सरकारी संस्थानों को इसलिए प्रतिबंधित किया गया क्योंकि वह खिलाड़ियों का संघ बनाने में नाकाम रहे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली एजीएम में बंगाल क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि होंगे, जिसके वह अध्यक्ष हैं। भारत के एक अन्य पूर्व कप्तान मुहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। रजत शर्मा (दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ), जय शाह (सौराष्ट्र क्रिकेट संघ), अरुण सिंह धूमल (हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ) और बृजेश पटेल (कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ) अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। एजीएम में भाग लेने से रोके जाने वाले ज्यादातर राज्यों के द्वारा इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की संभावना है, जिससे एजीएम अधर में पड़ सकता है।

इससे पहले बुधवार को प्रशासकों की समिति ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए), महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) और हरियाणा क्रिकेट संघ (एचसीए) को एजीएम में भाग लेने से रोक दिया था। टीएनसीए का प्रतिनिधित्व सचिव एसएस रामास्वामी को करना था, जबकि हरियाणा की नुमाइंदगी मृणाल ओझा कर रहे थे। महाराष्ट्र को एजीएम से हटा दिया गया क्योंकि चैरिटी आयुक्त ने क्रिकेट संघ के संशोधित संविधान में विसंगतियां पाई थी। एमसीए अब भी बीसीसीआइ के पूर्व सचिव अजय शिर्के के नियंत्रण में है जिसका प्रतिनिधित्व रियाज बागबान को करना था।

टीएनसीए ने बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ को हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। आरोप है कि टीएनसीए के 21 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें लोढ़ा समिति की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया गया है जिसमें उम्र सीमा और दो कार्यकाल के बीच बाहर रहने के लिए तय अनिवार्य अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) का अनुपालन नहीं किया जाना शामिल है। हरियाणा और महाराष्ट्र को भी इसी तर्ज पर रोका गया है।

मतदान में भाग लेने वाले राज्य संघ और उनके प्रतिनिधि

संघ	प्रतिनिधि	संघ	प्रतिनिधि
1. आंध्र प्रदेश क्रिकेट संघ	शरथ चंद्र रेड्डी	16. जम्मू एवं कश्मीर क्रिकेट संघ	आबिद सलाम
2. अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट संघ	नबम विवेक	17. झारखंड राज्य क्रिकेट संघ	नफीस अख्तर
3. असम क्रिकेट संघ	देवाजीत साइकिया	18. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ	बृजेश पटेल
4. बड़ौदा क्रिकेट संघ	प्रणव अमीन	19. केरल क्रिकेट संघ	जयेश ज्यॉर्ज
5. बिहार क्रिकेट संघ	राकेश कुमार तिवारी	20. मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ	राजू सिंह चौहान
6. छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ	प्रभतेज सिंह भाटिया	21. मेघालय क्रिकेट संघ	एल खारकोनगोर
7. बंगाल क्रिकेट संघ	सौरव गांगुली	22. मुंबई क्रिकेट संघ	संजय मधुकर नायक
8. मिजोरम क्रिकेट संघ	एम खैरुल जमाल	23. नगालैंड क्रिकेट संघ	हयूनिलो अनिलो खिंग
9. पुडुचेरी क्रिकेट संघ	पी दामोदरन	24. ओडिशा क्रिकेट संघ	संजय बहरा
10. उत्तराखंड क्रिकेट संघ	महिम वर्मा	25. पंजाब क्रिकेट संघ	राकेश राठौर
11. दिल्ली एंव जिला क्रिकेट संघ	रजत शर्मा	26. राजस्थान क्रिकेट संघ	वैभव गहलोत
12. गोवा क्रिकेट संघ	सूरज लोटलीकर	27. सिक्किम क्रिकेट संघ	लोबजांग जी तेनजिंग
13. गुजरात क्रिकेट संघ	जय शाह	28. सौराष्ट्र क्रिकेट संघ	जयदेव शाह
14. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ	अरुण सिंह धूमल	29. त्रिपुरा क्रिकेट संघ	मानिक साहा
15. हैदराबाद क्रिकेट संघ	मुहम्मद अजहरुद्दीन	30. विदर्भ क्रिकेट संघ	आनंद मनोहर देशपांडे

सीओए का फैसला मनमाना और गलत

कोलकाता, प्रेट्र : बीसीसीआइ के पूर्व प्रमुख कानूनी सलाहकार ऊषा नाथ बनर्जी ने तीन राज्य संघों को बोर्ड की एजीएम में भाग लेने से रोकने के सीओए के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे 'पूरी तरह मनमाना और गलत' करार दिया। बनर्जी ने हालांकि कहा कि अगर किसी राज्य ने बदलावों का अनुपालन नहीं किया है तो उसे पहले साल के लिए वित्तीय अनुदान और अन्य लाभों से वंचित किया जा सकता है, लेकिन एजीएम में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता है। बनर्जी ने कहा, 'एक बार जब राज्य संघ पूर्ण सदस्य के तौर पर मान्यता प्राप्त कर लेता है, तब एजीएम में भाग लेना और मतदान करना उसका कानूनी और संवैधानिक अधिकार है।'

रोक लगने वाले संघ और उनके प्रतिनिधि

संघ	प्रतिनिधि
उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ	राजीव शुक्ला
तमिलनाडु क्रिकेट संघ	एस एस रामास्वामी
हरियाणा क्रिकेट संघ	मृणाल ओझा
महाराष्ट्र क्रिकेट संघ	रियाज बागबान
मणिपुर क्रिकेट संघ	
रेलवे	हरविंदर सिंह
सेना	संजय वर्मा
भारतीय विश्वविद्यालय	राजीव नय्यर

आइसीसी टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनीं भारत की लक्ष्मी

आइसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप क्वालीफायर के लीग चरण के मैचों के लिए अधिकारियों की सूची घोषित

दुबई, एएनआइ: भारत की जीएस लक्ष्मी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के टूर्नामेंट की पहली महिला रेफरी बन गई हैं। आइसीसी ने गुरुवार को आइसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप क्वालीफायर-2019 के लीग चरण के लिए मैच अधिकारियों की सूची की घोषणा की। लक्ष्मी के साथ-साथ न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जेफ क्रो भी इसमें शामिल हैं। क्रो को तीन आइसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप सहित 488 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आधिकारिक रूप से काम करने का अनुभव है।

आइसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप क्वालीफायर-2019 का आयोजन यूएई में 18 अक्टूबर से दो नवंबर के दौरान होगा। लक्ष्मी अबू धाबी के जायद स्टेडियम में हांगकांग और आयरलैंड के बीच होने वाले मैच में रेफरी की भूमिका निभाएंगी। इस मैच में अंपायर सैम नोगाज्स्की और सुंदरम रवि होंगे। इसके अलावा क्रो ओमान बनाम यूएई मैच में रेफरी होंगे। इस मैचों में अंपायर एलेक्स व्हार्फ और अल्लाहुद्दीन पालेकर होंगे।

आइसीसी ने इसी साल मई में लक्ष्मी को अपने मैच रेफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल में जगह दी थी। वह इस पैनल में जगह पाने वाली पहली महिला बनी थीं। आइसीसी की तरफ से बताया गया था कि लक्ष्मी तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय मैचों में रेफरी की भूमिका निभाने के योग्य हो गई हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली 51 साल की लक्ष्मी ने 2008-2009 में पहली बार घरेलू महिला क्रिकेट में मैच रेफरी की भूमिका निभाई थी। वह एक महिला वनडे अंतरराष्ट्रीय और तीन महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रेफरी रह चुकी हैं। लक्ष्मी और क्रो के अलावा इस टूर्नामेंट के लिए दक्षिण अफ्रीका के गेरहार्डस पाइनेयर तीसरे मैच रेफरी हैं। सूची में कुल 12 अंपायर हैं।

आइसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप क्वालीफायर-2019 के मैच अधिकारी

मैच रेफरी: जेफ क्रो, जीएस लक्ष्मी और गेरहार्डस पाइनेर।
अंपायर: रोलैंड ब्लैक, क्रिस ब्राउन, लिंडन हैनिबल, सैम नोगाज्स्की, अहमद शाह पकाते, अल्लाहुद्दीन पालेकर, राशिद रियाज, सुंदरम रवि, अहसान रजा, शर्फुद्दीन इब्ने शाहिद, एलेक्स व्हार्फ और रवींद्र विमलसिरी।

लंदन में हार्दिक पांड्या से मिली नीता अंबानी

लंदन, आइएएनएस : हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने हाल में लंदन में सर्जरी करवाई है। सर्जरी के बाद रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी हार्दिक का हालचाल पूछने पहुंचीं। नीता भी इस समय स्पोर्ट्स बिजनेस समिट में भाग लेने के लिए लंदन में हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स समिट में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कहानी साझा की थी। नीता ने बुधवार को हार्दिक से मुलाकात की। इस संबंध में हार्दिक ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है।

मुझे लगता है कि नेमार ने बार्सिलोना छोड़कर गलती की है।
– लियोन मेसी, बार्सिलोना के फुटबॉलर

40 साल बाद ईरानी महिलाओं ने देखा फुटबॉल मैच

फुटबॉल डायरी ▶ ईरान ने फुटबॉल या दूसरे स्टेडियमों में महिलाओं के आने पर लगा रखी थी रोक

ईरान ने विश्व कप क्वालीफायर मैच में कंबोडिया को 14–0 से रौंदा

तेहरान, रायटर : ईरानी महिलाओं ने गुरुवार को 40 साल बाद पहली बार यहां अपने देश का कोई फुटबॉल मैच स्टेडियम में देखा। ईरान ने करीब 40 वर्षों से अपने यहां किसी फुटबॉल या दूसरे स्टेडियमों में महिलाओं के आने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन हाल ही में फुटबॉल की शीर्ष संस्था फीफा ने उसे यहां के स्टेडियमों में महिलाओं के आने पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद निलंबन से डरकर ईरानी फुटबॉल संघ ने फीफा को आश्वस्त किया था कि वह महिलाओं को स्टेडियम में आने की इजाजत देगा।

2022 फीफा विश्व कप क्वालीफायर में ईरान ने दनादन गोल करते हुए कंबोडिया को 14-0 से रौंद दिया। टीम के लिए करीम अंसारीफर्द (40, 48, 60, 88वें मिनट), सरदार अजमून (11, 35, 44वें मिनट), मेहदी टरेमी (22, 54वें मिनट) मुहम्मद मोहेबी (65, 67वें मिनट), अहमद नौरल्लाही (05वें मिनट), होस्सेइन कनानीजादेगन (18वें मिनट) और मेहरदाद (85वें मिनट) ने गोल किए।

ब्लू गर्ल को श्रद्धांजलि : आजादी स्टेडियम में एक हिस्सा महिलाओं के लिए रखा गया था और 3000 से अधिक महिलाओं ने मैच देखा। इस दौरान महिलाओं की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि वे झंडे, वुजुजेला हॉर्न और टीम के रंग वाली लाल, हरे और सफेद रंग के कपड़े पहनकर मैच देख रही थीं। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने ब्लू गर्ल को श्रद्धांजलि दी, जबकि फीफा को भी धन्यवाद किया। ब्लू गर्ल नाम से मशहूर एक ईरानी फुटबॉल प्रशंसक की हाल ही में हुई मृत्यु के बाद यह मामला शुरू हुआ था। उस महिला प्रशंसक को सुरक्षा अधिकारियों ने उस समय पकड़ लिया था जब वह पुरुष के भेष में एक मैच देखने के लिए स्टेडियम में घुसने का प्रयास कर रही थी। इसके बाद उसने जेल जाने के डर से खुद को आग लगा दी, जिसके बाद उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।

एक ईरानी महिला प्रशंसक ने कहा, 'हमें अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा नाम उन महिलाओं में गिना जाएगा जो 40 साल बाद स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने पहुंची थीं। सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में एक महिला प्रशंसक राष्ट्रीय झंडे के साथ रोते हुए मैच के दौरान मैदान में घुस गई। प्रशंसक ने कहा, 'मेरे पास अपनी खुशी जताने के लिए शब्द नहीं है। हमें यहां आने की अनुमति देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।' प्रचारक चाहते हैं कि महिलाओं को सभी खेलों के लिए स्टेडियम में जाने दिया जाए ना कि विश्व कप क्वालीफायर में जो फीफा की जिम्मेदारी के तहत मैच होते हैं।

ईरान और कंबोडिया के बीच हुए मैच को देखने बड़ी संख्या में ईरानी महिलाएं पहुंचीं। एएफपी

भारतीय टीम काफी हद तक छेत्री पर निर्भर : भूटिया

कोलकाता, प्रेट्र : पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने गुरुवार को कहा कि भारतीय फुटबॉल टीम के स्ट्राइकर काफी हद तक सुनील छेत्री के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि गोल करने के मौके बनाने के लिए दूसरे खिलाड़ियों को भी खेल के स्तर को ऊंचा करना होगा। भूटिया ने कहा, 'हमारी मुख्य चिंता डिफेंस की रही है और अगर टीम अपने प्रदर्शन को बनाए रखती है तो अच्छा होगा। अब बांग्लादेश के खिलाफ मैच स्ट्राइकरों के लिए बड़ी परीक्षा होगा। अब डिफेंस की जगह स्ट्राइकरों को योगदान करना होगा। मुझे लगता है कतर के खिलाफ (ड्रॉ मैच में) भारत ने अच्छा बचाव किया।

मेसी के बिना अर्जेंटीना ने जर्मनी से खेला ड्रॉ

डॉर्टमंड (जर्मनी), एएफपी : सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी के बिना खेल रही अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने दोस्ताना मैच में जर्मनी के खिलाफ 2–2 से रोमांचक ड्रॉ खेला। मैच में अर्जेंटीना की टीम ने दो गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मुकाबला ड्रॉ किया। मेसी इस मैच में नहीं खेले। स्पेनिश क्लब एफसी बार्सिलोना से खेलने वाले मेसी को दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ (कोनमबोल) ने तीन महीनों के लिए निलंबित किया हुआ है। मेसी ने इस साल हुए कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के दौरान कोनमबोल की आलोचना की थी जिसके कारण उन्हें तीन महीने का निलंबन झेलना पड़ रहा है। अपने घर पर खेल रही जर्मनी ने मैच की दमदार शुरुआत की और पहले मिनट से आक्रामक अंदाज में फुटबॉल खेली। 15वें मिनट में सर्गी ग्नाबरी ने गोल करते हुए मेजबान टीम को बढ़त दिला दी। जर्मनी की टीम जल्द ही अपनी बढ़त को दोगुना करने में भी कामयाब रही। 22वें मिनट में काई हार्वटेज को मौका मिला और उन्होंने गोल करते हुए मेजबान टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया।

स्मिथ गेंदबाजों को असमंजस में डाल रहे हैं : स्टेन

जोहानिसबर्ग, आइएएनएस : दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की उनकी निरंतरता के लिए तारीफ की है। स्मिथ पर बॉल टेंपरिंग के कारण एक साल का प्रतिबंध लगा था। प्रतिबंध के बाद वापसी करते हुए स्मिथ ने एशेज सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की और 110.57 की औसत से 774 रन जोड़े। साथ ही वह भारत के विराट कोहलो को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में नंबर-1 रैंकिंग पर भी कब्जा जमाया।

स्टेन ने कहा कि स्टीव के पास जो तकनीक है, जो उन्होंने विकसित की है, उससे वे गेंदबाजों को बाएं, दाएं और मध्य में आकर असमंजस में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह शानदार खिलाड़ी हैं। उनकी आंखे बेहतरीन काम करती हैं। उनकी तकनीक अलग और मुश्किल है जो उनके लिए अच्छी तरह काम कर रही है। एक ओर जहां स्मिथ ने एशेज में दमदार प्रदर्शन किया था वहीं उनके ही साथ एक साल के लिए प्रतिबंधित किए गए सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर एशेज में खराब फॉर्म में थे। स्टेन ने वार्नर का बचाव भी किया है। स्टेन ने कहा कि मैंने जितने भी बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी की है उनमें वह सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। वह पहली गेंद और टेस्ट में पहले दिन से आप पर दबाव डालते हैं। विश्व स्तर के खिलाड़ी रातों-रात खराब नहीं बनते, खासकर एक खराब दौरे से भी नहीं। वह फॉर्म में आ जाएंगे। मैं उन्हें टीम से बाहर नहीं करूंगा।

कप्तानी की चर्चाओं को परे रख खेल पर ध्यान दे रहे हैं कैरी

नई दिल्ली, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया की सीमित ओवरों की टीम के उप–कप्तान एलेक्स कैरी टेस्ट में कप्तानी की चर्चाओं पर ध्यान न देकर अपने खेल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चर्चा है कि विकेटकीपर कैरी टेस्ट में टिम पेन के विकल्प के रूप में स्थान ले सकते हैं। पेन विकेटकीपर भी हैं और कप्तान भी। कैरी हालांकि इन सभी बातों के बचाना चाहते हैं। कैरी ने कहा कि मैं उन लोगों का समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा नाम आगे किया, लेकिन मैंने अपने खिलाड़ी के तौर पर किए गए सफर में यह पाया है कि जब तक आपका नाम टीम में न आए तब तक कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलने को सपने के तौर पर देखा है। मैं खेल भी इसलिए रहा हूं कि मैं सुधार कर सकूं और ऑस्ट्रेलिया तथा दुनिया का नंबर–1 विकेटकीपर बन सकूं। कैरी ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टी–20 टीम के उप–कप्तान हैं और टीम के मध्य क्रम में योगदान निभाते हैं। कैरी कहते हैं कि वह अपनी टीम के लिए वही फिनिशर का काम करना चाहते हैं जो महेंद्र सिंह धौनी भारत और जोस बटलर इंग्लैंड के लिए कर रहे हैं।

पहली बार भारत का ओलंपिक आतिथ्य गृह होगा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए पहली बार भारत का ओलंपिक आतिथ्य गृह बनेगा। भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) और जेएसडब्ल्यू समूह ने गुरुवार को इस सुविधा को बनाने के लिए साझेदारी की।

ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले कई देश गेम्स के दौरान अपना आतिथ्य गृह बनाते हैं, लेकिन भारत के लिए यह पहली बार होगा। इसमें भारतीय संस्कृति और विरासत को दिखाया जाएगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और महासचिव राजीव मेहता की मौजूदगी में इंडिया हाउस के लोगो का अनावरण किया। रिजिजू ने कहा, 'टोक्यों में होने वाले ओलंपिक के लिए इंडिया हाउस शानदार विचार है। हमें ऐसी टीम की जरूरत है जो चैंपियन खिलाड़ी बना सके। ओलंपिक के लिए हमें खिलाड़ियों को सही माहौल देना होगा। टोक्यो गेम्स में इंडिया हाउस भारत की झलक पेश करेगा। इंडिया हाउस अगले साल जुलाई में खुल जाएगा और इसका निर्माण खेल गांव के और खेल परिसर के पास 2,200 स्क्वॉयर मीटर क्षेत्र में होगा। यह भारतीय एथलीटों के लिए घर जैसा माहौल उपलब्ध कराएगा, जहां उनके लिए चिकित्सा सुविधा के साथ भोजन भी उपलब्ध रहेगा।'

रिजिजू ने कहा कि भारत अगर 2028 ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष-10 में नहीं आता तो वह खेल मंत्री के रूप में नाकाम रहेंगे। भारत कुछ साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और खेलों में भी वह पीछे नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, 'हमारा देश 2022 या 2024 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हम अगले चार-पांच साल में कई क्षेत्रों में शीर्ष-तीन में रहेंगे। ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने का कोई कारण नहीं है।

तेज गेंदबाजों ने भारतीय क्रिकेट का रुख बदल दिया : कपिल

मुंबई, प्रेट्र : दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव ने मौजूदा तेज आक्रमण की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले चार-पांच साल में इन गेंदबाजों ने भारतीय क्रिकेट का रुख बदल दिया।

▶ कहा, मुझे भारतीय गेंदबाजों की प्रतिभा पर गर्व है

▶ उन्हें शानदार प्रदर्शन करते देखना अच्छा लगता है

कपिल से जब पूछा गया कि क्या मौजूदा भारतीय तेज आक्रमण सर्वश्रेष्ठ है तो उन्होंने कहा, 'क्या मुझे यह कहने की जरूरत है? ऐसे तेज गेंदबाजों का आक्रमण हमने देखा नहीं था, सोचा थी नहीं था। इसलिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है और हां, बिना किसी संदेह के पिछले चार-पांच वर्षों में तेज गेंदबाजों ने भारतीय क्रिकेट का रुख बदल कर रख दिया।'

मौजूदा भारतीय तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, मुहम्मद शमी, इशांत शर्मा, दीपक चाहर और नवदीप सैनी शामिल हैं। चोट के कारण बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज की टीम में नहीं हैं, लेकिन शमी ने विशाखापत्तनम में पहले टेस्ट में शानदार गेंदबाजी कर उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। कपिल ने कहा, 'इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह रैंकिंग में शीर्ष-10 में शामिल नहीं हैं। यह मायने रखता है कि वह टीम के लिए कितने प्रभावशाली हैं। उन्हें शानदार प्रदर्शन करते देखना अच्छा लगता है।'

कपिल ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि भारत से ऐसे विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे भारतीय गेंदबाजों की प्रतिभा पर गर्व है। वे अच्छी संख्या में आ रहे हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण का विकास होने में समय लगता है। अभी जितनी क्रिकेट खेली जा रही उसे देखकर अच्छा लगता है। आइपीएल के कारण कई तेज गेंदबाजों को मौका मिल रहा है।' उन्होंने तेज गेंदबाजों का भविष्य उज्ज्वल बताया।

दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव। (फाइल)

'मानद क्षमता में बैठक में भाग लेना हितों का टकराव नहीं हो सकता'

मुंबई, प्रेट्र : हितों के टकराव के आरोप के बाद क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) से इस्तीफा देने वाले पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने गुरुवार को यहां कहा कि क्रिकेट के पेशेवर काम के साथ मानद क्षमता में बैठक में भाग लेना हितों का टकराव नहीं हो सकता।

कपिल की अगुआई में क्रिकेट सलाहकार समिति ने भारतीय टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री का चयन किया था। बीसीसीआइ के नैतिक अधिकारी डीके जैन ने सीएसी (कपिल, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी) को नोटिस भेजकर उनके खिलाफ लगे हितों के टकराव के आरोपों का जवाब देने को कहा था। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने इनके खिलाफ शिकायत दायर की थी, जिन्होंने अगस्त में मुख्य कोच के पद पर रवि शास्त्री को चुना था। नोटिस मिलने के बाद सीएसी के तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। कपिल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'हितों का टकराव क्या है। टकराव तब होता है जब आप नियमित काम करते हैं। आपको एक बैठक के लिए बुलाया जाता है तो वह टकराव नहीं होता है। आप पे रोल (नियमित वेतन) पर हैं तो यह टकराव है। अगर आप किसी मानद काम के लिए जाते हैं तो वह हितों का टकराव नहीं है।'

पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर बोले मिस्बाह, टीम बहुत खराब खेली

लाहौर, आइएएनएस : पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और चयनकर्ता प्रमुख मिस्बाह उल हक दोयम दर्जे की श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में टीम के प्रदर्शन से काफी नाखुश हैं। श्रीलंका ने ओशादा फनार्डो (नाबाद 78) के बाद मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बने वानिंदु हसरंगा के तीन विकेटों की मदद से श्रीलंका ने यहां गद्दाफी स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए तीसरे टी-20 मैच में दुनिया की नंबर एक टीम पाकिस्तान को 13 रनों से हराकर तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली।

मिस्बाह ने कहा कि उन्होंने हमें खेल के सभी विभागों में हरा दिया। श्रीलंका ने हमें एकतरफा अंदाज में शिकस्त दी। यह काफी निराशाजनक है और हम बहुत खराब खेले, लेकिन इसी टीम ने हमें नंबर वन बनाया था। मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता दोनों पदों पर काबिज मिस्बाह ने खुद का बचाव करते हुए कहा कि आप मुझे दोषी मानते हैं तो मैं दस दिन पहले ही आया हूं।

विविध

कांवड़ लाने वाले बाबू खां को परिजनों ने जमकर पीटा

जासं, बागपत : दो साल से कांवड़ लाने वाले बाबू खां की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अब भगवान गणेश और गाय माता की मूर्ति रखकर पूजा करते समय परिजनों ने उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय इलाज कराने की नसीहत देकर टरका दिया। बाबू खां ने उप्र के बागपत कलक्ट्रेट प्रभारी से आरोपित परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

गुरुवार को कलक्ट्रेट पहुंचे बाबू खां ने बताया कि पांच अक्टूबर की सुबह पांच बजे वह घर पर मूर्तियां रखकर पूजा कर रहे थे। तभी पत्नी, दो बेटों, भाई और भाभी ने हमला कर उनके साथ मारपीट की। उनके मुंह व पैर में काफी चोट आई। थाना बिनौली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच नहीं कराई। पुलिस ने दो के खिलाफ शांतिभंग में चालान कर मामला रफा-दफा करने का काम किया है। कहा कि यदि पुलिस-प्रशासन से इंसाफ नहीं मिला तो वह लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। डिप्टी कलक्टर रामनयन सिंह ने बाबू खां को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना बिनौली प्रभारी निरीक्षक रवेंद्र कुमार ने कहा कि बाबू खां की तहरीर पर कार्रवाई की गई है।

हवा हुए एकजुटता के दावे, कैप्टन सरकार और एसजीपीसी के मंच अलग–अलग

हरनेक सिंह जैनपुरी, कपूरथला

श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मिलकर मनाने के दावे करने वाली पंजाब सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने अब अलग-अलग रास्ते अपना लिए हैं। नानक नगरी सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा श्री बेर साहिब के पास सरकार स्टेज और पंडाल बनवा रही है। दूसरी ओर एसजीपीसी ने गुरु नानक स्टेडियम में स्टेज और पंडाल लगाने का ठेका आठ करोड़ रुपये में दे दिया है।

गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों के विपरीत पंजाब सरकार और एसजीपीसी एक मंच पर आने को तैयार नहीं हैं। एसजीपीसी का आरोप है कि कैप्टन सरकार मनमर्जी करना चाहती है, जबकि पंजाब सरकार एसजीपीसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। 12 नवंबर को सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश-विदेश से संगत पहुंचेगी। दुनिया में एकजुटता का संदेश जाए इसलिए श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने भी सरकार और एसजीपीसी को सभी समारोह मिलकर करवाने के आदेश दे रखे हैं। इसके बावजूद सरकार और एसजीपीसी अपने-अपने समारोह करवाने की तैयारी में जुट गई हैं। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब के पास पंजाब सरकार के विशाल पंडाल में 50 से 70 हजार संगत के बैठने की व्यवस्था होगी। पंडाल को भव्य रूप दिया जा रहा है। करीब 70 फीसद काम पूरा भी हो चुका है। 20 अक्टूबर तक स्टेज और पंडाल तैयार हो जाएंगे। दूसरी ओर एसजीपीसी ने भी गुरु नानक स्टेडियम में स्टेज और पंडाल लगाने के लिए दिल्ली की एक फर्म को ठेका दे दिया है।

बीबी जागीर कौर बोलीं, सीएम ने बैठक तक नहीं बुलाई

एसजीपीसी की तालमेल कमेटी की सदस्य बीबी जागीर कौर का कहना है कि एसजीपीसी कौम की सबसे बड़ी जत्थेबंदी है। धार्मिक समागम करवाना उसका हक है। सरकार का काम कानून व्यवस्था, यातायात और संगत को सुविधाएं मुहैया करवाना है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज तक एक भी बैठक नहीं बुलाई है। इसके विपरीत एसजीपीसी को कोस रहे हैं। अगर एसजीपीसी के समागम में बादल परिवार आता है तो क्या वह सिख नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आ सकते हैं।

'मंच संचालन की जिम्मेदारी खुद रखना चाहती है एसजीपीसी'

पंजाब सरकार की तालमेल कमेटी के सदस्य एवं कैबिनेट मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी का कहना है कि सीएम गुरु नानक जी के प्रकश पर्व को मिलकर मनाना चाहते हैं। एसजीपीसी मंच संचालन की जिम्मेदारी अपने पास रखना चाहती है। वह पहले ही अपने कार्यक्रम स्टेडियम में करवाने की घोषणा कर चुकी है। एसजीपीसी को गुरुद्वारा साहिब के अंदर धार्मिक आयोजन करने चाहिए जिसमें सीएम भी जाएंगे। बादल परिवार एसजीपीसी को निजी हितों के लिए उपयोग करता है जो संगत को पसंद नहीं है।

अखिलेश बोले, संघ देशहित में नहीं

जागरण संवाददाता, झांसी : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत पर तंज कसते हुए कहा कि उनके कार्य देशहित में नहीं हैं। अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा।

मुठभेड़ में मारे गए पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से मुलाकात के बाद झांसी में ही डेरा डाले सपा प्रमुख गुरुवार को फिर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार स्वदेशी का नारा बुलंद करती रही है, लेकिन संघ प्रमुख विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। इससे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार संघ प्रमुख से अपनी बात कहलवा रही है या वह सरकार का पक्ष ले रहे हैं। कहा कि झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का सपना दिखाया गया है, लेकिन सरकार इजरायल, अमेरिका, फ्रांस से रक्षा के सामान खरीद रही है।

चाचा शिवपाल सिंह यादव की वापसी के सवाल पर अखिलेश भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब हम साथ थे तो परिवारवाद का आरोप लगाते थे। अब लोकतंत्र हो गया तो कहते हैं एक हो जाओ। हमारे घर में लोकतंत्र है। एक ही टेबल पर कई दल हो सकते हैं।

जहानाबाद में प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद हिंसक झड़प

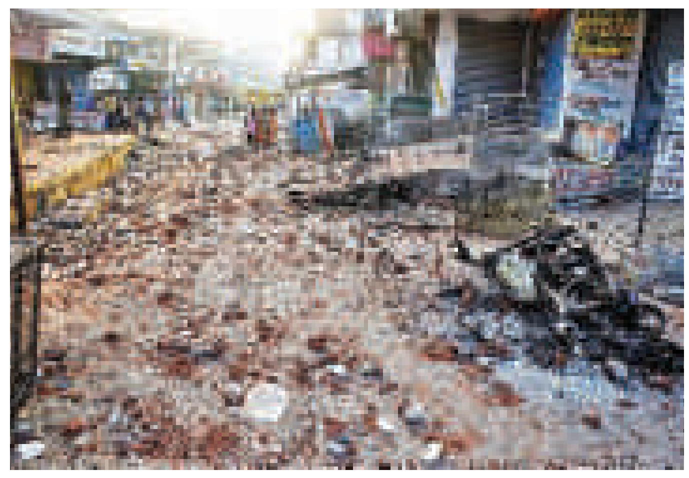

बिहार के जहानाबाद में हिंसक झड़प के बाद सड़क पर बिखरे पत्थर और जली मोटरसाइकिल। जागरण

जागरण संवाददाता, जहानाबाद

▶ विसर्जन के दौरान प्रतिमा पर पत्थर फेंकने के बाद शुरू हुआ बवाल, इंटरनेट बंद

बिहार के जहानाबाद में विसर्जन जुलूस पर पथराव से प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर बुधवार की देर रात दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प गुरुवार को भी जारी रही। पथराव के साथ शरारती तत्वों ने कई स्थानों पर आगजनी की और दुकानों में तोड़फोड़ तथा लूटपाट की।

इस दौरान सड़क पर खड़ी कई बाइकों में आग लगा दी गई। उपद्रव के बाद तनाव की जानकारी मिलते ही एडीजी (विधि व्यवस्था) अमित कुमार व आइजी पारसनाथ रैफ जवानों तथा भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे तब जाकर उपद्रवी भागे। दोनों अधिकारियों ने माहौल को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। स्थिति बिगड़ते देख शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर धारा 144 लागू कर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। शांति स्थापित करने के लिए अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च भी किया।

बुधवार देर शाम विभिन्न पूजा पंडालों से मां दुर्गा की प्रतिमा लेकर श्रद्धालु विसर्जन के लिए जा रहे थे। श्रद्धालुओं का आरोप है कि इसी दौरान किसी शरारती तत्व ने प्रतिमा पर पत्थर फेंककर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया।

उप्र में पत्रकार की गला रेतकर हत्या, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुशीनगर

▶ रंजिश में गई जान, पुलिस से एक दिन पहले जताई थी हत्या की आशंका

उप्र के कुशीनगर में एक दैनिक अखबार के पत्रकार और निजी विद्यालय में शिक्षक राधेश्याम शर्मा (55) की गुरुवार सुबह गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। दो लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने उनके साथ पढ़ाने वाले शिक्षक को गिरफ्तार किया है। एक आरोपित फरार है। पत्रकार ने एक दिन पूर्व सीओ को फोन कर हत्या का अंदेशा जताया था।

राधेश्याम हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकटिया के टोला बनटोलवा के निवासी थे। दुबौली गांव के निकट निर्जन स्थान पर उनका रक्तरंजित शव दिखने पर स्कूल जा रहे बच्चों ने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के गांवों के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। राधेश्याम सुबह लगभग साढ़े आठ बजे बाइक से अध्यापन के लिए अंजुमन बालिका इंटर कॉलेज सोहसा पट्टीगोसी जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने उन्हें रोका और फिर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मौके से पत्रकार की बाइक और मोबाइल बरामद किया है। डाग स्क्वायड व फारेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान खोजी कुत्ता हत्यारोपित पत्रकार के गांव के ही तेज प्रताप के घर में घुस गया और खून से सना कपड़ा ढूंढ़ निकाला। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान हत्यारोपित तेजपाल वहीं कपड़े पहने हुए था। पुलिस ने हत्यारोपित रामगोपाल सिंह को विद्यालय से ही गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार के पुत्र अजय शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही राम गोपाल सिंह व तेज प्रताप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि कुछ तथ्य सामने आए गए हैं।

गैंगस्टर सुनीव राठी तीस हजारी कोर्ट में किया गया पेश

जासं, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के आरोपित गैंगस्टर सुनील राठी को तिहाड़ जेल से तीस हजारी अदालत में पेश किया गया। राठी को एक अभियंता की हत्या के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हत्या के मामले की सुनवाई उत्तराखंड की रुड़की जिला अदालत से 2011 में दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तत्कालीन अभियंता राधे श्याम की 2006 में हत्या हुई थी, जिसका आरोप राठी पर है। राधे श्याम उस वक्त गंगा लिंक कैनाल प्रोजेक्ट का काम देख रहे थे। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राठी ने अदालत में कहा कि राधे श्याम की हत्या के मामले में उसे फंसाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके खिलाफ गलत और झूठी जांच की है। राठी ने अदालत में यह भी कहा कि उसने अदालत में गवाही न देने के लिए राधे श्याम के परिवार को कोई धमकी नहीं दी है।

'बिग बॉस–13' पर अश्लीलता फैलाने के आरोप की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

▶ विधायक के शिकायती पत्र पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लिया संज्ञान

▶ फिल्म अभिनेता सलमान खान पर रासुका लगाने की मांग

'बिग बॉस-13' रियलिटी शो पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इसके होस्ट और अभिनेता सलमान खान के अलावा संबंधित चैनल के मालिक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की भी मांग की है। मंत्रालय ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है। उधर, गुरुवार को कुछ हिंदूवादी संगठनों ने शो के विरोध में गाजियाबाद में सलमान का पुतला भी फूंका।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र भेजकर लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि इस शो को प्राइम टाइम पर प्रसारित किया जा रहा है, जबकि उस समय आमतौर पर पूरा परिवार एक साथ टीवी देखता है। पत्र में उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं यह चैनल अश्लीलता और द्वेष की भावना परोस रहा है। परिवार के साथ बैठकर इस शो को देखना मुश्किल हो गया है। हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाले इस शो पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए।

सूत्रों का कहना है कि विधायक ने शिकायत में कहा है कि अलग-अलग समुदाय के जोड़ों को शो में बिस्तर साझा कराया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है। सूत्रों की मानें तो पत्र पर संज्ञान लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। इस पर जांच शुरू भी हो गई है।

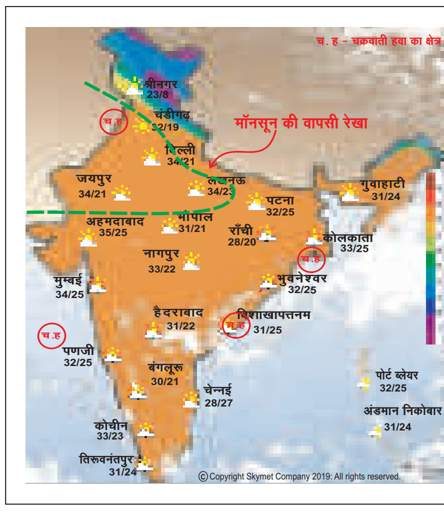

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। सुहावनी सुबह में हल्की धुंध रहेगी। छिटपुट बादलों के साथ दिन गर्म रहेगा। रात भी सुहावनी रहेगी। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह शीतल और सुहावनी रहेगी। दिन आरामदायक रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/25/व	अहमदाबाद	36/26/व
कोलकाता	34/25/आंबा	बड़ौदा	36/25/सा
चेन्नई	36/27/आंबा	नागपुर	34/23/व
हैदराबाद	31/22/सा	इन्दौर	31/22/सा
बंगलूरू	28/20/सा	रांची	30/22/व
त्रिवेन्द्रम	30/24/व	पटना	31/22/सा
गुवाहाटी	31/24/आंबा	जमशेदपुर	32/23/आंबा
गंगटोक	14/04/व	पुणे	31/22/व

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत हुई

2012 में आज ही संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया में बालिकाओं के साथ हो रहे अपराध और हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दुनिया में हर दस में से एक लड़की बीस साल की उम्र तक पहुंचने से पहले यौन शोषण का शिकार बनती है।

भारतीय सेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की

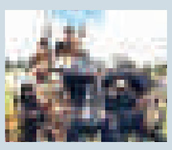

1987 में आज ही भारत की शांति सेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की। यह अभियान लिट्टे का कब्जा खत्म कर जाफना को मुफ्त कराने के लिए छेड़ा गया था। लगभग तीन सप्ताह तक चले इस अभियान से भारत की शांति सेना ने लिट्टे से जाफना को अपने नियंत्रण में ले लिया था।

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को जन्मदिन मुबारक हो

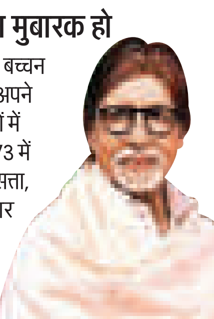

हिंदी सिनेमा के एंग्री यंग मैन, शहंशाह, बिग बी अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में प्रयागराज (इलाहाबाद) में हुआ था। अपने पचास साल के फिल्मी करियर में 190 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1969 में आई सात हिंदुस्तानी पहली फिल्म रही। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने बुलंदियों पर पहुंचाया। दीवार, डॉन, सत्ते पर सत्ता, त्रिशूल, सिलसिला जैसी अनेक बेहतरीन फिल्में रहीं। भारत सरकार ने उन्हें 1984 में पद्मश्री से, 2001 में पद्म भूषण से और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। हाल ही में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है।

ओल्गा और पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल

सम्मान ▶ स्वीडिश एकेडमी ने 2018 और 2019 के लिए विजेताओं का एलान किया

पिछले साल विवादों के चलते स्थगित कर दिया गया था यह पुरस्कार

पोलैंड की ओल्गा तोकार्जुक और ऑस्ट्रिया के पीटर हैंडके। एएफपी

स्टॉकहोम, एएफपी : साहित्य के क्षेत्र में नोबेल विजेताओं के नाम के लिए दो साल का इंतजार गुरुवार को खत्म हो गया। नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था संभालने वाली स्वीडिश एकेडमी ने 2018 और 2019 के लिए साहित्य का नोबेल जीतने वालों के नाम का एलान कर दिया है। 2018 की विजेता पोलैंड की लेखिका ओल्गा तोकार्जुक और 2019 के विजेता ऑस्ट्रिया के उपन्यासकार व पटकथा लेखक पीटर हैंडके बने हैं।

पिछले साल एक सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद उपजे विवाद के चलते स्वीडिश एकेडमी ने साहित्य के नोबेल विजेता का एलान नहीं किया था। इसलिए इस साल साहित्य के नोबेल को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई थी। 2018 के लिए विजेता चुनी गई ओल्गा को पोलैंड में अपनी पीढ़ी की सर्वाधिक प्रतिभाशाली उपन्यासकारों में शुमार किया जाता है। एकेडमी ने बताया कि ओल्गा को एक ऐसे विमर्श की परिकल्पना के लिए सम्मान मिला है, जो सीमाओं को लांघने की विश्वव्यापी चाहत को दर्शाती है। वहीं, हैंडके की किताबें सरल भाषा में मानव अनुभवों का नया आयाम दिखाती हैं। एकेडमी ने कहा कि हैंडके ने खुद को यूरोप के सर्वाधिक प्रभावशाली लेखकों में शुमार कराया है। उनके काम में कुछ नया खोजने और उस खोज को साहित्य के जरिये जीवन में लाने की ललक दिखाई देती है। ओल्गा और हैंडके में से प्रत्येक को 90 लाख स्वीडिश क्रोनर (करीब 6.46 करोड़ रुपये) की राशि बतौर पुरस्कार मिलेगी। 1901 से अब तक 116 लोगों को साहित्य का नोबेल मिल चुका है। तोकार्जुक इनमें 15वीं महिला हैं।

नोबेल पुरस्कार के आलोचक रहे हैं हैंडके : ऑस्ट्रिया के पीटर हैंडके साहित्य में मिलने वाले नोबेल के आलोचक रहे हैं। 2014 में उन्होंने कहा था कि यह पुरस्कार कुछ देर लोगों का ध्यान विजेता की ओर खींचता है, अखबार के कुछ पन्ने उसके लिए रंग दिए जाते हैं और उसे नकली संत जैसी उपाधि मिल जाती है। हैंडके 1929 के नोबेल विजेता और जर्मन साहित्यकार थॉमस मैन को बेहद घटिया लेखक मानते हैं। 1942 में जन्मे हैंडके 1966 में अपने उपन्यास 'द हॉर्नेट्स' से लोगों की निगाह में आए थे। उनकी किताब 'अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स' को भी खासी लोकप्रियता मिली। 1971 में मां की खुदकशी के बाद उन्होंने यह किताब लिखी थी। वह कई फिल्मों के पटकथा लेखक भी रहे हैं।

आज शांति के नोबेल विजेता का आएगा नाम : इस साल नोबेल विजेताओं के नाम के एलान की शुरुआत सोमवार को चिकित्सा क्षेत्र के विजेताओं से हुई थी। मंगलवार को भौतिकी और बुधवार को रसायन के क्षेत्र में नोबेल विजेताओं का नाम सामने आया। इस कड़ी में शुक्रवार को शांति के नोबेल विजेता का नाम बताया जाएगा। अगले सोमवार को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता के एलान के साथ इस साल के विजेताओं की घोषणा का क्रम पूरा होगा। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य व अर्थशास्त्र का नोबेल और ओस्लो में शांति का नोबेल दिया जाएगा।

कई बेस्टसेलर हैं ओल्गा के नाम

▶ पर्यावरणविद ओल्गा की पहचान एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी है, वह पोलैंड सरकार की आलोचना करने के लिए सुर्खियों में रहती हैं

57 वर्षीय ओल्गा तोकार्जुक के नाम कई बेस्टसेलर किताबें हैं। ओल्गा सच और रहस्य को मिलाकर खास अंदाज में लिखती हैं। शाकाहारी और पर्यावरणविद ओल्गा की पहचान एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी है, जो पोलैंड की दक्षिणपंथी सरकार की आलोचना करने से भी नहीं चूकती हैं। तोकार्जुक ने एक साक्षात्कार में कहा था, 'मेरे पास अपनी कोई जीवनी नहीं है, जिसे मैं याद कर सकूं। मैं बहुत से अलग-अलग चरित्रों से बनी हूं, जो मेरे दिमाग से निकले हैं और जिन्हें मैंने गढ़ा है।' उनकी किताबों पर नाटक और फिल्में बन चुकी हैं और हिंदी, जापानी समेत 25 से ज्यादा भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। 2007 में लिखे उपन्यास 'फ्लाइट्स' के लिए उन्हें किताब की अनुवादक जेनिफर क्रॉफ्ट के साथ बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिल चुका है।

इधर-उधर की

पेरिस में चोर ने कलाई से छीनी छह करोड़ की घड़ी

पेरिस, एजेंसी : फ्रांस की राजधानी पेरिस में सिगरेट लेने होटल से बाहर आए एक जापानी व्यक्ति की कलाई से चोर छह करोड़ रुपये (7.7 लाख यूरो) की हीरे जड़ित घड़ी छीनकर भाग गया। तीस वर्षीय पीड़ित होटल के बाहर सिगरेट लेने निकला था। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और सिगरेट मांगने लगा। जैसे ही जापानी व्यक्ति ने सिगरेट देने के लिए हाथ बढ़ाया तो चोर ने तेजी से उसकी कलाई पर बंधी घड़ी पर झपट्टा मारा और भाग गया। रिचर्ड मिले कंपनी की इस घड़ी की कीमत छह करोड़ रुपये है। हालांकि भागते समय चोर का मोबाइल घटनास्थल पर गिर गया था, जिसके माध्यम से पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जनवरी और सितंबर के बीच पेरिस और आसपास के उपनगरों में चार और रिचर्ड मिले घड़ी की चोरी हो चुकी है, जिनकी कीमत 109,000 डॉलर है।

स्वच्छ पर्यावरण के लिए निर्माण उद्योग घटाएगा 44 फीसद उत्सर्जन

कोपेहेगन, आइएएनएस : स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए निर्माण उद्योगों का उत्सर्जन भी उतना ही खतरनाक है, जितने अन्य कारक। जलवायु की विविधता को यदि बचाए रखना है तो निर्माण उद्योगों के उत्सर्जन में भी कमी लानी होगी। कई देशों में इसके लिए बनी नीतियों पर काम भी शुरू हो चुका है और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी आधार पर एक रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि वर्ष 2050 तक निर्माण उद्योग उत्सर्जन में कम से कम 44 फीसद कटौती कर सकता है। 'बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंजंप्शन इमीशन' नामक यह रिपोर्ट सी40 शहरों द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें लीड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने निर्माण के छह मुख्य क्षेत्रों में सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि निर्माण के कारण जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके।

ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने से होने वाले फायदों को देखते हुए शोधकर्ताओं ने कहा कि यदि हम निर्माण उद्योग के उत्सर्जन में भी कटौती करें तो इसके सामाजिक, आर्थिक लाभ देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम 'स्वच्छ निर्माण' की ओर बढ़ते हैं तो इससे पर्यावरण तो स्वच्छ होगा ही, साथ ही वायु और ध्वनि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा इस उद्योग में मामूली परिवर्तन किए जाएं तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे।

शोध अनुसंधान

अच्छे खानपान से कम होता है अवसाद का खतरा

अच्छा खानपान शरीर ही नहीं, दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी जरूरी है। हालिया शोध के मुताबिक, फल एवं सब्जियों वाले स्वास्थ्यप्रद खानपान की मदद से अवसाद का खतरा कम करने में भी मदद मिलती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अवसाद के ऐसे मरीज जिनका खानपान सही नहीं था, तीन हफ्ते लगातार स्वास्थ्यप्रद खानपान देने से उनमें अवसाद के लक्षण कम हो गए। शोध में 17 से 35 साल के 76 लोगों को शामिल किया गया था। इसमें एक समूह को बेहतर खानपान की जानकारी देते हुए अपनी डाइट को सही रखने के लिए कहा गया, जबकि दूसरा समूह अपनी सामान्य दिनचर्या और डाइट पर बना रहा। तीन हफ्ते बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि डाइट में सुधार करने वाले समूह में अवसाद के लक्षण उल्लेखनीय रूप से कम हो गए। खानपान सही रखने वालों में तीन महीने बाद भी अन्य की तुलना में अवसाद के लक्षण बहुत कम रहे। - प्रेट्र

नपुंसकता को दूर करने में मददगार हो सकता है टमाटर

वातावरण में बढ़ते प्रदूषण और अनियमित खानपान जैसे कारणों से नपुंसकता एक गंभीर समस्या की तरह सामने आई है। अब वैज्ञानिकों ने इसके इलाज की दिशा में नई कामयाबी हासिल की है। हालिया शोध के मुताबिक, टमाटर में लैक्टोलाइकोपीन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो नपुंसकता दूर करने में मददगार हो सकता है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के एलन पेसी ने कहा, 'शोध की शुरुआत में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन नतीजे देखते ही मैं उछल पड़ा था।' शोध के दौरान 19 से 30 साल के 60 स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि नतीजे नपुंसकता की समस्या को देखने का नया नजरिया दे सकते हैं। एक सप्लीमेंट की मदद से इस परेशानी से निपटने का रास्ता मिलने की उम्मीद बनी है। हालांकि अभी इस दिशा में और अध्ययन की जरूरत है। - आइएएनएस

शोधकर्ताओं ने खोज निकाला सिंगल यूज प्लास्टिक को नष्ट करने वाला बैक्टीरिया

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▶ ग्रेटर नोएडा के शिव नाडर विश्वविद्यालय के छात्रों ने वेटलैंड से खोजे दो जीवाणु

प्रतीकात्मक

पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन चुके सिंगल यूज प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए जैविक तरीका खोज लिया गया है। ग्रेटर नोएडा स्थित शिव नाडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने परिसर से सटे वेटलैंड में दो ऐसे जीवाणुओं की खोज की है जो सिंगल यूज प्लास्टिक के मुख्य तत्व पॉलीस्टीरीन विघटित करने की क्षमता रखते हैं। यह खोज वैश्विक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक से उपजी समस्या से निपटने में कारगर हो सकती है। यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल रॉयल सोसाइटी ऑफ केमेस्ट्री में प्रकाशित भी हो चुका है।

पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसी समस्या बन चुका है जिसका निदान सरकार भी नहीं तलाश पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण में देशवासियों से भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का आह्वान किया था। धरती पर मौजूद सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट करने में सैकड़ों साल लगेंगे। ऐसे में शिव नाडर विवि के शोधकर्ताओं की खोज पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए सिंगल यूज प्लास्टिक को जैविक तरीके से नष्ट करने में मददगार होगी। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि एक्जिबोबैक्टीरियम सिबिरिकम स्ट्रेन डीआर 11 व एक्जिगुओबैक्टीरियम स्ट्रेन डीआर 14 में सिंगल यूज प्लास्टिक के मुख्य तत्व पॉलीस्टीरीन को विघटित करने की क्षमता है। पॉलीस्टीरीन का आणुविक भार अधिक व रासायनिक श्रृंखला लंबी होने के कारण इसका प्राकृतिक तरीके से विघटन सैकड़ों साल में हो पाता है। खोजे गए बैक्टीरिया विघटन की इस प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक को नष्ट होने में कम समय लगेगा। विवि की एसोसिएट प्रोफेसर ऋचा प्रियदर्शिनी ने बताया कि वेटलैंड प्रकृति की जैव विविधता का मुख्य स्रोत हैं। वेटलैंड में पाए जाने वाले जीवाणु की मदद से सिंगल यूज प्लास्टिक को जैविक तरीके से नष्ट किया जा सकता है। भारत में सालाना 16.5 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक की खपत है। इसमें करीब 14 मिलियन मिट्रिक टन पॉलीस्टरीन का उत्पादन होता है। इसे नष्ट होने में 450 साल तक का लंबा वक्त लगता है।

65 सालों में धरती से टकरा सकता है 2019 एसयू 3

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने एक ऐसे क्षुद्र ग्रह की खोज की है, जो 65 सालों में यानी 16 सितंबर, 2084 को धरती से टकरा सकता है। हालांकि धरती से टकराने की आशंका .65 फीसद है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम 2019 एसयू 3 रखा है। इस आकाशीय पिंड का अनुमानित व्यास 46 फीट है और इसे चौथे सबसे खतरनाक क्षुद्रग्रह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

कम दूरी बन सकती है खतरा : ईएसए के मुताबिक, 16 सितंबर, 2084 को यह क्षुद्रग्रह धरती से टकरा सकता है और यह केवल 73,435 मील की दूरी से पृथ्वी के बेहद पास से गुजरेगा। क्योंकि यह पृथ्वी के इतने निकट से गुजरेगा, विशेषज्ञों का मानना है कि धरती के पड़ोसी ग्रहों के गुरुत्वीय खिंचाव की वजह से यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है।

अपोलो क्षुद्रग्रह : एजेंसी के मुताबिक, 2019 एसयू 3 एक अपोलो क्षुद्रग्रह है, जो 1930 के दशक में खोजे गए क्षुद्रग्रहों के एक समूह का हिस्सा है। इस क्षुद्र ग्रह ने शुक्र, बुध और मंगल की कक्षाओं को पार कर लिया है, जहां से घातक गुरुत्वीय खिंचाव आ सकता है।

नहीं पड़ेगा ज्यादा प्रभाव

वैज्ञानिकों का कहना है यदि क्षुद्रग्रह धरती से टकरा भी जाता है तो इसका इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आकार में यह ज्यादा बड़ा नहीं है।

भविष्य में खतरा

पिछले महीने ही एजेंसी ने उल्लेख किया है कि अगले 100 वर्षों पृथ्वी से छोटे-बड़े 878 क्षुद्रग्रह टकरा सकते हैं और यह भी बताया कि एक छोटे से क्षुद्रग्रह से भी गंभीर तबाही हो सकती है। ऐसे में धरती से टकराव के जोखिम को कम करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कई अन्य समूह मिलकर इन क्षुद्रग्रहों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने में लगे हैं।

ब्राजील में समुद्र तटों पर फैला तेल

ब्राजील के अराकाजू में समुद्र तटों पर खतरनाक ढंग से फैल रहा कच्चा तेल पर्यावरण के साथ-साथ समुद्री जीव-जंतुओं के लिए प्राणघातक सिद्ध हो रहा है। पर्यावरण मंत्री रिकार्डो सालेस ने आशंका व्यक्त की है कि पूर्वोत्तर समुद्र तटों को प्रदूषित करने वाला तेल वेनेजुएला से आ रहा है। हालांकि वेनेजुएला ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। करीब 130 समुद्र तटों पर 100 टन से ज्यादा कच्चा तेल जमा हो गया है और यह देश के करीब नौ प्रदेशों तक फैला है। इसे गंभीर आपदा के रूप में देखा जा रहा है। _एपी

अपना दूध पिलाकर चीते की परवरिश कर रही मादा डॉग

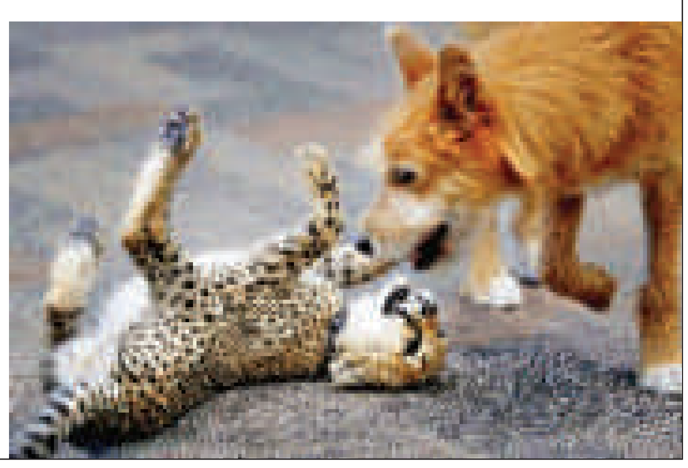

अमेरिका के ओहियो प्रांत के प्रमुख शहर सिनसिनाटी के चिड़ियाघर एवं बॉटनिकल गार्डन में मादा कुत्ते के साथ खेलता चीते का शावक क्रेस। इस शावक का 7 जुलाई को ही मैस्ट ब्रीडिंग सेंटर में जन्म हुआ है। भारत में करीब 70 साल पहले ही चीते को लुप्त प्राणी घोषित कर दिया गया था, लेकिन कुछ देशों में लुप्त प्रजाति के चीतों के संरक्षण काम किया जा रहा है। इस चिड़ियाघर में चीते और कुत्ते की एक साथ रहने वाली सफल जोड़ी है। क्रेस, एकमात्र जीवित शावक है जिसे मादा कुत्ता अपना दूध पिलाकर परवरिश कर रही है। एपी

स्क्रीन शॉट

अक्षय ने दिखाई 'सूर्यवंशी' की झलक

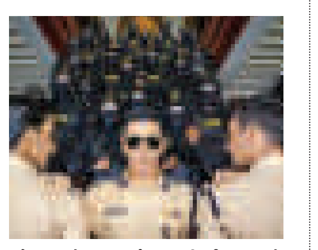

अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म 'सूर्यवंशी' की रिलीज तारीख की घोषणा कर दी है। उन्होंने रोहित शेट्टी निर्देशित 'सूर्यवंशी' की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें वह सिंबा यानी रणवीर सिंह और सिंघम यानी अजय देवगन तीनों पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ अक्षय ने लिखा है, 'कॉप यूनिवर्स के देसी एवेंजर्स! जब बाजीराव सिंघम की मुलाकात होती है संग्राम सिंबा भालेराव और सूर्यवंशी से तो 27 मार्च 2020 को केवल पटाखों की नहीं, बल्कि ब्लास्ट की उम्मीद करें।' 'सूर्यवंशी' पहले अगले वर्ष ईद पर रिलीज होने वाली थी। उसी दिन सलमान खान की 'इंशाअल्लाह' को भी रिलीज होना था। सलमान के आग्रह पर रोहित ने फिल्म की रिलीज तारीख बदलकर 27 मार्च कर दी थी। 'इंशाअल्लाह' के न बनने की खबर के बाद अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' को अगले साल ईद पर रिलीज करने की घोषणा कर दी है। अब ईद पर भले ही 'सूर्यवंशी' के साथ नहीं, लेकिन 22 मई 2020 को रिलीज होने वाली 'लक्ष्मी बॉम्ब' के साथ सलमान की फिल्म का मुकाबला होगा। खबरें हैं कि ईद पर सलमान खान की फिल्म 'इंडियाज मोस्ट वांटेड कॉप राधे' रिलीज हो सकती है। सूत्रों की माने तो सोहैल खान के ऑफिस में प्रभुदेवा और सलमान खान की मुलाकात इसी फिल्म को लेकर हुई थी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म कोरियन फिल्म 'द आउटलॉज' की हिंदी रीमेक हो सकती है। फिलहाल सलमान खान अपनी आगामी फिल्म 'दबंग 3' में व्यस्त हैं, जो इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होगी।

फिल्म 'बाला' की वजह से टली 'मरजावां' की रिलीज डेट

रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म 'मरजावां' की रिलीज डेट एक बार फिर आगे खिसक गई है। सात नवंबर को आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म 'बाला' के रिलीज होने की वजह से फिल्म 'मरजावां' अब 15 नवंबर को रिलीज होगी। इससे पहले 'मरजावां' दो अक्टूबर को रिलीज होनी थी पर 'वार' और 'सैय रा नरसिम्हा रेड्डी' जैसी दो बड़ी फिल्में रिलीज होने के कारण इसकी रिलीज को टाल दिया गया। 23 अगस्त को जारी किए गए पोस्टर में 'मरजावां' की रिलीज डेट को 22 नवंबर बताया गया था। तीन सितंबर को एक बार फिर निर्माताओं द्वारा फिल्म की रिलीज डेट को बदल कर आठ नवंबर कर दिया। फिल्म 'बाला' की रिलीज डेट में भी काफी उलटफेर किया गया। इससे पहले करण जौहर ने 15 नवंबर को 'बाला' के रिलीज होने की घोषणा की थी। गुरुवार को रिलीज हुए 'बाला' के ट्रेलर में रिलीज डेट सात नवंबर दिखाई गई है। 'मरजावां' की रिलीज डेट टलने पर फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने ट्वीट किया, 'मैडॉक फिल्म्स के साथ मेरा पुराना नाता रहा है, और दिनेश विजन मेरे अच्छे मित्र हैं। मैंने 'बाला' के लिए 'मरजावां' कि रिलीज को 15 नवंबर 2019 तक आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मेरी तरफ से टीम को शुभकामनाएं।' मिलाप जावेरी निर्देशित 'मरजावां' में रितेश और सिद्धार्थ के अलावा तारा सुतारिया, रकुलप्रीत सिंह और रवि किशन मुख्य भूमिकाओं में हैं।

'टर्मिनेटर : डार्क फेट' में अर्नाल्ड का एक्शन होगा अनोखा!

हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म की फेहरिस्त में 'टर्मिनेटर' एक ऐसी फिल्म है, जिसकी सीरीज वर्ष 1984 से अब तक बन रही है। 1984 में रिलीज हुई फिल्म 'द टर्मिनेटर' ने अर्नाल्ड श्वार्जनेगर को मेगास्टार का खिताब दिलाया था। अब इस फ्रेंचाइजी की नई फिल्म 'टर्मिनेटर : डार्क फेट' रिलीज के लिए तैयार है। यह फिल्म छह भाषाओं में एक नवंबर को रिलीज होगी। इस सीरीज की खास बात होगी फिल्म का विजुअल इफेक्ट और एक्शन। अर्नाल्ड के मुताबिक, अब तक की उनकी सभी टर्मिनेटर वाली फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म का एक्शन अनोखा होगा और जिस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल फिल्म में किया गया है, वैसा पहले नहीं देखा गया है। फिल्म में अर्नाल्ड के साथ अभिनेत्री लिंडा हैमिल्टन भी होंगी, जो उनके साथ पहली 'टर्मिनेटर' फिल्म में भी थीं। लिंडा के फिल्म में होने से अर्नाल्ड बेहद खुश हैं, उनका कहना है कि यह पुराने दिनों में लौटने जैसा है, लेकिन फिल्म की कहानी बेहद अलग होगी। फिल्म में निर्देशक जेम्स कैमरून की छाप देखने को मिलेगी। वर्ष 1984 में रिलीज हुई 'द टर्मिनेटर' की यादों को ताजा करते हुए अर्नाल्ड ने बताया कि उन्हें इस फिल्म में मशीन बनना था। उन्होंने इस किरदार के लिए अभिनेता यूल ब्रायनर की फिल्म 'वेस्टवर्ल्ड' के किरदार से प्रेरणा ली थी। अर्नाल्ड का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने इस किरदार को निभाया था, वह विश्वसनीय और दमदार था। दरअसल, अर्नाल्ड पहली 'टर्मिनेटर' फिल्म के लिए निर्देशक जेम्स कैमरून से फिल्म के दूसरे किरदार रीज के लिए बात करने गए थे, लेकिन जेम्स को लगा कि अर्नाल्ड टर्मिनेटर का किरदार अच्छी तरह से निभा सकते हैं। 'टर्मिनेटर-डार्क फेट' इस सीरीज की छठवीं फिल्म होगी।

एक्शन फिल्मों के प्रति बदली धारणा

रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वॉर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है। फिल्म ने सात दिनों में ही 200 करोड़ की कमाई कर ली है। इस रिस्पांस से अभिभूत रितिक ने कहा, 'हम ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे, जो पश्चिम की श्रेष्ठ एक्शन फिल्मों का मुकाबला कर सके। इस फिल्म से भारत की एक्शन फिल्मों के बारे में धारणा बदली है।' उन्होंने कहा, मै 'वॉर' के सभी कलाकारों और टीम से बेहद खुश हूं, क्योंकि हम सभी ने बहुत मेहनत की।' दूसरी और टाइगर मानते हैं कि इस फिल्म की सफलता उनके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उन्हें इस फिल्म में उनके प्रेरणास्रोत रितिक के साथ काम करने का मौका मिला। टाइगर कहते हैं -जिस तरह से फिल्म को लगातार सफलता मिल रही है, वह उनके लिए बड़ी बात है।

अध्ययन

विज्ञान के पहलुओं को जोड़ती है नैनो तकनीक

यह अणुओं और परमाणुओं की इंजीनियरिंग है जो जैव-सूचना व प्रौद्योगिकी जैसे विषयों को साथ लाती है, नैनोकण के उपयोग से मानव जीवन सरल हुआ है, पर इनका अत्यधिक प्रयोग हानिकारक हो सकता है...

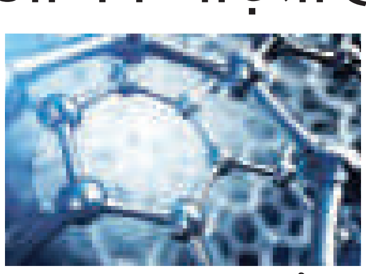

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : नैनो तकनीक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। नैनो एक ग्रीक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ सूक्ष्म या छोटा होता है। हर वो कण जिसका आकर 100 नैनोमीटर या इससे छोटा हो नैनोकण माना जाता है। किसी नैनोकण की सूक्ष्मता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मनुष्य के बालों का व्यास 60 हजार नैनोमीटर होता है। नैनो-टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1974 में नॉरियो तानिगुची द्वारा किया गया था। यह अणुओं और परमाणुओं की इंजीनियरिंग है, जो भौतिकी, रसायन, जैव-सूचना व जैव-प्रौद्योगिकी विज्ञान जैसे विषयों को आपस में जोड़ती है। धरती पर जीवन के आरंभ के समय से निरंतर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ- विभिन्न नैनोकणों का निर्माण हो रहा है।

अत्यधिक सूक्ष्म आकार के कारण नैनोकणों के रसायनिक एवं भौतिक लक्षण बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए जिंक धातु के नैनोकण बनने पर ये पारदर्शी हो जाते हैं। नैनोकणों का उपयोग उपभोक्ता उत्पादों से लेकर चिकित्सा उपकरणों, सौंदर्य प्रसाधन, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रकाशिकी, पर्यावरण, भोजन तथा पैकेजिंग, ईंधन, ऊर्जा, कपड़ा और पेंट, नई पीढ़ी की दवाएं और प्लास्टिक इत्यादि में हो रहा है।

कृषि क्षेत्र में भी हो रहा उपयोग : भारतीय शोधकर्ताओं ने रबड़ से बनी हाई-परफार्मेंस नैनो-कम्पोजिट सामग्री विकसित की है, जिसका उपयोग टायरों की भीतरी ट्यूब और इनर लाइनरों को मजबूती प्रदान करने में किया जा सकता है। कृषि में नैनोकणों का उपयोग नैनो-उर्वरक, नैनो कीटनाशक/खरपतवारनाशी, भंडारण, संरक्षण, उत्पाद गुणवत्ता सुधार तथा फ्लेवर आदि में हो रहा है। नैनोकणों ने न सिर्फ फसलों की वृद्धि, बल्कि कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीवों को भी प्रभावित किया है।

दो प्रकार के होते हैं नैनोकण : मोटे तौर पर नैनोकणों को कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। अकार्बनिक नैनोकण धातु (चांदी, एल्यूमीनियम, टिन, सोना, कोबाल्ट, तांबा, लोहा, मोलिब्डेनम, निकल, टाइटेनियम) एवं उनके धातु-ऑक्साइड का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। वही, जिंक ऑक्साइड नैनोकणों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। गोल्ड नैनोकणों की कोटिंग से ऊंची इमारतों या गाड़ियों के ग्लास आसानी से साफ किए जा सकते हैं। कॉपर के नैनोकण फफूंद तथा जीवाणुनाशक के रूप में चिकित्सा में प्रयोग हो रहे हैं। इनमें बैक्टीरिया तथा फफूंद को नष्ट करने की क्षमता होती है।

बढ़ी स्वास्थ्य की चिंता : नैनोकणों के उपयोग के साथ कुछ चुनौतियां भी उभर रही हैं। धात्विक नैनोकणों के उत्पादन और उपयोग में लगातार वृद्धि होने के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिट्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नैनोकणों का भंडार बन रही है। शोध पत्रिका साइंस एंड टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित शोध के मुताबिक शुद्ध पानी में उगाए गए पौधों की तुलना में कॉपर-ऑक्साइड नैनोकणों से प्रदूषित पानी में उगाए गए जौ की जड़ों में कॉपर की मात्रा 5.7 गुना और पत्तियों में 6.4 गुना अधिक पाई गई है।